वार्षिक रिपोर्ट

1974-75

भारत सरकार
शिक्षा तथा समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय
(शिक्षा तथा संस्कृति विभाग)
नई दिल्ली
1975

-54
370.6
IND-R
1974-75

प्रकाशन संख्या 1/75- हिन्दी

विषय-सूची

		पृष्ठ
प्रस्तावना	. . . .	(i)
शिक्षा विभाग		
आध्याय		
1.	स्कूल शिक्षा	1
2.	उच्च शिक्षा और अनुसन्धान . . .	14
3.	तकनीकी शिक्षा	39
4.	छात्रवृत्तियां	54
5.	पुस्तक प्रोन्नति तथा कॉपीराइट . .	68
6.	युवक कल्याण, राष्ट्रीय एकता, खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा	76
7	भाषाएं	93
8.	यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग और शैक्षिक आयोजकों एवं प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालेज	110
9.	प्रौढ़ शिक्षा	117
10.	संघ-शासित क्षेत्रों में शिक्षा . . .	121
11.	निकासी गृह कार्य	134
संस्कृति विभाग		
1.	सांस्कृतिक कार्य	139
2.	पुरातत्व	160
3.	भारत का नरतत्वीय सर्वेक्षण . . .	165
4.	संग्रहालय, कला वीथीयां, अभिलेखागार और पुस्तकालय	168
	शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	182
	परिशिष्ट : चर्चित बिषयों का वित्तीय आवन्टन	185
	चार्ट	207

प्रस्तावना

सन् 1968 में संसद द्वारा पारित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षिक विकास के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आरम्भ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है। यह बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में एक सर्वोच्च सलाहकार संस्था है जिसमें सभी राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के शिक्षा मन्त्री तथा विख्यात शिक्षाविद् सम्मिलित हैं। सितम्बर 1972 में हुए अपने 36 वें अधिवेशन में, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने ऐसा पुनरीक्षण किया था और पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए विस्तृत कार्यक्रमों की सिफारिश की थी। इन कार्यक्रमों पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 3,320 रुपये खर्च होने का अनुमान था। आशा की गई थी कि इस विशाल राशि तथा योजनेतर साधनों के उपयोग से राज्य सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति करेंगी। तथापि, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले यह स्पष्ट हो गया कि शिक्षा के लिए योजनागत संसाधन 2200 करोड़ रुपये से अधिक उपलब्ध न हो सकेंगे। तदनुसार, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने एक संशोधित कार्यक्रम तैयार किया जिसमें 2200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकताओं के अन्दर ही प्राथमिकताएं दर्शायी गई थीं। किन्तु पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में केवल 1726 करोड़ रुपये की व्यवस्था ही की जा सकी। इसका कारण प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां हैं, वार्षिक योजनाओं के लिए उपलब्ध की गई राशि भी आशा से कम ही रही।

तदनुसार, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की फिर बैठक हुई और उसने 4-5 नवम्बर 1974 को हुए अपने 37वें अधिवेशन में इस स्थिति पर विचार किया। इससे पहले सभी राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों की भी बैठक हुई जिसमें इस परिस्थिति पर विचार किया गया और उन्होंने बोर्ड के सम्मुख अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। बोर्ड को प्रधान मन्त्री की सुनने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। बोर्ड इस बात से सहमत था कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों में, जिनमें से देश गुजर रहा ह, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त शिक्षा को भी आर्थिक कठिनाइयों का

सामना करना होगा। तथापि, बोर्ड ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि देश और समाजार्थिक प्रगति के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लिए बड़ी मात्रा में कटौतियों का प्रभाव अच्छा नहीं होगा।

बोर्ड ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश की कि उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत ही यथा सम्भव सर्वोत्तम शैक्षिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं :-

(1) सभी योजनेतर खर्च का पुनरीक्षण, ताकि ऐसे कार्यक्रमों और प्रणालियों को छोड़ा जा सके जो अब उपयुक्त नहीं हैं तथा धन का उपयोग नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने अथवा कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए, जिन्हें अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, किया जाए।

(2) योजनागत तथा योजनेतर धन को इकट्ठा करना जिससे कि योजनेतर मदों से होने वाली बचतों का उपयोग विकास कार्यकलापों के लिए किया जा सके।

(3) शैक्षिक कर्मचारियों का और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग।

(4) उपलब्ध भवनों और उपस्कर का और अच्छा उपयोग जिससे कि और अधिक छात्रों को उसके अन्तर्गत लाया जा सके अथवा नये कार्यक्रमों का विकास किया जा सके; और

(5) योजनागत आबंटन के समर्थन में सामुदायिक सहयोग का उपयोग करना।

बोर्ड ने चार सूत्री सामान्य नीति की भी सिफारिश की जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :—

(i) विद्यमान संस्थाओं को युक्तिसंगत बनाकर, समुचित स्तर बनाए रखकर और दाखिले में वृद्धि को नियमित करके माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अवस्थित और अनियोजित विस्तार को नियंत्रित करना। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना में कठोरता बरती जाए और सिवाय उन क्षेत्रों में जो अविकसित हैं नए कालेज स्थापित न किए जायें। यद्यपि पूर्णकालिक आधार पर दाखिले में विस्तार को, पिछड़े वर्गों और समाज के निर्धन लोगों के लिए समुचित आरक्षण करके नियन्त्रित किया जाना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि उच्च शिक्षा उन सभी व्यक्तियों को मिल सके जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं।

(ii) कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर, जो विशेष महत्व और प्राथमिकता वाले हैं, प्रयास केन्द्रित किया जाना चाहिए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों को सर्वव्यापी बनाना, गुणात्मक सुधार, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, 10+2+3 की एकसमान पद्धति अपनाना, युवक सेवाओं का विकास और 15-29 आयु वर्ग के गैर–स्कूली युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम सम्मिलित है ।

(iii) शिक्षा की केवल औपचारिक पद्धति पर ही बल नहीं दिया जाना चाहिए और इस पद्धति के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा भी सम्मिलित की जानी चाहिए । बहुस्थलीय प्रवेश और अंशकालिक शिक्षा के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर अपनाएं जाने चाहिएं । माध्यमिक और विश्वविद्यालयीय स्तरों पर अंशकालिक तथा पत्राचार शिक्षा का विकास किया जाना चाहिये ।

(4) शैक्षिक पुनर्गठन के सभी कार्यक्रमों में अध्यापकों, विद्यार्थियों और समाज के सक्रिय सहयोग के माध्यम से सभी शिक्षा संस्थाओं में उत्साहपूर्ण और कठोर कार्य का वातावरण तैयार किया जाना चाहिए ।

आलोच्य वर्ष के दौरान, कठिन आर्थिक परिस्थिति और फलस्वरूप साधनों की अपर्याप्तता के बावजूद, अनेक दिशाओं में अच्छी प्रगति की रिपोर्टें मिली हैं ।

प्रमुख उपलब्धियों में, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के स्तर में सुधार के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित हैं । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक प्रमुख सिफारिश की गई थी । सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कालेजों तथा कुछ अन्य केन्द्रीय उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के लिए संशोधित वेतनमान स्वीकार किए गए । तद्नुसार, राज्य सरकारों को, संशोधित वेतनमान अपनाने के फलस्वरूप पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अतिरिक्त खर्च के 80 प्रतिशत तक सहायता की पेशकश की गई है (पांचवीं योजना के पश्चात आशा है कि वित्त आयोग इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की आवश्यकताओं पर विचार करेगा) । राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत और प्रौद्योगिकी संस्थानों में तथा स्नातकोत्तर इंजीनियरी संस्थाओं में छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि की गई ।

शैक्षिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यत: राज्य सरकारें ही उत्तरदायी हैं । इनमें से अधिकांश ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में समझे जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में कार्यवाही करनी प्रारम्भ कर दी है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है ।

राज्य योजनाएं

वर्ष 1974-75 के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु कुल 184.77 करोड़ रुपए का योजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसमें से 60.07 करोड़ रुपए केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये और 124.70 करोड़ रुपए राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए थे। योजनागत कुल 124.70 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 1974-75 के दौरान 109 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। वर्ष 1974-75 के लिए कुल परिव्यय अर्थात् 60.09 करोड़ रुपए का लगभग 50% प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया था जिस पर संभावित खर्च लगभग 50 करोड़ रुपए होगा। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए अपनी-अपनी योजनाओं में सम्मिलित प्रमुख कार्यक्रमों में, प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार, 10+2+3 शिक्षा पद्धति, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण, कार्यानुभव, कोटि सुधार कार्यक्रम, युवक सेवा कार्यक्रम और समाज शिक्षा सम्मिलित हैं। यद्यपि 1974-75 में असम, जम्मू और काश्मीर और पश्चिम बंगाल आदि ने 10+2+3 की नई शिक्षा पद्धति प्रारम्भ करने की व्यवस्था कर ली थी तथापि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल ने यह शिक्षा पद्धति पहले ही लागू कर दी है। अधिकांश राज्यों ने व्यावसायीकरण और कार्यानुभव की योजनाओं के लिए व्यवस्था कर दी थी।

वर्ष 1974-75 के लिए शिक्षा की वार्षिक योजना का आकार संभवत: 181 करोड़ रुपए का होगा जिसमें से 118 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र में होंगे। वित्तीय साधनों की तंगी के कारण अगले वर्ष की योजनाओं में अधिकांश योजनाएं सतत योजनाए होंगी।

10+2+3 की नई शिक्षा पद्धति

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल राज्यों ने शिक्षा की यह नवीन प्रणाली लागू कर दी है। असम, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम-बंगाल तथा गोआ, दमन व दीव ने इसे लागू करने का निर्णय कर लिया है। उत्तर प्रदेश में स्कूल स्तर पर पहले से ही 12 वर्षीय प्रणाली लागू है। अब इस राज्य के लिए 2 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में बदलना शेष है। अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली तथा लक्ष्यद्वीप संघशासित क्षेत्रों के सभी स्कूल, जो केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से सम्बद्ध हैं, केन्द्रीय बोर्ड के निर्णय के अनुसार, मई, 1975 में शुरू

होने वाले शैक्षणिक सत्र से नई पद्धति लागू करेंगे । शेष संघशासित क्षेत्रों के स्कूल, निकटवर्ती राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध हैं तथा उन बोर्डों द्वारा किए गए परिवर्तन उन संघशासित क्षेत्रों में भी लागू होंगे ।

नई पद्धति लागू करने के संबंध में निर्णय करने वाले दूसरे प्रकार के राज्यों में, जिन्होंने नई पद्धति लागू करने के बारे में कदम उठाए हैं, गुजरात ने आठवीं कक्षा में जून, 1973 से संशोधित पाठ्य-विवरण लागू किया है । जून, 1975 से यह पद्धति अन्य कक्षाओं में भी लागू हो जाएगी । महाराष्ट्र ने नई पद्धति को 1974 से पूर्णत: लागू कर दिया, जिसने जून, 1972 में इसे आठवीं कक्षा से प्रारम्भ किया । पश्चिम बंगाल ने अप्रल, 1974 में नई पाठ्यचर्या तथा पाठ्य-विवरण लागू किया । नई पद्धति लागू होने के बाद गोआ ने विज्ञान तथा गणित के माध्यमिक अध्यापकों के लिए अनुस्थापन तथा विषय-वस्तु पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए कदम उठाए हैं । राज्य ने 1975-76 से शुरू होने वाली नई उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य-विवरण तैयार करने हेतु प्रारम्भिक कदम उठाए हैं । नई पद्धति के अन्तर्गत 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा के एक भाग के रूप में जम्मू और काश्मीर ने 13 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पूर्व विश्वविद्यालय कक्षाएं प्रारम्भ की हैं ।

व्यावसायीकरण तथा कार्यानुभव

शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा कार्यानुभव प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर लिए निर्णय के अनुरूप, असम ने सभी स्कूलों में उपयक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए ह । गुजरात ने 1974-75 से आठवीं कक्षा में अनुभव कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है । राजस्थान ने छ: उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में एक वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किया है । जिन विद्यार्थियों ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास की है, उन्हें पाठ्यक्रम में दाखिल कर लिया जाता है जो व्यापक होते हैं और जिनका उद्देश्य स्वत: रोजगार पैदा करना होता है ।

अनौपचारिक शिक्षा

हाल ही में लिया गया एक निर्णय, शिक्षा को औपचारिक स्वरूप प्रदान करना है । इस निर्णय के अनुसरण में हरियाणा ने, 11-13 आयु वर्ग के हरिजन बच्चों तथा लड़कियों के लिए अंशकालिक शिक्षा की एक नई योजना तैयार की है । चौथी कक्षा तक बच्चों के लिए, उनकी सुविधानसार समय में, महाराष्ट्र सरकार का विचार 2½ वर्ष की अवधि की अंशकालिक कक्षाएं चलाने का है । 14-25

आयु वर्ग के युवकों के लिए, गोआ, दमन और दीव का विचार अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का है। जम्मू और काश्मीर ने, अंशकालिक कक्षाओं के लिए 45 केन्द्र और अनौपचारिक पाठ्यक्रमों के लिए 40 केन्द्र प्रारंभ किए हैं ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

निम्न तालिका में, स्कूल स्तर पर दाखिलों के संबंध में अब तक हुई पर्याप्त प्रगति तथा भावी सम्भावनाओं के बारे में दर्शाय गया है । तथापि संविधान में निर्धारित लक्ष्य अभी भी, वित्तीय तंगी के कारण काफी दूर है । तालिका में अब तक हुई प्रगति का उल्लेख है और भावी सम्भाव्यताएं भी दर्शायी गई हैं।

आयु वर्ग (6-11)	1950-51	1974-75 (सम्भावित)
दाखिला-कक्षाएं I-V	182 लाख	646 लाख
जनसंख्या का अनुपात	43%	83.8%
आयु वर्ग (11-14)		
दाखिला-कक्षाएं VI-VIII	31 लाख	168 लाख
जनसंख्या (11-14) का अनुपात	13%	%

देश के सभी भागों में स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों तथा सरकारी स्कूलों में I से V कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है । उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पं० बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में VI से VII कक्षाओं में भी शिक्षा निःशुल्क है । इन राज्यों का, पांचवीं योजना के अन्त तक आठवीं कक्षा तक भी शिक्षा निःशुल्क करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उन्हें आवश्यक धन उपलब्ध हो जाय ।

मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम विद्यमान हैं । जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का संबंध है, दिल्ली, अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूहों तथा चण्डीगढ़ में ऐसे विधान मौजूद हैं।

कोटि सुधार

आ ोच्य अवधि के दौरान कोटि सुधार के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किए गए । सप्रथवंम रा० शै० अनु० तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं, जिनमें राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों और स्टाफ के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों के लेखकों और मूल्यांककों, शिक्षक प्रशिक्षकों, भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों

के लिए पाठ्यक्रम, स्कूल अध्यापकों और शिक्षा के प्रशिक्षकों के लिए 95 ग्रीष्म विज्ञान संस्थान और मानविकी तथा मनोविज्ञान में शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए ग्रीष्म संस्थान शामिल हैं । देश के सभी भागों के हजारों अध्यापकों ने अपनी व्यावसायिक कार्यक्षमता सुधारने हेतु इन कार्यक्रमों का लाभ उठाया ।

अपने शक्षिक कार्यक्रमों की विषय-वस्तु की कोटि सुधारने में राज्य भी पीछे नही रहे है । महाराष्ट्र ने नये शैक्षिक तकनीकों में पब्लिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को जारी रखा । इन पाठ्यक्रमों में 25 अध्यापकों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों में जिलेवार ग्रीष्म संस्थान, विस्तार अधिकारियों और शिक्षक शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम, चुने हुए स्कूल अध्यापकों के लिए क्रमबद्ध शिक्षण में पाठ्यक्रम, कार्यानुभव में अनुस्थापन कार्यक्रम और अन्तत: राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित विधि मास्टर्स के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम उल्लेखनीय हैं, जिसमें 23 विधि मास्टर्स को 6 और 8 कक्षाओं के लिए संशोधित विज्ञान पाठ्य-विवरण से अवगत कराया गया। इन सबके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 100 और स्कूल कम्पलेक्स शुरू किये । अध्यापक केन्द्रित और छात्र केन्द्रित-दो प्रकार के कार्यकलापों को तेजी से चलाया जा रहा है ताकि शिक्षा की कोटि में सुधार हो सके । असम ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 2 सप्ताह का एक सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया ।, आकाशवाणी गोहाटी के जरिए एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया। कार्यक्रम में माध्यमिक स्तर के विभिन्न विषयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का स्कूली कार्यक्रम सम्मिलित था। डिबरूगढ़ में पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राथमिक अध्यापकों के लिए 22 बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र और मिडिल स्कूल अध्यापकों के लिए सात केन्द्र आयोजित किए गए। गुजरात ने प्राथमिक अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 12 अतिरिक्त कक्षाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान की । इन कक्षाओं में 540 और अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा । कक्षा 1 से 6 तक विज्ञान और गणित पढ़ने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें अध्यापकों को नयी पाठ्यचर्या के प्रति शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराया गया । प्राथमिक स्कूलों के 1550 अध्यापकों और मिडिल स्कूलों के 3600 अध्यापकों के लिए 1974-75 के दौरान यूनिसेफ की सहायता से एक और गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्वीकृत किया गया । दिल्ली राज्य शिक्षा संस्थान के गणित एकक ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया । लक्षद्वीप ने 20 अमैट्रिक

अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये 2 महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया।

युवक सेवाएं

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना, जो अब काफी लोकप्रिय हो गई है, सभी राज्यों में चल रही है। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में अध्यापकों और छात्रों के स्वैच्छिक सहयोग से शुरू की गई यह योजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी फैल गई है। आलोच्य वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में 579 शिविर आयोजित किए गए। योजना के संचालन में तथा "युवक बनाम गंदगी और बिमारी" नामक कार्यक्रम के आयोजन में उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, और कर्नाटक राज्य द्वारा की गई प्रगति विशेषरूप से उल्लेखनीय है।

ग्रामीण खेलकूद

वर्ष के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण घटना ग्रामीण खेलों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। मंत्रालय ने, वारंगल, आन्ध्र-प्रदेश में अक्टूबर 1974 में 16 वर्ष से कम आयु के जनजातीय और ग्रामीण युवकों के लिए पहला अखिल भारतीय ग्रामीण हाकी टूर्नामेंट आयोजित किया। भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से 16 होनहार खिलाड़ियों को चुना गया और उन्हें नई दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ग्रामीण तथा जन-जातीय क्षेत्रों में खेल-प्रतिभा का पता लगाने का यह बहुत ही सफल प्रयास था।

ग्रामीण खेल टूर्नामेंट के प्रोत्साहन में राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। असम ने इस वर्ष के प्रारंभ में कामरूप जिले में मिर्जा में तीसरी वार्षिक ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता आयोजित की। ग्रामीण खेलों की लोकप्रियता इस बात से सिद्ध होती है कि इस वर्ष के प्रारंभ में दिल्ली में हुए अन्तर-ब्लाक स्तरीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट में विभिन्न खेलों में 5000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। फरवरी, 1975 में शिमोगो में हुए पाँचवे अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट के लिए दिल्ली की टुकड़ी में भाग लेने वालों के लिए विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए।

केन्द्र की प्रमुख शैक्षिक घटनाएं

प्रारम्भ में, शिक्षा और संस्कृति दोनों विभागों के वर्ष 1974-75 के लिए बजट प्राक्कलन दिए गए हैं। उसके बाद आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा

शिक्षा और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित महत्वपूर्ण कार्यों का ब्यौरा संक्षेप में दिया गया है ।

बजट प्राक्कलन

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 हेतु, इस विभाग के बजट अनुदानों में की गई कुल बजट व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

(रुपये लाखों में)

विवरण	बजट 1974-75	संशोधित 1974-75	बजट 1975-76
1	2	3	4
मांग संख्या 21—शिक्षा विभाग विभाग का सचिवालय, आतिथ्य तथा जलपान और शिक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि	118.39	130.79	140.51
मांग संख्या 25—शिक्षा सामान्य शिक्षा के लिए व्यवस्था, विभाग का अन्य राजस्व खर्च जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के संबंध में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सहायक अनुदान के लिए व्यवस्था तथा छात्रावासों के निर्माण के लिए ऋणों की व्यवस्था आदि तथा केन्द्रीय व केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अन्य शैक्षिक ऋण भी सम्मिलित हैं ।	11181.68	11543.25	13508.28
कुल जोड़	11300.07	11674.04	13548.79

मांग संख्या 24—शिक्षा विभाग; के अन्तर्गत आयोजनेत्तर और योजनागत स्थापना संबंधी अनुरक्षण खर्च ; शिक्षा मंत्री का विवेकाधीन अनुदान तथा आतिथ्य और जलपान सम्मिलित हैं । 1974-75 के संशोधित प्राक्कलनों में बढ़ोतरी (12.40 लाख रुपये), मुख्यत: प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों पर महगाई भत्ते की अदायगी व जनवरी, 1975 में सरकार द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की तीन अतिरिक्त किस्तों के कारण खर्च को पूरा करने के लिए की गई अतिरिक्त व्यवस्था के कारण है। दो अनुपूरक मांगें—एक 7 लाख रुपये की तथा दूसरी 9.72 लाख रुपये की प्राप्त की गई। संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में 1975-76 के बजट प्राक्कलनों में बढ़ोतरी (9.72 लाख रु० मुख्यत: मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के प्रत्याशित खर्च की वजह से है ।

अन्य मांग संख्या 25—शिक्षा के अन्तर्गत व्यवस्था आयोजनेत्तर तथा योजनागत दोनों प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए है । इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय-यूनेस्को को अंशदान-आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास ; राज्यों/संघीय प्रशासनों को अनुदान ; कालेजों/संस्थाओं में छात्रावासों के निर्माण हेतु ऋण तथा अन्य शैक्षिक ऋण की व्यवस्था भी सम्मिलित है । 1974-75 के संशोधित प्राक्कलनों में कुल 3.62 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो मुख्यत: चालू वर्ष में आयात किए जा रहे नार्वेयाई कागज के लिए प्रासंगिक व्यय तथा सीमा शुल्क की अदायगी तथा पहले आयात किए गए स्वीडन के कागज के लिए कुछ पिछली प्रासंगिक अदायगी (1.63 करोड़ रुपये) तथा मंत्रालय के स्वायत्त निकायों /संगठनों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की तीन अतिरिक्त किस्तों के भुगतान (1.72 लाख रुपये) के लिए आवश्यक व्यवस्था सम्मिलित है । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान पर बंगलौर के लिए एक- एक हजार रुपये की नाममात्र की अनुपूरक मांग प्राप्त की गई क्योंकि इन संगठनों के लिए अनुदान, 'सेवा की नई पद्धति' के लिए निर्धारित सीमाएं, इनके लिए निर्धारित बजट प्राक्कलनों को पार कर गई । मंहगाई भत्ते की तीन अतिरिक्त किस्तों के भुगतान के लिए 1.72 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जा रहा है ।

वर्ष 1975-76 के बजट प्राक्कलनों में संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में 1965 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई गई है । इसका मुख्य कारण निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रमों तथा संस्थाओं के लिए अनुदानों म वृद्धि है :– (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 1.35 करोड़ रुपये से अधिक, (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 5.93 करोड़ , (iii) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के

शिक्षकों के वेतनमानों में सुधार हेतु राज्यों को 3.44 करोड़ रुपये के अनुदान ; (iv) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए 90 लाख रुपये से अधिक ; (v) नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना हेतु 62 लाख रुपये; (vi) राज्यों द्वारा अपने अधिकार में लिए गए रा० अ० यो० के निदेशकों के वेतन व भत्तों के लिए अनुदान हेतु 53 लाख रुपये से अधिक; (vii) विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृतियों की दरों में वृद्धि के लिए 50 लाख रुपये; (viii) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति की योजना तथा योजनाओं / कार्यक्रमों में विविध अधिकताओं के लिए 55 लाख रुपये ।

संस्कृति विभाग

संस्कृति विभाग के लिए वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के लिए बजट व्यवस्था इस प्रकार है :– (रुपये लाखों में)

विवरण	बजट 1974-75	संशोधित 1974-75	बजट 1975-76
संस्कृति विभाग	678.38	532.49	678.41
पुरातत्व	517.56	473.35	590.32
जोड़	1195.94	1005.84	1268.73

"संस्कृति विभाग" के अन्तर्गत की गई व्यवस्था, विभाग और उसके संलग्न व अधीनस्थ कार्यालयों के सामान्य प्रशासन तथा संग्रहालयों, पुस्तकालयों और सांस्कृतिक अकादमियों सहित संस्कृति के अंतर्गत विविध योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए है ।

संशोधित प्राक्कलनों में कमी (145.89 लाख रुपये) सरकारी खर्च में बचत करने के अभियान तथा योजनागत योजनाओं की स्वीकृति का परिणाम है ।

वर्ष 1975-76 के बजट प्राक्कलनों तथा वर्ष 1974-75 के संशोधित प्राक्कलनों में बढ़ोतरी (145.92 लाख रुपये), आंशिक रूप से आयोजनेत्तर खर्च में वृद्धि के कारण और आंशिक रूप से वर्ष 1975-76 के लिए अधिक वार्षिक योजनागत आवंटन में बढ़ोतरी के कारण, मंहगाई भत्ते के लिये आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था के कारण भी वृद्धि हुई है । भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार

ग्रौर नृविज्ञान सर्वेक्षण को वर्ष 1975-76 से संस्कृति विभाग के लिए मांगों में सम्मिलित किया गया है ।

पुरातत्व के ग्रधीन की गई व्यवस्था, पुरातत्वीय स्मारकों के ग्रनुरक्षण, खोज तथा खुदाई ग्रौर विशेष मरम्मतों के लिए है । यह ग्रधिकांशत: सामान्य ग्रनुररक्षण खर्च है । 1974-75 के संशोधित प्राक्कलनों में कमी (44.21 लाख रुपये) मुख्यत: योजनागत योजनाग्रों की ग्रस्वीकृति के कारण ग्रौर ग्रंशत: खर्च में बाचत के कारण है जिसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान ग्रधिकांश कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका ।

वर्ष 1975-76 के बजट प्राक्कलनों ग्रर्थात् वर्ष 1974-75 के संशोधित प्राक्कलनों में बढ़ोत्तरी (116.97 लाख रुपये) ग्रांशिक रूप से ग्रनुरक्षण खर्च में सामान्य बढ़ोत्तरी के कारण ग्रौर ग्रंशत: पुरावशेष तथा कला निधि ग्रधिनियम के लागू होने तथा प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय खोजों तथा खुदाइयों व केन्द्रीय पुरातत्वीय संग्रहालयों के लिए की गई व्यवस्थाग्रों के कारण है। इसके ग्रंतार्गत मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए ग्रपेक्षित ग्रतिरिक्त व्यवस्था भी सम्मिलित है ।

स्कूल शिक्षा

इस वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय शिक्षा ग्रनुसंधान का पुनर्गठन किया गया, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा ग्रनुसंधान ग्रौर प्रशिक्षण परिषद् का ही एक ग्रंग है, ताकि शैक्षिक तथा ग्रनुसंधान कार्य में समन्वय ग्रौर गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों में प्रगति सुनिश्चित की जा सके। ग्रालोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, जिसने 17 ग्रौर विद्यालय खोले थे, अपने पिछले वर्षों के उत्तम रिकार्ड को बनाए रखा। वर्ष 1975 से विद्यालयों का विचार 10+2 की स्कूली पद्धति को ग्रपनाने का है । केन्द्रीय मंत्रालय ने चुने हुए उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जाने के लिए, व्यावसायीकरण की एक योजना तैयार की है। हाल में शुरू की गई शैक्षिक प्रौद्योगिकी परियोजना ने केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रगति की।

उच्च शिक्षा

देश की ग्रार्थिक ग्रौर सामाजिक प्रगति के लिये उच्च शिक्षा का विकास महत्वपूर्ण है । उच्च शिक्षा ग्राशाजनक भूमिका निभा सकती है यदि प्रतिभाशाली

व्यक्ति विश्वविद्यालयों और कालेजों की ओर आकर्षित हों जो कि तभी सम्भव है यदि विश्वविद्यालय तथा कालेज के अध्यापकों के वेतनमान आकर्षक हों । आशा है कि अध्यापन तथा अनुसंधान में लगे व्यक्तियों के कार्य की स्थितियों में सुधार के फलस्वरूप, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने तथा उच्च शिक्षा की पद्धति स्थापित करने के लिये जिससे कि राष्ट्रीय विकास में मदद मिलेगी, अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा । तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये संशोधित वेतनमान, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के लिये स्वीकृत किये गये हैं तथा इन वेतनमानों को राज्य सरकारों को स्वीकृति के लिये भी सिफारिश की गई है । पांचवीं योजनावधि के अन्त तक राज्य सरकारों को अतिरिक्त व्यय के 80 प्रतिशत तक की सहायता की पेशकश की गई है । उसके बाद आशा है कि राज्य सरकारें समस्त उत्तरदायित्व सम्भाल लेंगी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नये गुणात्मक एवं नवीन कार्यक्रम, जैसे परीक्षा सुधार तथा स्वायत्त कालेज एवं पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन प्रारम्भ किया है । परीक्षा सुधार के क्षेत्र में, आयोग ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किये हैं तथा कार्रवाई की एक आयोजना शुरू की है जिसमें शिक्षण की नई पद्धतियों और कक्षा के अनुभवों पर आधारित व छात्रों के विभिन्न वर्गों के स्तरों और उपलब्धियों के उपयुक्त नए प्रकार के परीक्षा प्रश्न-पत्रों की व्यवस्था है । वर्ष के दौरान, आयोग के संकाय सुधार तथा अनुसन्धान अधिछात्रवृत्तियों की व्यवस्था जैसे अन्य कार्यक्रम जारी रहे ।

हैदराबाद में नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर, 1974 को अस्तित्व में आया । आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने सामान्य कार्यों को जारी रखा । वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में अनुसंधान कार्यक्रमों में तीव्र प्रगति हुई ।

तकनीकी शिक्षा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने आलोच्य वर्ष के दौरान हुई एक बैठक में महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं और ये सिफारिशें उद्योग तथा शैक्षिक अनुसंधान संस्थाओं के बीच उपयुक्त सम्पर्कों की स्थापना, व्यावसायीकरण के कार्यक्रमों और प्रबन्ध शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की

2—956MofEdu.&SW/74

स्थापना के बारे में हैं। विशेषज्ञ निकायों द्वारा की गई समीक्षा के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अब महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे। इनके तथा अन्य कार्यक्रमों के ब्यौरे रिपोर्ट के तीसरे अध्याय में दिए गए हैं।

छात्रवृत्तियां

केन्द्रीय तथा समाज कल्याण मंत्रालय की विभिन्न छात्रवृत्तियों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संचालन की प्रगति को वर्ष के दौरान जारी रखा गया।

पुस्तक प्रोन्नति

छठा राष्ट्रीय पुस्तक मेला बम्बई में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तत्वावधान में भारतीय पुस्तक उद्योग का सर्वेक्षण, जो कि पहली बार किया गया था, वर्ष के दौरान पूरा किया गया। सर्वेक्षण की रिपोर्ट से देश में पुस्तक प्रकाशन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत रूप से सूचना दी गई है।

युवक कल्याण राष्ट्रीय एकता, खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा

राष्ट्रीय सेवा योजना के सक्रिय होने पर 1973 में शुरू किए गए "युवकों बनाम अकाल" अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति होने पर, "युवक बनाम गन्दगी तथा बीमारी" नामक एक विशेष शिविर कार्यक्रम वर्ष 1974 में शुरू किया गया। इस वर्ष "राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा योजना" शुरू करने का विचार है, जिसके अन्तर्गत स्नातकों के लिए एक वर्ष के लिए मासिक वजीफे के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष ग्रामीण खेलों के क्षेत्र में और प्रगति हुई तथा खेलकूद गतिविधियों को व्यापक आधार प्रदान करने पर बल दिया गया, ताकि खेलकूदों में ग्रामीण तथा जन-जातीय युवकों को शामिल किया जा सके। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की सलाह पर सरकार ने कुछ मार्गदर्शी रूपरेखाएं इस वर्ष के आरम्भ में निर्धारित की थीं, जिसके अनुसार राष्ट्रीय संघों/एसोसिएशनों को राजकीय वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध की जायेगी।

भाषाएं

केन्द्रीय मंत्रालय ने, हिन्दी आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत और साथ ही अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति और विकास के

लिए पूर्ण सहायता देना जारी रखा। भाषा विकास और भाषा शिक्षण तथा हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का संचालन जारी रखा गया। इस वर्ष के दौरान तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, ताकि उर्दू में पुस्तकों के निर्माण के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने की व्यवस्था को तेज बनाया जा सके।

यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

यूनेस्को के महा-सम्मेलन का अठारहवां अधिवेशन 17 अक्तूबर से 24 अक्तूबर, 1974 तक पैरिस में हुआ था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री ने किया।

यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का ग्यारहवां सम्मेलन 3-4 अक्तूबर, 1974 को नई दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन ने यूनेस्को के 1975-76 के दो वर्ष के लिए बजट तथा कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशें पेश कीं।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में पांचवीं योजना के कार्यक्रम इनसे संबंधित होंगे, जैसे 15 से 25 वर्ष के आयु वर्गों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, 15 और उससे ऊपर के आयु वर्गों के विकास-कार्यकलापों से संबंधित कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम तथा शहरी कामगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने, आलोच्य वर्ष में अपना कार्य जारी रखा तथा उसे प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रलेखन केन्द्र के रूप में मनोनीत किया गया।

सांस्कृतिक मामले

जिन देशों के साथ सांस्कृतिक करार किये गये उनके नाम हैं:— यमन लोक जनवादी गणराज्य, सेअलने, टोना, कीगर्जेन्लम्बिया, कोरिया, सूडान, गुयाना, यू० ए० ई०, मारीशस, तंजानिया तथा बहरीन। भारत-अमेरिका संयुक्त आयोग करार के अन्तर्गत, जिस पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं, दोनों देशों के बीच शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक उप-आयोग की स्थापना की गई है। खान्डा, इटली तथा श्रीलंका

से सांस्कृतिक करार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, बारह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक करार करने की बात विभिन्न स्तरों पर है। अन्य दस देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आलोच्य वर्ष में तैयार किये गए। पिछले वर्षों की तरह आलोच्य वर्ष में भी भारत व अन्य कई देशों के बीच सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों के दौरों के जरिए पर्याप्त परस्पर विनिमय हुआ। अकादमियों तथा अन्य संस्थाओं ने आलोच्य वर्ष के दौरान अपने कार्य की गति को बनाये रखा।

पुरातत्व

आलोच्य वर्ष की अवधि में, पुरातत्वीय सर्वेक्षणों, खोजों तथा खुदाइयों तथा खण्डों तथा पुरातत्व के प्रकाशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

संग्रहालय तथा पुस्तकालय

राज्य सभा ने रज़ा पुस्तकालय विधेयक 1974 में पारित कर दिया तथा यह आजकल लोक सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। इस विधेयक का उद्देश्य रज़ा पुस्तकालय, रामपुर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के लिए प्रशासन प्रदान कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक 1972 पर विचार करने वाली दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने जुलाई 1974 में अपनी रिपोर्ट लोक सभा में पेश कर दी। विधेयक आजकल लोक सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

संग्रहालयों, कला वीथियों तथा अभिलेखागारों से संबंधित सभी कार्य-कलापों में आलोच्य अवधि के दौरान संतोषजनक प्रगति हुई।

अन्त में

शैक्षिक सुधार लागू करने से पहले यह आवश्यक है कि उन सभी के साथ जिनका इससे संबंध हो, जैसे कि अध्यापकों, विद्यार्थियों, शैक्षिक प्रशासकों तथा अभिभावकों के साथ विचार-विमर्श किया जाये, क्योंकि इसके अभाव में इस बात का भय बना रहेगा कि शुरू किये गये सुधार, स्वरूप के तो हों, किन्तु भावना में नहीं। यह भी इतना ही आवश्यक है कि इससे, क्रान्तिकारी सुधार करने के प्रारम्भिक स्तरों पर शैक्षिक पद्धति में कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो। परिणामतः विकास की गति लोगों को अति धीमी लगेगी जिसकी वे अपेक्षा करते थे। अतीत की दृष्टि से शैक्षिक सुधार

का. क्रम सदैव महत्वपूर्ण श्रौर भावी विकास का मूलाधार सिद्ध होता है। यह कहा जा सकता है कि आलोच्य वर्ष के दौरान शिक्षा के पुनर्गठन तथा उसके नवीनीकरण पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया श्रौर शैक्षिक विचारकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा जनता के सभी वर्गों में उसे प्रसारित किया गया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के मतानुसार यदि अतिरिक्त साधन जुटाए जाएं श्रौर कठिन काम करने के लिए सही वातावरण हो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त प्रगति उपलब्ध की जा सकती है।

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग

पहला अध्याय

स्कूल शिक्षा

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की प्रमुख संस्थाएं तथा कार्यक्रम इस प्रकार हैं :–

(1) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण ;

(2) शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रायोजना ;

(3) स्कूल शिक्षा में कोटि सुधार कार्यक्रम;

(4) स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण का पुनर्गठन तथा प्रसार ;

(5) स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था ।

इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से कार्यान्वित किए जाते हैं, वे हैं :–

(1) नि:शुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, तथा

(2) 10+2+3 शिक्षा पद्धति का कार्यान्वयन ।

जिन संस्थाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं :–

(1) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्,

(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, और

(3) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चुने हुए उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय व्यावसायीकरण की एक योजना पर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव है कि इस अवधि के दौरान देश भर में 1000 स्कूलों का

चयन किया जाय तथा प्रत्येक स्कूल द्वारा प्रति वर्ष 100 छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए।

नए गैर-इंजीनियरी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरू करने तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विविधीकरण पर बल दिया जाएगा, ताकि इनको पालिटेक्निकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा पहले से ही संचालित पाठ्यक्रमों के साथ-साथ चलाया जा सके। स्वत: रोजगार के लिए प्रशिक्षण तथा आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा देने पर बल दिया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का दाखिला जिले में उपलब्ध रोजागार के अवसरों के अनुसार होगा। रोजगार की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने तथा योजना के कार्यान्वियन के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। 10+2+3 वर्षीय पद्धति के अंतर्गत प्रस्तावित 2 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पालिटेक्निकों, बहुद्देशीय स्कूलों तथा अवर तकनीकी स्कूलों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता तथा सुविधाओं के उपयोग का प्रस्ताव है। बहुत-सी राज्य सरकारों ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण कार्यक्रम के लिए वित्तीय विनिधान किए हैं।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

शैक्षिक प्रौद्योगिकी परियोजना का उद्देश्य, प्रौढ़ों की अनौपचारिक शिक्षा सहित, शिक्षा के सभी स्तरों पर जन संचार माध्यम तथा शिक्षण प्रौद्योगिकी के समेकित उपयोग को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करना और उसके फलस्वरूप गुणात्मक सुधार व कम लागत पर अधिक प्रचार करना है। इस परियोजना का प्रबन्ध दिल्ली में रा० शै० अ० प्र० प० के एक अलग संगठन के रूप में स्थापित शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा; और राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों द्वारा किया जाता है। इन सैलों की स्थापना क्रमिक रूप से की जा रही है।

योजना के अंतर्गत, वर्तमान वर्ष के दौरान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र तथा राजस्थान में ऐसे सैल पहले से ही विद्यमान हैं।

ऐसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों की स्थापना के लिए अन्य राज्यों को भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी।

आशा है कि उपग्रह शिक्षण टेलीविजन प्रयोग के अंतर्गत अगस्त, 1975 से प्रसारण आरम्भ हो जाएंगें। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के 400 ग्रामों के समूहों में टेलीविजन लगाए जा रहे हैं। राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल, स्कूली टेलीविजन-प्रसारणों के संबंध में अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और अनुवर्ती कारंवाई के बारे में मदद देगें। स्कूल प्रसारण 20 मिनट का और 220 दिन के लिए होगा।

राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल

महाराष्ट्र में स्थापित शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल के अतिरिक्त, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में भी ऐसे सैल स्थापित किए गए हैं। आशा है कि मध्य-प्रदेश, बिहार तथा कर्नाटक में और बाद में अन्य राज्यों में भी क्रमिक रूप से ये सैल स्थापित किए जाएंगें।

महाराष्ट्र में इस सैल का मुख्य काम यह है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि 24 जून, 1974 से हफ्ते में तीन बार जो शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं उनका बम्बई तथा पूना में 564 माध्यमिक स्कूलों में मार्गदर्शी रूपरेखाएं प्रचारित करके कक्षा में उपयोग किया जाय। यह, विषय समितियां नियुक्त करके और सेमिनारों तथा वर्कशापों के माध्यम से कार्यक्रमों की कोटि भी सुनिश्चित करता है। अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान संबंधी समितियां, टेलीविजन के लिए विषय चुनने में मदद करती हैं। तीन अध्यापक गाइडों तथा कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए प्रोफार्मा संकलित किया गया है। कार्य क्रम कार्मिकों के चयन के लिए दो वर्कशाप तथा टी० वी० कार्यक्रमों की कोटि के मूल्यांकन की समीक्षा करने के लिए एक सेमीनार आयोजित किया गया। नीति विषयक मामलों में सैलों को सलाह देने के लिए एक उपयुक्त समिति स्थापित की गई है।

राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा मे सैलों की स्थापना का कार्य चल रहा है।

कोटि सुधार कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

स्कूल शिक्षा में कोटि सुधार के बहुत से कार्यक्रमों का कार्यान्वियन रा०शै० अ०प्र०प० के माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष रा०शै०अ०प्र०प० का पुनर्गठन

किया गया है ताकि शैक्षणिक तथा अनुसंधान कार्य में अधिक समन्वय सुनिश्चित किया जा सके और विकास-स्कंधों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

अब इसमें 5 शैक्षिक विभाग, 4 सेवा उत्पादन विभाग तथा विशेष कार्यों के लिए 6 कार्यात्मक एकक हैं। प्रत्येक विभाग में एक सलाहकार बोर्ड है जो कार्यान्वयन से पूर्व सभी कार्यक्रमों की जांच करता है तथा उन्हें मंजूर करता है। क्योंकि परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट संसद् के सम्मुख अलग से प्रस्तुत की जाती है इसलिए यहां परिषद् के कार्यक्रमों का ब्यौरा संक्षेप में दिया गया है।

अनुसंधान कार्यकलाप

वर्ष के दौरान, परिषद् की शैक्षिक अनुसंधान तथा नवीकरण समिति की सिफारिश के आधार पर, 51 अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ की गईं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित अनुसंधान के कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

(i) भाषा, विचार तथा पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में मूलभूत अनुसंधान;

(ii) सामाजिक विज्ञानों में विचारधाराएं तथा नई घटनाएं और कक्षा-1 से 10 में स्कूली शिक्षा में उनका निहितार्थ ;

(iii) 5 ½–11 वर्ष के आयु-वर्ग के लिए विकासात्मक मानदंड परियोजना ;

(iv) 7–16 वर्ष के आयु-वर्ग के लिए बुद्धि-परीक्षा;

(v) प्रतिभा की खोज परीक्षा–समय संबंधी स्थिरता;

(vi) कार्यक्रमबद्ध अध्ययन की प्रभावशीलता;

(vii) शिक्षक शिक्षा के लिए जनशक्ति आयोजना के संबंध में अध्ययन;

(viii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के स्वत: श्रेणीकरण के लिए साधन।

विकास कार्य

इस क्षेत्र में परिषद् के प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :–

(i) मुख्य विषयों, अर्थात भाषा, विज्ञान, गणित तथा समाज-विज्ञान में 10+2 वर्ष की स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षण गाइडों जैसी पाठ्यचर्या तथा अनुदेशात्मक सामग्रियों का विकास;

(ii) पाठ्यचर्या विकास के भाग के रूप में विज्ञान किटों जैसे शिक्षण साधनों तथा फिल्म-पट्टियों, चार्टों आदि जैसे दृश्य-श्रव्य साधनों का तैयार किया जाना ;

(iii) विभिन्न राज्यों में यूनिसेफ सहायता प्राप्त विज्ञान परियोजना का विस्तार;

(iv) स्कूल पाठ्यचर्या के एक मुख्य क्षेत्र के रूप में कार्य-अनुभव तथा शिक्षा के व्यावसायीकरण का विकास ;

(v) पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन ;

(vi) विज्ञान तथा मानविकी के विषयों में अनुपूरक पठन-सामग्री का तैयार किया जाना ;

(vii) पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षक गाइडों तथा अनुपूरक पुस्तकों आदि अनुसंधान मोनोग्राफों तथा रिपोर्टों का प्रकाशन ;

(viii) स्कूल पाठ्यचर्चा में जनसंख्या शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता का शुरू किया जाना ;

(ix) कार्यक्रमबद्ध अध्ययन सामग्रियों का विकास ।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज

शिक्षा के चार क्षेत्रीय कालेजों ने वर्ष के दौरान अपने सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखा । दो वर्षीय एम० एस० सी० पाठ्यक्रम के लिए उत्तर-स्नातक विज्ञान कार्यक्रम इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास था ।

विज्ञान प्रतिभा खोज

वर्ष के दौरान 350 अध्येताओं के एक नए दल का चयन किया गया था तथा राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी । इन अध्येताओं के लिए तथा साथ ही उनके लिए जिन्हें पिछले वर्षों में ऐसी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं, विशेष ग्रीष्म संस्थान आयोजित किये गये ।

क्षेत्रीय कार्यालयों को सुदृढ़ बनाना

राज्यों में क्षेत्र सलाहकारों/अधिकारियों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है, ताकि राज्यों के साथ सम्पर्क को सुदृढ़ बनाया जा सके । क्षेत्र सलाहकार राज्य की समस्याओं को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद तक पहुंचाते हैं तथा रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद के विशेष ज्ञान को

राज्यों को उपलब्ध कराते हैं। इस समय लगभग सभी प्रमुख राज्यों में क्षेत्र सलाहकार का कार्यालय है।

स्कूल स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का पुनर्गठन तथा उसका विस्तार

स्कूल विज्ञान सुधार कार्यक्रम जो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ से जो सहायता मिलेगी उसमें प्राथमिक स्कूल की अवधि पर तथा बच्चे की रहन-सहन की परिस्थिति म विज्ञान के योग पर जोर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप यूनिसेफ माध्यमिक स्कूलों की विज्ञान शिक्षा के लिए पहले जो सहायता देता था वह अब इस रूप में दी जाएगी कि केवल उन स्कूलों को किट दिए जाएंगे जिनको ये किट पहले से ही दिये जा रहे थे और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खर्च का कुछ भाग दिया जाएगा।

तथापि, उन राज्यों को, जिन्होंने अभी तक यह प्रयोग पूरा नहीं किया हो इसे पूरा करने का अवसर दिया जायेगा, और इस प्रयोजन से उन्हें प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल दोनों स्तरों पर सहायता दी जाएगी।

प्राथमिक स्तर पर कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा और राज्यों को भी इसके व्यापक प्रसार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उपरोक्त प्रकार का एक अनुपूरक करार यूनिसेफ के साथ किया जाएगा।

अब तक यूनिसेफ से लगभग 3668 मीट्रिक टन कागज प्राप्त हुआ है और विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों, टीचर्स गाइडों आदि को छापने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को दिया गया है। यहां भी, यूनिसेफ प्राथमिक स्तर पर राज्यों/संघशासित प्रदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

जर्मन संघीय गणतन्त्र से उपहारस्वरूप प्राप्त पाठ्यपुस्तक छापेखाने

इस योजना के अंतर्गत चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मैसूर में तीन पाठ्यपुस्तक प्रेसों को स्थापित किया जाना था। इनके लिए उपकरण तो जर्मन संघीय गणतंत्र द्वारा मुफ्त दिये जाने हैं और भवनों और स्टाफ की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी। चंडीगढ़ प्रेस को चौथी योजना के दौरान शुरू किया गया था। यह प्रैस वर्ष में एक करोड़ पुस्तकें छाप सकता है।

भुवनेश्वर प्रैस के लिए मशीनरी के शीघ्र आने की संभावना है। इसके लिए भवन पूरा कर लिया गया है। मैसूर प्रैस की मशीनरी के लिए आर्डर दे दिये

गये हैं। इस प्रैस के लिए भवन लगभग पूरा होने वाला है। इन दोनों प्रैसों के अब 1975-76 के दौरान शुरू होने की आशा है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

बोर्ड ने कक्षा 9 से आरंभ होने वाले नये शैक्षणिक ढांचे को मई 1975 से कार्यान्वित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। विशेष कार्यदल द्वारा तैयार की गई कक्षा 9 और 10 के अध्ययन की योजना को विभिन्न एजेन्सियों और बोर्ड के सदस्य-स्कूलों से विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया गया। इस योजना में पाठ्यक्रम की कोटि में सुधार के अतिरिक्त छात्रों के संतुलित विकास, ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार और त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भाषा के अध्ययन के उद्देश्यों पर भी ध्यान दिया गया है। छात्रों की अभिरुचि, क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं स्कूल के साधनों के अनुकूल सृजनात्मक विकास, आत्मनिर्भरता और श्रम के महत्व के लिए उपलब्ध 41 प्रकार के कार्यानुभवों से कार्य-अनुभव प्राप्त करना आवश्यक होता है। नयी योजना में नियमित विषयों के अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक सेवा की व्यवस्था भी की गई है। योजना में भौतिक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है और बाहरी परीक्षा के मामले में छात्रों का मूल्यांकन पांच-सूत्री मापदण्ड के आधार पर किया जाएगा। नयी योजना के लिए पाठ्यचर्याओं और पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आवश्यकताओं और रोजगार के अवसरों का सर्वेक्षण करने के बाद बोर्ड ने तीन व्यावसायिक विषयों में पाठ्यक्रम तैयार किए हैं।

प्रकाशन

बोर्ड द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और भौतिक विज्ञान में 10 प्रकाशन निकाले गए हैं। बोर्ड द्वारा समुद्रपार विकास एजेन्सी ब्रिटेन और ब्रिटिश कौंसिल के सहयोग से एक संयुक्त सहयोग परियोजना शुरू की गई है। प्रारंभिक कार्यवाही के रूप में "स्कूलों में प्रौद्योगिकी परियोजना" नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया और इसका वितरण सदस्य-स्कूलों में किया गया है।

शिक्षकों की कार्यशाला

शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अगस्त, सितम्बर, 1974 में उच्च गणितीय शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, ब्रिटेन के सहयोग से गणित में एक अनुस्थापन कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय शिक्षकों द्वारा उच्च गणितीय

शिक्षा और प्रौद्योगिकी केन्द्र में पहले तैयार की गई सामग्री को इस कार्यशाला में अन्तिम रूप दिया गया और यह साधन-सामग्री के रूप में प्रकाशित की जा रही है। नयी प्रणाली के अंतर्गत बोर्ड द्वारा तैयार की गई समाज विज्ञान की नयी पाठ्यचर्या का विवरण प्रस्तुत करने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्ली के सहयोग से एक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। बोर्ड के लिए नयी विज्ञान पाठ्यचर्या के आधार पर पुस्तकें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनेक अखिल भारतीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। बोर्ड द्वारा राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्ली के सहयोग से फरवरी, मार्च, 1974 में अर्थशास्त्र के शिक्षकों के लिए तीसरी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इससे सदस्य-स्कूलों के लगभग 450 अर्थशास्त्र के शिक्षकों को अर्थशास्त्र के नये दृष्टिकोण और विकास में प्रशिक्षित किया गया।

स्कूल में गणित की शिक्षा का सुधार

आधुनिक गणित में उच्च प्रशिक्षण के लिए और साधन-सामग्री तैयार करने के लिए तीन गणित शिक्षकों के दूसरे दल को उच्च गणितीय शिक्षा तथा प्रोद्योगिकी केन्द्र, ब्रिटेन में भेजा गया।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

यह संगठन देश में 187 केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन करता है, जिनमें से एक काठमांडु में है तथा यह केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान, 17 केन्द्रीय विद्यालय खोले गए थे, जिनमें से कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्गम रक्षा स्थलों में, सार्वजनिक उद्योगों, उपक्रमों तथा नागरिक क्षेत्रों में खोले गए थे।

केन्द्रीय विद्यालय एक सामान्य पाठ्यचर्या के अनुसार न केवल शिक्षा के समान उच्च स्तर को बनाते हैं बल्कि ये अपने छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बढ़ाते हैं जिसकी आज देश में बहुत जरूरत है। वर्ष 1974 में अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में केन्द्रीय विद्यालयों के जो छात्र बैठे थे, उनके पास होने की प्रतिशतता 87.6 थी, जबकि कुल पास प्रतिशतता 75 थी। जिन 133 विद्यालयों ने अपने छात्र इस परीक्षा के लिए भजे थे, उनमें से 23 विद्यालयों ने शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त किए थे। 10 केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने योग्यता सूची में स्थान प्राप्त किए थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आदि की प्रवेश-परीक्षाओं में भी केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने काफी अच्छे परिणाम दिखाए हैं ।

शिक्षा मंत्रालय तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय वर्ष, 1975 से स्कूली शिक्षा की 10+2 वर्षीय पद्धति अपनाने जा रहे हैं । (क) वर्ष, 1975 तथा 1976 में कक्षा 9 तथा 10 में सामान्य पाठ्यक्रम तथा (ख) बाद के वर्षों में कक्षा 11 तथा 12 में शैक्षिक तथा व्यावसायिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा लागू करने के संबंध में प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । सभी चार कक्षाओं के लिए पाठ्य-विवरण तैयार करने के लिए रूपरेखाएं तैयार करने में केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित उप-समितियों और कार्यकारी दलों में स्टाफ के 35 सदस्य भाग ले रहे हैं ।

अन्य कार्यक्रम

बाल भवन सोसायटी

रचनात्मक आधार पर बच्चों का विकास करने के आशय से यह बाल मनोरंजन तथा शैक्षिक केन्द्र ललित कलाओं, मानविकी, विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करता रहा ।

वर्ष के दौरान 7 प्रदर्शनियां तथा 19 वर्कशाप आयोजित किए गए । ये लेखा-चित्रों, कालेज निर्माण, फोटोग्राफी, कठपुतली निर्माण, मिट्टी के नमूने, शिल्प कलाओं, लकड़ी के कार्य, बटिक कार्य तथा चित्रकला से संबंधित थीं । अभिभावकों तथा अध्यापकों ने इन वर्कशापों में भाग लिया था तथा इनमें अफ़गानिस्तान से नामज़द व्यक्ति तथा भारत के विभिन्न जवाहर बाल भवनों से अनुदेशक भी शामिल हुए थे ।

इसके अतिरिक्त, 7 सप्ताहांत पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए थे जिनमें स्थानीय स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया था । "कला में जानकारी" नामक एक विशेष कार्यक्रम में भी स्थानीय स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया था ।

स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, 6000 बच्चों ने दो ऋतु उत्सवों को भी देखा था ।

3—956 M of Edu & SW/74

बाल भवन के विशेष दल (रेपरटरी ग्रुप) ने ग्रामीण स्कूली बच्चों तथा झुग्गी और झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। बाल भवन में ग्रामीण कलाकारों द्वारा कुछ रोचक संगीतमय सुखांत नाटक तथा लघु नाटकों का अभिनय किया गया था। उन्हें टेलीविजन द्वारा प्रसारित किया गया था ताकि वर्ष 1975 में वे ग्रामीण श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत किये जा सकें।

स्कूल अध्यापकों का कल्याण

मंत्रालय, लगातार राज्य सरकारों पर अध्यापकों की परिलब्धियों, सेवा शर्तों और योग्यताओं में सुधार करने की आवश्यकता पर दबाव डालता रहा। इसके अलावा, मंत्रालय सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा त्रिलाभ योजना (पेंशन, भविष्यनिधि तथा बीमा) अपनाने की आवश्यकता पर बल देता रहा है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मनीपुर, उड़ीसा त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने इस योजना को कार्यान्वित कर लिया है, और अन्य राज्य सरकारें इस पर विचार कर रही हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सरकारों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू उदार पेंशन योजना आरंभ की है। जहां तक संघशासित प्रदेशों का संबंध है, भारत सरकार ने उक्त योजना की मंजूरी अप्रैल, 1965 से दे दी है।

अध्यापकों के बच्चों को विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों में विभिन्न स्तरों तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

5 सितम्बर 1974 को अध्यापक दिवस समारोह के एक भाग के रूप में देश-भर में एक बहुत ही प्रभावशाली चन्दा अभियान आयोजित किया गया था। अध्यापकों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

वर्ष के दौरान कुल चंदा लगभग 41 लाख रुपये इकट्ठा हुआ। इस में से 80 प्रतिशत की अदायगी राज्यों और संघशासित प्रदेशों को कर दी गयी है। अब तक 27 राज्य और संघशासित कार्यकारी समितियों को 2.53 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने अभी तक इसमें भाग नहीं लिया है। प्रतिष्ठान ने

लगभग 2.65 करोड़ रुपये का संग्रह कर लिया है । इस पर कमाये गये ब्याज को अध्यापकों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए दिया जाता है ।

राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार

वर्ष 1974 के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा परम्परागत पाठशालाओं, और टोलों के 96 संस्कृत अध्यापकों की इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है । इन पुरस्कारों में एक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा 1000/- रुपये का नकद भुगतान किया जाता है ।

नेहरू बाल पुस्तकालय

इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अभी तक 32 मौलिक पुस्तकों और 267 अनूदित पुस्तकों को प्रकाशित किया है । इसी वर्ष के दौरान चार और पुस्तकों को प्रकाशित करने की आशा है । इन पुस्तकों को बाजार में 1.50 रुपये प्रति पुस्तक की कीमत पर बेचा जाता है और राज्य सरकारों को 50 पैसे प्रति पुस्तक की दर से रियायत दी जाती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नेहरू बाल पुस्तकालय योजना के लिए 50.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1974-75 के लिए 6.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है तथा वर्ष 1975-76 के लिए 9.00 लाख रुपये की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्

पुनर्गठित राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की बैठक मार्च, 1974 में हुई थी जिसमें अनेक सिफारिशें की गयी थीं । महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) रा० म० शि० परिषद् द्वारा प्रत्येक बैठक में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करने और पथप्रदर्शन करने और लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक राज्य में चालू की गयी योजनाओं तथा विशेष उपायों की प्रगति को देखने के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना ;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के रूप में काम करने के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जाने चाहिएं :–

(क) उन महिलाओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों में स्थान आरक्षित किये जाने चाहिएं जिन्होंने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षा के सघन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तथा दाखिले की आयु से संबंधित नियम में छूट दी जानी चाहिए।

(ख) मौजूदा कुछ सघन पाठ्यक्रमों को सघन अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूप में परिवर्तित करने की संभावना की जांच की जाय।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के रूप में कार्य करने की, इच्छुक स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए चुना जाय तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें उपर्युक्त वजीफा भी दिया जाए ताकि अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद उन्हें उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक अध्यापकों के रूप में नियुक्त किया जाय जिन क्षेत्रों से वे संबंधित हैं।

(3) लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में राज्य महिला शिक्षा परिषदें स्थापित की जायें और इनमें सुधार करने के लिए योजनाएं आरंभ की जायें।

स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना

यद्यपि इस वर्ष के दौरान कोई नये अनुदानों की व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि यह योजना अप्रैल, 1972 से रुकी हुई है, परन्तु इस वर्ष के दौरान उन्हीं संस्थाओं को अनुदानों का भुगतान किया गया, जिनकी परियोजनाओं के बारे में पहले से अनुमोदन दे दिया गया था और जिन्हें सरकारी अनुदान की अनुवर्ती किस्तें देय थीं। वर्ष 1974-75 के दौरान, 20 संस्थाओं को अनुदानों का भुगतान किया गया था। डा० ग्राहम्स

होम, कालिमपोंग को (7,000/- रु०) और अंतरराज्य आंग्ल-भारतीय शिक्षा बोर्ड को (4,000/-- रु०) के अनुदानों का भी भुगतान किया गया था ।

श्री अरविन्द बाल केन्द्र

ये बाल केन्द्र गन्दी बस्तियों के बच्चों के लिए मनोरंजन तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं। उनका संवितरण निम्नलिखित है :–

1.	कलकत्ता	4
2.	बम्बई	4
3.	दिल्ली	3
4.	मद्रास	2
5.	हैदराबाद	1
6.	बंगलौर	1
7.	अहमदाबाद	1
	कुल	16

दिल्ली को छोड़कर सभी संबंधित राज्य सरकारों को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति बाल केन्द्र के लिए 62,000/- रु० की दर से अनावर्ती अनुदान मंजूर किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों ने आयोजना समितियां गठित की हैं तथा इन बाल केन्द्रों की स्थापना का कार्य विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है ।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय भगवान महावीर शताब्दी वर्ष में अर्थात् 13 नवम्बर 1974 से 15 नवम्बर 1975 के दौरान मोटे तौर पर श्री अरविन्द बाल केन्द्रों की पद्धति पर अन्य 16 बाल केन्द्रों की स्थापना करने जा रहा है ।

इन नये 16 केन्द्रों को मद्रास, मदुरै, पूना, बम्बई, अहमदाबाद, नागपुर, पटना, कलकत्ता, जबलपुर, इन्दौर, लखनऊ, आगरा, जयपुर और हैदराबाद में एक-एक और कानपुर में दो केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

दूसरा अध्याय

उच्च शिक्षा और अनुसंधान

शिक्षा मंत्रालय मुख्यत: उच्च शिक्षा में स्तरों के अनुरक्षण और निर्धारण के लिए उत्तरदायी है ; यह कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से किया जाता है । कार्यक्रम में शिक्षा के गुणात्मक समेकन और सुधार पर विशेष बल दिया गया है । मंत्रालय, छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सुधार तथा शिक्षकों के स्तरों को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दे रहा है । मंत्रालय ने, समाज शास्त्र तथा ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए भी संगठनों को अलग से धन दिया है । उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में अलग से अध्याय चार में उल्लेख किया गया है ।

इस क्षेत्र में भारत सरकार की संस्थाएं निम्नलिखित हैं :—

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ; (ii) केन्द्रीय विश्व-विद्यालय, अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, जवाहर-लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्वभारती और उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय तथा कुछ समय पूर्व स्थापित हैदराबाद विश्व-विद्यालय; (iii) शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान; (iv) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला ; (v) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्; और (vi) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी पूर्व-स्वीकृत विकास परियोजनाओं के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जारी रखा । जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षण तथा तकनीकी कर्मचारी, वैज्ञानिक उपस्कर, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं, शिक्षा भवन, छात्रावास तथा कर्मचारियों के मकान हैं । आयोग ने अपने द्वारा चलाये गए प्रमुख गुण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण भी पूरा कर लिया है । ऐसे कार्यक्रम जिनकी सहायता जारी रखी जा रही है, ये हैं:— उच्च अध्ययन के केन्द्र, संकाय सुधार, चुने हुए विश्वविद्यालयों के

विभागों का सुधार तथा कालेज विज्ञान कार्यक्रम सुधार । नये गुणात्मक तथा सुधारात्मक कार्यक्रमों को भी शुरू कर दिया गया है, जैसे परीक्षा सुधार, स्वायत्त-शासी कालेज, पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, अनुसंधान में सहायता तथा कालेज मानविकी कार्यक्रमों में सुधार । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकलापों की विस्तृत रिपोर्ट संसद में अलग से पेश की जाएगी । निम्नलिखित कार्यक्रमों /समस्याओं/ नीतियों पर जोर देने की आवश्यकता है ।

पांचवीं योजना के दौरान इस बात पर बल दिया जाएगा कि मौजूदा विभागों का पुनर्गठन, वृद्धि तथा उनमें उपर्युक्त परिवर्तन किए जाएं ताकि औपचारिक तथा पूर्णकालिक शिक्षा, विशेषकर अवर स्नातक के स्तर पर, दाखिले में पर्याप्त प्रतिबंध लग सके । क्योंकि काफी बड़ी संख्या में छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं, इसलिए स्नातकोत्तर शिक्षण का यथासंभव समेकन किया जाना है । प्रादेशिक असन्तुलन को हटाने के लिए और समाज के पिछड़े वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष यत्न किये जाएंगे ।

कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के पाठ्यक्रमों में, विशेषत: अवर-स्नातक स्तर पर, सामान्य शिक्षा में विविधता लाई जायेगी तथा जहां तक सम्भव हो ऐसे पाठ्यक्रमों की स्थानीय उपयुक्त उद्योग, व्यवसायों तथा व्यापारिक संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा । विश्वविद्यालयों से प्राप्त नई योजना के सुझावों की विशेषज्ञ समिति की सहायता से जांच की जा रही है और उसकी सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालयों के लिए पांचवीं योजना के सुझावों को अन्तिम रूप दिया जाएगा । अवर-स्नातक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं में सुधार लाने के प्रयोजन से प्रत्येक कालेज के लिए पांच लाख रुपये तक के परिव्यय के सुधार संबंधी सुझाव भी मांगे गये हैं ।

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना पर भी रोक रहेगी जिसके लिए आयोग ने सभी राज्य सरकारों को मार्ग निर्देश दे दिये हैं । नये कालेजों की स्थापना पर भी रोक रहेगी क्योंकि जून, 1972 के बाद बने केवल उन कालेजों को आयोग की सहायता उपलब्ध होगी जो स्थायी रूप से सम्बद्ध कालेज हों ।

आयोग ने कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम के द्वारा 1970-71 से कालेज शिक्षा में सुधार का कार्यक्रम तैयार किया है । इस समय 26 विश्वविद्यालय विभाग तथा 117 कालेज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं । इसके द्वारा अवरस्नातक स्तर तक विज्ञान की शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार लाने में चुने हुए विभागों तथा

कालेजों को मदद मिली है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं के कार्य के लिए नयी पाठ्य-सामग्री, नये प्रदर्शन उपस्कर तथा अन्य शिक्षण साधन भी बनाए जा सकते हैं । अवर-स्नातक स्तर के कालेजों में मानविकी और समाज विज्ञान के शिक्षण में मजबूती लाने के लिए और अवर-स्नातक स्तर तक के लिए विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए जिससे विद्यार्थी अपनी अभिरुचि के विषयों के अध्ययन में अपनी क्षमता, रुचि तथा योग्यता को बढ़ा सकें, इसी प्रकार का कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था । इस कार्यक्रम के लिए अब तक 42 कालेजों को चुना गया है ।

एक विशेषज्ञ समिति अध्ययन पाठ्यक्रम के पुनर्स्थापन के लिए कार्यक्रम बना रही है जो ग्रामीण वातावरण तथा शहरी आवश्यकताओं के उपयुक्त हो । यह, वर्तमान अध्ययन पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है ताकि वे देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं के प्रति अधिक संगत हो सके । विद्यार्थियों के रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए विशेष डिप्लोमा पाठ्यक्रम कई विश्वविद्यालयों में शुरू किए गए हैं, जैसे गुजरात, आंध्र, जम्मू तथा मद्रास विश्वविद्यालय ।

रुड़की भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में अनेक उत्पादन यूनिट स्थापित किए गए हैं । ताकि विद्यार्थियों को काम का व्यावहारिक अनुभव हो जाय । एक विशेषज्ञ समिति इस समय काम के अनुभव को शिक्षा के अनुरूप बनाने के लिए परियोजना का ब्यौरा तैयार कर रही है ।

आयोग ने संकाय सुधार कार्यक्रमों तथा संकाय पुरस्कारों को प्राथमिकता दी है । संस्थानिक संकाय सुधार कार्यक्रम का भी कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम तथा कालेज मानविकी कार्यक्रमों के साथ एकीकरण कर दिया गया है ।

विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान के विषयों में तथा इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान छात्रवृत्तियों की व्यवस्था जारी रखी गई । विद्यार्थी कल्याण और सुविधाओं के लिए व्यवस्था हेतु सहायता का दिया जाना जारी रहा ।

आयोग के परीक्षा सुधार के लिए महत्व के कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके लिए भावी कार्य की योजना को तैयार कर लिया है । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 12 विश्वविद्यालयों से विशेष सैल स्थापित करने के लिए कहा

गया है जो मार्ग-दर्शन का काम करेंगे। विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के स्तर तथा उनकी कोटि को देखते हुए तथा कक्षा के अनुभवों के आधार पर नयी शिक्षण पद्धति तथा नए परीक्षा-प्रश्नों को बनाया जायेगा।

कालेजों की स्वायत्तता

आयोग ने चुने हुए कालेजों को स्वायत्तता देने के कदम उठाये हैं, ताकि वे नयी शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग कर सकें जिससे वे अध्यापन पद्धति, पाठ्यक्रमों तथा मूल्यांकन की तकनीक में आवश्यक परिवर्तन ला सकें। इस तरह के कालेजों के चुनाव के लिए मार्गदर्शन तथा मानक की सूचना विश्वविद्यालयों को दी जा चुकी है तथा ऐसे कालेजों का चुनाव भी शुरू कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय समझे जाने वाले संस्थान

(i) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।
(ii) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
(iii) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।
(iv) टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के अनुसार इन संस्थानों को अनुरक्षण अनुदान घाटा पूरा करने के आधार पर दिया जाता है तथा उसी के अनुसार विकास अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष इन संस्थानों ने अपने सामान्य कार्यक्रमों को जारी रखा।

काशी विद्यापीठ वाराणसी को विश्वविद्यालय माना जाता है। इसे **उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम** के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय के तौर पर अधिसूचित किया गया।

विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमानों को और आगे संशोधित करना मान लिया है। अनुमोदित संशोधित वेतनमान निम्नलिखित हैं :–

विश्वविद्यालय

लेक्चरार . . .	700–40–1100–50–1600 रुपये
रीडर . . .	1200–50–1500–60–1900 रुपये
प्रोफेसर . .	1500–60–1800–100–2000–125/2–2500 रुपये

सम्बद्ध कालेज (स्नातकोत्तर तथा अवर-स्नातक)

निदर्शक/ट्यूटर . .	500–20–700–25–900 रुपये
(विद्यमान पदधारी)	
लेक्चरार . . .	700–40–1100–50–1300–मूल्यांकन 50–1600 रुपये
प्रिंसिपल . . .	(i) 1200–50–1300–60–1900 रुपये
	(ii) 1500–60–1800–100–2000–125/2–2500 रुपये

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वीकृति दे दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबन्धक संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान के बारे में भी इसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सरकार के निर्णय से अवगत कर दिया है। पहली जनवरी, 1973 से संशोधित वेतनमान लागू हो जाएंगे। भारत सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए स्वीकृत वेतनमानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी पेश की है। यदि राज्य सरकारें इन वेतनमानों से भिन्न परन्तु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वेतनमानों से कम वेतनमान लागू करने का निर्णय करें तो भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। संशोधित वेतनमानों को 1-1-1973 से अथवा उसके पश्चात् लागू किया जा सकता है। कुल अतिरिक्त व्यय के 80 प्रतिशत तक राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाएगी तथा 1-1-1973 से अथवा कार्यान्वयन की तारीख से 31 मार्च, 1979 तक उपलब्ध होगी।

कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति की पद्धति, अधिवार्षिकी आयु, परीक्षा-कार्य के लिए पारिश्रमिक आदि के सम्बन्ध में कुछ शर्तों के अधीन, संशोधित वेतनमान होंगे।

संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा सरकार द्वारा स्वीकृत सूत्र के अनुसार होगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

कार्यकारी परिषद् का, विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबन्धों तथा संशोधित संविधियों के अनुसार, जिन्हें शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया था, जून, 1974 में गठन किया गया था और पुनर्गठित कार्यकारी परिषद् की प्रथम बैठक 25 जून, 1974 को हुई थी। विश्वविद्यालय-कोर्ट का अभी तक पुनर्गठन नहीं हुआ है क्योंकि कोर्ट के कुछेक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुए हैं।

प्रोफेसर के० ए० निज़ामी, सम-कुलपति ने, जो प्रोफेसर अब्दुल अलीम के स्थान पर कुलपति के रूप में कार्य कर रहे थे और जिन्होंने 3-1-1974 को त्याग-पत्र दे दिया था, 30-8-1974 को अपने कार्यालय का कार्यभार त्याग दिया और वरिष्ठतम प्रोफेसर एच० एस० शर्मा, ने कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया। यह अस्थायी व्यवस्था 19 सितम्बर, 1974 तक जारी रही और आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली के निर्देशक प्रो० ए० एम० खुसरो को 20 सितम्बर, 1974 को संविधि 2 के अधीन कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया।

खेलकूद तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यकलाप

आलोच्य वर्ष की अवधि के दौरान, खेलकूद तथा सांस्कृतिक समितियों के अन्तर्गत विभिन्न क्लबों ने अपनी गतिविधियों को अबाध रूप से जारी रखा। छात्रों ने उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया। क्रिकेट में विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों सें से एक खिलाड़ी को सी० के० नायडू ट्राफी के लिए यू० पी० क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। वालीबाल टीम ने अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट में भाग लिया।

सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व

विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सामान्य रूप से भारत में तथा भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/गोष्ठियों/सेमिनारों में भाग लेना जारी रखा।

डा० मोहम्मद अहमद ने, सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में क्यूबेक नगर, कनाडा में हुई कार्डिक मैटाबोलिजम में अनुसंधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन दल की 7वीं वार्षिक बैठक का नेतृत्व करके एक अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त की।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के पालिटेक्निक के प्रिंसिपल श्री एस० ए० अब्बास, भारतीय

प्रतिनिधिमण्डल द्वारा तीन प्रौद्योगिकी संस्थानों के सम्बन्ध में संकलित परियोजना रिपोर्ट की रूपरेखा के बारे में ईराक सरकार से विचार-विमर्श करने के लिए प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में ईराक गए। ईराक में इन तीन संस्थानों का निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है।

सेमिनार

विश्वविद्यालय के परिसर में भी गत वर्ष की भांति अनेक सेमिनार आयोजित किए गए।

विशिष्ट आगन्तुक

आलोच्य वर्ष के दौरान, अनेक विशिष्ट आगन्तुकों का विश्वविद्यालय में स्वागत किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, महामहिम जायेद बिन सुलतान अल नहयान का दौरा विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

विस्तार सेवाएं

शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे विस्तार सेवा एकक और मौलाना आजाद पुस्तकालय ने वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों को जारी रखा।

पुरातत्वीय प्रयोगशाला

उच्च अध्ययन केन्द्र, इतिहास विभाग में स्थापित पुरातत्वीय प्रयोगशाला ने केन्द्र द्वारा की गई खुदाइयों में प्राप्त पौध-अवशेषों पर पुरातत्वीय जांच के कार्य को गति प्रदान की।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विकास प्रस्ताव

विश्वविद्यालय ने, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या तथा पाठ्येतर गतिविधियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की हैं, तथा ये प्रस्ताव अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं। विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय, आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

भवन परियोजनाएं

कुछ शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक भवनों को पूरा करने के कार्य में, विशेषकर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को निर्माण कार्य सौंपे जाने के बाद, पर्याप्त प्रगति हुई है।

वित्त

विश्वविद्यालय जिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू मैडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल में बिस्तरों के अनुरक्षण के लिये इस वर्ष 7.50 लाख रुपय का अनुदान दिया है। यद्यपि चालू वर्ष के दौरान सामान्य बजट के अन्तर्गत विभिन्न मदों के खर्चों में पर्याप्त कटौती की गई, फिर भी, सामग्री, पुस्तकों, कागज की कीमतों और प्रयोगशाला को चलाने के खर्चों में तेजी से वृद्धि के कारण, बजट प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के अनुरक्षण बजट के लिये अब तक 3,01,89,000/– रुपये की राशि दी है। वेतनमानों में संशोधन होने के कारण स्टाफ को बकाया भुगतान के लिए 53,23,000/– रुपये का अनुदान भी प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विश्वविद्यालय की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 अन्य मदों के अन्तर्गत भी अनुदान स्वीकृत किया है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

सम्मेलन, सेमिनार, इत्यादि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 79 शिक्षकों को देश में सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए तथा 18 शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4 शिक्षकों ने भी विदेशों का दौरा किया। विभिन्न विनियम कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेश से 25 प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्रियों ने विश्वविद्यालय का दौरा किया। निम्नलिखित गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए गए :

(i) अर्थशास्त्र और वाणिज्य में कालेज शिक्षकों के लिए छः दिवसीय पुनश्चर्या कार्यक्रम ;

(ii) भ्रूणविज्ञान पर भारत-फ्रेंच सेमिनार ;

(iii) पशु शरीरविज्ञान में अखिल भारतीय उच्च स्तर ग्रीष्म संस्थान ; और

(iv) विश्वविद्यालय के महिला विद्यालय में स्त्रियों की शिक्षा पर अखिल भारतीय सम्मेलन।

नियुक्तियां

व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के अन्तर्गत पदोन्नतियां, वर्ष के दौरान लगभग पूरी कर ली गई थीं। 48 प्राध्यापकों को रीडरों के पदों पर तथा 24 रीडरों को प्रोफेसरों के पदों पर पदोन्नत किया गया। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 5 प्रोफेसरों, 13 रीडरों तथा 64 प्राध्यापकों को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया।

अनुसन्धान परियोजनाएं

वर्ष के दौरान तीन अनुसंधान परियोजनाएं संस्वीकृत की गई। प्रयोगशाला तथा कर्मशाला तकनीशियनों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जून-जुलाई, 1974 में आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने 165 पी० एच० डी० तथा 4,932 अवर-स्नातक तथा स्नातक की डिग्रियां प्रदान कीं। विश्वविद्यालय के 3 शिक्षकों को फैलोशिप/पदक प्राप्त हुए।

छात्रों को छात्रवृत्तियाँ तथा वित्तीय सहायता

विश्वविद्यालय, 250/—रुपये के प्रति माह की 210 अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इनमें से 90 छात्रवृत्तियां वर्ष के दौरान दी गईं और शेष का नवीकरण किया गया। 300 रुपये के मूल्य की (अब बढ़ाकर 400/—रुपये की कर दी गई) लगभग 60 जूनियर अनुसंधान छात्रवृत्तियां भी प्रतिमाह दी गईं। इनके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के छात्रों को 370 वि० आ० आ०/बे० औ० अनु० परि०, जूनियर/वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप तथा उत्तर डाक्टोरल फैलोशिप संस्वीकृत की गई। छात्रों को छात्र कल्याण निधि में से 18,062 रुपये तक की विशेष वित्तीय सहायता दी गईं। ऐसे अनुसंधान छात्रों को जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली उन्हें अपने शोध कार्य को टाइप कराने के लिए 14,000/— रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

विकास

चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजनाएं पूरी हो गईं, सिवाय कुछ भवनों के जो अंशतः निर्माण कार्य पर प्रतिबंध के कारण तथा अंशतः भवन परियोजनाओं के आकार और स्वरूप के कारण पूरी न हो सकीं। विश्वविद्यालय अपने कार्यकलापों को सुदृढ़ करने तथा भाषा विज्ञान तथा पत्रकारिता में नए पाठ्यक्रम, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा विज्ञानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने में समर्थ हो सका। विभिन्न प्रयोगशालाएं आधुनिक तथा सूक्ष्म उपस्करों से सज्जित की गईं और पुस्तकालयों को समृद्ध किया गया। खेल-कूद के क्षेत्र में अधिकांश महत्वपूर्ण खेलों के लिए

अतिरिक्त प्रशिक्षकों की व्यवस्था की गई, छात्रों को खेल सामग्री उपलब्ध की गई, खेल के मैदानों का विकास किया गया और तैरने के तालाबों का सुधार किया गया। उत्तम भोजन, जल तथा विद्युत सुविधाओं सहित अतिरिक्त छात्रावास स्थान की व्यवस्था की गई। शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक स्टाफ के लिए 71 अतिरिक्त क्वार्टरों का भी निर्माण किया गया।

विश्वविद्यालय के पांचवें योजना के प्रस्तावों का उद्देश्य गुणात्मक सुधार, शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार और विभागीय एवं संकायवार अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना सहित सीनियर तथा जूनियर शिक्षकों के पदों के अनुपात में सुधार करना है। इसमें अंतर-विषयक शिक्षण तथा अनुसंधान, शिक्षण की उच्च विशिष्ट शाखाएं आरंभ करना, देश और विदेश में अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ समन्वय, परिसर विकास, आधुनिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि भी सम्मिलित है।

वित्त

निम्नलिखित आंकड़े समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की अनुमानित वित्तीय स्थिति दर्शाते हैं :—

लेखा शीर्ष	आय	व्यय
	(रुपये लाखों में)	
1. योजनेत्तर . . .	564	588
2. निर्धारित . . .	68	67
3. विभागीय जमा आदि . .	856	849
	1488	1504

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा करने तक निम्नलिखित मूलभूत अनुदान संस्वीकृत किये हैं :-

1. विज्ञान, मानविकी तथा समाजशास्त्र . . 12.50 लाख रु०
2. चिकित्सा शास्त्र संस्थान . . . 8.00 लाख रु०
3. इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी . . . 4.00 लाख रु०

विश्वविद्यालय ने, वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियों पर प्रतिबंध, नये भवनों के निर्माण में स्थगन और सेमिनारों/

संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के खर्चों में-कमी करके बचत के लिए कुछ कदम उठाए हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति श्री जी० पार्थासार्थी ने 29 अप्रैल, 1974 को अपनी पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद कुलपति के पद का कार्यभार त्याग दिया। डा० वी० डी० नाग चौधरी ने, 1 जुलाई, 1974 को विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्यभार संभाल लिया।

शैक्षिक परिषद् ने यह सिफारिश करने का निर्णय किया कि समय-समय पर संसद द्वारा पास किये गये प्रस्तावों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यार्थियों के लिए अध्ययन के सभी कार्यक्रमों में सभी अध्ययन स्कूलों की 20% स्थान आरक्षित करने चाहिएं।

स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित सामग्री सहित भारत के एक समकालीन इतिहास अभिलेखागार की स्थापना की गई, यह सामग्री भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास पर कार्य कर रहे शोधकर्त्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

विश्वविद्यालय ने, कुछ विशेष शर्तों के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संगठन को मान्यता प्रदान की।

आलोच्य अवधि के दौरान, भारतीय भाषाओं का एक केन्द्र स्थापित किया गया और भाषाओं के स्कल को इसका कार्य सौंपा गया।

अध्ययन के नये कार्यक्रम

वर्ष के दौरान अध्ययन के निम्नलिखित नये कार्यक्रम प्रारंभ किए गए :—

1. समाज शास्त्र स्कूल

(i) शैक्षणिक अध्ययनों के लिए ज़ाकिर हुसैन केन्द्र में एम० फिल०/ पी० एच० डी० कार्यक्रम ;

(ii) क्षेत्रीय विकास के लिए केन्द्र में जनसंख्या अध्ययन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम ;

2. भाषाओं का स्कूल

(i) अंग्रेजी, भाषा-विज्ञान, उर्दू और हिन्दी में मास्टर्स डिग्री के अध्ययन का द्विवर्षीय कार्यक्रम ।

(ii) विशिष्ट अनुवाद तथा जापानी में व्याख्या म पांच वर्षीय (10 सेमस्टर) कार्यक्रम ।

(iii) इतालवी और पुर्तगाली भाषा में प्रवीणता प्रमाणपत्र ।

अनुसंधान

आलोच्य अवधि के दौरान, संकाय के सदस्यों द्वारा 187 पुस्तकें/अनुसंधान-निबंध/लेख प्रकाशित किए गए । 52 अनुसंधान-निबंध/लेख/परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं और प्रकाशन के लिए तैयार हैं ।

विश्वविद्यालय के जीव-विज्ञान, स्कूल में अनुकूलनशील जीव विज्ञान, विकास जीव विज्ञान, फोटो जीव-विज्ञान, पकिरण जीव विज्ञान, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी, आणविक जीव-विज्ञान तथा शरीर विज्ञान के अतिरिक्त जीव-भौतिकी में अनुसंधान कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए कदम उठाये हैं । स्कूल पर्यावरण विज्ञानों तथा विकास अध्ययनों जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों को शुरू करने की सम्भावनाओं की भी खोज कर रहा है ।

पुस्तकालय

सप्रू हाउस और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में स्थित पुस्तकालय एककों को मुख्य परिसर में स्थानान्तरित करके पुस्तकालय पद्धति के सुदृढ़ीकरण का प्रथम चरण पूरा किया गया ।

आलोच्य अवधि के दौरान, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के पत्रिका एकक ने परिसर में कार्य करना प्रारंभ कर दिया । एकक को मुख्यत: समाज विज्ञानों के क्षेत्र में प्रकाशित लगभग 2,230 पत्रिकाएं प्राप्त हुई । नि:संदेह इसने हमारे संकाय और समाज विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे शोधकर्त्ताओं को लाभ पहुंचाया है । विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा मानविकी तथा विज्ञान में हाल ही में प्राप्त पत्रिकाओं को भी इस एकक में प्रदर्शित किया गया ।

4—956MofEdu&SW/74

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय पुस्तकालय में लगभग 24,000 पुस्तकों की अभिवृद्धि की गई। इस प्रकार केन्द्रीय पुस्तकालय में कुल 2,07,000 पुस्तकों का संग्रह हो गया है। कनाडा और आस्ट्रेलिया के स्थानीय दूतावासों, प्रधानमंत्री सचिवालय, डा० ज्ञान चन्द्र राष्ट्रीय पुस्तकालय (पीकिंग) और सोवियत रूस की विज्ञान अकादमी के पुस्तकालय से पर्याप्त पुस्तकें भेंट स्वरूप प्राप्त हुईं। आलोच्य वर्ष के दौरान, भेंट स्वरूप प्राप्त अनुसंधान सामग्री का प्रतिशत पुस्तकालय में प्राप्त हुई कुल अभिवृद्धियों का लगभग 25 है।

प्रलेखन

प्रलेखन कार्य ने पिछले वर्ष में पुस्तकालय गतिविधियों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। मानविकी और समाज विज्ञानों में 1,000 से अधिक पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका संबंधी कार्य, जिसमें 25,000 से अधिक प्रविष्टियां होंगी, पूरा हो जायेगा। प्राणी विज्ञानों तथा राष्ट्रीय विज्ञानों की पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका संबंधी कार्य भी शुरू हो गया है।

परिसर विकास

शैक्षणिक सत्र 1975-76 के आरम्भ तक नए परिसर में निम्नलिखित भवन उपलब्ध हो जायेंगे :–

(1) 1000 छात्रों के लिए छात्रावास और वार्डनों के लिए 20 रहने के मकान।

(2) संकाय के 144 सदस्यों और स्टाफ के अन्य सदस्यों के लिए रिहायशी मकान।

(3) गैर-शैक्षिक स्टाफ के लिए 82 स्टाफ क्वार्टर्स।

(4) एक सुलभ विपणन केन्द्र।

(5) परिकलक केन्द्र भवन।

(6) एक स्कूल भवन।

पांचवीं योजना में एक और स्कूल भवन के निर्माण का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

देहली से बाहर शैक्षिक कार्यकलाप

विश्वविद्यालय, इम्फाल (मणिपुर) स्थित एक उत्तर-स्नातक अध्ययन केन्द्र का संचालन करता है। केन्द्र के अनुरक्षण पर होने वाला आवर्ती खर्च मणिपुर

सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जहां तक योजनागत खर्चे का संबंध है, इसमें से अधिकांश खर्चा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों में से और अंशत: मणिपुर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों में से पूरा किया जाता है। 1974-75 के दौरान इस केन्द्र पर कुल अनुमानित योजनागत खर्च इस प्रकार है :—

		(रु० लाखों में)
(i)	मणिपुर राज्य सरकार का अंश . .	1.28
(iii)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंश . .	15.96

अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय के रजिस्टर में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1973-74 में 1,24,530 की तुलना में, 1974-75 में 1,35,828 हो गई। इस तरह पिछले वर्ष की संख्या में 11,298 की बढ़ोतरी हुई। विश्वविद्यालय में 78,362 नियमित विद्यार्थी हैं, 37,486 विद्यार्थी बाह्य कक्ष में हैं, 13,211 पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल में और 6,719 गैर-कालिजिएट स्त्री शिक्षा बोर्ड के छात्र हैं।

पी० एच० डी० डिग्री के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2447 है। आयुर्विज्ञान संकाय के रजिस्टर में विभिन्न अवर-स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रियों एवं डिप्लोमाओं के लिए 2746 छात्र हैं। प्रौद्योगिकी संकाय में 1258 छात्र नामांकित हैं। विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान और समाज विज्ञान के आनर्स पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या 21,268 है। इनमें से 3505 छात्र विज्ञान में आनर्स पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं।

नए कालेज

चालू वर्ष के दौरान कोई भी नया कालेज नहीं खोला गया। केन्द्रीय शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय ने अपने अधीन ले लिया है और इसे संरक्षित संस्थान की तरह चलाया जाएगा।

नए पाठ्यक्रम

निम्नलिखित नए अवर स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं :—

(अ) ललित कला स्नातक (पेन्टिंग–चित्रकला)

(ब) ललित कला स्नातक (मूर्तिकला)

(स) ललित कला स्नातक (प्रयुक्त कला)

उच्च अध्ययन केन्द्र

विश्वविद्यालय ने चालू वर्ष के दौरान समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक-शास्त्र व खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा जीवविज्ञान के छ: उच्च शिक्षा केन्द्रों में अपने कार्य को जारी रखा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना का आबंटन

विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इस समय यह बताना कठिन है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसलिए यह सुझाव है कि विश्वविद्यालय अपने विकास कार्यक्रम इस प्रकार तैयार करे कि पांचवीं योजना में उनके लिए आयोग से 300 लाख रु० से अधिक की राशि न मांगनी पड़े। इन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है–– प्रथम 50 प्रतिशत, दूसरा 25 प्रतिशत तथा शेष 25 प्रतिशत।

उपरोक्त राशियां विश्वविद्यालय के मानविकी, समाज विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, विधि तथा भाषा विभागों के विकास कार्यों के लिए है। इनमें उनकी सामान्य जरूरतों का खर्च भी शामिल है, जैसी कि पहली योजना की अवधि में व्यवस्था थी।

दक्षिण दिल्ली परिसर

दक्षिण दिल्ली परिसर ने, जो कि नौ स्नातकोत्तर विभागों के साथ जुलाई, 1973 में स्थापित किया गया था, वर्ष 1973-74 की भांति ही, उसी परिसर में और उसी आधार पर कार्य करना जारी रखा। 1974-75 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ कर 497 से 960 हो गई। कुछ अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की गई थी तथा कुछ और भर्ती की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसके पुनर्गठन के लिए योजना विचाराधीन है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 1973 में 10,116 थी। अब यह बढ़कर 13,867 हो गई है। इसके अतिरिक्त 150 पत्रिकाएं भी पुस्तकालय में आ रही हैं।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

नया केन्द्रीय हैदराबाद विश्वविद्यालय, 2 अक्तूबर, 1974 को स्थापित हुआ। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गुरुबक्स सिंह को इसका उप-कुलपति नियुक्त किया गया है।

उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय

उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम के द्वारा 19 जुलाई, 1973 को स्थापित किया गया। इसका क्षेत्र मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल, प्रदेश तथा मिजोराम है। अधिनियम में मेघालय तथा नागालैण्ड में इसके कैम्पसों की व्यवस्था है तथा विश्वविद्यालय को यह अधिकार दिया गया है कि "वह अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य जगहों में भी जहां उचित समझा जाए, कैम्पस स्थापित करे"। उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय "उत्तर-पूर्व क्षेत्र के पर्वतीय लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा उनकी भलाई पर विशेष ध्यान देगा, विशेषकर उनकी बौद्धिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रगति पर वह विशेष ध्यान देगा।"

अपनी स्थापना के पहले वर्ष में ही विश्वविद्यालय ने अपना पहला अन्तर-कालेज खेलकूद प्रतियोगिता, (विश्व युवक केन्द्र, दिल्ली के सहयोग से) विद्यार्थी नेतृत्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा कालेज अध्यापकों के लिए समाज विज्ञान वर्कशाप का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त इसने एक मासिक समाचार पत्रिका, 'ड्रमवीटस' भी शुरू किया।

इस समय विश्वविद्यालय अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणिशास्त्र तथा गणित में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित करता है। पी० एच० डी०, एम० लिट० तथा बी० लिट० पाठ्यक्रम भी जल्दी ही शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, अध्यापन के विषयों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आजकल भाषा विद्यालय, समाज विज्ञान विद्यालय, जीवन विज्ञान विद्यालय तथा भौतिक विज्ञान विद्यालय के शिक्षण संकाय इसमें हैं।

स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :–

अंग्रेजी के 72 छात्र, दर्शनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा जीवन विज्ञान में प्रत्येक में पन्द्रह छात्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा गणित में प्रत्येक में चालीस छात्र हैं।

विश्वविद्यालय के 22 सम्बद्ध कालेजों में कुल 570 प्राध्यापक हैं। पूर्व-विश्वविद्यालय, बी० ए० (पास), बी० एस० सी० (सामान्य) तथा बी०ए० और बी० एस० सी० (आनर्स) में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 14050 है।

विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर महिला विद्यार्थियों के लिए एक छोटा-सा छात्रावास खोला है ।

विश्व भारती

विश्वविद्यालय के 21 प्राध्यापकों को मिलाकर पी० एच० डी० डिग्री के अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या 106 है ।

विश्व भारती समिति

सरकार द्वारा गठित विश्व भारती समिति की बैठक न्यायमूर्ति श्री एस० ए० मसूड की अध्यक्षता में कई बार हुई । इस समिति का कार्य विश्वभारती को और विकसित कराने के उपाय तय करना तथा विश्वभारती अधिनियम में परिवर्तन के लिए मार्गदर्शक सुझावों की सिफारिश करना है । इसकी रिपोर्ट जल्दी निकलने वाली है ।

पांचवीं योजना के कार्यक्रम

विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए मार्ग-दर्शन के अनुरूप अपनी भौतिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए अपनी पांचवीं योजना की आवश्यकताओं को पेश कर दिया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति से चौथी योजना के अधूरे कार्यों को 1974-75 में पूरा किया जाएगा ।

अखिल भारतीय महत्व की उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून, लोक सेवा महाविद्यालय, लोक भारती, सनोसरा, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना तथा श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी ने सरकार से अनुदान प्राप्त करना जारी रखा ।

डा० जाकिर हुसैन स्मारक कार्यक्रम

(i) डा० जाकिर हुसैन स्मारक न्यास

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में डा० जाकिर हुसैन स्मारक न्यास की प्रथम बैठक 16 अप्रैल, 1974 को हुई । इस न्यास ने डा० जाकिर हुसैन स्मारक न्यास के सचिव के रूप में दिल्ली कालेज (जिसका नाम अब बदलकर डा० जाकिर हुसैन स्मारक रख दिया गया है) के प्रिंसिपल डा०एस० अहमद अली की नियुक्ति स्वीकृत

की। न्यास स्मारक नियमावली के अनुच्छेद 2(vi) के अनुसार कालेज के शासकीय निकाय के लिए डा० जाकिर हुसैन स्मारक न्यास ने भी 12 सदस्य मनोनीत किए हैं।

न्यास ने मिन्टो रोड क्षेत्र में कालेज के लिए स्थान लेने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया। कालेज के लिए स्थान को शीघ्र लेने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ii) डा० जाकिर हुसैन स्मारक व्याख्यान

स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन की स्मृति बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक लाख रुपए की स्थाई निधि की आय से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रयेक वर्ष क्रम से डा० जाकिर हुसैन स्मारक व्याख्यान आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया।

(iii) डा० जाकिर हुसैन इस्लामी अध्ययन संस्थान की स्थापना

जामिया मिलिया इस्लामिया में, 3,00,000 रुपए की अक्षय निधि से स्थापित इस्लामी अध्ययन विभाग ने वर्तमान वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों को जारी रखा है।

भारतीय तथा अमरीकी विद्वानों का सम्मेलन

7 से 10 जनवरी, 1974 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय तथा अमरीकी विद्वानों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच शैक्षिक विनिमय तथा अनुसंधान पर विचार किया गया जिसमें विद्यार्थी, विद्वान तथा संस्थाएं शामिल हैं और दोनों देशों के शैक्षिक समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाने पर विचार किया गया।

शास्त्री भारत कनाडा संस्थान

संस्थान के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करने तथा भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के लिए सोलह फैलो/भाषा अध्यापक भारत आए हैं। अपने पुस्तकालय कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान ने सितम्बर, 1974 के अन्त तक कनाडा की अपनी सदस्य संस्थाओं में बांटने के लिए लगभग 1.04 लाख रुपये की कीमत की 29,211 पुस्तकें तथा प्रकाशन क्रय करके भेजे थे। कनाडा ने कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन के क्षेत्र में संस्थान के कार्यक्रमों की प्रगति तथा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर,

1974 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए संस्थान के कार्यकलापों को बढ़ाने का निर्णय किया है। 1974-75 के दौरान 12 लाख रुपए का अनुदान संस्थान को दिया गया है।

1974 में संस्थान द्वारा आयोजित ग्रीष्म कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं तथा सभ्यता के प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हाई स्कूल अध्यापकों तथा अवर-स्नातक प्राध्यापकों के दूसरे दल ने भारत का भ्रमण किया।

भारत-रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

1974-75 के दौरान रूसी भाषा तथा साहित्य के शिक्षण के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में 41 रूसी भाषा शिक्षक आए हैं।

भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

1974-75 के दौरान फ्रेंच भाषा तथा साहित्य के शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में पांच फ्रेंच शिक्षक आए।

भारत-जर्मन संघीय गणतंत्र सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

जर्मन भाषा तथा साहित्य के शिक्षण के लिए चौदह जर्मन भाषा शिक्षक विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्य करेंगे।

भारत-बंगला देश का सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित सेमिनार/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बंगला देश से पांच प्रतिनिधि भारत आए। इन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा टाटा समाज शास्त्र संस्थान, बम्बई ने आमन्त्रित किया था। इसके अतिरिक्त, बंगला देश द्वारा आयोजित सम्मेलनों में 12 भारतीय विद्वान शामिल हुए थे। ढाका विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, प्रोफेसर, एस० एन० बोस को समर्पित भौतिकी संगोष्ठी में बारह भारतीय विद्वानों ने भाग लिया।

ग्रामीण संस्थान

वर्ष 1974-75 के दौरान, ग्रामीण संस्थानों को 14 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा 1974 में आयोजित विभिन्न डिप्लोमा/प्रमाण-पत्रों पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक परीक्षा देने वालों की संख्या 983 थी। उनमें से 711 उत्तीर्ण घोषित किए गए थे।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

1965 में स्थापित इस संस्थान द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों एवं अन्य ऐसे संगठनों के शिक्षकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं को, उच्च शिक्षा से संबंधित विविध विषयों पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जहां कि ऐसी सुविधाएं सुलभ नहीं हैं।

पिछले वर्ष के शैक्षिक सत्र के दौरान 41 अतिथि-अधिछात्रों (फैलो) और दो अधिछात्रों ने अपना अनुसंधान-कार्य जारी रखा। 10 विद्वानों ने इस संस्थान में अतिथि अधिछात्रों के रूप में लाभ उठाया। इस अवधि में इस संस्थान द्वारा दो अतिथि प्राध्यापकों को भी आमंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त 5 अतिथि अधिछात्र एवं अनुसंधानकर्त्ताओं ने 'प्राचीन भारत एवं एशियाई सभ्यता का स्त्रोत ग्रंथ' इस योजना पर काम किया और एक अन्य अतिथि अधिछात्र ने 'भारत -200/ईसवीं' शीर्षक अनुसंधान परियोजना पर अपना काम जारी रखा।

अगले शैक्षिक सत्र के दौरान दो और अधिछात्र और नौ अतिरिक्त अतिथि अधिछात्र इस संस्थान में प्रवेश करेंगे।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्

1969 में इस परिषद् की स्थापना इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम, रिपोर्ट के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान, होते चले जा रहे हैं, यद्यपि वर्ष के दौरान योजना विनिधान में की गई 36 प्रतिशत कटौती के कारण उनकी मात्रा को कुछ घटा देना पड़ा था।

जनवरी 1973 में इस परिषद् ने डा० मालकोम एस० आदिशेहोया की अध्यक्षता में पहली बार एक समीक्षा समिति नियुक्त की थी। इस समिति को निम्नलिखित कार्यभार सौंपा गया :–भारत में समाज विज्ञान अनुसंधान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा तथा इसका भविष्य; समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा चार वर्षों में किये गये कार्य का मूल्यांकन तथा इस परिषद् के काम में पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान किए जाने वाले सुधार। इस समीक्षा समिति की रिपोर्ट नवम्बर, 1973 में मिली। इस समिति की बहुत-सी सिफारिशें, परिषद् की विभिन्न

शाखाओं में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद स्वीकार कर ली गई हैं। सिफारिशों में ये हैं :– (i) इस परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की नियुक्ति का ढंग, (ii) परिषद् का गठन, (iii) परिषद् के अन्तर्गत आने वाले काम के प्रकार, (iv) परिषद् के केन्द्रों की स्थापना, (v) अनुसंधान छात्रवृत्तियों की संख्या को दुगना करना, (vi) विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक अनुसंधान विधि-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का शुरू किया जाना, (vii) परिषद् द्वारा अन्तर-विषय अनुसन्धान विधि-पाठ्यक्रमों को आयोजन, (viii) परिषद् के ढांचे का विकेन्द्रीकरण, कुशल कार्य-पद्धति के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों को स्थापित करना; (ix) युवक समाज वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन, (x) सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ उनके व्यावसायिक प्राकृतिक काम में वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों के सामान व्यवहार तथा इन सभी से महत्वपूर्ण है, (xi) परिषद् को अपनी प्रोत्साहन संबंधी भूमिका को अधिक महत्व देने की आवश्यकता, अर्थात अपनी प्रतिक्रियात्मक भूमिका, जिससे सामाजिक महत्व विशेषरूप से पांचवीं योजना के उद्देश्यों से संबंधित विषयों की आन्तरिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। इस समिति ने 12 अन्तर-विषय अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है जिसमें परिषद् ने चार और विषय जोड़ दिए हैं और इस तरह कुल मिलाकर ऐसे 16 प्राथमिकता के विषय बने हैं : (1) निर्धनता एवं बेरोजगारी, (2) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों, (3) विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, (4) मुसलमान, (5) सरकारी पद्धतियां एवं विकास, (6) शिक्षा, (7) क्षेत्रीय और अन्तर-क्षेत्रीय योजनाएं, (8) अशांति एवं हिंसा, (9) शहरीकरण सम्बन्धी अध्ययन, (10) एशियाई क्षेत्रीय अध्ययन, (11) निवेश में दक्षता, (12) राजनीतिक पद्धतियां एवं प्रक्रिया, (13) सामाजिक विकास, (14) सूखा पड़ना, (15) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामाजिक पहलू, (16) जन-सांख्यिकीय एवं जनसंख्या अध्ययन, भारतीय जनगणना सम्बन्धी अध्ययन। अन्तिम सिफारिश के महत्व को ध्यान में रखते हुए परिषद् ने यह फैसला किया है कि इसके अधिकतर साधनों का उपयोग प्राथमिकता के कामों के अनुसन्धान संबंधी खर्च के लिए किया जाए (इसके प्रोत्साहनात्मक तथा उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिकाओं दोनों के संबंध में)। परिषद् ने यह भी फैसला किया है कि सभी विभिन्न अनुसन्धान के साधनों (जैसे, अनुसंधान के कार्यक्रम, अनुसंधान की परियोजनाएं, अध्यापकों को पुरस्कार, फैलोशिप तथा प्रकाशन के लिए अनुदान) का उपयोग प्राथमिकता के काम में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए किया जाए।

सितम्बर, 1974 में व्यावसायिक शिक्षा में सामाजिक विज्ञानों पर एक त्रि-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्बन्ध में स्थापित किए गए अध्ययन दल की रिपोर्ट को इस वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया जाने वाला है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में शिक्षा के अध्ययन (जिसमें 26 भिन्न-भिन्न अध्ययन सम्मिलित हैं) के मुख्य कार्य को भी इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। परिषद् ने कम मूल्य-भवन निर्माण टेक्नोलॉजी पर एक सेमीनार का त्रिवेन्द्रम में आयोजन किया था और उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान शिक्षण संबंधी विकास पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन किया था। परिषद् ने दो अनुसंधान विधि-तन्त्र पर बुनियादी पाठ्यक्रमों एवं दो विशेष विषय संबंधी पाठयक्रमों का भी आयोजन किया था। परिषद् की समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा वैज्ञानिक-औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से संयुक्त समितियां भी बनाई गई हैं।

रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान दो राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां, पांच वरिष्ठ छात्रवृत्तियां, चार उत्तर-डाक्टर छात्रवृत्तियां और 53 डाक्टरल छात्रवृत्तियां (अनुसंधान संस्थानों को दी गई आठ छात्रवृत्तियों समेत) दी गई हैं।

पी० एच० डी० शोध प्रबंध अथवा अनुसंधान रिपोर्टों के प्रकाशन लिए एक लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया है।

परिषद् ने 44 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसमें 9,23,344/- रुपये का व्यय होगा। पुस्तकालय एवं बम्बई और हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों का भवन निर्माण कार्य समाप्त ही होने वाला है। विशेष वैज्ञानिकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए परिषद् ने पांच विदेशी सामाजिक वैज्ञानिकों को भारत आने के लिए निमंत्रित किया है और 15 भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों को विदेशों में होने वाले सम्मेलनों/सभाओं में भाग लेने के लिए अथवा पहले से ही विदेश गए वैज्ञानिकों की वहां रहने की अवधि को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी ताकि उनके व्यावसायिक हित में वृद्धि हो।

'वर्ष के आरम्भ में परिषद् के सामग्री लेखागार ने सामाजिक विज्ञान संबंधी सामग्री का विश्लेषण करने के लिए एस० पी० एस० एस० कम्प्यूटर प्रोग्राम पैकेज

को प्रयोग में लाने के लिए एक दो-साप्ताहिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भारत के विभिन्न भागों के 30 अनुसंधान-कर्त्ताओं और विश्वविद्यालय एवं कालेज के अध्यापकों ने भाग लिया। सामग्री लेखागार ने युवा सामाजिक वैज्ञानिकों की सामग्री, कार्यविधि एवं इसके विश्लेषण-कार्य में सहायता करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित पांच चुनी हुई अनुसंधान संस्थाओं में मार्गदर्शी एवं परामर्शदायी सेवा का भी कार्य आरम्भ किया है।

अपनी सामान्य पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशनों के अतिरिक्त, परिषद् ने कई समूल्य तथा मुफ्त पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। इस संबंध में समाज विज्ञान, एवं सामाजिक मानव विज्ञान अनुसंधान सर्वेक्षण, खण्ड -I तथा खण्ड-II का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। लोक प्रशासन, जन-सांख्यिकी, प्रबन्ध अर्थनिति (इक्नामेटिक्स), औद्योगिक अर्थशास्त्र तथा कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान सर्वेक्षण संबंधी सामग्री प्रैस में है और वर्ष के समाप्त होने से पहले उनका प्रकाशन कार्य पूरा हो जाएगा।

परिषद् के सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र ने आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदश, केरल, पश्चिम बगाल, दिल्ली की समाज विज्ञान पत्रिकाओं का संघीय सूचीपत्र, समाज विज्ञान पर भारत की पत्रिकाओं की सूची एवं मोहन दास कर्मचन्द गांधी : एक ग्रंथसूची (अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में), इस साल के दौरान, प्रकाशित की है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पत्रिका एकक द्वारा लगभग प्रत्येक भारतीय सामाजिक विज्ञान की पत्रिका मंगाई जाती है। यह एकक समाज विज्ञान की लगभग एक हजार विदेशी पत्रिकाएं मंगाता है। यह एकक के संकाय के सदस्यों एवं विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों को सेवाएं प्रदान करता है। प्रलेखन केन्द्र ने एक अमानती पुस्तकालय (डिपोजिटरी लायब्रेरी) स्थापित किया है जिसमें दिल्ली स्थित कई पुस्तकालयों ने पत्रिकाओं तथा समाचारों की फाइलें तथा सरकारी प्रलेख रखे हैं। इन प्रलेखनों में समितियां, आयोगों की रिपोर्ट तथा विधान सभाओं में की गई बहस सम्मिलित है। इस अमानती पुस्तकालय में इस समय 25,000 ग्रंथों का संकलन हो चुका है। यह केन्द्र, पी० एच० डी० पंजीकृत 52 छात्रों को अध्ययन अनुदान प्रदान करता है जिससे कि वे छात्र अपने अनुसंधान कार्य के लिए दिल्ली के पुस्तकालयों में जा सकें। इस प्रलेखन केन्द्र ने ग्रंथ विज्ञान एवं प्रलेखन सम्बन्धी कामों के लिए सहायक अनुदान देने का कार्यक्रम जारी रखा। केन्द्र ने, भारत

सरकार के प्रकाशनों के नियंत्रक के सहयोग से भारत सरकार के महत्वपूर्ण समाज विज्ञान के प्रकाशनों को देश के विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं को बेचने के लिए विक्रय सेवा भी स्थापित कर रहा है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

इस परिषद् ने 10 अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया है और इस कार्य के लिए 45,272/- रुपये भी दे दिये हैं। परिषद् ने अनुसंधानकर्त्ताओं को 13 शिक्षावृत्तियां भी दी हैं जिनकी राशि 1,00,773/- रुपये है।

18 शोधपत्रों/प्रबंधों/अलोचनात्मक सम्पादित/अनुवादित-स्त्रोत-सामग्रियों को प्रकाशन-सहायतार्थ-अनुमोदित कर दिया गया है। इनकी पाण्डुलिपियां इस समय प्रकाशन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इनके प्रकाशन के सहायतार्थ 2,500 रुपये की राशि दे दी गई है। इस परिषद् ने पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए एवं इतिहासकारों के व्यावसायिक संगठनों के लिए 30,200/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस परिषद् ने 25 सालों के इतिहास की 27 समीक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षणों का कार्य भी आरम्भ किया था। इस कार्य की पहले ही 6 रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं जिनका प्रकाशन हो रहा है।

भारतीय इतिहास की स्त्रोत सामग्री

परिषद् ने प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की स्त्रोत पुस्तकों का संकलन प्रारम्भ कर दिया है। यह कार्य संकलन को विभिन्न अवस्थाओं में है। इनमें प्राचीन भारतीय इतिहास के पांच खण्ड मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सात खन्ड, जिसमें अकबर के राज्य-पूर्व के स्रोतों का हिन्दी अनुवाद भी सम्मिलित है और आधुनिक भारतीय इतिहास के सात खण्ड शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त परिषद् ने दुर्लभ और अप्राप्त पुस्तकों को प्रकाशित करने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। इस शृंखला को 26 पुस्तकें इतिसाहकारों को दे दी गई हैं।

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकों का अनुवाद

परिषद् के अनुवाद कार्य के अन्तर्गत 600 से अधिक अनुवादकों को कार्य सौंप दिया गया है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 12 स्थानीय एकक स्थापित कर दिये गए हैं। परिषद् ने 28 पाण्डुलिपियों को प्राप्त कर लिया है जो प्रकाशन के लिए तैयार हैं।

अन्य परियोजनाएं एवं प्रकाशन

भारतीय संस्कृति पर आधार-ग्रंथ तैयार करने के कार्य की शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की आशा है। यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित की जाएगी और इसके प्रत्येक भाग में 600 पृष्ठ होंगे।

'स्वतंत्रता की दिशा में' नामक परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और ग्रंथ-सूची का कार्य पूर्ण हो चुका है। परिषद् ने 'मध्येशिया की सभ्यता का अध्ययन' नामक परियोजना का कार्य भी प्रारम्भ किया है।

यह परिषद् 'स्वतंत्रता संग्राम में विधान सभाओं की भूमिका' के 11 खण्ड प्रकाशित करेगा। दिसम्बर, 1974 के अन्त तक 3 खण्ड प्रकाशनार्थ तैयार हो जाएंगे।

भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा–एक द्विवार्षिकी पत्रिका

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् की द्विवार्षिक पत्रिका दॉ इण्डियन हिस्टारिकल रिव्यू०' का प्रथम संस्करण मार्च, 1974 में प्रकाशित हुआ था। 'व्यापार एवं वाणिज्य' से सम्बन्धित पत्रिका के दूसरे संस्करण के शीघ्र ही प्रकाशित होने की सम्भावना है।

आई० सी० एच० आर० न्यूज़लेटर के खण्ड-2 और 3 भी प्रकाशित हो चुके हैं।

परिषद् ने 'भारतीय समाज: ऐतिहासक परीक्षण' नामक डी० डी० कोसाम्बी अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित किया है।

तीसरा अध्याय

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :–

(1) स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान का विकास,

(2) तकनीकी संस्थाओं और उद्योग के बीच सम्पर्क स्थापित करना,

(3) तकनीकी शिक्षा को जन-सम्पर्क की आवश्यकताओं के साथ जोड़ना,

(4) विद्यमान इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों को सुदृढ़ बनाना,

(5) डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन,

(6) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए संकाय विकास,

(7) पाठ्यचर्या विकास,

(8) पाठ्यक्रमों का विविधीकरण, और

(9) प्रबन्ध शिक्षा का विकास ।

ये सभी कार्यक्रम इंजीनियरी शिक्षा कमप्लेक्स के माध्यम से चलाए जाते हैं, जिसम प्रौद्योगिकी संस्थान, इंजीनियरी तथा टेक्नोलोजी के विश्वविद्यालय विभाग, प्रबन्ध संस्थान, खनन तथा वास्तुकला में विशिष्ट संस्थान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य इंजीनियरी कालेज और पालिटेक्निक शामिल हैं ।

देश में इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों में कुल दाखिलों की संख्या में सुधार हुआ है । वर्ष 1972-73 में इंजीनियरी कालेजों में 19,997 और पालिटेक्निकों में 36,675 की वास्तविक संख्या की अपेक्षा वर्ष 1973-74 में इंजीनियरी कालेजों में 21,199 और पालिटेक्निकों में 31,333 विद्यार्थी वस्तुत: दाखिल हुए । वर्ष 1973-74 में पास होने वाले स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की संख्या क्रमश: 16,342 और 13,848 थी । अखिल-भारतीय

तकनीकी शिक्षा परिषद् ने, जो देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास और सुधार के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देती है, सिफारिश की थी कि वर्ष 1966-67 में तकनीकी संस्थाओं ने जितने छात्र दाखिल किए थे, उन्हें , इंजीनियरों के लिए रोजगार की सम्भावनाओं पर विचार करते हुए और प्रत्येक संस्था में पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के बाद, फिर से धीरे-धीरे उतने ही विद्यार्थी दाखिल करने दिए जाएं। पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने और छठी योजना के आकार और क्षेत्र के बारे में कुछ संकेत मिल जाने पर, अखिल-भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, जन-शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं का एक दीर्घकालिक आधार पर सार्थक और व्यापक मूल्यांकन किया जाना है । इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इसी बीच और अगले एक अथवा दो वर्ष के लिए तकनीकी संस्थाओं में वास्तविक दाखिलों को, विद्यमान स्वीकृत दाखिले की कुल क्षमताओं के अन्तर्गत और प्रत्येक संस्था में उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं के अनुसार, नियमित किया जाय । दाखिलों के स्तर को पर्याप्त शिथिलनीय रखा जाय ताकि सभी पात्र छात्रों को विद्यमान स्वीकृत दाखिले की क्षमताओं के अन्तर्गत दाखिल किया जा सके ।

साधनों की तंगी के कारण विभिन्न विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में खर्च को सीमित करने के लिए 1974-75 के दौरान उठाए कदमों के बावजूद वार्षिक योजना का सम्भावित खर्च 10.16 करोड़ रुपये होगा, जबकि तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए 9.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

तकनीकी शिक्षा की कोटि और स्तर को सुधारने के उद्देश्य से डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन और उनके लिए उपलब्ध विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ़ करना, वर्ष 1974-75 की गतिविधियों का प्रमुख कार्य रहा । अध्यापकों को उच्च योग्यताओं के लिए सुविधाएं अथवा ग्रीष्म संस्थानों में अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करके अथवा उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करके संस्थाओं में शिक्षण की कोटि सुधारने के वास्ते कोटि सुधार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार करना और उन्हें शिक्षण की आधुनिक पद्धतियों से अवगत कराना था । इनके मूल्यांकन से और अधिक पी० एच० डी० डिग्री कार्यक्रमों और उद्योगों से अधिक अवधि तक सम्बद्ध रहने की आवश्यकता अनुभव की गई है । पांचवीं तथा उसके बाद की योजनाओं में भी अध्यापकों के सुधार पर ध्यान दिया जाता रहेगा ।

वर्ष 1974-75 के दौरान भी तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं को सभी स्तरों पर एक नया आयाम देने के वास्ते प्रयत्न जारी रहे ताकि उद्योगों के लिए कोटि और प्रशिक्षण की दृष्टि से तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्यक्रमों में उद्योगों के परामर्श से सुधार जारी रहा जिससे कि अनुसन्धान, विकास और डिजाइन के लिए उच्च विशिष्ठता वाले तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके ।

बहुत-सी संस्थाओं ने उद्योगों से संबंधित समस्या समाधान क्षमता और अनुसन्धान करने हेतु विशिष्टिता का विकास किया है । तकनीकी संस्थाओं म पहले से ही विद्यमान, व्यापक सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु, उद्योग के तीव्र विकास को सुविधासय बनाने हेतु तथा उद्योग के सहयोग का लाभ उठाने की दृष्टि से, ताकि संस्थाओं में अच्छा प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, तकनीकी संस्थाओं, उद्योग और अनुसंधान संस्थाओं के बीच निकट संपर्क स्थापित करने के प्रयत्न किए गए । इस प्रयोजन हेतु कुछ संस्थाओं में औद्योगिक संपर्क कें स्थापित किए गए थे ।

स्नातकोत्तर, इंजीनियरी, अध्ययन और अनुसन्धान बोर्ड ने जो पांचवीं योजना के दौरान, स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रमों के विकास के लिए रूप-रेखा तैयार करने हेतु नियुक्त कार्यदल, द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, देश में स्नातकोत्तर इंजीनियरी, शिक्षा और अनुसन्धान के समन्वित विकास के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करता है, सिफारिश की है कि पहले से ही अनुमोदित-पाठ्यक्रमों के समुचित विकास और समेकन पर, उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सर्वप्रथम महत्व दिया जाए । पाठ्यक्रमों के विविधीकरण को भी रोका जाना चाहिए । उन विषयों में जिनकी स्थायी मांग हो अथवा उन विषयों में जिनकी भविष्य में आवश्यकता होगी, सम्बधित संस्थाओं और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों की क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद, अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्वीकृत किए जा सकते हैं ।

कोटि सुधार कार्यक्रम

कोटि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटि और पाठ्यचर्या विकास की विभिन्न योजनाएं वर्ष 1974-75 में जारी रहीं ।

संकाय विकास

वर्ष 1974-75 म इंजीनियरी कालेजों में 177 अध्यापक एम० टेक० तथा पी० एच० डी० डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल हुए । एम० टेक और पी० एच० डी०

5—956M of Edu & SW/74

कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापकों की कुल संख्या अब 708 है।

वर्ष 1973-74 के अन्त तक इंजीनियरी कालेजों के 1134 और पालिटैक्निकों के 2886 अध्यापकों को विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों द्वारा लाभ पहुंचा। 1974-75 में डिग्री स्तर पर 14 और डिप्लोमा स्तर पर 37 अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान आयोजन किया जा चुका है। 6 महीने की शेष अवधि के दौरान डिग्री स्तर पर 27 और डिप्लोमा स्तर पर 60 पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। ग्रीष्म स्कूल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या इस वर्ष 1200-1400 रही। सेवारत अध्यापकों के लिए उद्योगों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इंजीनियरी कालेजों और पौलिटैक्निकों के अब तक 1624 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है।

पाठ्यचर्या विकास

डिग्री स्तर पर 6 संस्थाओं में और डिप्लोमा स्तर पर पांच संस्थाओं में पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम का आयोजन जारी रहा।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई प्रगति और उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कोटि सुधार के पूरे कार्यक्रम का पुनरावलोकन किया गया है और योजना में आवश्यक संशोधन सुझाए गए हैं जिनमें पांचवीं योजना के दौरान इसका और विस्तार करना भी सम्मिलित है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान कार्य

इस योजना के अंतर्गत इंजीनियरों तथा शिल्प वैज्ञानिकों के उच्च प्रशिक्षण के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास के लिए देश में चुनींदा राज्य सरकार तथा गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेजों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता, भवनों, उपकरणों, रख-रखाव, स्टाफ तथा सभी छात्रों के लिए 250 रुपये प्रतिमास प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास के लिए अन्य खर्च के लिए होती है। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 1200 छात्रों की कुल भर्ती क्षमता के साथ इस योजना के अन्तर्गत 38 सरकारी तथा गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेजों को सहायता दी जाती है।

शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य, उद्योग में सार्थक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, तकनीकी संस्थाओं से उत्तीर्ण होने वाले डिग्री तथा डिप्लोमा-धारियों को अवसर प्रदान करना है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जो कि सामान्यत: एक वर्ष की होती है, डिग्री-धारियों को 250 रु० प्रति मास तथा डिप्लोमाधारियों को 150 रु० प्रति मास की वृत्तिका दी जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यत: हर वर्ष सितम्बर/अक्तूबर से आरम्भ होता है। उम्मीदवारों का चयन अन्तिम अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर पूर्णत: योग्यता के आधार पर किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हर वर्ष लगभग 10,000 छात्रों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। परन्तु वर्ष 1974-75 के दौरान निधियों की कमी के कारण 1973-74 के दौरान चुने गए 3100 शिक्षार्थियों के अतिरिक्त जिनका प्रशिक्षण चालू वर्ष में पूरा हो जाएगा, लगभग 5,714 नए प्रशिक्षार्थियों को वृत्तिकाएं दिए जाने की संभावना है। 1974-75 में इस योजना के लिए 121.00 लाख रु० (81.00 लाख रु० योजनागत तथा 40.00 लाख रु० योजनेत्तर) की बजट व्यवस्था की गई है।

शिक्षुता अधिनियम, 1961 को संशोधित कर दिया गया है ताकि इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों का प्रशिक्षण इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सके। शिक्षुता (संशोधन) अधिनियम, 1973 को 7 जून, 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। शिक्षुता संशोधन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय के परामर्श से श्रम मन्त्रालय द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं। संशोधित अधिनियम, भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि से लागू होगा।

विकास तथा सुधार के लिए गैर-सरकारी वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं को अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत, प्रथम डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर गैर-सरकारी इंजीनियरी तथा शिल्पवैज्ञानिक संस्थाओं को उनकी स्थापना तथा विकास के लिए, तथा लड़कियों के लिए तकनीकी संस्थाओं, जूनियर तकनीकी स्कूलों इत्यादि को सहायक अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं। इन संस्थाओं को प्रायोजित करने वाली प्राइवेट एजेंसियां स्वयं अथवा संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से निर्धारित

खर्चों का गैर-सरकारी भाग वहन करती हैं। योजना का उद्देश्य शिक्षा भवनों, वर्कशापों, उपस्कर, पुस्तकालय, फर्नीचर, स्टाफ इत्यादि के रूप में भौतिक सुविधाएं प्रदान करके, गैर-सरकारी तकनीकी संस्थाओं का विकास तथा सुधार करना है। इस योजना के अन्तर्गत, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता की पद्धति के अनुसार प्रथम योजना अवधि के दौरान इस योजना के आरम्भ होने से अब तक 100 से अधिक संस्थाएं स्थापित/विकसित की गई हैं।

वर्ष 1974-75 में इस योजना के लिए 30.00 लाख रु० (योजनागत) की बजट व्यवस्था की गई है।

तकनीकी संस्थानों में छात्रावासों के निर्माण के लिए ऋण

तकनीकी संस्थानों में छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार की तकनीकी संस्थाओं के कुल विद्यार्थियों के 50 प्रतिशत तक ऋण दिए जाते हैं। गैर-सरकारी तकनीकी संस्थानों द्वारा छात्रावास ऋणों के भुगतान में अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि पहले दिए गए ऋण के 50 प्रतिशत भाग को बट्टे खाते डाल दिया जाए और शेष 50 प्रतिशत को बाकी बची हुई किस्तों में वसूल कर लिया जाए। 90 गैर-सरकारी संस्थाएं इस प्रस्ताव से लाभ उठाने के लिए सहमत हो गयी हैं। यह भी निश्चय किया गया है कि अनुमोदित ऋणों के शेष भाग को इन तकनीकी संस्थाओं को 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाए जिसे 25 वार्षिक किश्तों में वसूल किया जाएगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पहले छात्रावासों में 61,400 स्थानों की व्यवस्था कर दी गई थी। 1974-75 के अन्त तक 875 अतिरिक्त स्थान उपलब्ध किए जायेंगे।

वर्ष 1974-75 में योजना के लिए निम्नलिखित बजट व्यवस्था की गई है :

	ऋण	अनुदान	कुल
	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०
राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए	20.00	—	20.00 (योजनागत)
गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए	7.50	7.50	15.00 (योजनागत)

भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान

खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर और दिल्ली स्थित पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में जिनकी परिकल्पना, इंजीनियरी और प्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में उच्च अध्ययन की संस्थाओं के रूप में संकल्पना की गई थी, जिनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान का स्तर विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं के समान हो, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने वाले हैं। संस्थानों से, जिनके कामकाज की समीक्षा विशेषज्ञ निकायों द्वारा की गई थी, कहा गया है कि वे अपना कार्य निम्न-लिखित अनुदेशों के अनुसार करें :—

(1) उन्हें पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को वर्तमान स्तर तक ही सीमित कर देना चाहिए। तथापि, उन्हें स्नातकोत्तर तथा अनुसन्धान स्तरों पर भर्ती में वृद्धि करने की अनुमति होगी ताकि देश के उद्योगों, विज्ञान व प्रौद्योगिक योजनाओं और प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(2) विज्ञान स्नातकों के लिए तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों और पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रमों का चयन संबंधित संस्थान में उपलब्ध संरच-नात्मक सुविधाओं पर आधारित हो।

(3) यद्यपि संस्थानों को पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को सीमित करने के साथ-साथ पूर्व-स्नातकों की कुल संख्या को भी सीमित कर देना चाहिए किन्तु प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों और विषयों में छात्रों के कुल दाखिले के सम्बन्ध में ढील होनी चाहिए।

(4) संगणन सुविधाओं की शुरुआत अथवा उनमें वृद्धि को अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ये सुविधाएं आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरी में प्रशिक्षण और अनुसन्धान के मूल उपकरण समझे जाते हैं।

(5) भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक और दीर्घकालिक आवश्यक-ताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हित के नए क्षेत्रों में नये अध्यापन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए जायें।

(6) अनुसन्धान कार्यक्रमों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के विख्यात क्षेत्रों की दिशा मे अनुस्थापित किया जाए।

(7) राष्ट्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्तर विषयक अनुसन्धान स्कूलों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए।

(8) उद्योगों के साथ सहयोग, अन्य संस्थानों के साथ परस्पर-कार्रवाई, संकाय विकास, प्रशिक्षण और नियुक्ति सम्बन्धी कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए।

(9) अवर-स्नातक स्तर पर स्टाफ-छात्र का अनुपात 1:8 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1:4 होना चाहिए। भविष्य में अध्यापन कर्मचारियों को लेक्चरर, सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर नामक केवल तीन श्रेणियां होनी चाहिए।

(10) कनिष्ठ कक्षाओं के संचालन के लिए संकाय के किसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोत्साहित करना चाहिए।

1974-75 शैक्षिक सत्र के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में से दो संस्थान, (मद्रास और दिल्ली) (क) उत्पादन इंजीनियरी और (ख) वैज्ञानिक इंजीनियरी तथा जैव-इंजीनियरी व जैव-विज्ञानों के अन्तर-विषयक स्कूल में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने में समर्थ हो पाये हैं। अन्य तीन संस्थानों का 1975-76 शैक्षिक सत्र में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है :–

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

1. औद्योगिक प्रबन्ध पद्धति इंजीनियरी में एम०टैक०।
2. समेकित सर्किटस में एम० टैक०।
3. प्रशीतन एवं वायुनकूलन में एम० टैक०।
4. चट्टान यांत्रिकी में एम० टैक०।
5. ऊर्जा प्रणालियों में एम० टैक०।
6. (1) पदार्थ अध्ययन, (2) सामान्य पद्धति अध्ययन, (3) ऊर्जा अध्ययन, (4) इजीनियरिंग डिजाइन अध्ययन, (5) लैसर अनुप्रयोग, तथा (6) वस्त्र प्रौद्योगिकी के लिए औद्योगिक सहकारी अनुसन्धान केन्द्र में अन्तर-विषयक स्कूल।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

टेलीविजन इंजीनियरी में डी० आई० आई० टी० पाठ्यक्रम, एक वर्षीय उत्तर-बी० ई० पाठ्यक्रम, जिसे टेलीविजन प्रणाली साधनों का उद्योग,

चिकित्सा संस्थाओं तथा शिक्षा प्रौद्योगिकी में उपयोग करने पर विशेष बल सहित टेलीविजन इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा विकास कार्य के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई

उन्नत हवाई चित्र प्रतिपादन-सिविल इंजीनियरी; (2) विमान इंजन डिजाइन-वैमानिक इंजीनियरी में उत्तर स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

अन्तर पाठ्यचर्या दृष्टिकोण उत्तर-स्नातक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण बात-होगी । अनुसंधान कार्यक्रमों म, बुनियादी तथा प्रयुक्त अनुसन्धान तथा जीव इंजीनियरी, जीव-विज्ञान, जीव-चिकित्सा इंजीनियरी, चित्रण तथा पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन और निमन्त्रण आदि कार्यक्रम शामिल हैं । विशेषज्ञ इंजीनियरों तथा शिल्प-वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के अलावा संस्थान ऐसे क्षेत्रों में अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कार्यकलापों में व्यस्त हैं जो कि देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । कुछ संस्थानों ने उद्योगोंन्मुख कार्यक्रम आरम्भ किए हैं । इसके अतिरिक्त, प्रायोजित अनुसन्धान परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है । उदाहरणार्थ, विद्युत-इंजीनियरी विभाग की प्रयोगशालाओं का स्विच गियर दल देश में अनेक स्विच तथा फ्यूजगियर के उत्पादकों की स्विचों, सम्पर्क तथा सर्किट विच्छेदकों के देशी नमूने, परीक्षण विश्लेषण और विकास में सहायता कर रहा है ।

अनुसन्धान और विकास के लिए वर्तमान अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली तथा कानपुर स्थित संस्थानों में पहले से ही संगणक सुविधाएं उपलब्ध हैं । भा० प्रो० संस्थान, मद्रास ने पश्चिम जर्मन संघीय गणतन्त्र से एक आधुनिक संगणक प्राप्त कर लिया है । भा० प्रो० संस्थान, बम्बई ने सोवियत संगणक प्राप्त कर लिया है तथा भा० प्रो० संस्थान, खड़गपुर को अभी हाल ही में एक सोवियत संगणक की पेशकश की गई है । संगणक सुविधाएं न केवल स्टाफ और छात्रों के लिए उपलब्ध होगी, अपितु ये सुविधाएंस भी बाहरी संगठनों-शैक्षिक अनुसन्धान तथा उद्योग के लिए भी उपलब्ध होंगी ।

भा० प्रो० संस्थान, मद्रास की सहायता के लिए वर्तमान भारत जर्मन करार 30 नवम्बर, 1974 को समाप्त हो गया है । मुख्य रूप से वैज्ञानिकों, संयुक्त अनुसन्धान, उपस्कर, टी० वी० इंजीनियरी में प्रशिक्षण, में वैज्ञानिकों के विनिमय के लिए सहायता में और वृद्धि करने के लिए सहमति हो गयी है । भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में जीवन रसायन इंजीनियरी में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना के लिए स्विटजरलैण्ड और भारत सरकारों के बीच सहमति हो गई है।

पांचों संस्थानों में कुल छात्रों का दाखिला और उत्तीर्ण हुए स्नातकों की संख्या नीचे दी गई है :–

	वर्ष 1974-75 में दाखिला			
	अवर स्नातक	स्नातकोत्तर तथा अनुसन्धान	कुल	उत्तीर्ण हुए स्नातकों की संख्या
खड़गपुर .	1733	572	2305	590
बम्बई .	1328	764	2092	408
मद्रास .	1278	1034	2312	512
कानपुर .	1202	740	1942	301
दिल्ली .	1198	819	2017	291
	6739	3929	10668	2102

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के दाखिले के लिए स्थानों के आरक्षण हेतु एक नीति अपनायी गई थी, और उक्त जातियों के 230 विद्यार्थियों को वर्ष 1974-75 में प्रथम-वर्ष में दाखिला दिया गया था।

दो नए निदेशकों अर्थात् भा० प्रौ० संस्थान, बम्बई में डा० ए० के० डेने तथा खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रोफेसर सी० एस० झा ने कार्यभार संभाल लिया है तथा भा० संस्थान कानपुर में डा० जगदीश लाल ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के अभिशासी मण्डल के नए अध्यक्ष के रूप में 4 जनवरी 1975 से डा० एम० एल० धर को नियुक्त किया गया है।

भारतीय प्रबंध संस्थान

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता ने अपने दो क्षेत्रों, अर्थात् प्रथम, प्रबन्धकों के क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक उद्यमों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने तथा दूसरे, प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में मुख्यत: प्रबन्ध में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम; अल्पकालिक कार्यकारी विकास कार्यक्रमों, अनुसन्धान तथा परामर्श परियोजनाओं के माध्यम से सहायता देने में लगातार प्रगति की । अधिछात्रवृत्ति कार्यक्रम में छात्रों द्वारा संतोषजनक प्रगति की जा रही है ।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ने विश्वविद्यालयीय अध्यापकों तथा अनुसन्धानकर्ताओं सहित प्रबन्ध में अपने दो-वर्षीय उत्तर-स्नातक कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों/कार्यकलापों के माध्यम से प्रबन्ध में प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध प्रणालियों में सुधार के लिए अवसर प्रदान करने का कार्य जारी रखा । शैक्षिक सत्र 1974-75 से प्रारम्भ किए गए दो-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में कृषि में विशिष्टीकरण सम्मिलित है; यह कार्यक्रम कृषि में प्रबन्ध के लिए पहले एक वर्षीय कार्यक्रम के स्थान पर शुरू किया गया ह । कृषि में विशिष्टीकरण उन छात्रों के लिए दूसरे वर्ष में संभव है जो कृषि क्षेत्र में प्रबन्ध तथा अध्यापन के व्यवसायों को चुनना चाहते हों ।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

उक्त संस्थान में शैक्षिक सत्र 1974-75 में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या 1023 है, जिसमें अनुसन्धान छात्र भी सम्मिलित हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गयी नयी परियोजनाएं बड़ी तेजी से नियमित रूप से स्वत: जीविका कार्यकलापों के रूप में संस्थापित हो रही हैं ।

यह संस्थान पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर उसे दिए गए उन निदेशों के अनुसरण में अपना विकास कर रहा है जिनमें भौतिक तथा रसायन विज्ञानों के प्रति बल पर सुनियोजित परिवर्तन एक छात्र को वेहतर-पी० एच० डी० छात्र बनाने के लिए मास्टर्स डिग्री कार्यक्रम के पश्चात एक पूर्व-पी० एच० डी० कार्यक्रम, एकक प्रणाली को लागू करना, देश की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में अनुसन्धान परियोजनाएं आरम्भ करना, पूर्णकालिक छात्रों की संख्या एक हजार तक सीमित करना, उपकरणों के रख-रखाव और आधुनिकीकरण के लिए

महत्वपूर्ण निवेश, अनुसन्धान उपकरणों की संरचना, अन्य संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना, आगन्तुक वैज्ञानिकों के कार्यक्रम को तेज करना, अन्तर-संस्थागत सहयोग में वृद्धि करना शामिल है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

विभिन्न राज्यों में स्थापित 14 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इंजीनियरी शिक्षा में समेकन तथा और आगे विकास के कार्य-क्रमों सहित संतोषजनक प्रगति कर रहे हैं। इन सभी कालेजों में सिविल, यांत्रिकी, (मेकेनिकल) और विद्युत इंजीनियरी में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के अध्यापन की व्यवस्था है। इनमें से कुछ कालेजों में धातु-विज्ञान, इलैक्ट्रानिक्स तथा रसायन इंजीनियरी में भी अध्यापन की व्यवस्था है। इनमें से दस कालेज उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करके अपने विकास के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। इनमें से नौ कालेजों, उच्च-दाव बायलर तथा उप-साधनों, इस्पात प्लांटों के लिए भारी मशीनों, परिवहन इंजीनियरिंग, औद्योगिक तथा समुदाय संरचना, इलैक्ट्रानिक्स यन्त्रीकरण समेकित विद्युत प्रणालियों आदि के डिजाइन तथा उत्पादन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगोन्मुख उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। आशा है कि असम के लिए प्रस्तावित पन्द्रहवीं कालेज पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की वर्तमान प्रगति का पुनरीक्षण करने तथा ऐसी रूपरेखाओं को सुझाने के लिये जिनके आधार पर सुदृढ किया जा सके तथा उनका और विकास किया जा सके, योजना आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गयी पुनरीक्षण समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। राज्य सरकारों तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की टिप्पणियां प्राप्त की जा रही हैं और तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा सिफारिशों पर निर्णय किया जायेगा।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

मद्रास, कलकत्ता, नेपाल तथा चंडीगढ़ स्थित तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अपने अस्तित्व के लगभग एक दशक के दौरान अपने कार्यकलापों में लगभग व्यवस्थित हो गए हैं। अतः ऐसी स्थिति आ गई है जब कि इसके स्थापना के उद्देश्यों, उनकी विशिष्ट समस्याओं की जांच करने तथा विकास और कार्य-कलापों की भावी रूपरेखा के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए इन संस्थानों की प्रगति का पुनरीक्षण करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जाए, ताकि वे उच्च कोटि के संस्थानों के रूप में अपना कार्य जारी रख सकें। इस प्रयोजन के लिए

केन्द्रीय सरकार के डा० पी० के० केलकर, भूतपूर्व निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास ने वर्तमान वर्ष के दौरान "टेलीविजनों का रख-रखाव तथा मरम्मत" नामक एक अल्पावधिक पाठ्यक्रम आरम्भ किया है। संस्थान ने पालिटेकिनक अध्यापकों के लिए" अध्यापन साधनों तथा "गणित पर पाठ्यचर्या विकास कार्यशाला" के विषय में भी अल्प पाठ्यक्रम आयोजित किए।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़ को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार तथा नीदरलैण्ड की शाही सरकार के बीच हुआ करार, अपनी 5 वर्ष की आरम्भिक अवधि में दो वर्ष की अवधि बढ़ाने के पश्चात 31 अगस्त, 1974 को समाप्त हो गया।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल ने विशेषज्ञों, अधि-छात्रवृत्ति तथा उपकरणों के रूप में यू० के० सरकार से विदेशी सहायता प्राप्त करनी आरम्भ कर दी है।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की संभावना की सक्रिय रूप से खोज की जा रही है।

भारतीय खनन स्कूल, धनबाद

स्कूल में खनन इंजीनियरी, पैट्रोलियम इंजीनियरी, प्रयुक्त भूविज्ञान तथा प्रयुक्त भू-भौतिकी में पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अपने वर्तमान कार्यक्रम जारी रखे। पिछले वर्ष आरम्भ किए गए, खनन में एक दो-वर्षीय उद्योगोन्मुख एम० टेक० कार्यक्रम के अतिरिक्त, उन यांत्रिकी/विद्युत इंजीनियरी में डिग्रीधारियों के लिए, जो पहले से ही खनन उद्योग में सेवारत हैं, खनन मशीनरी में एक 3 मास का गहन स्नातकोत्तर कार्यक्रम इस वर्ष आयोजित किया है। यह संस्थान औद्योगन्मुख अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में भी व्यापक कार्यकलापों का विकास कर रहा है। इस स्कूल का, भू-विज्ञानों तथा खनन व पैट्रोलियम इंजीनियरी के बहुत से क्षेत्रों में एक अनुसन्धान कार्यक्रम है तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित सहित इस स्कूल में विभिन्न विषयों में उत्तर-डाक्ट्रेट सहित एम० एस० सी०/एम० टैक० तथा पी० एच० डी० डिग्री के लिए अनुसन्धान

कार्य कर रहे अनुसन्धान छात्रों तथा अधिछात्रों की संख्या लगभग 30 है। अनुसन्धान वृत्तिछात्रों/अध्येताओं सहित छात्रों की कुल संख्या 369 है।

प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

आलोच्य अवधि के दौरान, प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ने प्रशासनिक कार्मिकों को प्रशिक्षण देना तथा उन्हें दिन-प्रतिदिन की प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करने के उपायों के बारे में जानकारी देना जारी रखा।

आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल

यह स्कूल, पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए नगरीय तथा ग्रामीण आयोजन, और वास्तुकला में विभिन्न कार्यक्रम संचालित करता है। यह स्कूल नागरीय तथा ग्रामीण आयोजन, आवास तथा सामुदायिक आयोजन, यातायात तथा परिवहन आयोजन में अनुसन्धान कार्यकलाप संचालित करता है तथा प्राकृतिक-दृश्य वास्तुकला में अध्ययन आयोजित करता है।

विभिन्न प्रथम डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या प्रत्येक वर्ष धीरे-धीरे बढ़ रही है।

अन्य विशिष्ट संस्थान

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा के जिन उच्च-स्तरीय विशिष्ट संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है वे इस प्रकार हैं:–

विशिष्ट संस्थान

(1) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान

यह संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी तथा सम्बद्ध विषयों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह, औद्योगिक इंजीनियरी में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा औद्योगिक प्रशासकों के लिए विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करता ह। 1974-75 के दौरान छात्रों के दूसरे दल ने दो-वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। अगले शैक्षिक-सत्र से वार्षिक प्रवेश 20 से बढ़कर 25 हो जाने की सम्भावना है।

अनुसन्धान/डाक्ट्रेट कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई शिल्प विज्ञान संस्थान

संस्थान ढलाई तथा गढ़ाई तकनीशियनों, अनुदेशकों, इंजीनियरों तथा इंजीनियरी विशेषज्ञों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा ढलाई और गढ़ाई उद्योगों से सम्बन्धित अनुसन्धान तथा विकास कार्यकलापों को प्रोत्साहित करता है। यह, स्नातकों तथा डिप्लोमाधारी इंजीनियरों के लिए विभिन्न अल्पावधिक पाठ्यक्रम संचालित करता है तथा कच्चे माल और निर्मित उत्पादों के लिए परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान करता है।

संस्थान ने 18 महीनों की अवधि का पहला उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और ऐसे दूसरे तथा तीसरे पाठ्यक्रमों के मध्य में है। विभिन्न उद्योगों के लाभ के लिए अनुरोध किए जाने पर यह बहुत से अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रमों का भी आयोजन कर रहा है।

चौथा अध्याय

छात्रवृत्तियां

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा, छात्रवृत्तियों के अनेक कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं जो मुख्यत: निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :—

(क) भारत में भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां।

(ख) विदेशों में अध्ययन के लिये भारतीय छात्रों की छात्रवृत्तियां।

(ग) भारत में अध्ययन के लिये विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां।

उपरोक्त तीनों श्रेणियों में प्रत्येक की छात्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

(क) भारत में भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

(i) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य अध्ययन को जारी रखने के लिये गरीब किन्तु योग्य छात्रों की सहायता करना है। 1961 में आरम्भ की गई यह योजना 1974-75 में केन्द्रीय योजना के रूप में जारी रखी गई। छठे वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में शिक्षा योजनाओं में राज्यों की वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखा था और उनको उसी मात्रा में धन-राशि दी जो 1973-74 के अंत में थी। यह राशि राज्य सरकारों के वचनबद्ध व्यय का भाग थी। छठे वित्त आयोग की इस सिफारिश के फलस्वरूप भारत सरकार ने वर्ष 1974-75 की योजना में कोई अलग योजनेत्तर व्यवस्था नहीं की। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1973-74 की मात्रा में खर्च को पूरा करने के लिए केवल योजना के अंतर्गत ही धन-राशि की व्यवस्था की गई। इसमें दी जाने वाली अतिरिक्त छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में तीन हजार नई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। 1974-75 के आधार पर योजना को 1975-76 में जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ii) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी कराना है। वर्ष 1974-75 में इस योजना के अन्तर्गत 20,000 नई छात्रवृत्तियां दी गई। वर्ष 1975-76 में इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है।

(iii) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के बच्चों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

यह योजना 1961 में आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षकों द्वारा की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए उनके योग्य बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद देना है। इन छात्रवृत्तियों पर वर्ष 1973-74 तक जितना खर्च हुआ था उसके बराबर खर्च को राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन से उनको छठे वित्त आयोग द्वारा दी गई धन-राशि से पूरा किया।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की योजना

इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक अवसरों में अधिक समानता लाना तथा ग्रामीण प्रतिभा के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के अन्तर्गत (प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड को दो-दो छात्रवृत्तियों के हिसाब से) लगभग 10,000 नई छात्रवृत्तियां प्रत्येक वर्ष प्रदान की गई।

(v) हिन्दी में मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना है। वर्ष 1974-75 में इस योजना के अन्तर्गत एक हजार आठ सौ पचास नई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

(vi) स्वीकृत आवासी माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली बच्चों की सहायता करना है जिनके अभिभावकों की आय कम है तथा जिन्हें अच्छे पब्लिक आवासी स्कूलों में अध्ययन करने के अवसर नहीं मिलते। इस योजना के अन्तर्गत 1974-75 के दौरान 500 छात्रवृत्तियां दी गई थीं तथा 1975-76 में इतनी ही

छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है । कुल छात्रवृत्तियों में से क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं । मंत्रालय ने इस योजना के लिए देश भर में 64 पब्लिक/आवासीय स्कूल मंजूर किए हैं जिनमें चुने गए छात्र पढ़ रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस समय छात्रों की संख्या लगभग 1,450 है।

(ख) विदेशों में अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां

(i) आंशिक वित्तीय सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से विशिष्ट छात्रों को, जिन्होंने भारत में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध न होने वाले विषयों में अध्ययन के लिए विदेशी विद्यालयों, संगठनों आदि में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो, मार्ग व्यय के लिए ऋण देने की व्यवस्था है । अमेरीका, इंगलैण्ड और पश्चिमी जर्मनी में हमारे मिशनों द्वारा वास्तविक भारतीय छात्रों को आपतकालीन ऋण भी दिया जाता है। 1974-75 में 13 छात्रों को ऐसे ऋण मंजूर किए गये हैं।

(ii) देशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

यह योजना 1971-72 में आरम्भ की गई थी। इसके अन्तर्गत उन योग्य छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था है, जो भारत के नागरिक हैं तथा जिनके पास उच्च अध्ययन के लिये विदेशों में जाने के लिये साधन नहीं हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं । ये छात्रवृत्तियां स्नातकोत्तर अध्ययन, पी० एच० डी० तथा अनु-संधान प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध हैं। कुछ छात्रवृत्तियां स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला पाने वालों के लिये भी उपलब्ध हैं ।

ये छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं छात्रों को प्रदान की जाती हैं जिनके अभिभावकों/संरक्षकों की सभी साधनों से मासिक आय 1,000 रुपये से कम हो।

इस योजना के अन्तर्गत 1974-75 के दौरान चुनाव समिति द्वारा 41 छात्रों को चुना गया। इस योजना के अन्तर्गत इस समय 135 छात्र विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र

को यू० एस० ए० में 3,000 डालर तथा इंगलैण्ड और अन्य देशों में 900 पौ० प्रति मास अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार भी शिक्षा शुल्क तथा अन्य सभी अनिवार्य खर्चे, पुस्तकों और उपस्करों की लागत आदि छात्र के लिये देती है।

(iii) **राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां**

(क) आस्ट्रेलिया

राष्ट्रमण्डल छात्रवृति तथा फैलोशिप योजना, 1975 के अन्तर्गत 5 छात्र मनोनीत किये गए हैं।

(ख) कनाडा

राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजना (कनाडा), 1974 के अंतर्गत 11 छात्रवृत्ति पत्र भेज दिये गये हैं तथा वर्ष 1975 के लिये 20 नाम मांगे गये हैं।

(ग) हांगकांग

राष्ट्रमण्डलीय देशों को दी गई 4 छात्रवृत्तियों में से 3 नाम मांगे गए हैं।

(घ) जामैका

राष्ट्रमण्डलीय देशों को दी गई एक छात्रवृत्ति के लिये 2 नाम मांगे गये हैं।

(ङ) न्यूजीलैण्ड

वर्ष 1975 के लिये 4 छात्र मनोनीत किये गए हैं।

(च) नाइजीरिया

राष्ट्रमण्डलीय देशों को दी गई 25 छात्रवृत्तियों के लिये 3 नाम मांगे गए हैं।

(छ) श्रीलंका

तीन छात्र मनोनीत किये गए हैं।

6—956 M of Edu & S W/74

(ज) यूनाइटेड किंगडम

राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजना 1974 के अन्तर्गत 48 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा वर्ष 1975 में 67 नाम मांगे गए हैं।

वर्ष 1973-74 के दौरान 1973-74 की राष्ट्र मण्डल शिक्षा फैलोशिप के लिये एक छात्र यू० के० चला गया। वर्ष 1974-75 की 30 फैलोशिप के लिये 35 छात्र मनोनीत किये गये हैं। वर्ष 1975-76 की 30 फैलोशिप के लिये 35 छात्र मनोनीत किये गये हैं। राष्ट्रमण्डल अंशकालिक शिक्षा फैलोशिप योजना के अन्तर्गत 1972-73 में एक छात्र मनोनीत किया गया। यह छात्र जनवरी, 1975 में यू० के० जाएगा। 1973-74 में 10 फैलोशिप के लिए 15 नाम भेजे गये। इनमें अभी तक 8 नाम स्वीकृत किये गये हैं और इनमें से 7 विदेश चले गये हैं। 10 दीर्घकालिक फैलोशिप को 20 अंशकालिक फैलोशिप में बदल दिया गया है। इन 20 फैलोशिप में से 10 फैलोशिप सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को दे दी गई हैं। उनके नामों में से केवल एक स्वीकृत किया गया है और यू० के० चला गया है। 10 फैलोशिप के लिए 12 छात्र मनोनीत किये गये हैं। इनमें से तीन यू० के० चले गये हैं तथा जनवरी 1975 में चार और चले जायेंगे।

(iv) विदेशी सरकारों, संगठनों अथवा संस्थाओं द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां

(1) मिश्र-अरब गणराज्य

मिश्र-अरब गणराज्य से वर्ष 1974-75 के लिये 10 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके बारे में कार्यवाही की जा रही है।

(2) आस्ट्रेलिया

वर्ष 1974-75 में विभिन्न विषयों जैसे होटल, प्रबन्ध, चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा तथा खनन और धातु-विज्ञान के लिये अनिश्चित संख्या में छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया गया जिनके लिये भारत सरकार द्वारा 20 छात्रों को मनोनीत किया गया। उपरोक्त सभी विषयों में आस्ट्रियन सरकार ने केवल 8 छात्रों को स्वीकृति प्रदान की है।

(3) बल्गारिया

वर्ष 1973-74 में 3 छात्रवृत्तियों के लिए एक छात्र बल्गारिया चला गया है। अन्य छात्र भी शीघ्र जाने वाले हैं।

(4) चेकोस्लोवाकिया

चेकोस्लोवाकिया सरकार से वर्ष 1974-75 के लिये 5 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है परन्तु समय की कमी के कारण किसी प्रस्ताव के बारे में आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(5) डेनमार्क

वर्ष 1973-74 के प्रस्ताव के अनुसार जनवरी, 1974 में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 3 छात्र डेनमार्क चले गये। इसके अतिरिक्त हमने वर्ष 1974-75 के लिये 18 छात्र मनोनीत किये। छ: छात्रों को छात्रवृत्ति-पत्र भेज दिये गये हैं और वे 1975 के शुरू में डेनमार्क जाने वाले हैं।

(6) फ्रांस

फ्रांस सरकार की वर्ष 1974-75 में दौरान उच्च अध्ययन के लिये 20 छात्रवृत्तियों के लिये 19 छात्रों को नामांकित किया जिनमें से आठ फ्रांस चले गये हैं। पांच और नामांकनों के बारे में स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 1974 के अन्त तक ये छात्र भी जाने वाले हैं।

'वर्ष 1974-75 में फ्रेन्च के भारतीय प्रोफेसरों की फैलोशिप के लिये भेजे जाने वाले छात्रों के बारे में फ्रेन्च सरकार की अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

फ्रान्स सरकार ने वर्ष 1975-76 में उच्च अध्ययन के लिये 22 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है।

(7) जर्मन संघीय गणतंत्र

जर्मन शिक्षा विनिमय सेवा 1975 की फैलोशिप योजना के अन्तर्गत 10 फैलोशिप का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(8) फिनलैण्ड

फिनिश सरकार को उनकी स्वीकृति के लिये वर्ष 1973-74 के दौरान (तीन आरक्षित छात्रों समेत) 9 छात्रों का नामांकन भेज दिया गया है।

(9) जर्मन जनवादी गणतंत्र

जर्मन जनवादी गणतंत्र सरकार ने वर्ष 1974-75 के दौरान प्रशिक्षकों के लिये 6 छात्रवृत्तियों के लिए 6 छात्रों को स्वीकृति दी। अब तक 5 छात्र जर्मन जनवादी गणतंत्र जा चुके हैं। वर्ष 1974-75 के दौरान उत्तर-स्नातक अध्ययन के लिये 10 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(10) ग्रीक

ग्रीक सरकार से वर्ष 1974-75 के लिये 2 छात्रों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। वे शीघ्र ही ग्रीक जा रहे हैं।

(11) हंगरी

हंगरी सरकार की छात्रवृत्तियों के अंतर्गत वर्ष 1974-75 के लिये 5 छात्रों की स्वीकृति प्राप्त हो गई तथा शेष एक छात्र की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

(12) इटली

वर्ष 1975-76 के दौरान इटली सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिये 6 छात्रवृत्तियां प्रदान की है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(13) जापान

जापान सरकार से वर्ष 1974-75 के लिये 8 छात्रवृत्तियों के एक प्रस्ताव के फलस्वरूप 1974 के दौरान 6 छात्र चुने गये और वे जापान चले गये।

वर्ष 1975-76 के लिये 8 छात्रवृत्तियों का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

जापान फैलोशिप (फांउडेशन) के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शिक्षक के लिये अंशकालिक फैलोशिप तथा एक छात्र के लिये दीर्घ-कालिक फैलोशिप का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नाम शीघ्र भेजा जा रहा है।

(14) नीदरलैण्ड

1974-75 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिये एक प्रस्ताव के फलस्वरूप 62 छात्र चुने गये थे। डच सरकार ने अब तक केवल 28 छात्र अनुमोदित किये हैं। कुछ और छात्रों का अनुमोदन किया जाएगा।

(15) नार्वे

चालू वर्ष में 67 छात्र नार्वे चले गये।

(16) पोलैण्ड

पोलैण्ड सरकार से वर्ष 1974-75 के लिए 9 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 12 छात्रों का नाम, जिनमें 3 आरक्षित हैं, पोलिश सरकार के अनुमोदन के लिये भेजा गया है।

इसके अतिरिक्त कोमीकोन योजना 1974-75 के अंतर्गत पोलिश सरकार ने छात्रवृत्तियां देने के लिये 2 छात्रों को स्वीकृति दी है तथा ये छात्र पोलैण्ड चले गये हैं।

(17) रूमानिया

रूमानिया सरकार से 1974-75 के लिये 10 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। भारत सरकार द्वारा चुने गये सभी 10 छात्रों को रूमानिया सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

(18) साऊदी अरब

(1974-75) के प्रस्ताव के अनुसार साऊदी अरब सरकार ने चार छात्रों को स्वीकृति दे दी है।

(19) स्वीडन

वर्ष 1974-75 के दौरान उपसाला विश्वविद्यालय में भौतिकी के एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिये 3 छात्र स्वीडन चले गये हैं।

(20) यूनाइटेड किंगडम

वर्ष 1974-75 के दौरान इम्पीरियल रिलेशन ट्रस्ट, यू० के० के अन्तर्गत 2 फैलोशिप के लिए 2 नामांकन किये गये। दोनों अभ्यर्थियों को चुना गया था परन्तु यू० के० केवल एक अभ्यार्थी ही जा सका।

(21) ब्रिटिश काउंसिल छात्रवृत्ति के अंतर्गत 10 छात्रवृत्तियों के लिए 14 छात्र यू० के० चले गये हैं। वर्ष 1975-76 के लिये 10 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

ब्रिटिश उद्योग समुद्र पार छात्रवृत्ति संघ के अंतर्गत 4 छात्रवृत्तियों के लिए एक छात्र यू० के० चला गया है। 1973-75 के लिए 5 छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

रायल छात्रवृत्ति कमीशन के अंतर्गत सारे विश्व के लिए 10 छात्रवृत्तियों के प्रयोजन से 2 छात्रों को चुना गया है तथा एक यू० के० चला गया है। 1975-76 के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(22) सोवियत रूस

भारत-रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 1974-75 के अंतर्गत रूस सरकार ने 100 छात्रवृत्तियां दी थीं जिनमें विभिन्न भारतीय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के लिये 32 छात्रवृत्तियां सम्मिलित थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1974-75 के दौरान सोवियत मछली उद्योग मंत्रालय ने भी मछली उद्योग के विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये 65 छात्रवृत्तियां प्रदान कीं।

इस मंत्रालय को दी गई 83 छात्रवृत्तियों के लिए कुल 77 छात्र मनोनीत किये गये। इसके अतिरिक्त 6 अभ्यार्थियों के नाम, जिनमें एक आरक्षित था, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (रूसी अध्ययन केन्द्र), नई दिल्ली से प्राप्त हुए। उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सोवियत सरकार द्वारा दी गई 5 छात्रवृत्तियों के लिए 7 नाम, जिनमें 2 आरक्षित शामिल थे, आई० आई० टी०, बम्बई से प्राप्त हुए। ये नाम इस योजना के अंतर्गत सोवियत सरकार की स्वीकृति के लिये भेज दिए गये। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दी गई एक छात्रवृत्ति के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा एक अभ्यार्थी को मनोनीत किया गया है।

सोवियत महिला संघ ने भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ कीं 1974-75 के दौरान 8 छात्रवृत्तियां दीं। इस योजना के अन्तर्गत संघ ने 3 आरक्षित नामों को मिलाकर 11 व्यक्तियों की सिफारिश की थी। सोवियत अधिकारियों ने सभी 8 व्यक्तियों को मान लिया और वे चिकित्सा तथा शिक्षाशास्त्र में डिप्लोमा प्राप्त करने विदेश चले गये।

(23) युगोस्लाविया

सन् 1973-74 के लिए भारत तथा युगोस्लोविया के छात्रों के आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 व्यक्तियों को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी गई है।

(ग) भारत में अध्ययन के लिये विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

(i) सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत एशियां, अफ्रीका तथा अन्य देशों के नागरिकों के लिए हर वर्ष भारत में मैट्रिकुलेशन के आगे अध्ययन के लिए 180 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । 1974-75 के दौरान चयन समिति द्वारा 172 छात्रों का चुनाव किया गया । विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में 150 छात्रों ने अध्ययन शुरु कर दिया है तथा 10 और छात्र अध्ययन शुरू करने वाले हैं । छात्रवृत्तियां कृषि, इंजीनियरी, तथा टेक्नोलोजी, चिकित्सा, औषध, निर्माण विज्ञान, कला तथा मानविकी में दी गई हैं । यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1975-76 के दौरान 55 देशों के नागरिकों को 180 छात्रवृत्तियां दी जायं । इसके लिए आवेदन-पत्र मांगे गये हैं ।

(ii) बंगलादेश के नागरिकों के लिये छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजना

बंगला देश की सहायता के एक अंग के तौर पर भारत सरकार ने निश्चय किया है कि अन्य बातों के अलावा, बंगला देश के छात्रों के लिए देश में अध्ययन सुविधाओं की व्यवस्था की जाए । इस उद्देश्य से, 1972-73 में योजना बनाई गई । 1974-75 के दौरान भारत में विभिन्न विषयों में अध्ययन/अनुसंधान के लिए बंगलादेश को 100 छात्रवृत्तियां दी गई । इस समय, विभिन्न संस्थानों में कुल मिलाकर बंगलादेश के 150 छात्र चिकित्सा, इंजीनियरी तथा टेकनोलाजी, कृषि, मछलीपालन. ललित-कला में अध्ययन कर रहे हैं । स्नातक स्तर तक के लिए बंगलादेश के छात्रों की छात्रवृत्तियां की दर प्रतिमास 250 रु० से बढ़ाकर 300 रु० कर दी गई है । स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां 450 रु० प्रतिमास है । जो लोग बंगलादेश के विश्वविद्यालयों में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे हों तथा जो सरकारी या शैक्षिक संस्थाओं में काम कर रहे हों, यदि वे उच्च अध्ययन के लिय यहां आयें तो उनकी छात्रवृत्ति की दर वही होगी जो वे अपने विश्वविद्यालयों/कालेजों म वेतन के रूप में ले रहे हों पर यह हर स्थिति में अधिक-से-अधिक 1000 रु० होगी । यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1975-76 की अवधि में बंगलादेश के छात्रों को 100 छात्रवृत्तियां दी जाएं जिनके लिये आवेदन-पत्र मांग गए हैं ।

(iii) विदेशी छात्रों को विशेष अंग्रेजी पाठ्यक्रम

जिन विदेशी विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बाद अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कर सकने की योग्यता प्राप्त नहीं है, उनके लिए मंत्रालय

हर वर्ष विशेष अंग्रेजी पाठ्यक्रम का आयोजन करता रहा है । एक ऐसा पाठ्यक्रम सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना 1974-75 के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों के लिए चुने गए विदेशी छात्रों के लिए अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा के केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद म मार्च से जून 1974 तक आयोजित किया गया । कुछ चुने हुए देशों के 23 छात्र इस पाठ्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं । इसके अतिरिक्त , कुछ अपने खर्चे से अध्ययन कर रहे छात्रों को इस पाठ्यक्रम से लाभ उठाने की आज्ञा दी गई थी ।

(iv) कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह निर्माण

यह प्रस्ताव है कि कलकत्ता में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों म पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों के रहने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह का निर्माण किया जाय (भूमि की लागत को मिलाकर) भवन के निर्माण के लिए अनुमानित राशि 18 लाख रुपया है । इस खर्च की भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार बराबर-बराबर वहन करेगी । इस मंत्रालय ने चार लाख रुपये की राशि, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह सोसाइटी को दे दी है । इस सोसाइटी की स्थापना भवन निर्माण कार्य की देख-रेख करने के लिए की गई है । 1975-76 के अनुमानित बजट में इसके लिए 5 लाख रुपये की राशि को शामिल किया गया है ।

(v) राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजना—भारतीय छात्रवृत्तियां

(क) भारत सरकार 1961-62 से राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजना के अन्तर्गत सभी राष्ट्रमण्डलीय देशों के लिये 45 छात्रवृत्तियां तथा 5 फैलोशिप देती आ रही है । चालू वर्ष के दौरान 50 छात्रवृत्तियां दी गईं । इनमें से अब तक 19 छात्रों ने इनका उपयोग किया है तथा 6 और व्यक्तियों की 2 या 3 महीने में संस्थानों मे प्रवेश लेने की आशा है । पिछले वर्षों में दी गई छात्रवृत्तियों को मिलाकर इस समय भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय देशों के 61 छात्र अध्ययन कर रहे हैं । वर्ष 1975-76 के लिए 45 छात्रवृत्तियां तथा 5 फैलोशिप सभी राष्ट्रमण्डलीय देशों के लिए दी जा रही हैं ।

(ख) हस्तकला अनुदेशक के प्रशिक्षण के लिये विशेष छात्रवृत्तियां

विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय देशों के हस्तकला अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए प्राय: 10 विशेष छात्रवृत्तियां हर साल दी जाती है । 1974-75 के दौरान मद्रास, बम्बई तथा नई दिल्ली में स्थित अनुदेशकों के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों

में 7 प्रशिक्षार्थी (4 घाना के, 2 गुयाना के तथा 1 फिजी का) प्रशिक्षण ले रहे हैं । ये विशेष छात्रवृत्तियां एक वर्ष की अवधि की हैं । तंजानियाँ के दो प्रशिक्षार्थी जल्दी ही प्रवेश लेंगे ।

(ग) राष्ट्रमण्डलीय देशों के वरिष्ठ शिक्षाविदों की अल्पकालिक भारत यात्रा

राष्ट्रमण्डलीय देशों के वरिष्ठ शिक्षाविदों की अल्पकालिक भारत यात्रा की योजना राष्ट्रमण्डलीय शिक्षा सहयोग योजना की एक अंश है । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष तीन शिक्षाविदों को आमंत्रित करने की व्यवस्था है । 1974-75 के दौरान कोई शिक्षाविद आमंत्रित नहीं किये गए, किन्तु 1973-74 के लिए चुने गए वरिष्ठ शिक्षाविद इस वर्ष यात्रा कर रहे हैं । तीन वरिष्ठ शिक्षाविदों में से श्रीलंका के एक शिक्षाविद ने 26-8-1974 से 23-10-1974 तक भारत यात्रा की । अन्य शिक्षाविद जल्दी ही आएगा ।

(vi) कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना और विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीकी सहायता योजना

कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना और विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत, जो मुख्यत: वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य-विभाग) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, शिक्षा विभाग, कृषि और चिकित्सा के विषयों को छोड़कर, सामान्यत: इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और मानविकी विषयों से सम्बन्धित छात्रवृत्तियों का संचालन करना है ।

1974 के दौरान, दोनों योजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: 84 और 15 छात्र-वृत्तियां दी गई । वर्ष के दौरान 361 विद्यार्थियों ने अपना अध्ययन जारी रखा, जिनमें वे छात्र भी शामिल हैं जिन्हें पिछले वर्षों में छात्रवृत्तियां दी गई थीं ।

(vii) पारस्परिक छात्रवृत्ति योजना

पारस्परिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक दो वर्षों म भारत सरकार द्वारा 30 छात्रवृतियां दी जाती हैं । 1973-75 के चालू दो वर्ष में 30 छात्रवृत्तियां/फैलोशिप दी गई थीं जिनके लिए कुछ यूरोपीय, एशियाई और लैटिन अमरीकी देशों से 28 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और 16 छात्रों को विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में दाखिल किया जा चुका है ।

12 मामलों पर अभी कार्रवाई की जा रही है ।

(viii) पश्चिम जर्मनी के नागरिकों के लिये फैलोशिप

पश्चिम जर्मनी के नागरिकों के लिए फैलोशिप की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पश्चिम जर्मनी के नागरिकों को 10 छात्रवृत्तियां/फैलोशिप दी जाती हैं । 1970-71 से 1972-73 तक की फैलोशिप के लिए अध्ययन कर रहे 6 छात्रों ने अपना अध्ययन जारी रखा है । 1974-75 के लिए 4 नाम प्राप्त हुए हैं और उनका स्थान-निर्धारण तय कर लिया गया है ।

(ix) भारत विदेश सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम—छात्रवृत्तियां भारत में विदेशी नागरिकों के अध्ययन/अनुसंधान के लिये फैलोशिप

(क) अफ़गानिस्तान

30 छात्रवृत्तियों के विरुद्ध 40 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । 7 अध्ययन कर रहे हैं । एक देश छोड़कर चला गया है । सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में दोनों प्रवेश पा जाएँगे । 8 मामलों पर विचार हो रहा है । विश्वविद्यालयों द्वारा 15 के बारे में असमर्थता जाहिर की गई है । 7 ने अपने आवेदन-पत्र वापिस ले लिये थे ।

(ख) **बल्गारिया** : बल्गारिया को प्रत्येक वर्ष 3 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । भारत में इस समय बल्गारिया का एक छात्र अध्ययन कर रहा है ।

(स) **चेकोस्लोवाकिया** : चेकोस्लावाकिया को प्रत्येक वर्ष 5 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । कोई भी नाम प्राप्त नहीं हुआ है ।

(द) **फ्रांस** : फ्राँस को प्रत्येक वर्ष 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । 1974-75 की छात्रवृत्तियों के लिए 3 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर कार्रवाई की जा रही है । इस समय 5 छात्र अध्ययन कर रहे हैं ।

(ई) **जर्मन जनवादी गणराज्य** : वर्ष 1973-75 के लिए 3 छात्रवृत्तियां दी गई थीं । 3 नाम प्राप्त हुए और उनका हिसाब-किताव तय किया जा रहा है ।

(फ) **ग्रीक** : इस समय ग्रीक के 2 छात्र भारत में अध्ययन कर रहे हैं ।

(ज) **हंगरी** : हंगरी को प्रत्येक वर्ष 5 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । हंगरी का एक छात्र आजकल अध्ययन कर रहा है ।

(ह) **पोलैण्ड** : प्रत्येक वर्ष 5 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । एक भी पोलिश छात्र यहां पढ़ नहीं रहा है ।

(इ) **रूमानिया :** रूमानिया के नागरिकों को दी जानेवाली एक छात्रवृत्ति के लिए आजकल भारत में एक भी छात्र नहीं पढ़ रहा है ।

(जे) **सं० अ० ग० (अब अरब मिश्र गणराज्य) :** अ० मि० ग० के नागरिकों को 10 शिक्षावृत्तियां देने के लिए 1973-75 के दो वर्ष के लिए सांस्कृतिक करार को अन्तिम रूप दिया गया है । 7 छात्र अध्ययन कर रहे हैं ।

(के) **सोवियत रूस :** सामान्यत: प्रत्येक वर्ष 20-25 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । 22 नाम प्राप्त हुए थे । भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 19 छात्र अध्ययन कर रहे हैं ।

(ल) **यूगोस्लाविया :** प्रत्येक वर्ष यूगोस्लाविया को 3-4 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । वहां का एक छात्र भारत में अध्ययन कर रहा है ।

(x) **एन्यूरिन बीवन स्मारक शिक्षावृत्ति** 1974-75 :

भारतीय उच्चायुक्त, लन्दन के कार्यालय से एक नाम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है किन्तु इसका चुनाव अभी विचाराधीन है ।

(xi) **अफ्रीकी राष्ट्रिकों के लिये स्वर्गीय डा० अभील्कर काब्रल की स्मृति में छात्रवृत्ति :**

यह निर्णय किया गया है कि अफ्रीकी दिवस के अवसर पर अफ्रीकी राष्ट्रिकों के लिए विशेष भारतीय छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्वर्गीय डा० अभील्कर काब्रल की स्मृति में एक छात्रवृत्ति/फैलोशिप दी जाए । यह छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष उस अफ्रीकी राष्ट्रिक को दी जायेगी जो अफ्रीका के मुक्ति संघर्ष से सम्बद्ध रहा हो या जो रंगभेद की नीति के विरुद्ध लड़ा हो ।

—०—०—०—

पांचवां अध्याय

पुस्तक प्रोन्नति तथा कोपीराइट

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास के लिये एक प्रमुख आवश्यकता यह है कि प्रचुर मात्रा में पुस्तकें तथा अन्य पठन सामग्री उपलब्ध की जाये, शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व इसके साथ-साथ पढ़ने वाली सामान्य जनता के लिये पुस्तकों के विकास और प्रसार के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किया है ।

इसके कार्यकलाप संक्षेप में निम्नलिखित हैं :–

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास :

स्वतंत्रता के बाद देश में बढ़ती हुई साक्षरता एक सांस्कृतिक तथा बौद्धिक जागरूकता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1957 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में गठन किया गया था ताकि उन पाठकों को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उचित मूल्यों पर अच्छी सामान्य पठन सामग्री उपलब्ध हो सके जिन्हें उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो । न्यास, प्रौढ़ों तथा बच्चों दोनों के लिए विभिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न क्रममालाओं जैसे, 'भारत भूमि तथा लोग' 'राष्ट्रीय जीवनियां,' 'लोक प्रिय विज्ञान,' 'विश्व की उत्कृष्ठ पुस्तकें', 'आज का विश्व', 'भारत की लोक-कथायें' तथा 'यंग इन्डिया लायब्रेरी' के अन्तर्गत ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करता है, जिनमें वाणिज्यिक प्रकाशकों की रुचि न हो ।

पुस्तकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को सौंपा गया है । इसके अनुसरण में, न्यास ने राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेले आयोजित किये हैं । यह लेखकों, अनुवादकों, प्रकाशकों तथा बितरकों की समस्याओं के संबंध में सेमिनार, वर्कशाप तथा अंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है । इन गतिविधियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वियन

भी सौंपा गया है, जैसे आदान-प्रदान तथा नेहरू बाल पुस्तकालय, भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन में आर्थिक सहायता देना ।

न्यास द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं :-

(क) न्यास ने, देश के प्रकाशकों के दो व्यापारिक संगठनों, अर्थात् भारत में प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं के संगठनों का संघ तथा भारतीय प्रकाशक संघ व महाराष्ट्र प्रकाशक संगठन के सहयोग से 31 जनवरी से 11 फरवरी 1974 तक बम्बई में राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जो अपनी शृंखला में छठा था । मेले में 1971 के बाद से सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में देश में प्रकाशित 6000 पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया । मेले के दौरान, न्यास ने भारत में अपने किस्म का प्रथम प्रकाशक सम्पादकों की वर्कशाप, भारतीय भाषाओं में बच्चों की पुस्तकों के सहनिर्माण तथा देश के सांस्कृतिक जीवन में फुटकर पुस्तकों की दूकानों के स्थान के बारे में एक सेमिनार तथा कापीराइट भारत की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के संबंध में एक संगोष्ठी भी आयोजित की । प्राइवेट प्रकाशकों के अतिरिक्त, आन्ध्र-प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु की सरकारों ने भी मेले में भाग लिया ।

(ख) अंग्रेजी में भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिये आर्थिक सहायता की योजना :

अंग्रेजी में कम कीमत पर उपयुक्त पठन सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने व भारतीय लेखन को बढ़ावा देने के विचार से, चुनी हुई भारतीय कृतियों के प्रकाशन में आर्थिक सहायता देने की एक योजना 1970 से चल रही है ताकि ऐसे प्रकाशन विदेशी पाठ्य पुस्तकों से प्रतिस्पर्धा कर सकें । इस योजना में मौलिक पुस्तकें, प्रकाशित कार्य तथा भारतीय लेखकों द्वारा विदेशी पुस्तकों के रूपान्तर शामिल हैं। आलोच्य अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 16 पुस्तकों के लिए सहायता दी गई जिनको मिलाकर इस योजना के शुरू होने के समय से अब तक प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या 54 हो गई है । इसमें फिर से छपी पुस्तकें भी शामिल हैं ।

(ग) अंग्रेजी में भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन में आर्थिक सहायता की योजना जैसी एक योजना अमेरिकी सहायता

निधि की मदद से 1971-72 में शुरू की गई । इस निधि से अब तक 55 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । जिनमें से 28 आलोच्य अवधि में प्रकाशित हुई । इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 46 शीर्षकों को स्वीकार किया गया है ।

(घ) राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तत्वावधान में यूसेड निधि की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीयता प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा सितम्बर, 1972 में, भारत के पुस्तक उद्योग का व्यापक सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया । यह सर्वेक्षण, जो आलोच्य वर्ष में पूरा किया गया, देश के प्रकाशन उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्न था ।

(ङ) आदान-प्रदान

राष्ट्रीयता एकता को प्रोत्साहन करने तथा भारतीय संस्कृति को समग्र रूप से समझने के लिए सामान्य पुस्तकों की एक कड़ी तैयार करने के लिए, आदान प्रदान की एक योजना 1969 में शुरू की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत न्यास संविधान की आठवीं सूची में वर्णित प्रत्येक भाषा की प्रमुख पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित करता है । न्यास ने अब तक इस श्रृंखला के अन्तर्गत पुस्तकें तथा उनके अनुवाद प्रकाशित किए हैं । और इस समय 1212 प्रेस में हैं ।

राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शिक्षा स्रोत केन्द्र

इस केन्द्र की स्थापना जुलाई 1972 में की गई थी । जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रकाशन के लिए सूचना केन्द्र के रूप में तथा विदेशों से आयातित मुद्रित सामग्री के प्रलेखन व सांख्यिक विश्लेषण के रूप में कार्य करना है । प्रारम्भ में, केन्द्र ने देश में प्रकाशित विश्वविद्यालयीय स्तर की पुस्तकों तथा मंत्रालय के तीन सहयोग कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रकाशित विदेशी पाठ्य-पुस्तकों के सस्ते संस्करणों का एक संदर्भ संग्रह प्रारम्भ किया है । ये पुस्तकें, विश्वविद्यालयों के छात्रों तथा अध्यापकों के लिए संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं । पुस्तकों के विद्यमान क्षेत्र का सर्वेक्षण करने तथा नए प्रकाशनों की योजना तैयार करने के लिए पाठ्य-पुस्तकों के लेखक और प्रकाशक भी केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं । इस संदर्भ संग्रह में लगभग 30,000 पुस्तकें हैं । आलोच्य अवधि में लगभग 9340 विशिष्ठ पाठकों द्वारा इन पुस्तकों का अवलोकन किया गया ।

केन्द्र ने अभिवृद्धियों की ग्यारह पाक्षिक सूचियां पुस्तकालय को भेजी और साथ ही साथ सस्ते प्रकाशनों और महत्वपूर्ण पुस्तकों के स-टिप्पण, सूची पत्र का दूसरा खण्ड भी जारी किया। समय समय पर जारी किए जाने वाली विश्व-विद्यालय स्तर की पुस्तकों की राष्ट्रीय सूची के अनुपूरकों को भी एक संचयी खण्ड के रूप में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। उपलब्ध देशी पुस्तकों की ओर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और अध्यापकों का ध्यान आकर्षित करने के अपने-अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केन्द्र ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की तीन प्रदर्शनियां आयोजित की। केन्द्र ने "देश में विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में वास्तविक प्रयोग में पुस्तक चयन की विभिन्न पद्धतियों" का एक नमूने का सर्वेक्षण भी किया।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड

देश में पुस्तक उद्योग के संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक नया सलाहकार संस्था के रूप में राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की 1967 में स्थापना की थी। 1970 में बोर्ड का पुर्नगठन किया गया और प्रस्ताव है कि इसे कुछ अतिरिक्त कार्य सौंप कर और इसमें पुस्तक उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों का व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करके तीसरी बार इसका पुर्नगठन किया जाए।

विश्वविद्यालय स्तर की मानक शैक्षिक सामग्री के सस्ते संस्करण

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयातित मानक शैक्षिक सामग्री अधिकांश भारतीय छात्रों के साधनों से बाहर है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मानक स्वदेशी कृतियों के तैयार करने में कुछ समय लगेगा, भारत सरकार ने 1960, 1961, तथा 1965 में क्रमश: यू० के०, संयुक्त राज्य अमरीका तथा रूस की सरकारों के साथ सहयोग करार किए थे, ताकि इन देशों की मानक शैक्षिक सामग्री, भारतीय छात्रों को सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। इन संयुक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षिक सामग्री यू०के० तथा रूस में पुनर्मुद्रित की जाती है तथा उसे सामान्य व्यापारिक माध्यमों के जरिये भारत में बेचा जाता है। जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका का सम्बन्ध है, अनुमोदित अमरीकी पुस्तकों के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने के लिये भारतीय प्रकाशकों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनका मूल्य मौलिक अमरीकी संस्करणों का लगभग 1/5 होता है, बेचा जाता है। इन कार्यक्रमों की शुरूआत से अब तक 600 ब्रिटिश, 1350 अमरीकी तथा 230 रूसी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है।

अनुवादक अधिकार प्राप्त करना

राज्य सरकारों द्वारा भारतीय भाषाओं में चुनी गई पुस्तकों के सम्बन्ध में विदेशी कापीराइट मालिकों की स्वीकृति प्राप्त करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में होने वाले पत्र-व्यवहार को एक ही स्थान पर केन्द्रित करने के उद्देश्य से एक कापीराइट निकासी कोष्ठ (सेल) की स्थापना की थी। अधिकांश अमरीकी तथा ब्रिटिश प्रकाशकों के साथ समझौतों के प्रारूपों के बारे में बातचीत की गई। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये, सितम्बर, 1974 के अन्त तक, ब्रिटिश और अमरीकी प्रकाशकों के साथ अब तक कुल 1291 करार किये गये हैं।

आयात तथा निर्यात नीति :

निर्यात को प्रोत्साहन कार्य कलाप

विश्व के प्रमुख प्रकाशक देशों में से भारत एक है, तथा न केवल इंगलैंड और अमरीका जैसी सुस्थापित मंडियों में बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीकी देशों की नई मण्डियों में भी पुस्तक निर्यात करने की उसकी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों, प्रदर्शनियों, आदि में भाग लेने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को सौंपी गई है।

आलोच्य वर्ष के दौरान न्यास ने सिंगापुर में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (अप्रैल, 1974) ढाका में राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी (अप्रैल, 1974 तथा फरवरी, 1975) फ्रैंकफर्त अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (अक्टूबर, 1974), लन्दन में राष्ट्रीमण्डलीय पुस्तक मेला (अक्टूबर, नवम्बर, 1974), अंकारा में अन्तर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला (नवम्बर, 1974) तथा काहिरा में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (फरवरी, 1975) में भाग लिया। न्यास ने, विभिन्न प्राइवेट प्रकाशकों तथा स्वायत्त प्रकाशन यूनिटों द्वारा भेजी गई पुस्तकों को प्रदर्शित करने के लिये बैंकाक में (अप्रैल, 1974) न्यूयार्क में (जून, 1974) में आयोजित विशेष भारतीय पुस्तक प्रदर्शनी तथा सांयागो, गुयाना और मनीला स्थित भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों में भेजने का भी प्रबन्ध किया। बाल पुस्तक प्रदर्शनी, बोलोग्ना इटली (अप्रैल, 1974), बेलग्रैड में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (सितम्बर, 1974), श्रीलंका में प्रर्दशनी (सितम्बर, 1974) तथा बेरुत (फरवरी, 1975) में आयोजित बाल पुस्तक प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लिये भी पुस्तकें भेजी गई थीं।

न्यास केवल अपने निजी प्रकाशकों को ही प्रदर्शित नहीं करता बल्कि उन अन्य पब्लिक सैक्टर प्रकाशन यूनिटों के अलावा, उन भारतीय प्रकाशनों की संख्या को भी प्रदर्शित करता है जो इस प्रकार के मेलों में व्यक्तिगत रूप से भाग न ले सकते हैं ।

मंत्रालय को, विदेश स्थित भारतीय मिशनों के जरिए बाज़ार सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होती रहीं, जिन्हें प्रकाशक और पुस्तक विक्रेताओं के दो संघों के माध्यम से विभिन्न प्रकाशकों और पुस्तक निर्यातायों में परिचालित किया गया । भारतीय प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संगठनों के संघ की भी, विदेश परिचालन के लिए " बुक्स इण्डिया" नामक त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन में मदद की गई ।

पुस्तकों की आयात नीति

पुस्तकों, पत्रिकाओं, बाल साहित्य तथा अन्य शैक्षिक सामग्री के संबंध म आयात नीति का निर्धारण आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा मंत्रालय के परामर्श से किया जाता है । तथापि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आयतिक सामग्री से देश में पुस्तकों के विकास में बाधा न पहुँचे, आयातकर्ताओं से कहा जाता है कि वे उन पुस्तकों का आयात न करें जिनके भारतीय संस्करण उपलब्ध हों ।

आयात नीति की मुख्य बात यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना आयात लाइसेंस के अपने उपयोग के लिए 500 रुपए मूल्य तक की शैक्षिक पुस्तकों का प्रतिवर्ष आयात कर सकता है । वह लाइसेंस के आधार पर 400 रुपये तक की अतिरिक्त पुस्तकें भी प्रत्येक मामले में आयात कर सकता है । पुस्तकालय तथा शैक्षिक, संस्थाएं अपने निजी उपयोग के लिए प्रत्येक वर्ष 10 हज़ार रुपये तक की शैक्षिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकें बिना लाइसेंस के आयात कर सकते हैं । दस हजार रुपये से अधिक की अपनी आवश्यकता के लिए, वे इस प्रकार की पुस्तकों के आयात के लिए आयात-लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं ।

पुस्तकों के मान्य आयात कर्त्ताओं को पुस्तकें गैर-तकनीकी पत्रिकाओं, नई पत्रिकाओं आदि के आयात के लिए उनके बुनियादी कोटे के 100% तक के कोटे का लाइसेंस दिया जाता है । उन्हें शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों के आयात के लिये उनके कोटा लाइसेंस की कीमत से दुगने मूल्य का अनुपूरक लाइसेंस भी

7—956 M of Edu & SW/74

दिया जाता है । इन कोटा तथा अनुपूरक लाइसेंन्सों को वैज्ञानिक तथ तकनीकी पत्रिकाओं के आयात के लिये भी वैद्य किया जाता है ।

पुस्तकों के आयत व्यापार में नये आने वाले ऐसे व्यक्तियों को भी, जो पुस्तकों के आन्तरिक व्यापार में कम से कम पूरे एक वर्ष तक रहे हैं और जिनकी पुस्तकों का वार्षिक आन्तरिक क्रम व्यापार एक लाख रुपये का होता है, उनके आन्तरिक व्यापार की अवधि के वर्षो तथा उनके विक्रय के आधार पर दो लाख रुपये अथवा उससे अधिक की पुस्तकों के आयात के लिये भी आयात लाइसेंस दिये जाते हैं ।

राज्य व्यापार निगम ने जिसने पहलीबार वैज्ञानिक एवं शैक्षिक पत्रिकाओं का आयात शुरु किया था, विश्व-विद्यालयों तथा अन्य उच्च अध्ययन संस्थानों के उपयोग के लिये वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं को आयात करने का प्रबंध करके, उनकी सहायता की । राज्य व्यापार निगम की योजना न केवल विश्व-विद्यालयों तथा बड़ी संख्या में उच्च अध्ययन की अन्य संस्थाओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करने की है, अपितु उसकी ऐसी पुस्तकों के आयात की भी योजना है, जिन्हें विश्वविद्यालय, सामान्य व्यापार माध्यमों के जरिये प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं ।

कापीराइट

कापीराइट बोर्ड ने, जिसका गठन कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के उपबन्धों के अधीन किया गया था, एक अप्रैल, 1974 से 7 अक्टूबर, 1974 तक की अवधि के दौरान नए सुनवाई के लिये सूची में सम्मिलित 23 मामलों की सुनवाई के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में चार बैठकें आयोजित की तथा 13 मामलों का निर्णय किया ।

एक अप्रैल, 1974 से 7 अक्टूबर से 1974 तक की अवधि के दौरान कापी-राइट कार्यालय ने 956 कलात्मक कृत्तियों तथा 223 साहित्यिक कृत्तियों का पंजीकरण किया । इसने, कलात्मक कृतियों के कापीराइट के रजिस्टर में की गई 26 प्रविष्टियों में और साहित्यिक कृतियों के कापीराइट रजिस्टर में की गई 520 प्रविष्टियों में परिवर्तन भी किए ।

विद्यमान कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की कार्य-प्रणाली में पाई गई कुछ कमियों के कारण, भारतीय कापीराइट अधिनियम, 1957 में कुछ संशोधन स्वीकृत किये गए हैं तथा कापीराइट अधिनियम (संशोधन)

विधेयक को शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है । इसमें अन्य बातों के साथ साथ, दो अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट अभिसमयों अर्थात साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये बर्न अभिसमय तथा युनिवर्सल कापीराइट अभिसमय में किये गये संशोधन के कारण अपेक्षित परिवर्तन भी सम्मिलित होंगे, ये संशोधन पिछली बार जुलाई, 1971 में पैरिस में किये गये थे और इनमें विदेशी कृतियों के पुनर्भरणों तथा अनुवादों के क्षेत्र में सहायता करने के सम्बन्ध में धाराएँ शामिल थीं ।

आलोच्य अवधि के दौरान, भारत ने अनाधिकृत पुनरावृत्ति के विरुद्ध फोनोग्रामों के निर्माताओं के संरक्षण के लिये अभिसमय का अनुसमर्थन किया । भारत ने, साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये (क) यथासंशोधित तथा जुलाई, 1971 में पैरिस में हस्ताक्षरित बर्न अभिसयम की प्रशासनिक व्यवस्थाओं और (ख) 14 जुलाई 1967 को स्टाकहोम में हस्ताक्षरित विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन की स्थापना सम्बन्धी अभिसमय के प्रति अपनी सहमति प्रकट की ।

छठा अध्याय

युवक कल्याण, राष्ट्रीय एकता, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा

युवक कल्याण, राष्ट्रीय एकता, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किये :–

(1) छात्र और गैर-छात्र युवकों के लिए कार्यक्रम तथा युवक कल्याण से सम्बधित मामलों म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग ।

(2) स्कूली बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिविर तथा विश्वविद्यालयों और कालेजों में राष्ट्रीय एकता समितियों जैसे राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम ।

(3) खेलकूद, जिसके लिए खेलकूद संस्थान, पटियाला, लक्ष्मीबाई, शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर, राष्ट्रीय खेल संघों, राज्यों खेलकूद परिषदों को वित्तीय सहायता दी जाती है और ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं प्रशिक्षण शिविरों के क्षेत्र में विकासात्मक कार्यक्रम, खेल सुविधाओं की व्यवस्था और खेल प्रतिमा छात्रवृतियां ।

(4) शारीरिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर के कार्यकलाप, राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता अभियान तथा योग का प्रचार सम्मिलित है ।

(5) पर्वतारोहण पदयात्रा, स्काउटिंग तथा गाइडिंग जैसे अन्य कार्यक्रम ।

इस वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यान्वित किये गये कार्यकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा इस अध्याय में दिया गया है ।

(1) युवक कल्याण : राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प के अनुसरण में और कालेज छात्रों की शिक्षा को और अधिक पूर्ण तथा सार्थक बनाने की दृष्टि से शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत छात्रों के रचनात्मक और सामाजिक रूप से उपयुक्त कार्यकलाप सम्मिलित हैं । पांचवी योजना के

दौरान, इस योजना के अन्तर्गत अवकाश के दौरान शिविर लगाने के विशेष कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत कार्यरत प्रशिक्षण सहित यथासम्भव अधिकाधिक विषयों की पाठ्यर्चा के अध्ययन के साथ राष्ट्रीय सेवा को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ।

वितीय कठिनाइयों के बावजूद, अधिकाधिक छात्रों को शामिल करके राष्ट्रीय सेवा योजना की गति को बनाये रखा गया है । इस कार्यक्रम का ऐसे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों म विस्तार किया गया है जो चौथी योजना के दौरान इस योजना में भाग नहीं ले रहे थे । विभिन्न राज्यों को 1974-75 के दौरान 2 लाख छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । योजना की नियंत्रण कार्य पद्धति को सुदृढ़ कर दिया गया है और कार्यकलापों में गुणात्मक सुधार करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं ।

राष्ट्रीय सेवा को अध्ययन पाठ्यचर्या के साथ जोड़ने के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बातचीत की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तदनुसार सिफारिश की है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का अधिकाधिक विस्तार किया जाना चाहिय ताकि इसम अनिवार्य रूप से प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम स्तर के सभी छात्रों की शामिल किया जा सके। इसने यह भी सिफारिश की है कि राष्ट्रीय योजना को यथासम्भव अधिकाधिक विषयों के साथ जोड़ने पर विश्वविद्यालयों को विचार करना चाहिये।

राष्ट्रीय सेवा योजना के भाग के रूप में 1973 के दौरान शुरू किए गये "युवक बनाम अकाल" अभियान की उपयोगिता की सराहना किये जाने पर 1974 के दौरान "युवक बनाम गन्दगी और बीमारी" का विशेष अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया। युवक संगठनों के परामर्श से कार्यक्रम के लिए उचित मार्गदर्शी रूप रेखाएं और निर्देश तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी। युवक बनाम अकाल कार्यक्रम के विपरीत युवक बनाम गन्दगी और बीमारी अभियान के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों ने न केवल ग्रीष्म अवकाश के के दौरान अपितु वर्ष के अन्य अवकाशों के दौरान भी देश के विभिन्न भागों में शिविर आयोजित किए थे। विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को लगभग 43 लाख रुपए के अनुदान संस्वीकृत किये गये थे जिनके आधार पर राज्यों के खर्चे के भाग के साथ-साथ इस अभियान के अन्तर्गत

लगभग 75,000 छात्रों और गैर-छात्रों को शामिल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में, 10-15 दिनों की अवधि के शिविर आयोजित किये गये थे जिनमें लगभग 25-30 छात्र शामिल किये गये थे। आवश्यकतानुसार कुछ स्थानीय गैर-छात्र युवकों को भी साधन-स्रोत व्यक्तियों के रूप में शामिल किया गया था। शिविर लगाने के कार्यक्रमों में मुख्यतया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है :

(1) पर्यावरण सम्बन्धी सफाई,
(2) चिकित्सा सम्बन्धी सामाजिक कार्य जैसे कि निरोपय बीमारियों के विरुद्ध सामाजिक प्रतिरक्षण, और साथ में प्रारम्भिक टीका,
(3) सुवाह्य पानी की व्यवस्था, और
(4) गोबर गैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाना और उनका निर्माण करना।

अवकाशों के दौरान शिविर लगाने के विशेष कार्यक्रम को, राष्ट्रीय सेवा योजना का एक नियमित अंग बना दिया गया है।

राज्य और विश्वविद्यालय स्तर पर संबंध और सम्पर्क स्थापित करने और सामान्य रूप से विभिन्न युवक कार्यक्रमों और विशेष रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए अहमदाबाद, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास में 4 रा० से० यो० क्षेत्रीय केन्द्र और बंगलौर, भोपाल भुवनेश्वर, दिल्ली, गोहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पूना और त्रिवेन्द्रम में 11 क्षेत्रीय केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों के कार्य की गति को और अधिक तेज कर दिया गया है ताकि इन्हें सौंपे गए कार्यों के कार्यान्वयन में ये केन्द्र और अधिक कारगर सिद्ध हो सकें।

आयोजन मंच योजना

विश्वविद्यालयों और कालेजों में रजिस्टर्ड आयोजना मंचों को राज्य सरकारों के जरिय वित्तीय सहायता की योजना को जारी रखा गया है। आयोजन मंचों का उद्देश्य, विद्यार्थी तथा गैर-विद्यार्थी समुदाय में देश के नियोजित विकास के लिए आवश्यकता की जागरूकता की भावना पैदा करना तथा योजना सूचना केन्द्रों, प्रदर्शनियों, वार्ताओं, वाद-विवादों तथा चर्चाओं समाजार्थिक सर्वेक्षण आदि जैसे कार्यकलापों के माध्यम से आयोजन स्तर से ही राष्ट्रीय विकास प्रयत्नों में उन्हें सम्मिलित करना।

नानक भवन

कुछेक नानक भवनों का निर्माण कार्य, जिनके लिए पिछले वर्षों के दौरान अनुदान संस्वीकृत किये गये थे, इस वर्ष के दौरान भी जारी रहा। नानक भवनों के लिए राज्य सरकारों को दिए जाने वाले केन्द्रीय हिस्से की बकाया राशि के लिए 1973-74 में की गई 3 लाख रुपए की बजट व्यवस्था का आर्थिक तंगी के कारण उपयोग नहीं किया जा सका। इस प्रयोजन के लिए 1975-76 के योजनेत्तर बजट में उपयुक्त व्यवस्था की गई है।

युवक कल्याण बोर्ड और समितियां

इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा युवक कल्याण के लिए पूर्णकालिक निदेशक अथवा डीन और उसकी सहायता के लिए कुछ स्टाफ नियुक्त करने के लिए किए गए प्रशासनिक खर्चे तथा उसके अलावा कुछ स्वीकृत मदों पर किए गए फुटकर प्रासंगिक खर्चे के 50 प्रतिशत भाग को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। फिलहाल वर्ष 1975-76 के दौरान, वचनबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए योजनेत्तर बजट व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

गैर छात्र युवकों के लिये कार्यक्रम

राष्ट्रीय गैर-छात्र युवक कार्यक्रम में शामिल की गई योजनाओं में से, खेल के मैदानों के विकास और कार्य केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित दो योजनाएं 1971-72 में शुरू की गई थीं। 1972-73 में शुरू की गई जिला स्तर पर युवक केन्द्रों की स्थापना और युवा नेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता देने से सम्बन्धित दो अन्य योजनाओं को जारी रखा गया।

(क) जिलों में खेल के मैदान

इसका उद्देश्य, नगरों के खुले स्थानों का विकास करके और उनके रख-रखाव द्वारा बड़ी संख्या में लोगों की स्वस्थ बाहरी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। खेल के मदानों के विकास की योजना के अन्तर्गत, शहरी क्षेत्रों के खेल के मैदानों का विकास करने के लिए एक जिले में अधिकाधिक खेल के मैदानों के विकास की लागत का

लगभग 50% भाग पूरा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को प्रति जिले के हिसाब से 50,000 रुपए की दर से केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) कार्य केन्द्र

कार्य केन्द्रों का मूल उद्देश्य स्कूल से बाहर के युवकों को विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में स्वतः रोजगार प्राप्त करने की क्षमा के लिए प्रशिक्षित करना तथा इन कार्य केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने के बाद किसी उत्पादक व्यवसाय में लगाने में उनकी सहायता करना है। राज्यों की कार्य केन्द्र परियोजना के अनावर्ती खर्चे के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए, किन्तु 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं, तथा प्रति वर्ष प्रति परियोजना आवर्ती खर्चे के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए, किन्तु 60,000 रुपए से अधिक नहीं, केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है। समाज सेवा संगठनों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रायोजित कलकत्ता युवक स्वतः रोजगार केन्द्र सी० वाई० एस० ई० सी० नामक एक स्वैच्छिक संगठन को 1972-73 में एक लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया था। इस केन्द्र ने बहुत सी परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनके अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को स्वतः रोजगार प्राप्त करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1974-75 के दौरान पोर्ट ब्लेयर में एक कार्य केन्द्र की स्थापना के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को 57,600 रुपए का अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

नेहरू युवक केन्द्र

नेहरू युवक केन्द्रों की योजना में महानगरीय कस्बों के अलावा, जिलों के मुख्यालयों में युवक केन्द्रों की स्थापना करने की परिकल्पना है तथा इसका उद्देश्य गैर-छात्र युवकों को राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में शामिल करने के लिए जिला स्तर और ब्लाक स्तरों पर एक मंच की व्यवस्था करना है।

योजना का मुख्य उद्देश्य, गैर-छात्र युवकों के लिए नेहरू युवक केन्द्रों के जरिए निम्नलिखित कार्यक्रमों की व्यवस्था करना था :

(क) 15-25 आयु-वर्ग के सभी श्रेणियों के युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन में युवकों का भाग लेना,

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, विज्ञान संग्रहालय तथा पुस्तकालय सेवा की स्थापना, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, इत्यादि

(ख) युवकों में राष्ट्रीय स्तर के मान्य उद्देश्यों को, जैसे कि भारतीयता, आत्म-निर्भरता, समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता, प्रजातंत्र, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इत्यादि के गौरव को लोक प्रिय बनाना,

(ग) विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, खेलकूदों तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यकलापों का विस्तार करना,

(घ) सांस्कृतिक कार्यकलाप जैसे कि अभिनय कला, समूह गान, थियेटर तथा राष्ट्रीय एकता के प्रवर्धन में सहायक कार्य-कलापों में भाग लेना; और

(ङ) गैर-छात्र युवकों के साथ-साथ छात्रों को शामिल करते हुए सामाजिक तथा सामुदायिक कार्यक्रम।

14 नवम्बर, 1972 को योजना शुरू होने के बाद इस योजना के अन्तर्गत 83 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा इस वर्ष के दौरान 11 और अधिक केन्द्रों की संस्वीकृति दी गई है। वर्ष 74-75 के लिए 16 और अधिक केन्द्र संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

पांचवी योजनावधि के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों के लिए 600 लाख रुपए की योजनागत व्यवस्था की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 64.29 लाख रुपए की स्वीकृत बजट व्यवस्था है जिसमें से 34.29 लाख रुपए की योजनागत तथा 30 लाख रुपए की योजनेत्तर व्यवस्था है। 1974-75 के दौरान 30 सितम्बर, 1974 तक इस योजना पर 11 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं।

"आलोच्य वर्ष के दौरान, नेहरू युवक केन्द्रों के तत्वाधान में विभिन्न संस्थाओं के युवा नेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1,05,472 रु० की राशि मंजूर की गई है। वर्ष 1974-75 में स्वीकृत कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1975-76 में भी जारी रहेंगे।

अलोच्य वर्ष के दौरान 670 युवा नेताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।"

छात्रों के विनियम के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जाता है। 4 या 5 विभिन्न राज्यों के स्कूलों से भाग लेने वाले छात्र 10 से 15 दिन तक की अवधि के लिए किसी छठे राज्य के स्कूल में ठहरते हैं, जहां वे एक साथ रहते, खेलते और अपने सामान्य सम्बन्धों का पता लगाते हैं। 1974-75 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत रा० शि० अ० प्र० परिषद शिक्षक शिविरों का आयोजन करेगी। प्रत्येक शिविर में 100 अध्यापक होंगे, इन शिविरों का उद्देश्य शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना है। विभिन्न वर्गों, प्रदेशों, समुदायों, जातियों और भाषाई समूहों से अध्यापक लिए जाएंगे तथा वे 15 दिन की अवधि के लिए एक साथ रहेंगे। 200 अध्यापकों को शामिल करने के लिए अभी तक ऐसे दो शिविर संस्वीकृत किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय एकता समितियां

विश्वविद्यालयों और कालेजों में स्थापित राष्ट्रीय एकीकरण समितियों ने आलोच्य अवधि के दौरान राष्ट्रीय एकता के विकास से संबंधित अपने कार्यक्रमों को जारी रखा। इस समय, 60 समितियां विश्वविद्यालयों में, 57 संबंध कालेजों में तथा 3 सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य कर रही हैं। ये समितियां अपने विधान में उल्लिखित कार्यक्रमों को कार्यन्वित कर रही हैं। उनमें से कुछ पर्याप्त सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं तथा उन्होंने समर्थक कार्यक्रम शुरू किये हैं।

सभी कार्यकलाप अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तथापि, इन समितियों के कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की पर्याप्त गुंजाइश है, ताकि वे उन सशक्त काडरों में विकसित हो सकें, जो भ्रातृ भावनाओं को विकसित करने तथा साम्प्रदायिकता, जातियता और प्रादेशिकता की भावना का प्रतिरोध करने में ठोस भूमिका निभाने में समर्थ हो सकें। अधिक संख्या में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को शामिल करने हेतु समिति के कार्यक्रमों का विस्तार करने तथा पर्याप्त छात्र समुदाय को उनके अन्तर्गत सम्मिलित करने के आशय से उनकी सदस्यता का विस्तार करने के अतिरिक्त उनके कार्यक्रमों को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

खेलकूद

राष्ट्रीय नेताजी सुभाष खेलकूद संस्थान, पटियाला की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न खेलकूदों में योग्य प्रशिक्षकों को तैयार करना था। वर्ष 1973-74 के अन्त तक संस्थान ने विभिन्न प्रकार के 13 खेलों में 2528 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। 1974-75 के शैक्षिक सत्र में 321 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के आशय से चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षार्थियों का दाखिला 250 छात्र प्रति सत्र की पिछली सीमा से बढ़ाकर 321 तक कर दिया गया है। वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों में 12 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा काफी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। बंगला देश के पांच प्रशिक्षार्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

1974 के ग्रीष्म अवकाशों के दौरान संस्थान ने 6–6 सप्ताह के तीन अनुस्थापन पाठ्यक्रम पटियाला, दिल्ली और बंगलौर में आयोजित किए थे तथा उनमें 431 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों ने भाग लिया था। महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से पूर्व राष्ट्रीय टीमों के लिए संस्थान द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षित की गई टीमों में, प्रथम विश्व कप टूर्नामेन्ट के लिए महिला हाकी टीम एशियाई युवक प्रतियोगिताओं के लिए युवक फुटबाल टीम तथा 1974 के एशियाई खेलों के लिए विभिन्न टीमें शामिल हैं। उत्तम परिस्थितियों के अन्तर्गत दिए गए कड़े प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप तथा विशेषज्ञ शिक्षकों के अन्तर्गत संस्थान द्वारा प्रशिक्षित टीमों ने अपनी-अपनी प्रतियोगिताओं में खेलों का अच्छा प्रदर्शन किया था। महिला हाकी टीम ने, विश्व प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया था, भारतीय युवक फुटबाल टीम ईरान के साथ सह-विजयी रही तथा 1974 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीमों ने 28 पदक प्राप्त किए थे।

जर्मन जनवादी गणतंत्र से व्यायाम की कला में, टेबल टेनिस में (उत्तर कोरिया से दो प्रशिक्षक), पश्चिम जर्मनी से एक तैराकी प्रशिक्षक तथा सोवियत रूस से वेटलिफ्टिंग के एक विदेशी प्रशिक्षक ने संस्थान का दौरा किया। इन प्रशिक्षकों ने सेवाधीन प्रशिक्षकों के लिए क्लिनिकों का आयोजन किया और जूनियर तथा सीनियर खिलाड़ियों के लाभ के लिए अलग-अलग खेलों में प्रशिक्षण शिविर

भी आयोजित किए । राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के चार प्रशिक्षक, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नाइजेरिया, नेपाल और मारीशस गए हुए हैं ।

यूनेस्को तथा शरीर विज्ञान और सम्बद्ध विज्ञानों के रक्षा संस्थान के सहयोग से, संस्थान ने व्यायाम तथा खेलकूद शरीर विज्ञान के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अक्तूबर, 1974 में आयोजित की थी । 35 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 100 प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया । अपने प्रकाशन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान ने राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पत्रिका, खेलकूद औषधि, पत्रिका, एथलेटिक एशिया तथा एशिया इन्टरनेशनल नियमित रूप से जारी की । खेल मैदान की नियम-पुस्तक का एक संशोधित तथा वृहत संस्करण छप रहा है । इस पुस्तक का हिन्दी संस्करण पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है । संस्थान में निर्माणाधीन तैरने का तालाब के शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है । एक व्यायामशाला का भी निर्माण किया जा रहा है जिसके अगले वर्ष तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद

अप्रैल, 1972 में पुनर्गठित अखिल भारतीय खेल परिषद् ने देश में खेल के प्रसार और विकास से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने का अपना कार्य 1974-75 के दौरान भी जारी रखा । परिषद् की अप्रैल, अगस्त नवम्बर तथा दिसम्बर, 1974 में चार बैठकें हुईं ।

राज्य खेलकूद परिषदों को अनुदान

राज्य खेलकूद परिषदों को वित्तीय सहायता देने की योजना को वर्ष 1974-75 के दौरान जारी रखा गया, ताकि वे उपयोगिता स्टेडियमों, तैरने के तालाबों का निर्माण, स्टेडियमों को प्रदीप्त करना, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, खेल उपकरणों का क्रय तथा ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना कर सकें । वर्ष 1974 के अंत तक कुल 8.23 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किए गए ।

ग्रामीण खेलकूद केन्द्र

ग्रामीण खेलकूद के केन्द्रों की स्थापना की योजना को वर्ष 1974-75 के दौरान जारी रखा गया । अब तक 614 केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुदान दिए जा चुके हैं ।

स्कूली छात्रों के लिये खेलकूद प्रतिभा खोज छात्र वृत्तियां

राष्ट्रीय स्तर पर 600/- रुपये प्रतिवर्ष की 225 छात्रवृत्तियां तथा राज्य स्तर पर 300/- रुपये प्रतिवर्ष की 550 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, विगत वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की गई 100 तथा राज्य स्तर पर 180 छात्रवृत्तियों का नवीकरण किया गया।

राष्ट्रीय खेलकूद संघों को अनुदान

वर्ष 1974-75 के दौरान, वार्षिक प्रतियोगिताओं को आयोजित करने, अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने, विदेशी दलों द्वारा भारत के दौरों और वैतनिक सहायक सचिवों के वेतनों के भुगतान, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने तथा खेलकूद उपस्कर के क्रम के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संघों को कुल 6.97 लाख रुपये (योजनागत) 1.65 लाख रुपये (योजनेत्तर) के अनुदान स्वीकृत किए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा भाग लेना

(i) **1974 के 7 वें एशियाई खेल**

7वें एशियाई खेल तेहरान में 1 से 16 सितम्बर, 1974 तक हुए थे। 159 सदस्यों (प्रतियोगी, प्रबन्धक, प्रशिक्षक तथा दल के अधिकारी) के एक दल ने खेलों में भाग लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 12 कांस्य पदक जीते थे। भाग लेने वाले कुछ देशों में, जापान, ईरान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, तथा ईस्राइल के बाद भारत का 7वां स्थान।

(ii) नाईस में आयोजित प्रथम महिला विश्व कप हाकी प्रतियोगिता में महिला हाकी टीम ने भाग लिया। पहली बार में टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया।

(iii) **डेविस कप**

भारत, डेविस कप टूर्नामेन्ट, 1974 के फाइनल में पहुंच गया जहां उसे दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलना था। तथापि दक्षिण अफ्रीकी सरकार पृथग्वासन की नीति के पूर्ण विरोध की राष्ट्रीय नीति के अनुसार भारत दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध नहीं खेला था।

(iv) **एशियाई युवक फुटबाल प्रतियोगिताएं**

प्रतियोगिताओं में भारतीय युवक टीम और ईरान संयुक्त विजेता रहे ।

(v) उस अखिल स्टार एशियाई हाकी टीम के लिये सात भारतीय हाकी खिलाड़ी चुने गये थे, जो अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिये सितम्बर 1974 में ब्रसेल्स में हुए एक मैच में यूरोप की एक चुनी हुई टीम के विरुद्ध खेली थी । बाद में, संयुक्त एशियाई टीम ने अक्टूबर-नवम्बर, 1974 के दौरान पाकिस्तान तथा भारत में भी मैच खले थे ।

विनिमय कार्यक्रम

खेल के क्षेत्र में मित्र देशों के साथ महत्वपूर्ण विनिमय कार्यक्रमों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(क) भारतीय तैराकों को प्रशिक्षण देने के लिये जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला में कार्य करने के लिये तैरने में प्रशिक्षण देने वाले एक प्रशिक्षक की सेवायें 6 महीनों की अवधि के लिये प्रदान की थी ।

(ख) सोवियत रूस की सरकार ने क्लिनिक आयोजित करने तथा भारोतोलकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक भारोतोलक प्रशिक्षक की सेवायें 3 महीनों की अवधि के लिये प्रदान की ।

(ग) सोवियत रूस की एक बालीबाल प्रशिक्षक, जनवरी-फरवरी, 1975 में भारत का दौरा करेगा इस अवधि के दौरान प्रशिक्षकों के लिये क्लिनकें आयोजित करने के लिये वह राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला में कार्य करेंगे ।

(घ) शतरंज के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिये सोवियत रूस से एक शतरंज विशेषज्ञ फरवरी-मार्च, 1974 में भारत आ रहा है ।

राष्ट्रीय खेलकूद संघ

इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों की प्रगति का ब्यौरा जिसका उद्देश्य कालेजों के छात्रों को खेलों में प्रवीणता को प्रोन्नत करना है, नीचे दिया गया है :—

(क) **शारीरिक सुविधाएं** :—वित्तीय तंगी के कारण, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में व्यायामशाला तथा खेल के मदान के निर्माणार्थ नई योजनायें शुरू नहीं की जा सकीं । तथापि पहले से ही निर्माणाधीन

परियोजनाओं को जारी रखा गया और इस प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल 6.5 लाख रुपये के अनुदान दिये गये थे।

(ख) **प्रशिक्षण** : विभिन्न खेलकूदों के 76 प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना कार्य जारी रखा।

(ग) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (पहले भारत-श्री लंका अन्तर-विश्व-विद्यालयीय बोर्ड के नाम से जाना जाता था) ने विश्वविद्यालय तथा कालेज छात्रों के प्रशिक्षण आदि के अपने कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया। परिशोधित कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया है।

(i) **खेल प्रतिभा छात्रवृत्तियां** : छात्रवृतियां की संख्या जो चौथी योजना में प्रत्येक वर्ष 50 थी, बढ़ाकर 100 छात्रवृतियां प्रतिवर्ष कर दी जायेंगी।

(ii) **प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिताएं** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एथलैटिक्स (पुरुष तथा महिलायें), हाकी (पुरुष तथा महिलाएें), फुटबाल, कुश्ती तथा बालीबाल (पुरुष तथा महिलायें) में ग्रीष्म अवकाश के दौरान प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी। इन प्रशिक्षण शिविरों तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये क्षेत्रीय टीमों का चयन, अन्तर-विश्वविद्यालयीय टूर्नामेंटों के आधार पर किया जायगा। इन क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविरों तथा प्रतियोगिताओं के दौरान, महत्वपूर्ण प्रतिगिताओं में भाग लेने के लिये संबंधित खेलों के वास्ते संयुक्त विश्वविद्यालयीय टीमों को भी चुना जायेगा।

(iii) राष्ट्रीय खेल कूद संघों/एसोसिएशनों से संबद्धन :

प्रस्ताव है कि सभी प्रमुख खेलों से भारतीय विश्वविद्यालयों के खेल बोर्ड एसोसियेशन को संबद्ध किया जाय ताकि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं आदि में संयुक्त विश्वविद्यालयीय टीमें भाग ले सकें। फिलहाल, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, अखिल भारतीय लान टेनिस संघ, भारतीय हाकी, संघ, भारतीय एमच्योर एथलेटिक संघ और भारतीय बेडमिंटन संघ से ऐसा संबद्ध प्राप्त किया गया है।

(iv) वर्ष 1975-76 भारतीय विश्वविद्यालय संघ का स्वर्ण जयंती वर्ष है। इस वर्ष के दौरान पड़ोसी देशों में विश्वविद्यालयों की टीमें भारत में होने वाली अन्तर-विश्वविद्यालय प्रतियोगताओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव है।

खेलकूद को व्यापक बनाने के कार्यक्रम

खेलकूद संबंधी गतिविधियों को व्यापक रूप प्रदान करने तथा खेलकूदों में ग्रामीण तथा जनजातीय युवकों को शामिल करने के महत्व को वर्ष के दौरान बल देना जारी रखा गया। निम्नलिखित विशिष्ट गतिविधियों की व्यवस्था की गई :—

(1) 16 वर्ष से कम आयु वाले ग्रामीण जनजातीय युवकों के लिये प्रथम अखिल भारतीय ग्रामीण हाकी प्रतियोगिता अक्टूबर, 1974 के दौरान वारांगल (आंध्र प्रदेश) में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों में से 16 प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने गये और उन्हें नई दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण के लिये भेजा गया। इन खिलाड़ियों को एक टीम अखिल भारतीय जवाहरलाल नेहरू हाकी प्रतियोगिता में भेजी गई थी और वह फाइनल तक पहुंच गई थी।

(2) जलीय व्यवसाय पर निर्भर रहने वाले लोगों के बच्चों के लिये द्वितीय अखिल भारतीय ग्रामीण तैरने का प्रशिक्षण शिविर तथा प्रतियोगिता नई दिल्ली में सितम्बर-अक्तूबर, 1974 में आयोजित की गई थी। 12 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी-अपनी टीमें इस शिविर में भेजी थीं। इन युवक तैराकों को भी नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय चाचा नेहरू तरण आमन्त्रण प्रतियोगिता में भी भेजा गया था और इन्होंने तीन पदक जीते थे।

(3) दूसरी अखिल भारतीय ग्रामीण धनुर्विद्या प्रतियोगिता अगरतल्ला में अक्तूबर 1974 में आयोजित की गई थी। 8 राज्यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था।

(4) सितम्बर, 1974 के दौरान लड़कों तथा लड़कियों के लिये दूसरी अखिल भारतीय ग्रामीण एथलैटिक प्रतियोगिता सितम्बर 1974 के दौरान रांची में आयोजित की थी। प्रतियोगिता से पूर्व 2 सप्ताह की अवधि का एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। 15 राज्यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था।

(5) पांचवी अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता 1 से 5 फरवरी, 1975 तक शिमोगा (कर्नाटक) में आयोजित की जायेगी।

इस प्रतियोगिता में देशभर में से लगभग 1500 खिलाड़ियों द्वारा भाग लेने की आशा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975) के दौरान खेलकूद कार्यकलाप

वर्ष 1975 को "अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष" घोषित किया गया है। समारोहों के एक भाग के रूप में, 1975 के दौरान खेल-कूद, बास्केटबाल, हाकी, वालीबाल, तैराकी, व्यायाम तथा खो-खो में महिलाओं के लिये विशेष खेल-कूद कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे । ये कार्यक्रम जिला तथा राज्य स्तरों पर आयोजित किये जायेंगे और अन्त में अक्टूबर, 1975 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल-कूद समारोह होगा । राज्य सरकारों को इन्हीं आधारों पर महिलाओं के लिये उचित कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी गई है ।

शारीरिक शिक्षा

1. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (ग्वालियर)

कालेज ने छात्रों के दाखिले में वृद्धि करने की गति को बनाये रखा । शैक्षिक वर्ष 1974–75 में, 28 लड़कियों सहित 155 छात्रों को शारीरिक शिक्षा के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिल किया गया और चार लड़कियों सहित 18 छात्रों को शारीरिक शिक्षा के दो वर्षीय मास्टर्स पाठयक्रम में दाखिल किया गया। कालेज के इतिहास में पहली बार, स्नातक शारीरिक शिक्षा की सभी कक्षाओं में एक सौ से अधिक छात्र दाखिल हैं, जबकि स्नातक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में वार्षिक दाखिले की क्षमता 100 है। यह कालेज विदेशों के कुछ छात्रों सहित देश के लगभग सभी भागों से छात्रों को लगातार आकर्षित करता रहता है ।

2. राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (ग्वालियर) द्वारा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान नामक योजना लगातार आयोजित की जा रही है ।

वर्ष 1973–74 के अभियान में, वास्तविक रूप में भाग लेने वालों की संख्या 9 लाख थी ।

1974–75 में राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान को देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अक्टूबर, 1974 में आरम्भ किया गया जिसे जनवरी, 1975 तक चालू रखा गया ।

8—956 M of Edu & SW/74

शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिये चौदहवीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता :

शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिये चौदहवीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता ग्वालियर में 23 और 24 फरवरी, 1975 को आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से 65 प्रतियोगिओं ने भाग लिया जिनमें 16 स्त्रियां थी। 16 व्यक्तियों ने (6 स्त्रियों समेत) राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

3. योग का प्रसार

अनुसंधान तथा/अथवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के लिये, अखिल भारतीय स्तर की योग संस्थाओं को सहायता देने की भारत सरकार की नीति के अनुसरण में कैवल्यधाम श्रीमान माधव योग मंदिर-समिति, लोनावाला (पूना), तथा विश्वायातन योगाश्रम (दिल्ली तथा कटरा वैष्णव देवी केंद्र) को उनके आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये सहायता जारी रही। धन की कमी के कारण, अन्य योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना संभव नहीं हो सका है।

4. शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के संबंध में लोकप्रिय साहित्य को प्रोत्साहन

शारीरिक शिक्षा व खेल-कूद के संबंध में प्रकाशित साहित्य (1973-74) की चौथी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (ग्वालियर) के माध्यम से किया गया। प्रतियोगिता के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों के विरुद्ध केवल एक पुस्तक को ही राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये चुना गया।

इस योजना के अन्तर्गत पांचवीं राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता (1974-75) के लिये भी प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं।

अन्य कार्यक्रम

(क) पर्वतारोहण

भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान के लिये वित्तीय सहायता जारी रही। वर्ष के दौरान इस कार्य के लिय कुल 2.24 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने अब तक लगभग 30 पर्वतारोहण अभियानों के लिये सहायता दी है।

(ख) भा० प० प्र० को अनुदानों के अतिरिक्त, उन विश्वविद्यालयों को जिन्होंने पर्वतारोहण क्लब स्थापित कर रखे हैं, हिमालयाई पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग तथा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी को साहसिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये भी सहायता दी जाती है।

(ग) साहसिक कार्यों के लिये सुविधाएं

एक्सप्लोरर्स क्लब ग्राफ इण्डिया, कलकत्ता को जिसके अध्यक्ष एक विख्यात तराक श्री मिहिर सेन हैं, भारत के पूर्वी तट से बाली (इन्डोनेशिया) तक तथा वहां से वापस बडोच (गुजरात) तक के एक समुद्रीय नाव अभियान के लिये 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। नाव का निर्माण केंद्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० कलकत्ता द्वारा किया जा रहा है।

(घ) स्काउटिंग एवं गाइडिंग

स्काउटिंग एवं गाईडिंग के प्रसार के लिये भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स को वित्तीय सहायता दी जाती रही। संगठनात्मक एवं प्रशासनिक खर्चे के कुछ अंश को पूरा करने के अलावा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों, अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों तथा रैलियों में भाग लेने, प्रशिक्षण शिविरों जैसी अनुमोदित मदों के व्यय के लिये भी सहायता दी जाती है। उन क्षेत्रों में गैर-छात्र युवकों को स्काउटिंग/गाइडिंग में प्रशिक्षण देने के लिये स्काउट्स संघों की सेवाओं का उपयोग करने की संभावनाओं की भी खोज की जा रही है, जहां नेहरू युवक केंद्रों की स्थापना की गई है।

भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली को, जिसने नवम्बर, 1974 में फरीदाबाद में सातवीं अखिल भारतीय जम्बूरी का आयोजन किया था, इस प्रयोजन के लिये एक लाख रुपये का तदर्थ अनुदान दिया गया था। भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स को, सितम्बर, 1974 में ढाका विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रोवर स्काउट सप्ताह में भाग लेने हेतु रोवर स्काउट बंगला देश भेजने के वास्ते भी वित्तीय सहायता दी गई। उन्हें, विश्व बाय स्काउट एसोसियेशन द्वारा क्वालालुम्पुर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं दल पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु अपने सहायक राष्ट्रीय प्रशिक्षण भेजने के लिये भी वित्तीय सहायता दी गई।

(ङ) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

इस योजना के अन्तर्गत, उन अखिल भारतीय स्तर के युवक स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो निम्नलिखित कार्यों में लगे हैं :— राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति, महत्वपूर्ण प्रायोगिक अथवा मार्गदर्शी परियोजनायें, युवा कार्य में अनुसंधान, युवा कार्यों के लिये कार्मिकों का प्रशिक्षण, सम्मेलनों, दौरों, समारोहों, सेमिनारों पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, युवक कल्याण की समस्यायों से संबंधित वर्कशापों, शिविरों अथवा ऐसे किसी अन्य कार्यकलाप का आयोजन जिससे राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करने में सहायता मिलती हो। 1974–75 के दौरान अब तक, 5 निकायों को अनुदान दिया गया है।

सातवां अध्याय

भाषाएं

आलोच्य वर्ष के दौरान शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने, अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के अलावा हिन्दी, अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं और संस्कृत की उन्नति और विकास के लिये पूर्ण सहायता देना जारी रखा। निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रत्येक मद के अन्तर्गत की गयी विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यक्रमों का व्यौरा दिया गया है :—

(क) हिन्दी का प्रसार तथा विकास

अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को अपने-अपने स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। हिन्दी शिक्षण कक्षाएं आयोजित करने, कुछ अन्य कार्यों तथा मैट्रिक से आगे हिन्दी पढ़ने के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिये, अहिन्दी भाषी राज्यों के स्वैछिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए स्वैच्छिक आधार पर हिन्दी सीखने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केन्द्रीय संस्थान, आगरा द्वारा अहिन्दी भाषी छात्रों को हिन्दी पढ़ाने के तरीके का विकास करने; उपयुक्त शिक्षण सामिग्री तैयार करने तथा उच्च शिक्षण प्रशिक्षण शुरू करने का कार्य किया गया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी के माध्यम के रूप में अपनाने के लिये हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली के विकास का कार्य जारी रखा गया तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन और अहिन्दी भाषी राज्यों में पठन सामग्री के मुक्त वितरण को प्रोत्साहित करता रहा। निदेशालय के जरिये विस्तार संबंधी कार्य भी शुरु किया गया और विदेशों में हिन्दी के प्रचार का कार्य जारी रखा गया। मंत्रालय ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा को जनवरी 1975 में नागपुर में विश्व हिन्दी सम्मलन आयोजित करने के लिये सहायता प्रदान की।

(ख) आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रसार

केन्द्रीय भारतीय संस्थान, मैसूर ने उन्नत शिक्षण के तरीके, विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिये उपयुक्त शिक्षण सामग्रियां तैयार करने और अपने क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों में द्वितीय भाषा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का अपना कार्य जारी रखा; विश्वविद्यालयीय स्तर पर शिक्षा के रूप में प्रादेशिक भाषाओं तथा हिन्दी को अपनाए जाने के लिये इन भाषाओं में विश्वविद्यालय के स्तर की पुस्तकों के निर्माण की केन्द्रीय प्रयोजना के माध्यम से प्रोत्साहन दिया गया। अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में श्रेष्ठ कोटि की पुस्तक लिखने के लिये लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए गए ; उर्दू भाषी जनता को आधुनिक ज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध करने के लिये तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के मार्ग दर्शन में उर्दू में शैक्षिक तथा लोकप्रिय साहित्य का निर्माण कार्य जारी रखा गया, सिन्धी में पुस्तकों का निर्माण करने के लिये कार्य-वाही शुरू की गयी थी।

(ग) विदेशी भाषाओं के शिक्षण में सुधार :

केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद ने, जो कि एक विश्व-विद्यालय समझी जाने वाली संस्था है, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षण के सुधरे हुए तरीकों के विकास, इन भाषाओं के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने और विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में काम करने वाले विदेशी भाषा शिक्षकों के सेमिनार आयोजित करने में पर्याप्त प्रगति की। संस्थान के शिलांग स्थित क्षेत्रीय केन्द्र ने अपना कार्य जारी रखा।

(घ) संस्कृति की उन्नति

पांचवीं योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्कृत के व्यापक क्षेत्र में विकास कार्य किया गया। इस अध्याय में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा किये गये विभिन्न कार्यकलापों, निकाले गये प्रकाशनों, स्वीकृत की गयी छात्रवृत्तियों और इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की दी गयी वित्तीय सहायता के संबंध में प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है।

क. हिन्दी का प्रसार तथा विकास

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का शिक्षण

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षण के लिए मंत्रालय निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता रहा (i) अहिन्दी भाषी राज्यों को अपने स्कूलों में हिन्दी

शिक्षकों को नियुक्त करने और अपने हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना; (ii) अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को मैट्रिक से आगे हिन्दी पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियां देना; (iii) एच्छिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देकर हिन्दी शिक्षण की कक्षाओं के आयोजन में उन्हें प्रोत्साहन देना, (iv) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को अपने हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम को जारी रखने और उसके विस्तार के लिये धन राशि देना; (v) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के माध्यम से विभिन्न मातृभाषा वाले व्यक्तियों को हिन्दी पढ़ाने के तरीकों तथा संबंधित विषयों में अनुसंधान आयोजित करना।

अहिन्दी भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता

(i) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति

वर्ष 1973-74 में, चौथी पंचवर्षीय योजना के पूरे हो जाने पर उस योजना के अन्त तक नियुक्त किए गए लगभग 22,000 हिन्दी शिक्षकों की जिम्मेदारी अलग-अलग राज्य सरकारों को हो गयी थी। आलोच्य वर्ष के दौरान धन की तंगी के कारण, इस योजना के लिये केवल 75 लाख रु० का प्रावधान अंतिम रूप से उपलब्ध हो सका। विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों में लगभग 2200 अतिरिक्त हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये विभिन्न राज्यों को अनुदान देने के लिये इस राशि का उपयोग किया गया है। यह योजना अगले वर्ष भी जारी रखी जायगी और लगभग 1500 अध्यापक नियुक्त किये जाने की संभावना है।

(ii) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों/स्कंधों की स्थापना

पांचवीं पंच वर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने वाली यह योजना उसी योजना के क्रम में है जो पिछली पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गई थी। आलोच्य वर्ष के दौरान वर्तमान वित्तीय अभाव के कारण योजना के लिए अन्तिम रूप से केवल 1.50 लाख रुपए का ही प्रावधान उपलब्ध होने की संभावना है। तथापि, इस प्रावधान में से पहले से ही संस्वीकृत 13 अध्यापक कालेजों के अलावा मणिपुर तथा मिजोरम में दो नये अध्यापक कालेज/स्कंध स्वीकृत किए गए हैं।

(iii) हिन्दी के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देना

आलोच्य वर्ष के दौरान मंत्रालय ने अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को उत्तर मैट्रिक स्तर पर हिंदी अध्ययन के लिए 1850 छात्रवृत्तियां प्रदान की। आलोच्य वर्ष के लिए इस योजना के वास्ते 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। पांचवीं योजना के अन्त तक छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर लगभग 2500 तक प्रति वर्ष करने का विचार है।

(iv) स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता

1974-75 के दौरान हिंदी के प्रसार व विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 17 लाख रुपए से अधिक के अनुदान दिए जाने की आशा है। अनुमान है कि विभिन्न संगठन अहिन्दी भाषी राज्यों में 2000 से अधिक हिन्दी कक्षाएं चला रहे हैं। कुछ संगठन हिंदी टाइपराइटिंग कक्षाएं भी चला रहे हैं और हिंदी पुस्तकालय भी खोले हैं।

हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम

पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी अध्यापन की योजना इस क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण योजना है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने इस योजना को कार्यान्वित करना जारी रखा। देश-विदेश दोनों जगहों से इस पाठ्यक्रम में इस समय 6000 छात्र हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 350 थी। इस समय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है किन्तु वर्तमान व्यवस्थाओं का विस्तार करके पांचवीं योजना के दौरान धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं को भी माध्यम के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

(क) अनुसंधान तथा सामग्री का निर्माण

उक्त संस्थान ने विकसित पद्धति तथा सामग्री का प्रयोग करके अहिंदी भाषी छात्रों के लिए हिन्दी अध्यापन को सुविधाजनक बनाने हेतु अध्यापन पद्धति और सामग्री के निर्माण में अनुसंधान करना जारी रखा। संस्थान ने, बेसिक हिंदी रीडर,' द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें, हिंदी शब्दावलियां, स्वर-विज्ञान पुस्तकें, हिन्दी व्याकरण पुस्तकें, हिन्दी रचना संबंधी पुस्तकें, अनुवाद अभ्यास पुस्तकें, वार्ता-अभ्यास पुस्तकें, टेप, हिन्दी

स्वयं शिक्षा पुस्तकें तथा शैलीशास्त्र के विषय में पुस्तकें, आदि के रूप में विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त अध्यापन सामग्री तैयार की। संस्थान ने नागालैण्ड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में प्रयोग करने के लिए भी पाठ्यपुस्तकें, तीव्र रीडर, शब्दावलियां आदि भी तैयार की।

(ख) उच्च अध्यापक प्रशिक्षण

संस्थान ने, अहिन्दी भाषी राज्यों में कार्य कर रहे अध्यापकों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना जारी रखा। 1974 में इस संस्थान से 10 अध्यापकों ने निष्णात (एम०एड० के समकक्ष) परीक्षा में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, इस संस्थान के पारंगत (बी० एड० के समकक्ष) पाठ्यक्रम में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से 60 हिन्दी अध्यापकों ने भाग लिया।

संस्थान, (i) प्रशिक्षार्थी स्नातकों के लिए विस्तृत अध्यापन-एवं-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (ii) मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड के अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए विशेष विस्तृत हिन्दी अध्ययन-एवं-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और (iii) विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए अल्पकालीन उच्च दिक्विन्यास पाठ्यक्रम तथा स्कूल अध्यापकों के लिए अल्पकालीन दिक्विन्यास पाठ्यक्रम, योजनाओं के अन्तर्गत भी अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है। संस्थान ग्रीष्मकालीन भाषायी कार्यक्रम (हिंदी सीखने वालों के लिए विकासात्मक पाठ्यक्रम) तथा भाषा-विज्ञान में डिप्लोमा के पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

(ग) नई दिल्ली कैम्पस में गतिविधियाँ

यह संस्थान गृह मंत्रालय के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विस्तृत हिंदी पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। आलोच्य वर्ष के दौरान 120 अधिकारी प्रशिक्षित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने सचिवालय तथा प्रबन्ध संस्थान के 100 प्रशिक्षार्थियों तथा परिविक्षार्थियों के लिए एक माह का विस्तृत हिन्दी शिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किया। विदेश में हिंदी प्रचार योजना के अन्तर्गत भारत आए 21 विदेशियों के लिए हिन्दी पाठ्यक्रम भी संचालित किए गए।

अन्य गतिविधियाँ

संस्थान ने अनेक उपयोगी हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित कीं। इसने 'क्रियात्मक हिंदी' पर दो-दिन के सम्मेलन का भी संचालन किया। इसके अतिरक्त, इसने देश में हिन्दी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को विशेषज्ञ सहायता देना भी जारी रखा।

अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार

अहिंदी भाषी राज्यों के लेखकों को हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने ऐसे लेखकों द्वारा लिखी गई अच्छी पुस्तकों के लिए पुरस्कार देने की अपनी योजना को जारी रखा क्योंकि सम्पर्क-भाषा के रूप में हिंदी के विकास का विचार ही इस बात का द्योतक है कि अधिक-से-अधिक लोग, जिनकी मातृ-भाषा हिंदी नहीं है, अपनी मातृ-भाषा के अलावा हिन्दी का प्रयोग संचार एवं आत्म-अभिव्यक्ति के लिए करें। आलोच्य वर्ष के दौरान, अहिन्दी भाषी राज्यों के विभिन्न लेखकों को 13 पुरस्कार प्रदान करने का प्रस्ताव है। पहले पुरस्कार का मूल्य 1000/- रु० है तथा दूसरे का मूल्य 500/- रु० है।

पारिभाषिक शब्दावली का विकास

किसी भी भाषा में आवश्यक पारिभाषिक शब्दावली का उपलब्ध होना उस भाषा के आधुनिक ज्ञान तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी के संचार माध्यम होने के लिए पहली जरूरत है। अत: इस प्रयोजन से हिन्दी को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली स्थायी आयोग ने हिन्दी पारिभाषिक शब्दों के विकास तथा उनको अन्तिम रूप देने के अपने कार्य को जारी रखा। आलोच्य वर्ष के दौरान, 17600 कृषि पारिभाषिक शब्दों का समन्वय किया गया। बास्केटबाल तथा वालीबाल की मूल पारिभाषिक शब्दावली के कार्य को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इंजीनियरी पारिभाषिक शब्दावली की 8 शाखाओं का कार्य प्रगति पर है। इनमें लगभग 85,000 तकनीकी शब्द है। एक चिकित्सा-विज्ञान शब्दावली, जिसमें 36,000 चिकित्सा विज्ञान के शब्द, 9500 औषध विज्ञान के शब्द तथा 4500 भौतिक मानव-विज्ञान के शब्द हैं, प्रकाशित की जा चुकी हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न विद्याओं में 2,00,000 तकनीकी शब्दों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

सामान्य पुस्तकों का प्रकाशन एवं उनका प्रचार

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में प्रकाशकों के सहयोग से वर्ष के दौरान अपनी पुस्तक प्रकाशन योजना का कार्यक्रम जारी रखा। इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित की गई पुस्तकों की एक हजार प्रतियां निदेशालय खरीद लेता है और उन्हें नि:शुल्क स्कूलों, कालेजों, और पुस्तकालयों में वितरित करता है। इन योजना के अधीन प्रकाशित की गई पुस्तकों का उद्देश्य जन-साधारण में अद्यतन ज्ञान का प्रचार करना होता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 14 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और वर्ष के अंत तक 16 और पुस्तकों का प्रकाशन होने की आशा है।

निदेशालय ने अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों, कालेजों, संस्थाओं/सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपहार के रूप में वितरित की जाने वाली पुस्तकों को खरीदने की योजना का कार्य जारी रखा। आलोच्य वर्ष के दौरान, ऐसे वितरण के लिए 2 लाख रुपए की पुस्तकें खरीदी गई।

हिन्दी-जर्मन एवं जर्मन-हिन्दी शब्दकोशों की रचना संबंधी कार्य प्रगति कर रहा है। नवम्बर, 1974 में भारत आए दो जर्मन विशेषज्ञ इस काम को सम्पन्न करने में सहायता कर रहे हैं। हिन्दी-चेक तथा चेक-हिंदी शब्दकोशों की रचना संबंधी प्रारंभिक चर्चा भी हुई है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का विस्तार संबंधी कार्य

इस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय पत्राचार पाठ्यक्रम, पुस्तक प्रकाशन एवं उनके प्रचार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त विस्तार संबंधी कार्यक्रमों का भी वर्ष के दौरान कार्यान्वयन करता रहा है। इस निदेशालय ने देश के विभिन्न भागों में अहिंदी भाषी राज्यों के हिंदी लेखकों के अनेक वर्कशाप आयोजित किए तथा प्रसिद्ध हिन्दी लेखकों की भाषा यात्राएं आयोजित कीं। इसने विश्व-हिंदी सम्मेलन, नागपुर में हुई पुस्तक प्रदर्शनी के साथ-साथ देश में पांच और पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया।

विदेशों में हिन्दी का प्रचार

इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष के दौरान, उन विदेशी व्यक्तियों, के लिए जिन्होंने हिंदी पहले ही सीख ली है, अध्ययन सामग्री प्रदान करने

के लिए विदेशों में वितरण के लिए 1,15,000 रुपए की हिंदी पुस्तकें खरीदी गई। मौरिशस सरकार को एक हिंदी प्रैस भी उपहार के रूप में दिया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान मंत्रालय ने करीबियन देशों में काम करने वाले तीन हिंदी लैक्चररों एवं श्रीलंका में दो अंशकालिक रूप में काम करने वाले लैक्चचररों का भी कार्यक्रम जारी रखा। इस योजना के अन्तर्गत दिए गए फैलोशिप के आधार पर दो विद्यार्थी मंगोलिया, चार विद्यार्थी फिजी के, दो गुयना के, एवं एक विद्यार्थी कम्बोडिया का, इस समय भारत में हिंदी अध्ययन कर रहे हैं।

इसी योजना के अन्तर्गत मौरिशस के 20 कलाकारों का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत में आया। इन कलाकारों ने नागपुर में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया।

भारत-जर्मन-जनवादी-जनतंत्र सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन, हम्बोलट विश्वविद्यालय, बर्लिन, जी०डी०आर०, के सहयोग से, व्यापक जर्मन-हिंदी एवं हिंदी-जर्मन शब्दकोषों की रचना के लिए एक परियोजना का कार्य भी आरंभ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त होने वाले अन्य विशेषज्ञ प्रार्थनाओं का भी स्वागत किया जाता है जो हिंदी की प्रोन्नति में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। वर्तमान वर्ष में इस कार्य के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था थी परन्तु आर्थिक कटौती के कारण इसे अब घटाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। आशा की जाती है कि यह राशि पूर्णतः प्रयोग में लाई जाएगी।

हिन्दी शिक्षा समिति

हिंदी के विस्तार एवं विकास के क्षेत्र में यह समिति मंत्रालय को मूल्यवान सलाह देती रही है।

ख. आधुनिक भारतीय भाषाओं को उन्नति

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

संस्थान ने दूसरी भाषा के अध्ययन, अनुसंधान, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री तैयार करने और जनजातीय भाषाओं के अध्ययन के क्षेत्र में अपने शिक्षक प्रशिक्षण के कार्य जारी रखे। भाषा अध्ययन की उन्नति से सम्बन्धित संस्थान के सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वियन को सुविधाजनक बनाना है।

(क) शिक्षक प्रशिक्षण

आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान ने मैसूर, पूना, भुवनेश्वर, पटियाला और सोलन में अपने भाषा प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 13 भारतीय भाषाओं में 261 द्विभाषा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया तथा स्कूल स्तर पर इन भाषाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम बनाया। आगामी सत्र के लिए संस्थान ने विभिन्न राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों से 280 प्रशिक्षित अध्यापकों को अपने विभिन्न केन्द्रों में दाखिल किया। शिक्षक प्रशिक्षण के अपने नियमित कार्यक्रम के अतिरिक्त संस्थाष ने बोली जाने वाली कन्नड़ भाषा में त्रैमासिक पाठ्यक्रम का एक अनुपूरक कार्यक्रम भी आयोजित किया।

(ख) शिक्षण सामग्री की तैयारी

संस्थान में एक शिक्षण सामग्री एकक है जिसकी सहायतार्थ विभिन्न क्षेत्रीय भाषा केन्द्र हैं। तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम और सिंधी में बुनियादी पाठ्यक्रमों के लिए पूर्ण सामग्री वर्ष के अन्त तक प्रकाशन के लिए तैयार हो जाएगी। वर्ष के दौरान असमिया, बंगाली, उड़िया, गुजराती और पंजाबी में बुनियादी पाठ्यक्रमों की तैयारी में महत्वपूर्ण प्रगति होने की आशा है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने 22 पुस्तकें प्रकाशित कीं जिससे संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या 100 हो गई है। प्रकाशित नई पुस्तकों में तमिल, उड़िया, मलयालम तथा अन्य भाषाओं से सम्बन्धित भाषा शिक्षण की पुस्तकें शामिल हैं। सामान्य शब्दावली के क्षेत्र में, संस्थान ने हिंदी-कश्मीरी, हिंदी-तेलगू और हिंदी-उड़िया सामान्य शब्दावलियां तैयार की हैं। संस्थान ने बंगला, देवनागरी, असमिया, उर्दू, गुरुमुखी, तमिल, मलयालम, तेलगु, कन्नड़ तथा त्रिपुरी लिपियों के शिक्षण के लिए फिल्म-पट्टियां तैयार की हैं। संस्थान ने विभिन्न भाषाओं की शिक्षण सामग्री सम्बन्धी बहुत से टेप भी तैयार किए हैं। वर्ष के दौरान संस्थान ने अनेक सेमिनार, वर्कशाप तथा सम्मेलन का आयोजन किया जिनका उद्देश्य (दूसरी भाषा के शिक्षण में) सामग्री तैयार कर और शिक्षण विधि निकालकर संस्थान की मदद करना था।

(ग) जन-जातिय भाषाओं का अध्ययन

किए गए पहले के कार्यों के अतिरिक्त संस्थान ने लुशाई, जनतिया/सिमलिंग और अंगामी के आंकड़े एकत्र किए। मुन्दरी, कुवि, अंगामी

सेमा के ध्वन्यात्मक रीडर प्रकाशित हो चुके हैं। मुन्दरी, त्रिपुरी और ओनागा के व्याकरणों के साथ कुखख, मणिपुरी, बाल्टी, ब्रोकस्टाक और लद्दाखी के ध्वन्यात्मक रीडरों की छपाई हो रही है। ओ-नागा तथा थाडी के शब्दकोशों के साथ एक त्रिमाषी शब्दकोश, जिसमें लद्दाखी भाषा भी है, के शीघ्र तैयार हो जाने की आशा है।

(घ) अन्य कार्यक्रम

संस्थान के अन्य कार्यक्रमों की प्रगति भी जारी रही। इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शुरू की गई माह-भाषा शिक्षण परियोजना, समाज-भाषायी सर्वेक्षण परियोजना, अध्ययन परियोजना, लोक-साहित्य एकक तथा भाषायी-मानचित्रकला के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। संस्थान के पुस्तकालय और भाषा प्रयोगशाला संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में उपयोगी सहायता प्रदान करते रहे।

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन

(क) मुख्य योजना

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर केन्द्र द्वारा आयोजित योजना के पुस्तक प्रकाशन का कार्य 1968-69 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उच्चस्तर शिक्षा के लिए इन भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना है। पिछली योजना के दौरान राज्यों द्वारा की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इस योजना में भाग लेने वाली राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पांचवीं योजना में में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह निर्णय किया गया है कि इस योजना के अधीन पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के कार्यान्वियन के लिए भाग लेने वाले राज्यों को धन-राशि उपलब्ध की जाएगी, बशर्ते कि 1968-69 से किसी राज्य को दिया जाने वाला कुल अनुदान 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

मार्च 1974 के अन्त तक, भाग लेने वाले 15 राज्यों 572.32 लाख रुपए के अनुदान दिए गये। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 2500 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। इनमें से लगभग 500 अनूदित हैं और लगभग 2,000 मौलिक रचनायें

हैं। लगभग 1,000 और पुस्तकें प्रेस में बताई गई हैं। सूचित किया जाता है कि 3,500 और पुस्तकों का कार्य जारी है जो कि लेखन के विभिन्न चरणों में है। इस योजना में लगाई गई पूंजी से लाभ होना शुरू हो गया है और इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री से आय शीघ्र ही 200 लाख रुपये हो जाने की सम्भावना है।

(ख) केन्द्रीय उपयोजनायें

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड-उर्दू में पुस्तकों का प्रकाशन

(i) तरक्की ए-उर्दू बोर्ड

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड की स्थापना आधुनिक ज्ञान, विज्ञान को उर्दू में उपलब्ध करने के ख्याल से, उर्दू में शैक्षिक साहित्य के प्रकाशन से सम्बन्धित मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए ,जून, 1969 में की गई थी। विशेष परामर्श प्राप्त करने के लिए तथा प्रबन्ध करने के प्रयोजन से इस बोर्ड का पुनर्गठन पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ जनवरी, 1974 में किया गया। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में 12 उर्दू जानने वाले विशेषज्ञ और चार अन्य सदस्य शामिल हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, उर्दू और सिन्धी में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, 75 लाख रुपये का विनिधान प्रस्तावित किया गया है। कार्यक्रम के ब्यौरे के लिए, बोर्ड ने एक स्थायी समिति की स्थापना की है। इसमें बोर्ड के सात सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता बोर्ड का अध्यक्ष करता है। बोर्ड को, ब्यूरो फार प्रामोशन आफ उर्दू, जो एक सरकारी संगठन है, द्वारा सचिवालयी सहायता प्रदान की जाती है।

अब तक 57 पुस्तकों का प्रकाशन कर दिया गया है और आशा की जाती है कि 1974–75 के अन्त तक, बोर्ड लगभग 75 पुस्तकों का प्रकाशन कर देगा। संदर्भ पुस्तकों की तैयारी का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके 12 खण्डों में एक उर्दू विश्व कोष, 5 खण्डों में एक उर्दू शब्द-कोष और 5 खण्डों में एक अंग्रेजी-उर्दू शब्द कोष शामिल हैं। पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में, लगभग 10,000 उर्दू तकनीकी शब्दों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। भौतिकी रसायन-शास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षा, इतिहास और राजनीतिशास्त्र, भूगोल और भूगर्भ विज्ञान, सांख्यकी, अर्थशास्त्र और वाणिज्य के विषयों में कार्यचालन पारिभाषिक शब्दावली तैयार कर ली गई है। सुलेखकों के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली, बम्बई और हैदराबाद में तीन सुलेखन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(ii) **सिन्धी की पुस्तकों का प्रकाशन**

उर्दू की तरह सिन्धी भी किसी एक राज्य की भाषा नहीं है। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि सिन्धी की पुस्तकों के प्रकाशन को एक केन्द्रीय योजना की तरह किया जाएगा। पुस्तक जिस लिपि में लिखी जाएगी उसका चुनाव लेखक पर छोड़ दिया गया है। प्रारम्भ में योजना को लागू करने का काम केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को सौंपा गया है।

(iii) **मौलिक पुस्तकों का प्रकाशन**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन के लिए उपयुक्त मानक पुस्तकों का प्रकाशन करना है। ये पुस्तकें प्रारम्भ में अंग्रेजी में और बाद में आवश्यकतानुसार हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जा सकती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के ,अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा की कई पुस्तकों का प्रकाशन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने विज्ञान की मानक पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य शुरू कर दिया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने इतिहास में कुछ चुनी हुई पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद का काम शुरू कर दिया है। इस परिषद् ने भारत में इतिहास के शिक्षण तथा अध्ययन में आवश्यक स्रोत-सामग्री उपलब्ध करने के उद्देश्य से इतिहास में स्रोत-पुस्तकों की तैयारी का काम शुरू कर दिया है और छ: खण्डों में भारत के इतिहास का प्रकाशन भी शुरू कर दिया है। इस इतिहास में भारतीय इतिहास के व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया गया है। लगभग 10 पुस्तकों का प्रकाशन शीघ्र ही होने वाला है।

(iv) **पांडुलिपियां लिखने के लिए फैलोशिप**

यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को लिखने के लिए भारतीय लेखकों को प्रोत्साहन देना है। इस उद्देश्य से इस विषय के युवा विशेषज्ञों को फैलोशिप दी जाती है जिनके अन्तर्गत वे युवक वरिष्ठ प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में काम करके विभिन्न विषयों में मानक पुस्तकें तैयार करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 262 विषयों की अनुमति दे दी है। 26 विषयों की पाण्डुलिपियां शीघ्र ही तैयार हो जाएंगी।

(v) विश्वविद्यालय स्तर की मौलिक मानक पुस्तकों को लिखने के लिए लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

यह योजना विश्वविद्यालय स्तर की उन उत्कृष्ट पुस्तकों को लिखने के लिए लेखकों को सम्मान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो मूलत: भारतीय भाषाओं में लिखी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लेखक को 10,000 रूपये का पुरस्कार दिया जाता है। इस योजना के अंन्तर्गत पहले पुरस्कार सन् 1975 में किसी समय दिए जाएंगे। जिन विषयों तथा भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, उनकी घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कर दी है। यह आयोग इस योजना को लागू कर रहा है।

(vi) कृषि, चिकित्सा तथा इंजीनियरी में हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन

चूंकि चिकित्सा, कृषि तथा इंजीनियरी जैसे तकनीकी विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के काम में विशेष जानकारी की जरूरत होती है, इसलिए इन विषयों में पुस्तकों के प्रकाशन का काम केन्द्रीय रूप से शुरू किया गया है। अब तक इन विषयों में हिन्दी में 46 पुस्तकें तैयार की जा चुकी हैं, 45 पुस्तकें प्रैस में हैं और लगभग 547 पुस्तकों की तैयारी का काम जारी है।

(ग) देश में विदेशी भाषाओं के शिक्षण में सुधार

केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद

यह संस्थान जो कि उच्च अध्ययन की एक संस्था है तथा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय समझा जाता है, इस वर्ष के दौरान अनुसंधान शिक्षण सामग्री के निर्माण विस्तार सेवाओं की व्यवस्था अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा के अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा यूनिटों को सुदृढ़ बनाने के अपने कार्यक्रमों का तेजी से कार्यान्विय किया। शिलाँग स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्र ने भी अपना कार्य तेजी से जारी रखा। अपने अंग्रेजी विभागों के अतिरिक्त संस्थान ने जर्मन, रूसी तथा फ्रेंच विभाग भी स्थापित किए हैं तथा इन विभागों के कार्यक्रमों में संस्थान को जर्मन जनवादी गणतंत्र, सोवियतरूस तथा फ्रांस से इन विभागों के कार्यक्रमों में शैक्षिक सहयोग प्राप्त हो रहा है।

वर्ष के दौरान संस्थान ने जर्मन फ्रेंच तथा रूसी भाषा में शिक्षण के लिए स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों तथा इन भाषाओं में प्रवीणता प्रमाण पत्रों के

9—956 M of Edu. & SW/74

छात्रवृतियां

वर्ष के दौरान संस्कृत पाठशालाओं के 51 छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां दी गई। इनके अतिरिक्त शास्त्री तथा आचार्य के छात्रों को 90 छात्रवृत्तियां दी गई। और मैट्रिक से बाद के विद्यार्थियों को 180 से अधिक छात्रवृत्तियां दी गई।

वितीय सहायता

लगभग 600 एच्छिक संस्कृत संगठनों को और 17 गुरुकुलों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 20 लाख रुपए के अनुदान दिए जाने की संभावना है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

निम्नलिखित पांच केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 15 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई :–

1) कठिन परिस्थितियों में प्रमुख संस्कृत पंडितों को वित्तीय सहायता।
2) संस्कृत पढ़ने वाले उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्तियां।
3) माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण के लिए सुविधाएं।
4) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण।
5) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संस्कृत की उन्नति।

संस्कृत साहित्य

व्यक्तियों/ऐच्छिक संगठनों को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इन कामों के लिए दी गई है। मौलिक संस्कृत ग्रंथों के लिए टीका तथा अनुवाद, महत्व-पूर्ण संस्कृत पुस्तकों का संकलन तथा अनुवाद संस्कृत पांडुलिपियों की सूची का संक-लन तथा प्रकाशन, दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों तथा संस्कृत की पत्रिकाओं का सम्पा-दन तथा प्रकाशन। इनके अतिरिक्त, संस्कृत भाषा तथा साहित्य की दो लाख रुपए की प्रकाशित पुस्तकें खरीदी गई तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को बांटी गई।

संस्कृत के छात्रों के लिए अखिल भारतीय वाक् प्रतियोगिता तथा वैदिक सम्मेलन

संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों के लिए 13वीं अखिल भारतीय वाक् प्रति-योगिता तथा पांचवां वैदिक सम्मेलन 19 से 22 दिसम्बर 1974 के बीच केन्द्रीय

संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति में हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के आठ विषयों में से प्रत्येक में भाग लेने वाले पहले तीन विजेताओं को अलग-अलग पुरस्कार भी दिए गए। वैदिक सम्मेलन में लगभग 60 अध्येताओं ने भाग लिया।

संस्कृत दिवस समारोह

मंत्रालय ने, संसदीय संस्कृत परिषद् तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के सहयोग से, दिल्ली में, अगस्त 1974 में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर संस्कृत दिवस मनाया। देश भर से संस्कृत दिवस समारोहों के बारे में उत्साहजनक रिपोर्टें प्राप्त हुई।

केन्द्रीय संस्कृत परिषद तथा उसकी समितियां

केन्द्रीय संस्कृत परिषद् की विशेषज्ञ समिति की इस वर्ष में दो बैठकें हुई तथा उसने अपनी विशेषज्ञ सलाह दी।

अरबी तथा फारसी

मंत्रालय ने इस वर्ष के दौरान, संस्कृत के अतिरिक्त अरबी तथा फारसी जैसी श्रेण्य भाषाओं के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए दो योजनाएं आरंभ कीं। ये योजनाएं हैं: (1) संस्कृत के अतिरिक्त अन्य श्रेण्य भाषाओं के क्षेत्र में जिनमें अरबी तथा फारसी भी सम्मिलित है, कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता तथा (2) परम्परागत संस्थाओं के छात्रों के लिए अनुसंधान छात्रवृत्तियां। इन दोनों योजनाओं के लिए 0.60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी।

श्री अमाडो महतार'एम० बोव का नाम प्रस्तावित किया । श्री बोव 53वर्षीय सेनेगल-वासी हैं जिन्होंने अपने देश में मंत्री पद पर रहने के बाद 1970 से यूनेस्को के सहायक महानिदेशक के रूप में कार्य किया था । श्री एम० बोव को 14 नवम्बर 1974 को यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में चुना गया । उनके पक्ष में 123 मत पड़े जबकि विपक्ष में केवल एक मत था । अपने प्रथम नीति अभिभाषण में नए महानिदेशक ने कार्य की ऐसी नई पद्धतियां तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिनसे विरल साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने लम्बी-लम्बी बैठकों को यथा-सम्भव कम करने का प्रयत्न किया जा सके । उन्होंने यूनेस्को के गठन की पुनरीक्षा के प्रति भी अपनी इच्छा व्यक्त की जिससे कि उसकी अनभ्यता को कम किया जा सके और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रों को अधिकाधिक प्राधिकार और शक्ति प्रदान करके उसके अधिकारों और कार्यकलापों का और विकेन्द्रीकरण किया जा सके ।

नए महानिदेशक द्वारा दिया गया नीति सम्बन्धी वक्तव्य सामान्यत: भारत सरकार की उस नीति के अनुरूप है जिसे वह यूनेस्को के विभिन्न संगठनों में प्रस्तावित करता रहा है ।

26 अक्तूबर 1974 को दिए गए अपने प्रमुख भाषण में शिक्षा मंत्री, प्रो० एस० नूरुल हसन ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया ।

1) आधुनिक विश्व में प्राकृतिक और मानव साधनों के कुवितरण की समस्या और विकसित तथा विकासशील देशों के बीच अधिकाधिक सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने में यूनेस्को कितना महत्वपूर्ण योग दे सकता है ।

2) समाज शास्त्रीय तथा प्रौद्योगिकीय असन्तुलनों के कारण उत्पन्न नैतिक समस्याओं और मानव के भविष्य के लिए उत्पन्न गम्भीर खतरे; और

3) शैक्षिक पुनर्गठन के कार्यक्रमों के अनिवार्य तत्वों में अनौपचारिक शिक्षा द्वारा दिया जाने वाला महत्वपूर्ण योग ।

महा-सम्मेलन के 15 उपाध्यक्षों में से एक पद के लिए भारत भी प्रत्याशी था और वह चुना गया । इस प्रकार उसने महासम्मेलन के नीति-निर्धारण संगठन के साथ पूर्ण सहयोग और प्रतिनिधित्व के अपने पुराने सम्बन्ध को कायम रखा । भारत यूनेस्को की निम्नलिखित परिषदों अथवा निर्देशन समितियों के लिए भी उम्मीदवार था और उनके लिए चुना गया :–

संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति में हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के आठ विषयों में से प्रत्येक में भाग लेने वाले पहले तीन विजेताओं को अलग-अलग पुरस्कार भी दिए गए। वैदिक सम्मेलन में लगभग 60 अध्येताओं ने भाग लिया।

संस्कृत दिवस समारोह

मंत्रालय ने, संसदीय संस्कृत परिषद् तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के सहयोग से,दिल्ली में,अगस्त 1974 में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर संस्कृत दिवस मनाया। देश भर से संस्कृत दिवस समारोहों के बारे में उत्साहजनक रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

केन्द्रीय संस्कृत परिषद तथा उसकी समितियां

केन्द्रीय संस्कृत परिषद् की विशेषज्ञ समिति की इस वर्ष में दो बैठकें हुईं तथा उसने अपनी विशेषज्ञ सलाह दी।

अरबी तथा फारसी

मंत्रालय ने इस वर्ष के दौरान, संस्कृत के अतिरिक्त अरबी तथा फारसी जैसी श्रेण्य भाषाओं के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए दो योजनाएं आरंभ कीं। ये योजनाएं हैं: (1) संस्कृत के अतिरिक्त अन्य श्रेण्य भाषाओं के क्षेत्र में जिनमें अरबी तथा फारसी भी सम्मिलित है, कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता तथा (2) परम्परागत संस्थाओं के छात्रों के लिए अनुसंधान छात्रवृत्तियां। इन दोनों योजनाओं के लिए 0.60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी।

श्री अमाडो महतार'एम० बोव का नाम प्रस्तावित किया। श्री बोव 53वर्षीय सेनेगल-वासी हैं जिन्होंने अपने देश में मंत्री पद पर रहने के बाद 1970 से यूनेस्को के सहायक महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। श्री एम० बोव को 14 नवम्बर 1974 को यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में चुना गया। उनके पक्ष में 123 मत पड़े जबकि विपक्ष में केवल एक मत था। अपने प्रथम नीति अभिभाषण में नए महानिदेशक ने कार्य की ऐसी नई पद्धतियां तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिनसे विरल साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने लम्बी-लम्बी बैठकों को यथा-सम्भव कम करने का प्रयत्न किया जा सके। उन्होंने यूनेस्को के गठन की पुनरीक्षा के प्रति भी अपनी इच्छा व्यक्त की जिससे कि उसकी अनभ्यता को कम किया जा सके और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रों को अधिकाधिक प्राधिकार और शक्ति प्रदान करके उसके अधिकारों और कार्यकलापों का और विकेन्द्रीकरण किया जा सके।

नए महानिदेशक द्वारा दिया गया नीति सम्बन्धी वक्तव्य सामान्यत: भारत सरकार की उस नीति के अनुरूप है जिसे वह यूनेस्को के विभिन्न संगठनों में प्रस्तावित करता रहा है।

26 अक्तूबर 1974 को दिए गए अपने प्रमुख भाषण में शिक्षा मंत्री, प्रो० एस० नूरुल हसन ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया।

1) आधुनिक विश्व में प्राकृतिक और मानव साधनों के कुवितरण की समस्या और विकसित तथा विकासशील देशों के बीच अधिकाधिक सांमजस्य और संतुलन बनाए रखने में यूनेस्को कितना महत्वपूर्ण योग दे सकता है।

2) समाज शास्त्रीय तथा प्रौद्योगिकीय असन्तुलनों के कारण उत्पन्न नैतिक समस्याओं और मानव के भविष्य के लिए उत्पन्न गम्भीर खतरे; और

3) शैक्षिक पुनर्गठन के कार्यक्रमों के अनिवार्य तत्वों में अनौपचारिक शिक्षा द्वारा दिया जाने वाला महत्वपूर्ण योग।

महा-सम्मेलन के 15 उपाध्यक्षों में से एक पद के लिए भारत भी प्रत्याशी था और वह चुना गया। इस प्रकार उसने महासम्मेलन के नीति-निर्धारण संगठन के साथ पूर्ण सहयोग और प्रतिनिधित्व के अपने पुराने सम्बन्ध को कायम रखा। भारत यूनेस्को की निम्नलिखित परिषदों अथवा निर्देशन समितियों के लिए भी उम्मीदवार था और उनके लिए चुना गया :–

1) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद्,

2) मानव तथा जीव-मण्डलीय कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद्,

3) अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संबंधी कार्यक्रम की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्

4) "यूनिसिस्ट" की नीति निर्धारण समिति, और

5) न्यूबिया में स्मारकों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की कार्यकारी समिति।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के अनुरोध पर महा-सम्मेलन में यूनेस्को के महानिदेशक को, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले संगठनों के बीच, जो कागज की कमी के कारणों और प्रभावों से मुख्य रूप से सम्बन्धित हो, सहयोग स्थापित करने तथा निम्नलिखितों के सम्बन्ध में विश्व कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए प्राधिकृत किया गया :

(क) भावी दशाब्दी के लिए कागज और न्यूजप्रिन्ट के लिए विश्व की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ;

(ख) तत्काल उपलब्ध वैकल्पिक कच्ची सामग्री के आधार पर अतिरिक्त कागज के साधनों के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास; और

(ग) विश्व कागज बैंक की स्थापना जिससे उपलब्ध कागज के भण्डारों का पता लग सके अथवा उसे रखा जा सके ताकि देशों की, विशेष रूप से विकासशील देशों की, तत्कालिक शैक्षिक ,सांस्कृतिक और संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

सम्मेलन की अन्य मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं :–

1) महा-सम्मेलन की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में हंगरी की डा० (श्रीमती) मगडा जौबोरु का चुनाव (संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने के संदर्भ में यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण है)।

2) तीन नए सदस्य देशों, अर्थात् कोरिया जनवादी गणतन्त्र, सान मारिनों और गिनी विसाय् का प्रवेश, इससे यूनेस्को के सदस्य देशों की कुल संख्या 132 से बढ़कर 135 को गई।

शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालेज, नई दिल्ली में निदेशक का कार्यभार छोड़ दिया। पूर्वकालिक निदेशक की नियुक्ति होने तक स्टाफ कालेज में एशियाई कार्यक्रम प्रभाग के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश की नियुक्ति, अपने कार्यों के अतिरिक्त, निदेशक के चालू कार्यों की देखभाल के लिए की गई है। विकास के लिए शैक्षिक अभिनवीकरण के एशियाई केन्द्र, बैंगकाक और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, टोकियो द्वारा 'शिक्षा अभिनवीकरण' पर संयुक्त रूप से आयोजित सेमीनार में श्री वेद प्रकाश 26 अगस्त से 5 अक्तूबर, 1974 तक शामिल हुए थे।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्टाफ कालेज ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया :—

1) शैक्षिक प्रशासन के प्रथम सर्वेक्षण के कार्य की (तीसरे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के भाग के रूप में) प्रगति जारी रही।

2) उत्तर प्रदेश के दो राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए 15 से 17 अगस्त, 1974 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

3) उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उस राज्य के दो वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए इलाहाबाद में 26 अगस्त, से 6 सितम्बर 1974 तक, दो एक-साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

4) यूनेस्को के सहयोग से शिक्षा में जनसंख्या गतिशास्त्र के विशेषज्ञों की चार दिवसीय राष्ट्रीय बैठक 28 से 31 अक्तूबर, 1974 तक हुई थी।

5) शिक्षावृत्तियों के यू० एन० डी० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत अफगानिस्तान के सात शिक्षा अधिकारियों के लिए एक विशेष अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन 11 नवम्बर, 1974 से किया गया था।

6) कालेज ने कई प्रकाशनों को प्रकाशित किया जिनमें (1) इंस्टीट्यूट न्यूज (तीन अंक) और (2) एजूकेशन इनोवेशंस इन इण्डिया——सम एक्सपेरिमेंटस——शामिल थे।

भारत सरकार ने निर्णय किया है कि राष्ट्रीय स्टाफ कालेज, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र जेनेवा के सहयोग से शैक्षिक कार्यों को करने के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। शैक्षिक प्रशासन के लिए राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र के रूप में कालेज का विकास भी किया जा रहा है।

1) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद्,

2) मानव तथा जीव-मण्डलीय कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद्,

3) अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संबंधी कार्यक्रम की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्

4) "यूनिसिस्ट" की नीति निर्धारण समिति, और

5) न्यूबिया में स्मारकों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की कार्यकारी समिति।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के अनुरोध पर महा-सम्मेलन में यूनेस्को के महानिदेशक को, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले संगठनों के बीच, जो कागज की कमी के कारणों और प्रभावों से मुख्य रूप से सम्बन्धित हो, सहयोग स्थापित करने तथा निम्नलिखितों के सम्बन्ध में विश्व कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए प्राधिकृत किया गया :

(क) भावी दशाब्दी के लिए कागज और न्यूज़प्रिन्ट के लिए विश्व की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ;

(ख) तत्काल उपलब्ध वैकल्पिक कच्ची सामग्री के आधार पर अतिरिक्त कागज के साधनों के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास; और

(ग) विश्व कागज बैंक की स्थापना जिससे उपलब्ध कागज के भण्डारों का पता लग सके अथवा उसे रखा जा सके ताकि देशों की, विशेष रूप से विकासशील देशों की, तत्कालिक शैक्षिक ,सांस्कृतिक और संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

सम्मेलन की अन्य मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं :—

1) महा-सम्मेलन की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में हंगरी की डा० (श्रीमती) मगडा जौबोरु का चुनाव (संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने के संदर्भ में यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण है)।

2) तीन नए सदस्य देशों, अर्थात् कोरिया जनवादी गणतन्त्र, सान मारिनों और गिनी बिसायू का प्रवेश, इससे यूनेस्को के सदस्य देशों की कुल संख्या 132 से बढ़कर 135 को गई।

शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालेज, नई दिल्ली में निदेशक का कार्यभार छोड़ दिया। पूर्वकालिक निदेशक की नियुक्ति होने तक स्टाफ कालेज में एशियाई कार्यक्रम प्रभाग के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश की नियुक्ति, अपने कार्यों के अतिरिक्त, निदेशक के चालू कार्यों की देखभाल के लिए की गई है। विकास के लिए शैक्षिक अभिनवीकरण के एशियाई केन्द्र, बैंगकाक और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, टोकियो द्वारा 'शिक्षा अभिनवीकरण' पर संयुक्त रूप से आयोजित सेमीनार में श्री वेद प्रकाश 26 अगस्त से 5 अक्तूबर, 1974 तक शामिल हुए थे।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्टाफ कालेज ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया :–

1) शैक्षिक प्रशासन के प्रथम सर्वेक्षण के कार्य की (तीसरे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के भाग के रूप में) प्रगति जारी रही।

2) उत्तर प्रदेश के दो राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए 15 से 17 अगस्त, 1974 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

3) उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उस राज्य के दो वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए इलाहाबाद में 26 अगस्त, से 6 सितम्बर 1974 तक, दो एक-साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

4) यूनेस्को के सहयोग से शिक्षा में जनसंख्या गतिशास्त्र के विशेषज्ञों की चार दिवसीय राष्ट्रीय बैठक 28 से 31 अक्तूबर, 1974 तक हुई थी।

5) शिक्षावृत्तियों के यू० एन० डी० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत अफगानिस्तान के सात शिक्षा अधिकारियों के लिए एक विशेष अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन 11 नवम्बर, 1974 से किया गया था।

6) कालेज ने कई प्रकाशनों को प्रकाशित किया जिनमें (1) इंस्टीट्यूट न्यूज (तीन अंक) और (2) एजूकेशन इनोवेशंस इन इण्डिया––सम एक्सपेरिमेंटस––शामिल थे।

भारत सरकार ने निर्णय किया है कि राष्ट्रीय स्टाफ कालेज, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र जेनेवा के सहयोग से शैक्षिक कार्यों को करने के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। शैक्षिक प्रशासन के लिए राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र के रूप में कालेज का विकास भी किया जा रहा है।

नवां अध्याय

प्रौढ़ शिक्षा

पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष होने के नाते इस वर्ष के दौरान योजना बनाने, नये दृष्टिकोणों की परिभाषा करने और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने पर विशेष बल दिया गया। वर्तमान योजनाओं को सुदृढ़ बनाया गया।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को पांचवीं योजना के दौरान तीन प्रमुख दिशाओं में कार्यान्वित किया जायेगा तथा सहायक योजनाएं इनका यथा-वश्यक समर्थन करेंगी। ये हैं :–15-25 आयु वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 15 अथवा उससे ऊपर के आयु वर्ग के लिए विकास कार्यकलापों से संबंधित कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, तथा शहरी परि-स्थितियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

यह, पांचवीं योजना में शैक्षिक नीति की प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत एक कार्यक्रम है। चूंकि पूर्णकालिक संस्थागत शिक्षा प्रमुख शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है इसलिए शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी वर्गों तथा शिक्षा के सभी स्तरों के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा प्राप्त व प्रदान करने के लिए अनौपचारिक उपायों का विकास किया जाए। पांचवीं योजना के दौरान, 15–25 आयु वर्ग वाले युवकों के लिए इस दिशा में एक शुरूआत की जा रही है जिन्हें अधिकांशतः उत्पादन कार्य लगे होने, समाज उपयोगी सेवा करने में समर्थ होने, बहुत से सामाजिक कार्यकलापों में लगे होने और इन सबके अतिरिक्त परिवर्तनशील तथा सजग होने के कारण, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। निरक्षर युवक वर्ग को प्राथमिकता दी जायेगी और ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि 60 से 70 लाख युवकों को साक्षर बनाने का लक्ष्य पूरा हो सके। यह कार्यक्रम बहुरूपी विविधरूपी और युवकों की आवश्यकताओं, हितों

(i) नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता

सत्रहवीं प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया और विभिन्न भाषाओं की 28 पुरस्कृत पुस्तकों को एक-एक हजार रुपये के पुरस्कार प्रदान किये गए।

(ii) नवसाक्षरों के लिए साहित्य के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को अनुदान :

वर्ष 1974-75 के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को 2.5 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत किया गया।

(iii) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के जरिए नवसाक्षरों के लिए साहित्य का निर्माण

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए चार लाख रुपये की साक्षरता तथा अनुवर्ती सामग्री खरीदी तथा उसकी आपूर्ति की।

(iv) राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए निरक्षरता उन्मूलन के लिए साक्षरता सामग्री की आपूर्ति

विभिन्न विश्वविद्यालयों के रा० से० यो० यूनिटों को भी साक्षरता सामग्री के सैट सप्लाई किए गए।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

इस योजना के अन्तर्गत उन विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा गया जो प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन, और उत्तर-साक्षरता कार्यक्रमों में लगे हुए थे। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष होने के नाते, इस वर्ष महिलाओं के लिए कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया।

प्रकाशन

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशन निकाले।

नवां अध्याय

प्रौढ़ शिक्षा

पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष होने के नाते इस वर्ष के दौरान योजना बनाने, नये दृष्टिकोणों की परिभाषा करने और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने पर विशेष बल दिया गया। वर्तमान योजनाओं को सुदृढ़ बनाया गया।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को पांचवीं योजना के दौरान तीन प्रमुख दिशाओं में कार्यान्वित किया जायेगा तथा सहायक योजनाएं इनका यथावश्यक समर्थन करेंगी। ये हैं :–15-25 आयु वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 15 अथवा उससे ऊपर के आयु वर्ग के लिए विकास कार्यकलापों से संबंधित कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, तथा शहरी परिस्थितियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

यह, पांचवीं योजना में शैक्षिक नीति की प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत एक कार्यक्रम है। चूंकि पूर्णकालिक संस्थागत शिक्षा प्रमुख शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है इसलिए शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी वर्गों तथा शिक्षा के सभी स्तरों के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा प्राप्त व प्रदान करने के लिए अनौपचारिक उपायों का विकास किया जाए। पांचवीं योजना के दौरान, 15–25 आयु वर्ग वाले युवकों के लिए इस दिशा में एक शुरूआत की जा रही है जिन्हें अधिकांशत: उत्पादन कार्य लगे होने, समाज उपयोगी सेवा करने में समर्थ होने, बहुत से सामाजिक कार्यकलापों में लगे होने और इन सबके अतिरिक्त परिवर्तनशील तथा सजग होने के कारण, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। निरक्षर युवक वर्ग को प्राथमिकता दी जायेगी और ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि 60 से 70 लाख युवकों को साक्षर बनाने का लक्ष्य पूरा हो सके। यह कार्यक्रम बहुरूपी विविधरूपी और युवकों की आवश्यकताओं, हितों

(i) नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता

सत्रहवीं प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया और विभिन्न भाषाओं की 28 पुरस्कृत पुस्तकों को एक-एक हजार रुपये के पुरस्कार प्रदान किये गए।

(ii) नवसाक्षरों के लिए साहित्य के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को अनुदान :

वर्ष 1974-75 के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को 2.5 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत किया गया।

(iii) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के जरिए नवसाक्षरों के लिए साहित्य का निर्माण

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए चार लाख रुपये की साक्षरता तथा अनुवर्ती सामग्री खरीदी तथा उसकी आपूर्ति की।

(iv) राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए निरक्षरता उन्मूलन के लिए साक्षरता सामग्री की आपूर्ति

विभिन्न विश्वविद्यालयों के रा० से० यो० यूनिटों को भी साक्षरता सामग्री के सैट सप्लाई किए गए ।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

इस योजना के अन्तर्गत उन विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा गया जो प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन, और उत्तर-साक्षरता कार्यक्रमों में लगे हुए थे। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष होने के नाते, इस वर्ष महिलाओं के लिए कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया।

प्रकाशन

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशन निकाले।

दसवाँ अध्याय

संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

संघ-शासित क्षेत्रों में शिक्षा को जिम्मेदारी भारत सरकार की विशेष रूप से है। गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी तथा मिजोरम संघ क्षेत्रों के अपने विधानमण्डल हैं तथा वे संघीय क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दिल्ली में एक महानगर परिषद् एवं एक कार्यकारी परिषद है जो दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। अन्य संघ-शासित क्षेत्रों म, अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश में कोई विधानमंडल नहीं है। उपर्युक्त प्रत्येक संघ क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक तथा अन्य संबंधित सुविधाओं का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में शैक्षिक सुविधाएं

इस संघ-शासित क्षेत्र में 201 शैक्षिक संस्थाए हैं जिनमें एक सरकारी डिग्री कालेज, एक अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल, 15 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 30 सीनियर बेसिक स्कूल, 150 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 4 पूर्व-प्राथमिक स्कूल सम्मिलित हैं। इनमें छात्रों की कुल संख्या 25,090 है। अध्यापकों की कुल संख्या 1,331 है जिनमें स 435 महिलाएं हैं। इस द्वीपसमूह में स्कूल शिक्षा निःशुल्क है। मिडिल या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले जो छात्र 4 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं उनको मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। स्कूल के जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 2,500 रु० से कम हो और कालेज के जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 3,000 रु० से कम हो उनको मुफ्त पुस्तकें दी जाती हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 50 रु० प्रति माह की दर से वजीफ़े दिए जाते हैं। होस्टल के प्रत्येक जन-जाति आवासी को 10 रु० प्रति माह की अतिरिक्त राशि दी जाती

10—956MofEdu-&SW/74

है। आठवीं कक्षा तक के छात्रों को 20 पैसे प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस पर दोपहर का भोजन दिया जाता है। मुख्य भूमि पर उच्च शिक्षा के लिए उत्तर-माध्यमिक छात्रवृत्तियां उन विषयों के लिए दी जाती हैं जिनके लिए सरकारी कालेज में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न संस्थानों में प्रशासन ने सीटों के आरक्षण का भी प्रबन्ध किया है। उपरोक्त सुविधाओं से लाभ प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 37,410 है।

शिक्षक प्रशिक्षण

पोर्टब्लेयर में एक शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल है जो प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए अवरस्नातक स्तर पर दो-वर्षीय पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस स्कूल में 82 छात्र दर्ज हैं। पाठ्यचर्या की विषय-वस्तु तथा प्रणाली-विज्ञान पर जोर देकर पाठ्यक्रम को संशोधित कर दिया गया है।

अनसूचित जन-जातियों के लिए शिक्षा

जन-जातियों की आवश्यकताओं के लिए 1851 छात्रों की कुल संख्या के साथ यहां दो उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 6 सीनियर बुनियादी स्कूल, 24 जूनियर बुनियादी स्कूल तथा एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल है।

अरुणाचल प्रदेश

स्कूल शिक्षा

रिपोर्ट के वर्ष के दौरान 5 पूर्व-स्कूल शिक्षा केन्द्र तथा 40 प्राथमिक स्कूल खोले गए थे। 21 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया था तथा 3 मिडिल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक का दर्जा देने से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या 21 हो गई। दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.80 लाख रु० के कुल खर्चे पर 6–14 आयु वर्ग तक के चुने हुए स्कूलों के 1800 छात्र आते हैं। शिक्षा के व्यावसायीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत, कृषि तथा वाणिज्य व्यवसाय 2 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लागू कर दिये गए हैं।

विश्वविद्यालय शिक्षा

जे० एम० कालेज, पासीघाट ही केवल एक ऐसी संस्था है जो बी० ए० स्तर तक कालेज शिक्षा प्रदान करती है। कालेज में विज्ञान में पी० यू० सी० पाठ्यक्रम 1973 से शुरू हुआ था।

अध्यापक प्रशिक्षण

चंगलांग में एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्था है जो प्राथमिक/मिडिल स्कूलों के लिए मट्रिकुलेट अध्यापकों को प्रशिक्षित करती है।

विज्ञान शिक्षा

माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के उपस्करों के लिए 1.30 लाख रु० की यूनिसेफ सहायता मंजूर की गई है।

1973-74 में 34,805 छात्रों के मुकाबले में 42,273 छात्रों को प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की आशा की जाती है।

चण्डीगढ़

इस संघ-शासित क्षेत्र में शिक्षा का विकास प्रगति के पथ पर है।

स्कूल शिक्षा

पूर्व वर्षों की तुलना में विभिन्न स्तरों पर दाखिले में वृद्धि निम्न प्रकार से हुई है:-

स्तर	1973-74	1974-75	वृद्धि
कक्षा 1–v . .	32100	34700	2600
vi–viii . .	13600	14700	1100
ix–x . .	7400	8000	600

सरकारी स्कूलों में दाखिलों की वृद्धि के कारण 73 प्राथमिक अध्यापकों तथा 26 माध्यमिक अध्यापकों के पदों को बनाया गया। एक नया राजकीय आदर्श मिडिल स्कूल शुरू किया गया और एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में दो पालियों को लागू किया गया।

समाज के दुर्बल वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहन

प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों, अधिकतर छात्राओं, तथा गरीब बच्चों को 4 रु० प्रतिमास की उपस्थिति छात्रवृत्तियां

प्रदान की गई हैं। इस स्तर पर 2600 बच्चों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री मुफ्त दी गई थी।

विज्ञान शिक्षा

विज्ञान शिक्षा के सुधार के लिए, यूनिसेफ सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 40 विज्ञान किट तथा मिडिल स्तर पर 21 मिश्रित किट दिए गए हैं।

अनौपचारिक शिक्षा

पारिवारिक हालात के कारण जो व्यक्ति शिक्षा पूरी न कर सके और व्यवसाय में लग गये थे उनको शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 3 सायंकालीन स्कूल शुरू किए गए हैं।

कालेज/शिक्षा

इस स्तर पर दाखिले की संख्या 17600 से बढ़ कर 18000 हो गई है। राजकीय गृह विज्ञान कालेज में वस्त्र तथा वस्त्र उद्योग में एम० एस० सी० की कक्षायें प्रारम्भ की गई हैं।

छात्रवृत्तियां

मिडिल स्तर पर योग्यता एवं साधन की 10 नई छात्रवृत्तियां तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 10 छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं।

दादर तथा नागर हवेली

शैक्षिक सुविधाएं

इस संघशासित क्षेत्र में 4 पूर्व-प्राथमिक स्कूल, 157 प्राथमिक स्कूल और 4 हाई स्कूल हैं। एस० एस० सी० ई० स्तर तक सभी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 4 पूर्व-प्राथमिक स्कूलों सहित सभी राजकीय प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को मध्याह्न भोजन निःशुल्क दिया जाता है। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, नोट्स, स्लेटें आदि देने की सुविधा का विस्तार करके सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के छात्रों पर भी लागू कर दिया गया है। प्राथमिक स्कूलों

में ऐसे छात्रों को कपड़े भी मुफ्त दिये जाते हैं, वार्षिक निरीक्षण के पश्चात् प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों की चिकित्सा सेवा भी निःशुल्क की जाती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध है। 8 सरकारी सामाजिक कल्याण छात्रावास हैं जिनम 16 लड़कियों सहित कुल संख्या 463 है। इन छात्रावासों में रहने और भोजन का सारा खर्चा प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। दो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं और चालू वर्ष के दौरान एक नया पुस्तकालय खोलने का विचार है। सभी केन्द्रीय प्राथमिक स्कूलों और हाई स्कूलों में पुस्तकालय हैं।

छात्रवृत्तियां

आलोच्य वर्ष के दौरान, 3 पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, 11 उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, 3 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां और 2 राष्ट्रीय ऋण छात्र-वृत्तियां मंजूर की गई थीं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर ने दो हाई स्कूलों में वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों को जारी रखा। इसमें 166 लड़कियों सहित छात्रों की संख्या 346 थी।

प्रयुक्त पोषण कार्यक्रम

ऐसे 11 प्राथमिक स्कूल हैं जहां विकास खण्ड द्वारा प्रयुक्त पोषण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा व्यावसायीकरण

सभी चारों हाई स्कूलों में व्यावसायिक, तकनीकी और कृषि विषयों को लागू कर दिया गया है।

दिल्ली

स्कूल शिक्षा

बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली में स्कूल शिक्षा की सुविधाओं में और विस्तार किया गया है।

वर्ष के दौरान 20 नये उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 12 मिडिल स्कूल तथा 50 प्राथमिक स्कूल खोले गए थे। दाखिले की प्रतिशतता भी 6–11 आयु वर्ग में 97.9 प्रतिशत, 11–14 आयु वर्ग में 86.1 प्रतिशत तथा 14–17 आयु वर्ग में 64.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

विश्वविद्यालय शिक्षा

दिल्ली प्रशासन के अधीन 15 डिग्री कालेज कार्य कर रहे हैं तथा उन सभी छात्रों को जो प्रवेश पाने के पात्र हैं, दाखिल करने के लिए इन कालेजों में स्थानों की संख्या बढ़ा दी गई है ।

प्रौढ़ शिक्षा

दो सांयकालीन उच्चतर माध्यमिक स्कूल और शुरू करने से इन स्कूलों की संख्या 12 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 4,540 व्यक्तियों के लिए, जो स्कूलों में नहीं जा सकते, मैट्रीकुलेशन तथा उच्चतर माध्यमिक में पत्राचार पाठ्यक्रम का भी प्रबन्ध किया गया है ।

मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की सप्लाई

4.5 लाख रु० को पाठ्य-पुस्तकें उन छात्रों को मुफ्त दी गई हैं, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 300 रु० से कम है । पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो ने 13 पाठ्य-पुस्तकों की 11 लाख प्रतियां प्रदान की हैं ।

भवन

नये निर्माण पर प्रतिबन्ध होने से केवल अधूरे भवनों को पूरा किया गया, जिसमें शिक्षण-भवन, व्यायामशाला और आवासीय क्वार्टर सम्मिलित हैं ।

लड़कियों की शिक्षा

जहां लड़कियों की संख्या अधिक हो वहां अलग स्कूल खोले जाते हैं । लड़कियों के लिए 7 उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा 3 सह-शिक्षा स्कूल शुरू किए गए थे । ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा प्रदान की जाती है । इस समय 105 गांवों में 2100 लड़कियां यह सुविधा प्राप्त कर रही हैं ।

विज्ञान शिक्षण

298 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण की सुविधाएं हैं ।

छात्रवृत्तियां

26 छात्रवृत्ति की योजनाएं है जिनमें सभी योग्य छात्र आ जाते हैं ।

शिक्षक कल्याण

प्रत्येक वर्ष 10 अध्यापकों को जिनकी सेवाएं सराहनीय होती हैं राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ।

टेलीविजन

दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जो टेलीविजन द्वारा शिक्षा प्रदान करता है । यह सुविधा 424 उच्चतर माध्यमिक तथा 86 मिडिल स्कूलों में उपलब्ध है । एक टलीविजन प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है ।

कोटि सुधार

उन स्कूलों में कक्षा पांच के लिए नई विज्ञान पुस्तकें प्रदान की गई हैं जहां विज्ञान यूनिसेफ की एक परियोजना के अनुसार पढ़ाया जाता है । प्राथमिक स्कूलों को विभिन्न विषयों में 162 किट बांटे गए थे । 100 छात्रों को जूनियर विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी ।

गोआ, दमन तथा दीव

शैक्षिक सुविधाएं

इस संघशासित क्षेत्र में आठवीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त है । अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों को नवीं से ग्याहरवीं कक्षाओं में भी शुल्क न देने की छूट दी जाती है ।

प्राथमिक स्तर पर 1132 स्कूल हैं जिनमें छात्रों की कुल संख्या 1,25,000 है । मिडिल स्तर पर 362 स्कूल हैं जिनमें छात्रों की कुल संख्या 49,750 है । माध्यमिक स्तर पर 220 स्कूल हैं जिसमें एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल है । उनमें छात्रों की कुल संख्या 35,900 है । इस संघशासित क्षेत्र में 10+2+3 की नयी पद्धति कार्यान्वित हो रही है । इसके अन्तर्गत नई वरिष्ठ स्कूल प्रमाण-पत्र (एम० एस० सी०) कक्षा दसवीं के छात्रों की पहली टोली अप्रैल 1975 में परीक्षा में बैठेगी । नई द्वि-वर्षीय उच्चतर माध्यमिक कक्षा 1975-76 से लागू होगी तथा इस प्रयोजन से 6 नये उच्चतर माध्यमिक स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव है ।

कुल 8,866 छात्रों के साथ यहां 14 कालेज और एक स्नातकोत्तर केन्द्र है। यहां 45 छात्रों का एक संस्थान भी है जो पाक-शास्त्र, बेकरी तथा भोजन-कला, बुक-कीपिंग के पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

लड़कियों की शिक्षा

लड़कियों में शिक्षा के प्रसार के लिए गरीब वर्गों की लड़कियों को स्कूल की वर्दी, स्लेटें और किताबों के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष के दौरान 2,250 लड़कियों के लाभ के लिए 90,000 रु० की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

विज्ञान-शिक्षण

उच्च कक्षाओं में विज्ञान तथा गणित को पढ़ाने के लिए अध्यापकों के मार्ग-दर्शनार्थ इन विषयों के निरीक्षक के पदों को बनाया गया है।

छात्रवृत्तियां तथा अन्य रियायतें

50 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां, 35 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां, 15,000 वजीफे, 10 योग्यता छात्रवृत्तियां तथा 35 छात्रवृत्तियां संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रदान की गई हैं।

शिक्षक-प्रशिक्षण

प्रत्येक वर्ष 100 अप्रशिक्षित राजकीय अध्यापकों के दाखिले सहित प्राथमिक अध्यापकों के लिए राजकीय कालेज में दो-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। निजी प्रबंध के अन्तर्गत एक माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण कालेज है जो डिप्लोमा, बी०एड० तथा एम० एड० पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं

ऐसे छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त, मिडिल तथा सेकेन्डरी कक्षाओं के छात्रों को पुस्तकें तथा वर्दियां खरीदने के लिए वजीफे दिए जाते हैं। एक नयी योजना के अंतर्गत, सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तीनों स्तरों पर पुस्तकें तथा वर्दियां खरीदने के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव है। कालेजों में तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 35 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

215 प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र खोले गये थे और 7,000 प्रौढ़ों को दाखिल किया गया था ।

लक्षद्वीप

शैक्षिक सुविधाएं

द्वीप में, 41 शैक्षिक संस्थाएं है । जिनमें 1 जूनियर कालेज, 1 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 6 हाई स्कूल, 7 सीनियर बेसिक स्कल, 17 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 9 नर्सरी स्कूल शामिल हैं । छात्रों की कुल संख्या 8600 है जब कि वर्ष 1973-74 में यह संख्या 8092 थी । शिक्षकों की संख्या 384 है जब कि वर्ष 1973-74 के दौरान उनकी संख्या 359 थी । इस संघशासित क्षेत्र में पूर्व डिग्री तक की शिक्षा के लिए सुविधाएं विद्यमान हैं ।

लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं

3 सीनियर बेसिक स्कल तथा 1 जूनियर बेसिक स्कूल केवल लड़कियों के लिए ही हैं । कालपेनी स्थित हाई स्कूल में लड़कियों के लिए, हाई स्कूल कक्षाओं के लिए एक अलग सेक्शन है । उच्चतर माध्यमिक तथा कालेज छात्रों के लिए लड़कियों के 2 छात्रावास कावारत्ती मे प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं । इन छात्रावासों में आवास और भोजन की मुफ्त व्यवस्था है । स्कूलों में 8,600 छात्रों में से 3,340 छात्राएं हैं ।

विज्ञान शिक्षण के लिए सुविधाएं

सभी स्कूलों में सामान्य विज्ञान एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है । विज्ञान प्रतिभा खोज योजना उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कार्यान्वित की गई है । विज्ञान शिक्षकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका संचालन राज्य शिक्षा संस्थान केरल द्वारा किया जाता है ।

छात्रवृत्तियां तथा अनुदान

उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना को जारी रखा जा रहा है । जनवरी, 1975 से छात्रवृत्तियों की दरें तथा अनुदान बढ़ा दिए गए हैं । सभी स्तरों पर शिक्षा नि.शुल्क है । विश्वविद्यालय तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए मुख्य भूमि की

संस्थाओं में स्थान आरक्षित हैं । छात्रवृत्तिधारियों की कुल संख्या 748 है, जिसके अन्तर्गत भारत में अध्ययन के लिए 98 छात्रवृत्तिधारी भी शामिल हैं । अपने द्वीपों के अलावा अन्य द्वीपों में अध्ययन कर रहे छात्रों के निःशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें और लेखन सामग्री निःशुल्क दी जाती है । पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और मिडिल स्कूल कक्षाओं में निःशुल्क मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है ।

अध्यापक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं

प्रशिक्षण के लिए छात्रों को मुख्य भूमि की संस्थाओं में भेजा जाता है ।

अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं

इस क्षेत्र के रहने वाले लोग मस्लिम हैं जिनको अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाएं केवल उनके लिए ही होती हैं ।

प्रौढ़ साक्षरता

समाज शिक्षा प्रायोगिक परियोजना योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये जाते हैं । सभी द्वीपों में वाचनालय व पुस्तकालयों की स्थापना की गई है ।

अन्य विकास कार्यकलाप

तीन नये नर्सरी स्कूल प्रारम्भ किय गये हैं । चार फीडर स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर जूनियर बुनियादी स्कूलों का कर दिया गया । प्राथमिक स्कूलों में अरबी भी पढ़ाने का प्रस्ताव है । अतिरिक्त दाखिले से निपटने के लिये छः और मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है । एक सीनियर बुनियादी स्कूल का दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल का करने का विचार है । इस प्रकार हाई स्कूलों की कुल संख्या सात हो जाएगी । टाइपिंग और मत्स्य प्रौद्योगिकी के साथ ही साथ संगीत और नृत्य को भी हाई स्कूलों में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

मिज़ोरम

यह संघशासित क्षेत्र जनवरी 1972 में स्थापति हुआ। तब से शिक्षा के क्षेत्र में विकास के कार्य को तेज करने के लिए काफी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं।

इस क्षेत्र में 93 हाई स्कूल हैं, जिनमें से 83 प्राईवेट तौर पर संचालित किए जाते हैं, 208 मिडिल स्कूल हैं जिनमें से 140 प्राईवेट तौर पर संचालित किए जाते हैं और 457 निम्न प्राथमिक स्कूल हैं जिनमें से 31 गैर-सरकारी संस्थाएं हैं। प्राईवेट तौर पर संचालित संस्थाओं को अपनी भौतिक सुविधाओं में सुधार लाने और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाता है।

इस क्षेत्र में तीन कालेज हैं (1 सरकारी और दो गैर-सरकारी)। ये कालेज पहले गोहाटी विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, अब ये नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के क्षेत्राधिकार में आ गए हैं।

बड़ी संख्या में प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूलों में स्काउटों और गाइडों का काम आरम्भ किया गया है। अनेक शारीरिक दक्षता परीक्षण केन्द्र खोले गए हैं और युवक एवं कल्याण कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।

अनुसुचित जातियों/जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिए वजीफों/छात्रवृत्तियों के लिए केन्द्रीय अनुदान की मात्रा में वृद्धि की गई है जिससे कि यह क्षेत्र सभी योग्य उत्तर-मैट्रिक छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सके।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एज़िल का नया भवन तैयार है और संस्थान मार्च 1975 से पहले ही अपने भवन में आ जाएगा।

शिक्षा निदेशालय से आर्थिक सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित नये साक्षरता केन्द्रों की सहायता से 18-45 आयु वर्ग के 1,849 अशिक्षित प्रोढ़ों को शिक्षित किया गया।

हिंदी के प्रचार के लिए एक अलग विंग शुरू किया गया। अनेक हाई और मिडिल स्कूलों में हिंदी-पुस्तकालय खोले गए। 17 स्नातक और

47 पूर्व-स्नातक शिक्षकों ने अपना हिन्दी प्रशिक्षण पूरा किया और विभिन्न स्कूलों में उनको नियुक्त किया गया। वर्तमान दोनों ही संस्थानों में भरती की संख्या में वृद्धि द्वारा और वर्तमान एक-वर्षीय पाठयक्रम के स्थान पर दो-वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्रारंभ करके प्राथमिक स्कूल प्रशिक्षण का पुनर्गठन किया गया। एक बी० एड० प्रशिक्षण संस्थान का आरंभ 1974-75 में हो रहा है।

पाण्डिचेरी

प्राथमिक शिक्षा

3-5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए दो पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं। 6-11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 40 अतिरिक्त/नयी कक्षाएं तथा 60 मिडिल स्कल कक्षाएं (6 से 8) शुरू की गई हैं। बच्चों की नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने और शिक्षण के स्तर में सुधार करने के लिए 20,000 गरीब एवं योग्य बच्चों को बस्ते, स्लेट, पेंसिल आदि लेखन-सामग्री निशुल्क: प्रदान की गई है। विशेष पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 43,000 गरीब बच्चों को दोपहर का भोजन दिया गया है। यूनीसेफ की सहायता से 450 माध्य-मिक ग्रेड के शिक्षकों के अनुस्थापन/सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा विज्ञान और गणित के विषयों के शिक्षण को सुधारा गया।

माध्यमिक शिक्षा

स्कूल की सुविधाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2 नए हाई स्कूल और 21 अतिरिक्त कक्षाएं (9 से 11 तक) शुरू की गई थीं। दो हाई स्कूलों को विज्ञान के उपस्कर, पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें और फर्नीचर दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों के आठ हाई स्कूलों में विज्ञान क्लब और चार हाई स्कूलों में बुक बैंक स्थापित किए गए।

विश्वविद्यालय शिक्षा

सात कालेजों में और कक्षाएं/पाठ्यक्रम शुरू करके इस क्षेत्र की सु-विधाओं में विस्तार किया गया। गरीब एवं योग्य छात्रों के लिए 125 नयी छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गईं।

तकनीकी शिक्षा

इस संघशासित क्षेत्र में दो तकनीकी शिक्षण संस्थाएं कार्य कर रहीं हैं। इन संस्थाओं में रेडियो यांत्रिकी का एक नया पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। मोतीलाल नेहरू पालिटैकनिक, पांडिचेरी में भर्ती की संख्या को 140 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है।

खेल और युवक कल्याण के कार्यक्रम

शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत एक पृथक शारीरिक शिक्षा निरीक्षणालय कार्य कर रहा है।

अन्य शैक्षिक कार्यक्रम

इस संघशासित क्षेत्र का गजेटियर प्रकाशित करने के लिए एक गजेटियर एकक स्थापित किया गया है। गजेटियर के मसौदे की संवीक्षा की जा रही है और 1975-76 में इसके प्रकाशित होने की संभावना है।

विज्ञान शिक्षा

यूनीसेफ की सहायता से स्कूलों में विज्ञान और गणित की शिक्षा के सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 20 प्राथमिक और 30 उच्च प्राथमिक स्कूलों को सम्मिलित किया गया है। विज्ञान के उपकरणों के 85 सेट स्कूलों को दिए गए थे। यूनीसेफ द्वारा 162 रीम छपाई का कागज भी विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकें छापने और बच्चों में उनके निःशुल्क वितरण के लिए दिया गया।

ग्यारहवां अध्याय

निकासी गृहकार्य

शिक्षा के क्षेत्र में, केन्द्रीय सरकार का एक मुख्य कार्य सूचना के के निवासी गृह के रूप बें कार्य करना है। तदनुसार यह देश भर के शैक्षिक आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त, यह शिक्षा और संस्कृति के विषय में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में पत्रिकाएं तथा अन्य प्रकाशन निकालना है जिसमें से अधिकांश मंत्रालय के कुछ चुने हुए कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में होते हैं। मंत्रालय एक छात्र सूचना सेवा का संचालन करता है जो भारत और विदेश में उच्च शिक्षा की सुविधाओं के बारे में पूछताछ का उत्तर देता है।

इस अध्याय में इस क्षेत्र के अन्तर्गत किए जाने वाले भिन्न भिन्न क्रिया-कलापों तथा केन्द्रीय स्तर पर हुए मुख्य सम्मेलनों और बैठकों का विवरण दिया गया है।

राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों और शिक्षा/उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा निदेशकों का सम्मेलन

राज्यों तथा संघशासित क्षत्रों के शिक्षा सचिवों और शिक्षा/उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा के निदेशकों का सम्मेलन, साधनों पर पड़ रहे काफी दबाव के संदर्भ में शैक्षिक विकास के लिए अपनायी जाने वाली नीति के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सिफारिशें करने के लिए 1-3 नवम्बर, 1974 को हुआ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 37वीं बैठक

यह बैठक नई दिल्ली में 4 तथा 5 नवम्बर, 1974 को हुई थी और इसमें अन्यों के अतिरिक्त बोर्ड के सभी सदस्य, राज्यों के शिक्षा मंत्री, सदस्य (शिक्षा) योजना आयोग तथा श्री ओम मेहता, गृह मंत्रालय

में राज्य मंत्री, उपस्थित थे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रधान मंत्री ने, संसाधनों की वर्तमान कमी के संदर्भ में कार्य के महत्व पर बल दिया। बैठक का ब्यौरा इस रिपोर्ट के अध्यायों के पूर्व प्रारंभिक विवरण में दिया गया है।

शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी सलाहकार समिति

शैक्षिक और सांस्कृतिक आंकड़ों की वर्तमान सांख्यिकी प्रणाली की कमियों पर विचार करने के उद्देश्य से शैक्षिक और सांस्कृतिक सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में 30 अप्रैल तथा 1 मई, 1974 को हुई। बैठक में शैक्षिक आंकड़ों के संकलन में सुधार लाने के लिए बहुत से संशोधनों का सुझाव दिया गया। इन अस्थायी सिफारिशों की निकट भविष्य में होने वाले राज्य के सांख्यिकी अधिकारियों के सम्मेलन के सम्मुख रखा जाएगा।

प्रशिक्षण पाठ्क्रम

जिला तथा प्रभागीय स्तरों पर शैक्षिक सांख्यिकी के संकलन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए उज्जैन में सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करके मध्य प्रदेश सरकार की सहायता की।

त्वरित कार्यक्रम

शैक्षिक आंकड़ों के संकलन के बकाया कार्य के त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत, मंत्रालय के अधिकारियों ने, शैक्षिक आंकड़ों के शीघ्र तथा स्थान पर ही संकलन तथा अन्तिम रूप देने के लिए असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल-राज्यों तथा संघशासित अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। मंत्रालय के अधिकारी, शैक्षिक आंकड़ों का स्थान पर ही संकलन तथा समायोजन करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को बंगलौर, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, कर्नाटक, मदुरै, मैसूर, उत्तरी बंगाल तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों में भजा गया। इसके अतिरिक्त, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली संघशासित क्षेत्र ने अपने-अपने अधिकारियों को स्थान पर ही आंकड़ों के समायोजन व अन्तिम रूप देने के लिए शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में प्रतिनियुक्त किया।

प्रकाशन :

मंत्रालय के सांख्यिकी प्रभाग ने शैक्षिक सूचना तथा सांख्यिकी के विषय में मुद्रित और मिमियोग्राफ्ड रूप में 12 प्रलेख प्रकाशित किए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रकाशन एकक ने 23 प्रकाशन प्रकाशित किए। इसमें मंत्रालय की पत्रिकाएं 'दि एजूकेशन क्वाटरली', 'शिक्षा विवेचन' तथा 'संस्कृति' शामिल हैं।

छात्र सूचना एकक :

छात्र सूचना सेवा एकक ने, देश में छात्र सलाहकार ब्यूरो एवं छात्रों को मार्गदर्शी शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। इसने, भारत एवं विदेश में उच्च शिक्षा की सुविधाओं सम्बन्धी लगभग 7,350 पूछताछों का उत्तर दिया। भारत और विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के पाठ्य-विवरणों तथा केलैन्डरों का अध्ययन करने के लिए लगभग 2000 व्यक्तियों ने एकक के संदर्भ पुस्तकालय का दौरा किया। भारत तथा विदेश में उच्च अध्ययन की सुविधाओं की उपयोगी सामग्री के संकलन तथा संशोधन का कार्य जारी रहा। आलोच्य वर्ष के दौरान भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा के विषयों/विभिन्न प्रसंगों से संबंधित 80 संकलन प्रकाशित/संशोधित किए गए। भारत तथा विदेश से संबंधित नवीन कलेन्डरों, पाठ्यविवरणों तथा अन्य संदर्भ साहित्य को सम्मिलित करके एकक के सन्दर्भ पुस्तकालय में 672 संकलनों की वृद्धि की गई। विभिन्न विश्वविद्यालयों से संलग्न कुछ छात्र परामर्श ब्यूरों को उन्हें छात्रों से प्राप्त होने वाली पूछताछों से निपटने में सहायता करने हेतु जानकारी देने वाली सामग्री भी भेजी गई।

कागज की स्थिति :

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कागज की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह मंत्रालय, उद्योग तथा पूर्ति मंत्रालय के माध्यम से भारतीय मिलों से कागज प्राप्त करने में, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सहायता कर रहा है ताकि छात्रों को उचित दामों पर पाठ्यक्रम पुस्तकें तथा कापियां उपलब्ध हो सकें। उद्योग तथा पूर्ति मंत्रालय, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए, मिलों से रियायती दरों पर कागज आवंटित करने के लिए सहमत हो गया है।

31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंत्रालय ने, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा विश्वविद्यालयों को विभिन्न प्रयोजनों, जैसे स्कूली पाठ्य पुस्तकों, कापियों, स्कूल परीक्षाओं, निजी प्रकाशकों, ग्रन्थ अकादमियों, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए 68669 टन कागज आवंटित किया है।

संस्कृति विभाग

11—956 M of Edu & SW/74

पहला अध्याय

सांस्कृतिक कार्य

संस्कृति विभाग की प्रमुख संस्थाएं तथा कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगी अन्य संस्थाएं ।

(2) सांस्कृतिक करार, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, देश में आने वाले तथा देश से बाहर जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल ।

(3) शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक संस्थाओं को भवन अनुदान, कालेजों और स्कूलों के विद्यार्थियों में संस्कृति का प्रसार तथा नृत्य, नाटक और रंगमंच मंडलियों को वित्तीय सहायता ।

(4) सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां तथा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना; और

(5) गजेटियर

साहित्य अकादमी

अकादमी ने 13-3-1974 को अपने 20 वर्ष पूरे कर लिए तथा इस अवसर के उपलक्ष्य में 12 से 18 मार्च, 1974 तक रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी भाषाओं के सभी प्रकाशनों तथा पुस्तकों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई । पुरस्कार विजेताओं की एक विचार-गोष्ठी भी 19 मार्च, 1974 को आयोजित की गई ।

दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, साहित्य अकादमी के प्रथम सम्मानिक सदस्य के रूप में सेनेगल के राष्ट्रपति, परमश्रेष्ठ लियोपोल्ड सेदार सेंघोर का चुना जाना । नई दिल्ली में, 21-5-1974 को अयोजित एक समारोह में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्‌वारा सुविख्यात कवि तथा राजनेता को सदस्यता मंजूषा प्रदान की गई ।

अकादमी की महापरिषद् की 28-2-1974 को हुई बैठक में चार अन्य नये सदस्यों, अर्थात प्रो० वी० आर० त्रिवेदी, डा० मस्ती वेंकटेशआयेंगर, डा०

सुकुमार सेन तथा प्रो० बी. बी० मिराशी को भी चुना गया था। सूरत में 13-10-1974 को हुए एक विशेष फैलोशिप समारोह में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० यशवंत शुक्ल ने प्रो० बी० आर० त्रिवेदी को फैलोशिप प्रदान की।

वर्ष के दौरान अकादमी ने अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने अनौपचारिक साहित्य फोरम की बहुत सी बैठकें आयोजित की। अकादमी के विभिन्न कार्यालयों ने भी अनेक भाषाओं में कुल मिलाकर 27 प्रकाशन निकाले हैं। इनमें "इंडियन लिट्रैचर" नामक त्रैमासिक पत्रिका के दो दोहरे अंक भी शामिल हैं।

यूनियन एकेडेमिक इन्टरनेशनल के 48वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए उप-सचिव (कार्यक्रम), डा० बी० बी० अग्रवाल को अकादमी द्वारा 16 से 22 जून 1974 तक ब्रसेल भेजा गया।

साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड ने 1974 के अकादमी पुरस्कार प्रदान करने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं की 17 पुस्तकों का चयन किया। पुरस्कार विजेताओं के नाम हैं :— श्री सौरभ कुमार चालिहा (असमिया), श्री नीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती (बंगला), प्रोफेसर, मदन मोहन शर्मा (डोगरी), श्री अनन्तराय एम० रावल (गुजराती), डा० शिव मंगल सिंह 'सुमन' (हिन्दी) श्री एम० गोपालकृष्ण अडिबा (कन्नड़), श्री वेनीकुलम गोपाल कुरूप (मलयालम), श्री एम० कुन्जमोहन सिंह (मैनपुरी), श्री वी० वी० शिरवाडकर (मराठी), श्री सीताकान्त महापात्र (उड़िया), श्री सोहन सिंह शीतल (पंजाबी), श्री विजय दत्त देत्हा (राजस्थानी), डा० एस० वी० वार्नेकर (संस्कृत), श्री लाल पुष्प (सिन्धी), श्री के० डी० थिरूनावाक्करसू (तमिल), श्री दासार्थी (तेलुगू) तथा प्रोफेसर अली अहमद सरूर (उर्दू)। पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार 28 फरवरी, 1975 को आयोजित समारोह में प्रदान किये गये।

ललित कला अकादमी

दृश्य तथा प्लास्टिक कला की उन्नति के लिए ललित कला अकादमी को 1954 में स्थापित किया गया था। हालांकि अकादमी के उद्देश्य विस्तृत हैं, तथापि इसमें प्रकाशन और प्रदर्शनियों पर ज़ोर दिया गया है। इसने प्राचीन भारतीय कला पर बहु प्रशंसित विनिबंध-माला प्रकाशित की है तथा अपनी पत्रिकाओं में भारतीय कला में नए अनुसंधानों के निष्कर्षो को प्रकाशित किया है। इस संस्था ने हाल ही में बड़ी मात्रा म चित्रों की रंगीन अनुकृतियां देना भी शुरू कर दिया है।

पिछले वर्ष की सर्वोत्तम कृतियों को प्रस्तुत करने के लिए अकादमी वार्षिक राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करती है। तीन वर्षों में एक बार यह त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करती है। पिछले त्रैवार्षिक प्रदशनी में जो कि 1971 में आयोजित की गई थी, चालीस देशों ने भाग लिया था। फरवरी, 1975 में होने वाली तीसरी त्रैवार्षिक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए लगभग 23 देशों ने सहमति प्रकट की है।

देश में तथा विदेशों में आयोजित महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में, जिनमें अकादमी ने भाग लिया, निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(1) फ्लोरेन्स में मई-जून, 1974 में हुए चौथे द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेखाचित्रकला प्रदर्शन में भारत के भाग के रूप में जय कृष्ण ज्योति भट्ट, जगमोहन चोपड़ा तथा अनुपम सूद की कृतियों के 18 रेखाचित्र भेजे गए। जयकृष्ण ने अपने रेखा-चित्रों पर स्वर्ण-पदक प्राप्त किया।

(2) बहुरंगीय अनुकृति तथा रेखा-चित्रों की एक प्रदर्शनी अगरतला में आयोजित की गई।

(3) नई दिल्ली स्थित आस्ट्रेलियाई उच्च आयोग तथा ललित कला अकादमी ने मिलकर आस्ट्रेलिया के सुविख्यात कलाकार एलम लीच जोन्स के पट्ट-चित्रों तथा तेल-चित्रों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी ललितकला वीथी में 19 से 25 सितम्बर, 1974 तक खुली रही।

(4) यूनेस्को महासम्मेलन के उपलक्ष में पेरिस में प्रदर्शन के लिए अकादमी ने 21 लेप-चित्रों तथा भित्ति-चित्रों का संग्रह किया।

बम्बई में 4-10-1974 को हुए एक समारोह में, जिसकी अध्यक्षता बम्बई विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, प्रो० टी० के० टोपे ने की थी, प्रो० एन० एस० बेन्द्रे को अकादमी की फैलोशिप प्रदान की गई। इस अवसर पर अकादमी ने बेन्द्रे की कृतियों की पूर्व-व्यापी (रिट्रोस्पेक्टिव) प्रदर्शनी का आयोजन किया।

डा० मुल्क राज आनन्द को भी 2-11-1974 को अकादमी का सदस्य बनाया गया। डा० आनन्द ने 2 तथा 3 नवम्बर, 1974 को "भारतीय कला का विवेचन" शीर्षक से पांचवां कुमारस्वामी स्मारक भाषण भी दिया।

अकादमी के तत्वावधान में सितम्बर, 1974 में राज्य ललित कला अकादमियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में सामान्य हितों

के विषय पर विचार-विमर्श किया गया । इसकी अध्यक्षता श्री राम निवास मिर्धा ने की तथा इसमें विभिन्न राज्य अकादमियों, कला-संगटनों एवं संस्थाओं के 29 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

संगीत नाटक अकादमी

आलोच्य वर्ष के दौरान अकादमी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का विवरण नीचे दिया गया है :—

1. अकादमी ने विदेश मंत्रालय की ओर से भारत आने वाले अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मान में नृत्य और संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए । इन मेहमानों में विशेष रूप से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :— बर्मा के राष्ट्रपति, यू०ने० विन, तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका के विदेश सचिव, डा० हेनरी किसिंगर ।

2. अकादमी ने संस्कृति विभाग की तरफ से नई दिल्ली में 13, 14 तथा 15 अक्तूबर, 1974 को केन्द्रीय बाल थियेटर, मास्को द्वारा प्रस्तुत रामायण के तीन अभिनयों का आयोजन किया ।

3. अकादमी द्वारा निकाले जाने वाले महत्वपूर्ण प्रकाशनों में से कुछ नीचे दिए गए हैं :—

   (1) तमाशा पर विनिबन्ध ।

   (2) डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन के "साहित्य तथा कला में भारतीय शास्त्रीय नृत्य" का द्वितीय संस्करण ।

   (3) भारतीय लोक वाद्य—द्वितीय संस्करण ।

   (4) "भारतीय संगीतज्ञों का परिचय" परिशोधित संस्करण ;

   (5) "ध्रुपद संगीत बिहार" ।

   (6) भारत में संगीत शिक्षा पर विनिबन्ध ।

   (7) उदय शंकर पर विनिबन्ध ।

संगीत नाटक नामक पत्रिका के दो अंक संख्या 30 और 31 तथा अकादमी न्यूज बुलेटिन का एक अंक निकाला गया है ।

4. युवा नर्तकों का एक समारोह फरवरी, 1975 में आयोजित किया जाएगा । एक राष्ट्रव्यापी रंगशाला समारोह फरवरी, 1975 में भोपाल में

आयोजित करने का विचार है, जिसमें 4-5 भाषा के क्षेत्रों के प्रमुख नाट्य दल भाग लेंगे ।

इस अवधि के दौरान पुस्तकालय में 170 पुस्तकें तथा डिस्क रिकार्ड संग्रह में 29 डिस्कें शामिल की गई । पुस्तकालय, विशेषकर सुनने के कक्ष का, अध्येताओं तथा छात्रों दवारा बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता रहा । अकादमी के टेप-संग्रह के लिए, गायन और वादन दोनों में हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के कुछ कार्यक्रमों को अकादमी के स्टूडियों में रिकार्ड किया गया है ।

प्रलेखन

अकादमी का प्रलेखन एकक अभिलेखागार में प्रलेख-सामग्री के संचय म मुख्यत: लगा रहा । तीन हजार से अधिक फोटो चित्रों तथा स्लाइडों का उपयुक्त रूप से अभिग्रहण किया गया । मैप-प्रिंट के रूप में लगभग 6000 फुट 16एम० एम० चल-चित्र का संपादन किया गया तथा लगभग 150 घंटे की टेप की गई सामग्री की सूची बनाई गई । इस एकक का टेप-रिकार्डिंग, फिल्म बनाने तथा फोटोग्राफी के रूप में पंजाब का संगीत व नृत्य, अरुणाचल प्रदेश का आदिवासी संगीत और नृत्य, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की औराओं जन-जाति का संगीत और नृत्य, केरल का तैयार तेरा यत्तु (प्रथम चरण) तथा हिमाचल प्रदेश की करयाला लोक रंगशाला को शामिल करने का विचार है । इस एकक का अदिवासी नृत्यों पर 16 एम० एम० की दो रीलें तथा लोक-नृत्य-संगीत पर एक केसेट तैयार करन का कार्यक्रम भी है ।

पुरस्कार

अकादमी ने संगीत, नृत्य तथा नाटक में 1974 में पुरस्कार देने के लिए 14 उत्कृष्ट कलाकारों को चुना ।

संगीत

1. श्री कुमार गान्धर्व (भारतीय संगीत-गायन)
2. श्री निखिल बनर्जी (भारतीय संगीत वादन-सितार) ।
3. श्री एम० डी० रामानाथन (कर्नाटक संगीत-गायन)
4. श्री टी० एन० कृष्णन (कर्नाटक संगीत वादन-वायलिन)

नृत्य

1. श्री कट्टाप्पा पिल्ले (भरत नाट्यम अध्यापक)
2. श्री गौरी शंकर (कत्थक)
3. श्री कला मण्डलम रमन (कथकली) कुट्टी नायर
4. श्रीमती लीबेम्हल देवी (मैनपुरी)
5. श्री भगवान साहू (उड़िया लोक नृत्य)
6. श्री पूना राम (लोक- रंग-मंच पण्डावानी)

नाटक

1. श्री एस० डी० सुन्दरम् (तमिल में नाटक लेखन)
2. श्री डामू केन्द्रे (निर्देशन)
3. श्री तपस सेन (रंगशाला तकनीक)
4. श्री प्रानसुख नायक (अभिनय)

साहित्य तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगी संस्थाएं और संगठन-वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं :

1973-74 के दौरान परम्परागत संस्कृति संस्थान, मद्रास, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, भारतीय विद्या भवन, बम्बई न्यूमिस्मेटिक, सोसायटी, आफ इण्डिया, वाराणासी, पेन आल इण्डिया सेंटर, बम्बई, इस्लामिक कल्चर बोर्ड, हैदराबाद, जलियांवाला बाग स्माकर न्यास, अमृतसर आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई । निरीक्षण समितियों द्वारा रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, कलकत्ता, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता तथा भारतीय दर्शन शास्त्र अकादमी, कलकत्ता जैसी संस्थाओं के कार्य की जांच की गई । एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता तथा भारतीय दर्शन-शास्त्र अकादमी कलकत्ता के संबंध में रिपोर्टें मिल चकी हैं तथा उनकी जांच की जा रही है । रामकृष्ण मिशन संस्थान से संबंधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

नामग्याल तिब्बत दर्शन शास्त्र संस्थान, गंगटोक, सिक्किम

नामग्याल तिब्बत दर्शन-शास्त्र संस्थान, गंगटोक एक ऐसी संस्था है जो बौद्धमत पर अनुसंधान के कार्य में लगी है । इस संस्थान को सिक्किम प्रशासन तथा भारत सरकार, दोनों से ही सहायता मिलती है । इन दोनों सरकारों ने इस

संस्था के अनुरक्षण के लिए अपना वार्षिक अनुदान 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। "नामग्याल तिब्बती-शास्त्र संस्थान, गंगटोक में शिक्षा-वृत्ति" देने की योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1973-74 के लिए दो फैलों का चयन किया गया है।

दायरा तुल मारिफ़ इल उस्मानिया, हैदराबाद

दायरा तुल मारिफ इल उस्मानिया, हैदराबाद एक ऐसी संस्था है जो अरबी और फारसी में पांडुलिपियों के प्रकाशन में लगी हुई है। इस संस्था को 50 हजार रुपये प्रति वर्ष का अनुदान प्राप्त होता रहा है। एक निरीक्षण समिति ने इस संस्था के कार्य का पुनरीक्षण किया था। पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार, इस वार्षिक अनुदान को 60 हजार रुपये तक बढ़ाने का विचार है। इसके अतिरिक्त, 1974-75 के दौरान संस्थान को निर्माण-कार्य के लिए 30 हजार रुपये देने का भी प्रस्ताव है।

बौद्ध दर्शन शास्त्र स्कूल, लेह :

बौद्ध दर्शन-शास्त्र स्कूल, लेह की स्थापना अक्तूबर, 1959 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इस विभाग द्वारा इस स्कूल का पूरा खर्च उठाया जाता है। यह स्कूल जम्मू और कश्मीर सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है तथा इसका एक प्रबन्ध बोर्ड है, जिसम जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बौद्ध दर्शन-शास्त्र तथा तिब्बती भाषा के विद्वान, लद्दाख गोन्या संघ का एक प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारी हैं। योजनागत कार्यक्रमों के अंतर्गत एक छात्रावास का भवन और कुछ स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण शुरू किया जाना है तथा राज्य सरकार से इस कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अबुल कलाम आजाद ओरिएन्टल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

अबुल कलाम आजाद ओरिएन्टल अनुसंधान, हैदराबाद की स्थापना इतिहास, दर्शन-शास्त्र, संस्कृति, भाषा तथा अध्ययन के अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने के उद्देश्य से की गई है।

एक समीक्षा समिति की सिफारिशों पर संस्थान को निम्नलिखित कार्यों के लिए 12 हजार रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है :—

(क) अनुसंधान शिक्षावृत्तियां

(ख) पर्यवेक्षक भत्ता

(ग) अनुसंधान उपस्कर

(घ) प्रकाशन खर्च आदि ।

संस्था को भविष्य में अनुदान देने की पद्धति का पुनरीक्षण करने के लिए 1974-75 के दौरान संस्थान के कार्य की समीक्षा करने का विचार है ।

तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान, वाराणसी

इस संस्थान की स्थापना नवम्बर, 1967 में की गई थी । यहां मुख्यतः तिब्बती बौद्ध शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता है :—

1. पूर्व मध्यमा
2. उत्तर मध्यमा
3. शास्त्री
4. आचार्य
5. विशिष्टाचार्य
6. विद्यावारिधि

इस समय संस्था में लगभग 285 छात्र है तथा अध्यापकों की संख्या प्रिंसिपल सहित 19 है ।

संस्थान के कार्य का पुनरीक्षण भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1970 में गठित एक समिति द्वारा किया गया था । समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से कुछ सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं, जैसे शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 30 छात्रों का दाखिला, आचार्य पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 15 छात्रों का दाखिला, विशिष्टा-चार्य/विद्या-वारिधि पाठ्यक्रम में 5 छात्रों का दाखिला, निदेशक/रजिस्ट्रार का एक पद /वरिष्ठ प्राध्यापक के दो पद/कनिष्ठ प्राध्यापकों के दो पदों का सृजन ।

शताब्दी समारोह

वर्ष के दौरान सारे देश में छत्रपति शिवाजी का त्रिशताब्दी राज्यभिषेक समारोह मनाया गया था । इस समारोह के लिए कार्यक्रम इस प्रयोजन से प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित एक राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार किये गये थे ।

भगवान महावीर के निर्वाण की 2500 वीं वर्षगांठ 13 नवम्बर, 1974 को थी। इस प्रयोजन से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय समिति ने इस अवसर को उपयुक्त ढंग से मनाने के लिए उचित कार्यक्रम तैयार किए।

सांस्कृतिक करार

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सांस्कृतिक करार किए गए :—

(i) भारत-यमन जनवादी गणतंत्र सांस्कृतिक करार पर 15-3-1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार की ओर से इस करार पर शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री, प्रो० एस० नूरुल हसन ने तथा यमन जनवादी गणतंत्र की ओर से वहां के विदेश मंत्री श्री मोहम्मद सलेह मुति ने हस्ताक्षर किए।

(ii) भारत-सनेगल सांस्कृतिक करार पर 21-5-1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार की ओर से इस करार पर शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री, प्रो० एस० नूरुल हसन ने तथा सनेगल सरकार की ओर से श्री एसने बेक ने हस्ताक्षर किए।

(iii) भारत-अर्जेनटाइन सांस्कृतिक करार पर 29-5-1974 को ब्यूनोस आयर्स में हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार की ओर से इस करार पर विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने तथा अर्जेनटाइन सरकार की ओर से विदेश तथा उपासना मंत्री श्री एलबेर्टो जुन विगनस ने हस्ताक्षर किए।

(iv) भारत-कोलम्बिया सांस्कृतिक करार पर 25-5-1974 को बगोता में हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार की ओर से इस करार पर विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने तथा कोलम्बिया सरकार की ओर से श्री एलफ्रेडो बेझूस करीसोसा, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर किए।

(v) भारत-कोरिया सांस्कृतिक करार पर 12-8-1974 को स्यूल में हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार की ओर से इस करार पर विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने तथा कोरिया की सरकार की ओर से श्री डोंग जो किम वहां के विदेश मंत्री ने हस्ताक्षर किए।

(vi) भारत-सूडान सांस्कृतिक करार पर 28-11-974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार की ओर से इस करार पर शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री प्रो० एस० नूरुल हसन ने तथा सूडान की प्रजातंत्र सरकार की ओर से श्री मनसूर खालिद, विदेश मंत्री ने हस्ताक्षर किए।

(vii) भारत-गुयाना सांस्कृतिक करार पर 30-12-1974 को जार्ज-टाउन में हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार की ओर से इस करार पर भारत के उच्चायुक्त डा० गोपाल सिंह ने तथा गुयाना सरकार की ओर से श्री रामफल, विदेश मंत्री, ने हस्ताक्षर किए।

(viii) भारत-यू० ए०ई० सांस्कृतिक करार पर 3-1-1975 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार की ओर से इस करार पर शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री प्रो० एस० नूरुल हसन ने तथा यू० ए० ई० सरकार की ओर से श्री अहमद खलिफा- एल-सुवैदी, विदेश मंत्री, ने हस्ताक्षर किए।

(ix) भारत-मारिशस सांस्कृतिक करार, जिस पर पोर्टलुइस में 6-2-1973 को हस्ताक्षर किए गए थे, के अनुसमर्थन प्रपत्रों का विनियम भारत-मारिशस ने 3-1-1975 को नई दिल्ली में किया। यह विनियम भारत सरकार की ओर से सांस्कृतिक विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री मोहन मुकर्जी ने तथा भारत में मारिशस के उच्चायुक्त श्री आर० घुरबरुन ने अपनी सरकार की ओर से किया।

(x) भारत-बहरिन सांस्कृतिक करार पर 8-1-1975 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारत की ओर से इस करार पर शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृतिक मंत्री प्रो० एस० नूरुल हसन ने तथा बहरिन सरकार की ओर से श्री शेख मोहमद बिन मुबारक एल खलिफा, विदेश मंत्री, ने हस्ताक्षर किए।

(xi) भारत-तंजानिया सांस्कृतिक करार पर 17-1-1975 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारत की ओर से इस करार पर शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री प्रो० एस० नूरुल हसन ने तथा संयुक्त गणतंत्र तंजानिया सरकार की ओर से श्री जी० मपुंदा, श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री, ने हस्ताक्षर किए।

(xii) भारत-जाम्बिया सांस्कृतिक करार पर 26-1-1975 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारत की ओर से इस करार पर विदेश मंत्री वाई० बी० चव्हाण ने तथा गणतंत्र जाम्बिया की ओर से श्री बी० जे० वांगा, विदेश मंत्री, ने हस्ताक्षर किए।

इन करारों का उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ करना है जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के शैक्षणिक कार्यकलाप और खेलकूद, जन-सम्पर्क माध्यम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि भी शामिल है। इन सांस्कृतिक करारों के अंतर्गत नियमित सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिसमें प्रोफेसरों, लेखकों, कलाकारों के दौरे, उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों का दिया जाना एवं पुस्तकों तथा प्रकाशनों का विनिमय किया जाएगा। भारत -अमेरिका संयुक्त आयोग करार के अंतर्गत, जिसपर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। अन्य कार्यों के अतिरिक्त दोनों देशों के बीच शैक्षिणिक तथा सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए शिक्षा तथा संस्कृति उप-आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

भारत तथा अमेरिका के बीच इन क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार तथा उसको सुदृढ़ करने के लिए साधन तथा उपायों का पुनरीक्षण करने के प्रयोजन से, एक शिक्षा तथा संस्कृति उप-आयोग स्थापित किया गया है। इस उप-आयोग की एक बैठक नई दिल्ली में 3 से 5 फरवरी, 1975 को हुई थी जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के भूतपूर्व कुलपति श्री जी० पार्थसार्थी न्यूयार्क के अध्यक्ष डा० रोबर्ट एफ० गोहिन ने की थी। उप-आयोग ने विचार-विमर्श के दौरान बहुत से विषयों पर विचार किया तथा कई सिफारिशें की जिनमें एक यह भी प्रस्ताव था कि मौजूदा कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक सरकार से दूसरे सरकार के स्तर पेर शिक्षावृत्तियों तथा छात्रावृत्तियों का एक कार्यक्रम तैयार किया जाए।

निम्नलिखित देशों से सांस्कृतिक करार करने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है : (1) रवंदा (2) इटली (3) श्रीलंका (4) तंजानिया

निम्नलिखित देशों के साथ सांस्कृतिक करार करने की बातचीत विभिन्न चरणों में हैं :—

(1) चिली (2) मैक्सिको

(3) उरुग्वे (4) कम्बोडिया

(5) मलेशिया (6) थाईलैण्ड

(7) फिजी (8) अलजीरिया

(9) झैरी (10) लेबनान

(11) स्पेन (12) सीरिया

संस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

वर्ष के दौरान जो सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम तैयार किए गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) वर्ष 1974 तथा 1975 के लिए भारत-बेलजियम सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर 15-3-1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

(2) वर्ष 1974-76 के लिए भारत-रूस सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम पर 26-4-1974 को मास्कों में हस्ताक्षर किए गए।

(3) वर्ष 1973-75 के लिए भारत-जर्मन जनवादी गणतंत्र सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम पर 9-5-1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

(4) वर्ष 1974-76 के लिए भारत-चेकोस्लेवाकिया सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम पर 20-5-1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

(5) 1-4-1974 से 31-3-1976 तक की अवधि के लिए भारत-रुमानिया सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर 10-7-1974 को बुखारेस्ट में हस्ताक्षर किए गए।

(6) 1-10-1974 से 30-9-1975 तक की अवधि के लिए भारत-बंगला देश सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर 27-9-1974 को ढाका में हस्ताक्षर किए गए।

(7) वर्ष 1975 तथा 1976 के लिए भारत—संघीय जर्मन गणतंत्र सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर 15-11-1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

(8) वर्ष 1974-76 के लिए भारत-बुलगेरिया सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर 18 नवम्बर, 1974 को सोफिया में हस्ताक्षर किए गए।

(9) वर्ष 1974-75 के लिए भारत-जापान सांस्कृतिक विनिमय कार्य-क्रम के पत्रों का आदान-प्रदान 18 नवम्बर, 1974 को नई दिल्ली में किया गया ।

(10) वर्ष 1975 तथा 1976 के लिए भारत-मारिशस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर 9-1-1975 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए ।

इन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का सामान्य उद्देश्य शिक्षा, कला तथा संस्कृति, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस और फिल्म, स्वास्थ्य, खेलकूद आदि के क्षेत्रों में सहयोग करना है ।

सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल (देश में आने वाले)

आपसी सद्भावना तथा सौहार्द को बढ़ाने के लिए तथा विदेशों से निकट संबंध बनाने के लिए विभिन्न भारत-विदेशी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों और संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनेक सांस्कृतिक प्रति-निधि-मण्डलों एवं कला प्रदर्शनियों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।

भारत में भ्रमण के लिए आमंत्रित किए जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डलों में अभिनय प्रतिनिधि मंडल, गैर-अभिनय प्रतिनिधि मंडल, पत्रकार, शिक्षा-विद, अधिकारी, संगीतज्ञ, लेखक, चित्रकार, अध्येता, भारतीय विद्याशास्त्री आदि और चित्रों, समकालीन चित्रों, रंगशाला कला, फोटोग्राफों, रेखाचित्रिय कलाओं, पोस्टरों इत्यादि की प्रदर्शनियां शामिल होती हैं ।

28-2-1975 तक संस्कृति विभाग के विभिन्न भारत-विदेशी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप कार्यक्रमों के अंतर्गत 43 सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल (7 अभिनय, 35 गैर-अभिनय तथा एक कला प्रदर्शनी) भारत में आये ।

अभिनय दल जर्मन जनवादी गणतंत्र, रूस, कोरिया गणतंत्र (दक्षिण कोरिया), यूगोस्लाविया, भूटान, अफ़गानिस्तान तथा हंगरी के थे जिन्होंने भारत भ्रमण किया और आलोच्य वर्ष के दौरान अपने कार्यक्रम दिखाये ।

कला, साहित्य तथा संस्कृति में जिन ख्याति प्राप्त विशिष्ट लोगों ने भारत भ्रमण किया वे इन देशों के थे—बल्गारिया, रूस, रूमानियां,

बंगलादेश, जर्मन संघीय गणतंत्र, ईटली, बैल्जियम, फ्रांस, बर्मा, जर्मन जनवादी गणतंत्र, ट्रिनिडाड, इल-सेल्माडोर, श्रीलंका, ब्राजील, अमेरिका, ईराक, चैकोस्लावाकिया, अफ़गानिस्तान, हंगरी तथा स्वीडन। आलोच्य वर्ष में चैकोस्लावाकिया की कला पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

1 मार्च से 31 मार्च, 1975 तक संस्कृति विभाग के विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप कार्यक्रमों के अंतर्गत चार सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलों (गैर-अभिनय) के, हंगरी, जर्मनी जनवादी गणराज्य तथा थाईलैण्ड से आने की सम्भावना है।

1. विदेश में गए अभिनय प्रतिनिधि मण्डल

विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय/सांस्कृतिक कार्यकलापों के अंतर्गत भारतीय नर्तकों/संगीतज्ञों ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भाग लिया :—

(i) **चौथा भारतीय कला समारोह :** भारतीय कला सांस्कृतिक केन्द्र लिमिटेड, लंदन द्वारा मई-जून 1974 के दौरान आयोजित किया गया था।

इस समारोह में भाग लेने के लिए मई 1974 के दौरान एक छः सदस्यीय दल बिरजू महाराज के नेतृत्व में न्यूयार्क गया जो न्यूयार्क की निजी यात्रा पर थे। 1 जून 1974 में एक दूसरे 13-सदस्यीय संगीतज्ञों, नर्तकों तथा वादकों के दल ने इस समारोह में भाग लिया तथा इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा इटली में 25 दिन में 18 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रेस ने इन पर अच्छी रिपोर्ट दी।

(ii) **कोपनहेगन युवक बैंड समारोह, जुलाई, 1974 :** इस समारोह में श्रीमती रूमा गुह के नेतृत्व में कलकत्ता युवक कोयर के 20-सदस्यीय लोकगीत तथा नृत्य दल ने भाग लिया तथा कोपनहेगन युवक समारोह में प्रथम पुरस्कार जीता।

(iii) **अन्तर्राष्ट्रीय वृन्दगान समारोह:** मेदजीडोरजे तथा कला छात्र समारोह (एफ० ए० एम० ए०) स्वीनोन्जसाई (पोलैण्ड) में मई 1974 में आयोजित किया गया था।

कोमीवादिया द्वारा आयोजित प्राणज्योति अकादमी सहगान, बम्बई को इन समारोहों में भाग लेने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय

सहायता दी गई थी । उन्हें अपने विशिष्ट कलात्मक गुणों के लिए पोलिश रेडियो की ओर से पुरस्कार मिला।

(iv) **18वीं बर्लिन थियेटर तथा संगीत समारोह :** 1974 में जर्मन जनवादी गणतंत्र की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था । मुंबई मराठी साहित्य संघ, बम्बई के 40 सदस्यीय थियेटर दल ने इस समारोह में भाग लिया तथा ब्रेच के 'दी काकेसियन चाक सर्कल' का मराठी रूपान्तर प्रस्तुत किया । बर्लिन में प्रदर्शन करने के अलावा उन्होंने जर्मन जनवादी गणतंत्र का दौरा किया तथा ज़ुरिच में प्रदर्शन करने के लिए स्विटजरलैण्ड की भी यात्रा की । दर्शकों तथा थियेटर आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की बहुत ही सराहना की।

(v) **बेलग्रेड अंतर्राष्ट्रीय थियेटर समारोह-सितम्बर 1974 :** नृत्य/संगीत दल में पांच अन्य साथियों सहित (भारतनाट्यम नर्तकी) कुमारी एस० कणिका ने तथा श्री निर्मलेन्दु चौधरी के नेतृत्व में लोकगीत गायकों के एक दल ने इस समारोह में प्रदर्शन किया । इसके बाद उन्होंने रानी करणा (कथक नर्तकी) के साथ, उसके पांच अन्य साथियों सहित यूगोस्लाविया, रूमानिया, फ्रांस तथा रूस का दौरा, वहां प्रदर्शन करने के लिए किया । 'हाल' में बड़ी संख्या में दर्शकों ने उनके प्रदर्शनों को देखा तथा जोर-जोर से तालियां बजाकर उनकी सराहना की ।

(vi) कुमारी प्रतिभा पंडित के नेतृत्व में आर्य कन्या महाविद्यालय, बड़ौदा, के एक 21-सदस्यीय नृत्य/संगीत दल ने कुवैत, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस तथा इंग्लैण्ड का भ्रमण किया। इन सभी देशों में प्रदर्शनों के लिए दल की भूरि-भूरि सराहना की गई ।

II. विदेशों में जाने वाले लोग :

सांस्कृतिक विनिमय/सांस्कृतिक कार्यकलापों के अंतर्गत भारत के प्रमुख लोगों को बैठकों/सम्मेलनों में भाग लेने, अनुभव के आदान-प्रदान तथा अपने प्रतिपक्षियों के साथ यथासंभव मुलाकात के लिए विदेशों में भेजा गया था ।

प्रदर्शनियां :

(1) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली, ने इस विभाग की ओर से बल्गारिया, यूगोस्लेविया, बैल्जियम तथा पोलैण्ड में

12—956 M of Edu & SW/74

दिसम्बर, 1973 से अप्रैल, 1974 तक प्रदर्शन के लिए एक प्रदर्शनी भेजी। इस प्रदर्शनी से भारतीय कला में प्रयोग तथा उपलब्धि दोनों की व्यापक झलक मिली और यह बड़ी सफल रही।

(ii) ललित कला अकादमी के तकनीकी विशेषज्ञ श्री ए० दास गुप्त की देखरेख में ललित कला अकादमी, नई दिल्ली, द्वारा संकलित की गई भित्तिचित्रों तथा भित्ति-चित्रकारी की एक प्रदर्शनी अक्टूबर-नवम्बर, 1974 में होने वाले यूनेस्को के महा सम्मेलन के अवसर पर पेरिस में आयोजित की गई। इसके बाद यह प्रदर्शनी डेनमार्क में दिखाई गई और आजकल यूगोस्लेविया में दिखाई जा रही है। यह प्रदर्शनी रूमानिया और जर्मन लोकतंत्र गणराज्य में भी प्रदर्शित की जाएगी।

(iii) इस विभाग की ओर से राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, द्वारा संकलित भारत के लघु चित्रों की एक प्रदर्शनी ब्रसेल्स (बेल्जियम) में आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय के श्री ओ० पी० शर्मा गए थे। यह प्रदर्शनी बेल्जियम के राजा के संरक्षण में ब्रसेल्स के बिबलियोथिका रोयेल में अक्टूबर, 1974 में आयोजित की गई थी।

(iv) प्रोफेसर एन० रोरिच के चित्रों की एक प्रदर्शनी रूस में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत, रूस भेजी गई थी। इसके साथ श्री तथा श्रीमती एस० रोरिच गई थी।

(v) मिडलेहम बिन्नियल, आन्टवर्प (बेल्जियम) में मई 1975 में प्रदर्शन के लिए एक मूर्तियों की प्रदर्शनी भेजने का निर्णय किया गया है। इसमें दिखाई जाने वाली कृतियों की संख्या 30 है।

यात्रा के लिये आर्थिक सहायता

निम्नलिखित व्यक्तियों को विदेशों में सांस्कृतिक यात्रा करने के लिए हवाई यात्रा की किफायती श्रेणी के किराये का एक भाग मंजूर किया गया था :—

(i) मद्रास के संग्रहालयों के निदेशक डा० टी० एस० सत्यमूर्ति जो जून 1974 में कोपनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद् के सम्मेलन में भाग लेने गए थे।

(ii) तबला वादक श्री फैयाज खां जो जुलाई-अगस्त में आस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने तथा प्रदर्शन कार्यक्रम रखने के उपलक्ष में गए थे ।

(iii) विश्वविद्यालय महिला संघ द्वारा नामित प्रतिनिधि कुमारी एच० के० सिंह, कुमारी एम० रामदुराई तथा श्रीमती चित्रा घोष अगस्त 1974 में टोकियो के द्विवार्षिक सम्मेलन तथा कयोटो के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महिला संघ में भाग लेने गई थीं ।

योजनागत परियोजनाएं

इस विभाग की ओर से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला तथा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली में भारत तथा ऐशियाई सभ्यता पर एक आधार ग्रंथ लिखने का कार्य शीघ्रता से चल रहा है । आशा है कि परिषद् अपना कार्य दिसम्बर, 1974 तक पूरा कर लेगी और संस्थान का कार्य परियोजना के पूरे होने तक चलेगा ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परषिद् के हस्तांतरित विषय

1. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने 'हस्तांतरित विषयों' के अंतर्गत पांच सांस्कृतिक शिष्टमण्डल विदेश भेजे । इनमें ये शामिल हैं : श्रीमती शन्नो खुराना, गायिका, पण्डित शिव कुमार शर्मा, संतूरवादक, कुमारी सुमित्रा मित्रा, कत्थक नर्तक जो अफ़गानिस्तान गणतंत्र की पहली वार्षिकी के अवसर पर अफ़गानिस्तान गई थी ; अपनी पार्टी सहित श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर नेपाल गई थी । नृत्यकला नाट्य संस्थान की श्रीमती माया राव अपनी पार्टी सहित श्रीलंका गई थीं; अपनी पार्टी सहित श्रीमती मीरा बैनर्जी तथा कवि, संगीतकार और गायक श्री ज्योतिरिन्द्र मैत्रा, बंगलादेश में मनाई जाने वाली महात्मा गांधी की 105वीं जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष में बंगलादेश गए; श्रीमती स्वप्न सुन्दरी, कत्थक नर्तकी तथा उनका दल नेपाल गया; तथा रोहिनी भेटी व उनका दल पूना से कोलम्बो गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर गया, भारत के विभिन्न राज्यों के 8 सुप्रतिष्ठ लेखकों का एक दल बंगला अकादमी द्वारा फरवरी, 1975 में आयोजित, भाषा आन्दोलन में शहीदों की स्मृति में शहीद दिवस के अवसर पर सात-दिवसीय साहित्यिक सेमीनार में भाग लेने के लिए गया ।

2. फ्रांस, इथोपिया, केन्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भूटान, मैक्सिको, मारीशस, सिक्किम, थाइलैण्ड, टर्की, अरब गणतंत्र, चैकोस्लोवाकिया, फिजी, इंडोनेशिया, मालवी, गुयाना तथा अफगानिस्तान में हुई निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने वालों को दी जाने के लिए भारतीय दस्तकारी की वस्तुएं तथा पुस्तकें भेजी गई।

3. पुस्तकों को भेंट करने के कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकें इन देशों को भेजी गई जिनके नाम हैं—ईराक, जापान, केन्या, कोरिया, मलावी, मलेशिया. फिलिपाइन्स, थाईलैण्ड, टर्की, अफ़गानिस्तान, हंगरी, इन्डोनेशिया, मारीशस, अमेरिका, आस्ट्रिया, घाना, कोरिया गणतंत्र, सिंगापुर, दक्षिण वियतनाम, नाइजीरिया, बंगलादेश, यू० ए० ई०, इथोपिया, गुयाना, लेबनान, मैक्सिको, पनामा, पेरु सोमालिया, ट्यूनीसिया, ट्रिनिडाड, यूगोस्लाविया, ब्राजील, बल्गेरिया, नेपाल, श्रीलंका, तंजानियां, फिजी तथा पोलैण्ड।

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन संबंधी अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत धार्मिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, नगरपालिकाओं, स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों को छोड़कर वे सभी संगठन आते हैं जो नृत्य, ड्रामा, संगीत, ललित कला, भारतीय विद्या तथा साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। चल रहे आर्थिक संकट तथा निर्माण कार्यों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण मौजूदा वर्ष में भी सहायता के लिए विचार किए जाने के प्रयोजन से कोई नए आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं किए गए थे। तथापि पहले, चुनी गई संस्थाएं योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदानों की किस्तें, बराबर प्राप्त करती रहीं।

शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगताएं

इस वर्ष, इस प्रतियोगिता के लिए, जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, लगभग 120 देशों से लगभग 1,50,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं।

व्यावसायिक नृत्य नाटक तथा थियेटर संस्थाओं को वित्तीय सहायता

इस योजना का उद्देश्य देश के उन कला-प्रदर्शन दलों की सहायता करना है जो पिछले 10-15 सालों से इस क्षेत्र में केवल अपने प्रयत्नों से कार्य कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के 13 नृत्य-

नाटक तथा थियेटर दलों को सम्मिलित किया गया था। इस योजना को पांचवीं पंच वर्षीय योजना में भी जारी रखा जा रहा है तथा मौजूदा वर्ष में चौथी योजना के दौरान चुनी गई 13 संस्थाओं के अतिरिक्त और दो संस्थाएं भी शामिल की जाएंगी।

कालेज तथा स्कूल छात्रों में संस्कृति का प्रचार

वर्ष के दौरान, 150 शैक्षिक किट तैयार किए गए जिनमें प्रत्येक में एक प्रोजेक्टर, फिल्म पट्टियां, केसेट टेप रिकार्डर तथा टेप, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, थियेटर, आदि से संबंधित आठ पुस्तिकाएं और मूर्तिकला के लिए प्लास्टर कास्ट सम्मिलित हैं।

इन शैक्षिक किटों के 155 सेट शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय के उपमंत्री श्री डी० पी० यादव द्वारा 20 अगस्त 1974 को आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को औपचारिक रूप से भेंट किए गए थे। यकिट संगठन के उन स्कूलों को दिए जाएंगे जिनके शिक्षकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाता है। तीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनमें से एक मौजूदा वर्ष में पूना में होगा।

सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

भारत की विस्तृत सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक सम्पति के संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान तथा कला, पुरातत्व, मानवविज्ञान आदि की वस्तुओं के तकनीकी अध्ययन की बहुत अधिक आवश्यकता है तदनुसार, संस्कृति विभाग ने, एक योजनागत योजना तैयार की है जो सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए है। इस प्रयोगशाला को बाद में वैज्ञानिक विश्लेषण तथा भित्ति-चित्रों, संग्रहालय की वस्तुओं, कागज-सामग्री, वस्तुओं आदि की विकृति के संरक्षण की पद्धतियों के अनुसंधान के लिए प्रभागों के रूप में विभाजित कर दिया जाएगा। आजकल प्रयोगशाला की योजना तैयार की जा रही है।

सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कामगरों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां

इस योजना के अंतर्गत 18-28 आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को हिन्दुस्तानी कर्नाटक संगीत, पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत, भारतीय

नृत्य की शास्त्रीय शैलियों, परम्परागत थियेटर, ड्रामा, चित्रकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्रों में भारत में उच्च प्रशिक्षण के लिए 25 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक छात्रवृत्ति 250 रुपये प्रतिमास की होती है तथा इसकी अवधि दो वर्ष की है। असाधारण मामलों में छात्रवृत्ति की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाती है। इस योजना के लिए मौजूदा वर्ष के दौरान 1,70,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। अभी तक इस योजना को एक योजनेत्तर विषय के रूप में चलाया गया है। परंतु पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान वर्तमान वर्ष से 25 और छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए वर्ष 1974-75 के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना

यह एक योजनागत योजना है जिसके अंतर्गत 10-14 आयु वर्ग के उत्कृष्ट बच्चों को अनेक सांस्कृतिक क्षेत्रों में, जैसे, संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा मूर्तिकला में, उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। मौजूदा वर्ष के दौरान पिछले वर्ष प्रदान की गई 39 छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत 75 नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। छात्रवृत्ति एक बार एक वर्ष के लिए प्रदान की जाती है तथा यह शिक्षा का माध्यमिक स्तर पूरा होने अथवा जब तक अध्येता 21 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, इन दोनों में से जो भी पहले हो, हर वर्ष के लिए दी जाती रहती है। मौजूदा वर्ष के दौरान, 2,50,000 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्याशियों का प्राथमिक चयन नवम्बर, 1974 की समाप्ति तक पूरा हो जाएगा। सामान्य निवास के स्थान पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों की वार्षिक छात्रवृत्ति 600 रुपये है तथा अन्य स्थान पर रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए यह छात्रवृत्ति 1200 रुपये प्रति वर्ष है। इसके अतिरिक्त अध्येता को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है बशर्ते कि वह प्रति वर्ष 1000 रुपये से अधिक न हो।

स्वैच्छिक संगठनों को भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिये सहायता

यह योजना दूसरी पंच वर्षीय योजना के मध्य से लागू रही है। इसके अंतर्गत विश्वकोश, शब्दकोश, ज्ञान की पुस्तकें, विभिन्न भाषाओं की समानता दिखाने वाले प्रकाशन, पाण्डुलिपियों तथा सांस्कृतिक पुस्तकों की सूची,

साहित्य, भारतीय विद्या, भाषामूलक तथा वैज्ञानिक विषयों पर प्रकाशन निकालने के लिए अनुमोदित व्यय के 50 प्रतिशत अनुदान मंजूर किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित प्रकाशनों की प्रतियां भी खरीदी जाती हैं तथा अनेक भाषाओं में साहित्यिक सम्मेलनों, सेमिनारों, पुस्तकों की प्रदर्शनी आदि के आयोजन के लिए अनुदान भी देने की व्यवस्था है।

गजेटियर

भारत के गजेटियर का खण्ड-I देश और लोग—तथा खण्ड II – इतिहास और संस्कृति प्रकाशित हो चुके हैं। खण्ड I की सभी प्रतियां बेच दी गई थीं। इसका दूसरा संस्करण भी निकल चुका है। इस खण्ड के कुछ अध्याय, जैसे लोग, भाषाएं, भू-आकृति विज्ञान आदि को पुस्तिकाओं के रूप में अलग से निकाला गया है। खण्ड III आर्थिक ढांचा तथा कार्यकलाप—का अधिकांश भाग मुद्रित हो चुका है। तथा शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है।

2. जिला गजेटियरों के परिशोधन की योजना सभी राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा आरंभ कर दी गई है। 216 जिला गजेटियरों के प्रारूप पूरे हो चुके है जिनमें से 207 प्रारूप प्रकाशन के लिए अनुमोदित हो चुके हैं।

3. 'हू इज़ हू आफ इण्डियन मार्टर्स' परियोजना पूरी हो चुकी है तथा इसके तीनों ही खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं।

—o—o—o—

दूसरा अध्याय

पुरातत्व

आलोच्य अवधि के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने अधीन कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना ध्यान देना जारी रखा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) स्मारकों का संरक्षण :

स्मारकों के संरक्षण का एक ठोस कार्यक्रम, जोकि सर्वेक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी है, देश के विभिन्न भागों में आरम्भ किया गया। निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्मारकों की विशेष मरम्मत की गई :— अमरावती, जिला गुन्टूर में महास्तूप, मुखालिंगम, जिला श्रीकाकुलम में मुखालिंगम मन्दिर, गुडिमल्लम, जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश में परमेश्वर मन्दिर, असम में अहं महल; कुशिनगर में निर्वाण-स्तूपा तथा वैशाली, बिहार में खोदे गए अवशेष; दिल्ली में जफरमहल, लालकिला, जन्तर-मन्तर तथा रोशनारा बारादरी; द्वारका में द्वारकाधीश मन्दिर, अहमदाबाद, गुजरात में तीन द्वार; पुराने गोआ, गोआ में गिरजाघर; थानेसर, हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा; कर्नाटक में बीजापुर स्मारक; कोचीन, केरल में मत्तनचेरी महल; काश्मीर में मार्तन्ड और अवन्तिपुर के मन्दिर तथा पत्थर मस्जिद; मध्य प्रदेश, ग्वालियर में मुहम्मद घोस का मकबरा तथा भोजपुर में शिव मन्दिर; महाराष्ट्र के ज़िला कोलाबा का रायगढ़ किला तथा ज़िला औरंगाबाद में अजन्ता और एलोरा की पत्थर-शिला की गुफाएं; उड़ीसा ज़िला पुरी में कोणार्क का सूर्यमन्दिर तथा भुवनेश्वर का वराही मन्दिर; पंजाब में भटिंडा किला; राजस्थान में जिला सवाई माधोपुर का रणथम्भोर किला तथा भरतपुर किला; तमिलनाडु के ज़िला चिंगलपुट में महाबलिपुरम का शोरमन्दिर, ज़िला तिरुचिरापल्ली का एवरकोविल तथा कोदम्बलूर ; उत्तर प्रदेश में ज़िला आगरा का ताजमहल समूह और फतेहपुर सिकरी, तथा लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा।

उड़ीसा में पुरी का प्रख्यात जगन्नाथ मन्दिर, जो कि एक महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान है, तथा अपने वास्तुशिल्पीय शैली के लिए प्रख्यात है, राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक घोषित किया जा रहा है। अन्तिम अधिसूचना जारी की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ की जाने वाली मरम्मतों का उद्देश्य, छत की टपकन को रोकना तथा जिन भागों में दरारें आ गई हैं अथवा जो भाग टूट गए हैं उनको बदल कर इस के निर्माण को मज़बूत बनाना है।

(ii) भारत के बाहर अभियान :

सर्वेक्षण ने, अफगानिस्तान में बमियान स्थित प्रसिद्ध बौद्ध शिला मन्दिरों के संरक्षण तथा परिरक्षण के कार्य को जारी रखा। इस वर्ष के दौरान, विशाला बौद्ध मन्दिर (55 मी० ऊंचा) पर कार्य आरम्भ किया गया। बुद्ध के चरणों के आसपास के सफाई कार्य के दौरान, उस मंच सहित, जिस पर कि बुद्ध खड़े हैं, निचले भाग को साफ किया गया तथा परवर्ती दीवारों के स्टम्पों को बाहर निकाला गया।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के अनुरोध पर, सर्वेक्षण ने, बलख स्थित ख्वाजा पर्सा का मकबरा नामक उत्तर पन्द्रहवीं शताब्दी की तीमूरिद मस्जिद की मरम्मत का कार्य भी आरम्भ किया। भूकम्प के झटकों के कारण इमारत में बहुत सी दरारें आ गई थीं, तथा इस के आस-पास और भूमिगत कक्ष में जल खड़ा हो जाने के फलस्वरूप इसका अग्रभाग धंस गया था। दरारों को भरकर तथा गुम्बद् के भितल्लों के साथ मेहराबों की व्यवस्था करके इमारत को, मज़बूत बना दिया गया है।

(iii) खोज तथा खुदाई

यद्यपि सर्वेक्षण मुख्यत: ऐतिहासिक काल के पुरातत्वों से सम्बन्धित है, तथापि प्रागैतिहासिक काल की खोज भी जारी रही। इस कार्य में महाराष्ट्र के जिला धुलिया में यासर स्थित पुराप्रस्तर युगीन स्थल की खुदाई उल्लेखनीय है, जिससे प्राचीन, मध्य तथा परवर्ती प्रस्तरयुगों के औजार प्रकाश में लाए। आन्ध्र प्रदेश के कर्नूल तथा कुड्डापाह् ज़िलों में प्राचीन तथा मध्य प्रस्तरयुगों के स्थल भी खोज निकाले गए।

इस वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण खोज, महाराष्ट्र, के जिला अहमदनगर में देमाबाद में एक अद्विवतीय कला निधि है, इसमें चार कांस्य वस्तुएं हैं, जो कि एक रथ, जिसमें दो पशु जोते हुए दिखाए गए हैं : एक गैंडा, एक हाथी तथा एक सांड हैं।

सर्वेक्षण द्वारा ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई में मथुरा में की गई खुदाई उल्लेखनीय है, जहां नगर के पश्चिमी क्षेत्र में कटरा केशव देव और महाविद्या मन्दिर के बीच खुदाई आरम्भ की गई थी । इस खुदाई से, अन्य बातों के साथ-साथ, शक कुषाण युग की किलबन्दियों की लगभग पूरी रूपरेखा प्रकाश में आई । किलेबन्दियों के बाहर के कुषाण बस्ती की सीमाओं का पता लगाना अभी शेष है ।

आन्ध्र प्रदेश के ज़िला गुन्टूर में अमरावती में की गई खुदाई से ऐसे प्रमाण प्रकट हुए हैं जिन्हें पांच युगों में बांटा गया है, जोकि लगभग चौथी शताब्दी ईसा-पूर्व तथा ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी के बीच के हैं । इसके अतिरिक्त, खुदाई से महाचैती के प्राचीन इतिहास से संबंधित कालानुक्रमिक रूपरेखा के लिए ठोस आधार प्रदान करने में सहायता प्राप्त हुई है । निचले स्तरों में उत्तरी ब्लाक परिमार्जित मिट्टी के बर्तन की ठीकरियों की उपस्थिति से, देश के इस भाग में मिट्टी के बर्तन बनाने की पद्धति के पुष्टिकरण प्रमाण प्राप्त हुए हैं ।

उत्तर प्रदेश में बस्ती ज़िले के पिपरावा स्थान पर की गई और खुदाई से, जिसे प्राचीन कपिलवस्तु से सम्बन्धित माना गया है; 16 कक्षों तक के एक विशाल भवन—समूह के अवशेष प्रकाश में आए हैं । पूर्वी मठ में और आगे खुदाई जारी रखी गई जहां पहले पक्की हुई मिट्टी के मुद्रांकण पाए गए थे तथा इन से यह ज्ञात हुआ कि एक केन्द्रीय प्रांगण के आस-पास 33 कक्षों सहित इसकी योजना चतुर्भुजीय थी । अन्य पुरावस्तुओं के अतिरिक्त, लगभग एक दर्जन पकी हुई चिकनी मिट्टी की ठीकरियां, जिन पर खुदाई के चिह्न थे, पाई गई थी ।

बिहार के भागलपुर जिले के अंतचिक स्थल की खुदाई जारी रही, जिसे विक्रमसिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थल से संबंधित माना जाता है । कार्य के दौरान, अन्य इमारतों के अतिरिक्त, मठ के उत्तरी द्वार के पूर्व तक 15.25 मी० लम्बाई का एक कंकरों से भरा हुआ 3.63 मी० चौड़ा मार्ग प्रकाश में आया । महत्वपूर्ण प्राप्तियों में, अवलोकितश्वर की एक छोटी कांस्य मूर्ति, दो पक्की मिट्टी के मुद्रांकण, जिनमें से एक पर खुदाई की हुई है तथा दूसरी पर दो तिकोने चिह्न हैं; काले पत्थर से बनी हुई बुद्ध की एक धड़-प्रतिमा; हाथीदांत के पांसे, तांबे का घण्टा; लोहेकी वस्तुएं तथा पक्की मिट्टी की पशु लघु मूर्तियां, उल्लेखनीय हैं । उत्तर प्रदेश के ज़िला देहरादून के ऋषिकेश,

वीरभद्रा की खुदाई से, स्थल के पुरातन होने के महत्वपूर्ण प्रमाण के अतिरिक्त, गुप्त तथा गुप्तोत्तर युगों के दो ईट के मंदिरों के अवशेष प्रकाश में आए ।

(IV) रासायनिक परिरक्षण

निम्नलिखित स्मारकों का रासायनिक परिरक्षण किया गया था :—

हिमाचल प्रदेश के जिला लाहुल और स्पिति में ताबों स्थित बौद्ध मठों के चित्र; पश्चिम बंगाल के ज़िला मालदा में गौर स्थित लोटन मस्जिद की बहुरंगी एनैमल सजावट; उड़ीसा के जिला पुरी में कोणार्क स्थित सूर्य मन्दिर; महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में अजन्ता की चित्रकारी; विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार, तमिलनाडु के जिला चिंगलपुर में कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर की चित्रकारी तथा उभार; दिल्ली के लाल किला, रंगमहल की छत की चित्रकारी पुराने गोवा, गोवा के गिरजाघर ।

(V) पुरालेख विद्या :

वनवासी (प्राचीन वैजयन्ति) में हाल ही में पता लगाए गए सातवाहन युग (दूसरी शताब्दी ईसवीं) के एक महत्वपूर्ण शिलालेख की नकल की गई । इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में खंडगिरि के आसपास के क्षेत्र के शिलालेखों की भी नकल की गई ।

आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पाए गए 300 से अधिक अरबी तथा फारसी के शिलालेखों की नकल तथा जांच की गई । महत्वपूर्ण शिलालेखों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं; आन्ध्र प्रदेश के जिला नलगोंडा के कुतुब शाही शिलालेख ; दिल्ली के निकट महरौली में पाए गए कुलीन पुरुष शन्सी का एक समाधि-लेख; घियासुद्दीन बलबन का नया अभिलेख, जिसके लिए कहा जाता है कि वह मूलतः नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा से है तथा इस समय पटियाला संग्रहालय में है; तुगलकों तथा गुजरात के सुलतानों के शिला लेख तथा केरा और मेहसाना जिलों से 14 वीं शताब्दी के अन्य शिलालेख और गुजरात के काम्बे से प्राप्त 18वीं, 19वीं शताब्दी के शिलालेख; हुमायूं के अभिलेख तथा अब तक ध्यान न दिए गए हरियाणा से 16वीं शताब्दी के शिलालेख; मध्य प्रदेश के ज़िला पश्चिम निमार से प्राप्त शाहजहां के अभिलेख; राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर से प्राप्त 16वीं, 17वीं शताब्दी के शिलालेख, इत्यादि ।

(VI) प्रकाशन :

इस वर्ष के दौरान सर्वेक्षण के प्रकाशन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति हुई : **पुरातन भारत अंक** 22, **भारतीय पुरातत्व** 1965-66 तथा 1970-71, **पुरालेख भारत खंड** XXXVIII भाग-4, प्रकाशित किए गए; अजन्ता तथा सांची की मार्गदर्शी पुस्तकों के नए संस्करण पुर्नमुद्रित किए गए । निम्नलिखित स्थलों के पोस्टकार्ड आकार के चित्रों के सैट मुद्रित किए गए ; कोणार्क, सेट-'क', गिंगी, थनजावुर श्रृंगेरी, वांरगल, हनामकोंडा तथा पालमपेट, हलेविद तथा सोमनाथपुर ।

भारतीय पुरातत्व 1971-72, पहले से ही प्रेस में भेजा जा चुका है तथा वर्ष 1972-73 तथा 1966-67 के अंक प्रेस के लिए तैयार किए जा रहे हैं । **पुरातन भारत**, अंक-23 तथा उसके आगामी संयुक्तांक का भी संपादन कार्य आरम्भ किया जा रहा है । पुराना गोवा; कांचीपुरम; मार्तन्ड, अवन्तिपुर तथा पन्द्राथन की मार्गदर्शी पुस्तकें; **कारपस इनस्क्रिपशनम इंडिक्रम'** खंड-VI, प्रो० वी० वी० मिराशी लिखित सिलहरस के अभिलेख तथा डा० एच० बी० । त्रिवेदी द्वारा लिखित परमारस के अभिलेख, **कारपस इनस्क्रिपशनम इंडिक्रम,** प्रेस के लिए तैयार किए जा रहे हैं ।

निम्नलिखित प्रकाशन मुद्रण के विभिन्न स्तरों पर हैं; सांची, राजगीर (दोनों हिन्दी में), दिल्ली तथा उसके आसपास, के क्षेत्रों, खजुराहो तथा मंडू की मार्गदशी पुस्तकें, **दक्षिण भारतीय अभिलेख,** खंड XVIII ,XXI तथा XXII तथा वर्ष 1973-74 के लिए **भारतीय पुरालेख विद्या** सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट ।

तीसरा अध्याय

भारत का नरतत्वीय सर्वेक्षण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, भारत के नरतत्वीय सर्वेक्षण ने, भारत के विभिन्न आबादी-वर्गों, विशेष रूप से उपहिमालयाई सीमा क्षेत्र के निकटवर्ती वर्गों की समाजार्थिक तथा जीव-नरतत्वीय समस्याओं से संबंधित अपने कार्य का विस्तार किया है। सर्वेक्षण ने विभिन्न सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्रीय योजना संस्थाओं से सहयोग जारी रखा। वर्ष के दौरान, सर्वेक्षण के मुख्य कार्यकलाप संक्षेप में निम्नलिखित हैं :—

सांस्कृतिक नरतत्व प्रभाग

(1) 1973 में आरम्भ की गई राष्ट्रीय महत्व की दो मुख्य परियोजनाओं पर कार्य जारी रहा :

(क) भारतीय जनता के कमजोर वर्गों में समाजार्थिक परिवर्तन 11 राज्यों में 22 गांवों का अध्ययन दिया गया है।

(ख) उप-हिमालयाई सीमा क्षेत्र की जनता का समाज तथा संस्कृति सीमावर्ती गांवों में 8 नृवंश-संबंधी वर्गों का अध्ययन किया गया है।

(2) जन-जातीय समुदायों अर्थात पश्चिम बंगाल के संथालों तथा पर्वतीय खड़ियां, उड़ीसा के मनकिडी, लिटल अंडमान के ओंगे, ग्रेट निकोबार के ग्रेट अंडमानी तथा शोमपेन का जातिमत अध्ययन आरंभ कर दिया गया है।

(3) उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, कृषि परिवर्तन, लोक-चिकित्सा, पशु-पालकों की सामाजिक अर्थव्यवस्था, जन-जातीय राजनीतिक आन्दोलनों के सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में, सिंगभूम, रानीगंज कोयला-क्षेत्रों, हलदिया तथा सोना बेड़ा (उड़ीसा) में जनजातीय तथा कृषकों के जीवन पर, कलकत्ता

के भिखारियों तथा झाड़ूकशों तथा कलकत्ता के एंगलों-इण्डियन समाज पर उद्योगीकरण के प्रभाव का अध्ययन कार्य आरंभ कर दिया है।

(4) थाड़ौ-कुकी, चैंचू तथा भूटिया भाषाओं के संबंध में रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं और विभिन्न कुकी बोलियों का सर्वेक्षण आरंभ कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के बीच अन्तर-राज्य संचार कार्य के संबंध में भी कार्य किया गया है।

शारीरिक नरतत्व प्रभाग

(1) 1973 में प्रारम्भ की गई अखिल भारतीय जीव-नरतत्वीय सर्वेक्षण की मुख्य परियोजना के अन्तर्गत अभी तक देश के 173 विभिन्न स्थानों की, जिनमें 17,300 परिवार सम्मिलित थे, जांच की गई है। उत्पत्ति-संबंधी अव्यवस्थाओं, जन्मजात असंगतियों इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र कर लिए हैं।

(2) प्राचीन कंकाल अवशेषों की रसायनिक अभिक्रिया तथा परिरक्षण का कार्य जारी रखा गया है। दांतों के प्राचीन तथा आधुनिक संग्रहों का दन्तमापीय (ओडोन्टोमिट्रिक) अध्ययन पूरा हो चुका है। सतलडंगा, पश्चिम बंगाल में पाए गए मानव कंकाल-अवशेषों के संबंध में एक रिपोर्ट, पुरातत्व निदेशालय, पश्चिम बंगाल के सहयोग से पूरी कर ली गई है।

(3) "कलकत्ता के पांच मुस्लिम वर्गों के शारीरिक नरतत्व" तथा "मुर्शिदाबाद की मुस्लिम लड़कियों की वृद्धि तथा विकास" नामक परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रीय जांच पूरी हो चुकी है।

(4) असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक के विभिन्न आबादी-वर्गों के संबंध में चर्म-वज्ञानिक अनुसंधान आयोजित किए जा रहे हैं।

(5) जिन दूसरे विषयों पर अध्ययन कार्य चल रहा है, वे हैं: स्वत: गर्भ-स्राव के एक कारण के रूप में रक्त वर्गों की असंगति, उत्तर बंगला के तमंग, असम के मोटक, पश्चिम बंगाल के चमारों के बीच सीरम-नरतत्वीय अध्ययन, नवजातों में जन्मजात विकृतियों, बिहार के बहुत से जनजातीय वर्गों में रंग बोध की कमी, प्रसवोत्तर अनार्तव

की अवधि पर स्तन्यस्रवण का प्रभाव, कलकत्ता तथा बम्बई के अस्पतालों के कैंसर रोगियों में प्रजनन शक्ति तथा मृत्युसंख्या, उड़ीसा के जौंगो के बीच मधुमेहों की उत्पत्तिमूलक जनविद्या तथा भाजन व शरीर-रचना में मौसमी परिवर्तन।

अन्य कार्यकलाप

(1) 6 क्षेत्रीय नरतत्वीय संग्रहालयों के लिए नक्शे तैयार किए जा चुके हैं तथा नमूनों का संग्रह कार्य आरंभ हो चुका है।

(2) सर्वेक्षण के पुस्तकालयों में 600 पुस्तकों तथा 1790 पत्रिकाओं की वृद्धि हुई है।

(3) सर्वेक्षण के विभिन्न सदस्यों द्वारा 80 वैज्ञानिक निबन्ध, 5 पुस्तकें तथा 4 अवसरिक प्रकाशन प्रकाशित किए गए हैं।

व्यय :

1974-75 के लिए, योजनेत्तर बजट के अन्तर्गत 38,56,000 रु० तथा योजनागत बजट में 13,00,000 रु० की व्यवस्था की गई है।

—×—×—×—

चौथा अध्याय

संग्रहालय, कला वीथीयां, अभिलेखागार और पुस्तकालय

संग्रहालयों, कलावीथीयों, अभिलेखागारों तथा पुस्तकालयों के क्षेत्र में विभाग की संस्थाएं तथा कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय संरक्षण प्रयोगशाला; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद; भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता; विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली; भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, दिल्ली; डा० जाकिर हुसैन स्मारक संग्रहालय, दिल्ली; राष्ट्रीय आधुनिक कलावीथी, नई दिल्ली; गांधी दर्शन, दिल्ली।

(2) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली; खुदाबक्श ओरिएन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना; केन्द्रीय पुस्तकालय, टाउन हाल, बम्बई; अन्य पुस्तकालयों को अनुदान, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान और केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, केन्द्रीय भाषा पुस्तकालय (तुलसी सदन) सहित।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय संग्रहालय ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के संग्रह, परिरक्षण तथा प्रदर्शित करने के अपने कार्यकलापों का लगातार विस्तार किया। संग्रहालय के संग्रहों में हाल ही में शामिल की गई वस्तुओं में पटना से खोदकर निकाली गई दो मौर्यकालीन लकड़ी की बनी हुई प्रतिमाएं; तंजारे के शिवाजी महाराज को दर्शाने वाला एक हाथी दांत का चित्र तथा सागर के विश्वविद्यालय से नटराज को दर्शाने वाली एक पत्थर की मूर्ति शामिल है। राष्ट्रीय संग्रहालय को, तिरुचिरापल्ली के श्री टी० देशिकाचारी के संग्रह में से 3000 से भी अधिक भारतीय सिक्के उपहार के रूप में प्राप्त हुए थे।

संग्रहालय ने, "भारतीय कला में शिव" तथा "फारसी, चीनी, जापानी अफ्रीकी, कम्बोडियाई तथा यूरोपीय कलाओं की हाल ही की उपलब्धियां" नामक विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया था। पुस्तकालय रोयलो, ब्रसेल्स के निमंत्रण पर, संग्रहालय ने, ब्रसेल्स में भारतीय लघु-चित्रों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था। "भारत के गौरव के निर्माता" नामक प्रदर्शनी से सज्जित एक चलती-फिरती प्रदर्शनी गाड़ी दिल्ली के बहुत से स्कूलों तथा कालेजों और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भेजी गयी और इसे, अक्तूबर, 1974 में मथुरा में आयोजित अखिल भारतीय संग्रहालय के प्रतिनिधियों को तथा नवम्बर, 1974 में फरीदाबाद में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 7वें राष्ट्रीय समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था।

स्कूलों तथा कालेजों के छात्रों में संस्कृति के प्रसार की योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय संग्रहालय और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 150 किट संयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं। इनमें से, 53 केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्रदान किए गए हैं।

संग्रहालय में बहुत से व्याख्यानों का आयोजन किया गया था। निम्न-लिखित प्रकाशन भी प्रकाशित किए गए :–

(1) श्री सी० शिवराममूर्ति द्वारा "नटराज" पर एक वृहद पुस्तक ;
(2) श्री सी० शिवराममूर्ति द्वारा भारतीय मूर्तिकला में पक्षी और और पशु ; और
(3) राष्ट्रीय संग्रहालय दीर्घाओं के लिए गाइड।

संग्रहालय के प्रतिरूपण एकक (माडलिंग यूनिट) ने दर्शकों में बिक्री के लिए तथा साथ ही साथ अनुरोध किये जाने पर, शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को देने के लिए संग्रहालय के संग्रह में से भारतीय मूर्तियों की उत्कृष्ट कलाकृतियों की प्लाटर प्रतिकृतियां तैयार करना जारी रखा :

केन्द्रीय संरक्षण प्रयोगशाला

राष्ट्रीय संग्रहालय की केन्द्रीय संरक्षण प्रयोगशाला ने भारत के संग्रहालयों को उनकी महत्वपूर्ण वस्तुओं के सुरक्षित रखने में सलाह तथा सहायता देना जारी रखा। सिक्किम की सरकार को उनके एक मठ से दीवार-चित्र के स्थानान्तरण में सहायता प्रदान की गई थी। ईरान, अफगानिस्तान और बंगलादेश की, संरक्षण के मामलों में सहायता प्रदान की गई थी।

13—956 Edu. & SW/74

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद

संग्रहालय के संग्रह में, समस्त संसार से प्राप्त की गई कला वस्तुएं शामिल हैं तथा उनमें कुछ दुर्लभ तथा मूल्यवान पाण्डुलिपियां भी शामिल हैं। संग्रहालय के पुस्तकालय में 55,000 से अधिक मुद्रित पुस्तकें तथा 7,700 पाण्डुलिपियां हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान, संग्रहालय ने अनेक वीथियों में प्रदर्शन प्रबन्धों में सुधार करने, पाण्डुलिपि और कैलिग्राफी अनुभाग, शस्त्र तथा वस्त्र वीथियों के पुनर्गठन, संग्रहालय की विभिन्न कला-वस्तुओं के संरक्षण तथा उपचार आदि के संबंध में अपनी गतिविधियों को जारी रखा।

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता

भारतीय संग्रहालय के अन्तर्गत, जिसका प्रशासन एक न्यासी बोर्ड के अधीन है, छः अनुभाग हैं, अर्थात् कला, पुरातत्व, मानव-विज्ञान, भू-विज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा औद्योगिक वनस्पति।

संग्रहालय ने अपने परिसर में एक जावा-कम्बोडिया कक्ष स्थापित करने का कार्य आरंभ किया, जो कि अब पूरा होने वाला है। एक थांका-दीर्घा स्थापित करने की व्यवस्था भी प्रगति पर है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संग्रहालय द्वारा रेमब्रान्ड्स से रिप्रोडक्शन्स की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।

संग्रहालय के मानव-विज्ञान अनुभाग ने "पूर्वी भारत के जन-जातीय लोगों की भौतिक संस्कृति तथा कला का सर्वेक्षण" नामक एक योजना प्रारंभ की। उड़ीसा के कोरापुट जिला के जयपोर क्षेत्र में प्रारंभिक जांच की गई थी तथा क्षेत्र कार्य का एक छोटा सा कार्यक्रम "गदाबा" जन-जाति के बीच पूरा किया गया था। दस महत्वपूर्ण मानव-वैज्ञानिक नमूनों को वर्गीकृत किया गया था।

संग्रहालय के पुस्तकालय ने बहुत से विद्वानों तथा छात्रों को अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा। संग्रहालय ने बहुत से विख्यात अध्येताओं के लेक्चरों की भी व्यवस्था की।

विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अन्य नेमी कार्यकलापों के हाथ में लेने के अलावा, विक्टोरिया मेमोरियल हाल ने राष्ट्रीय नेता वीथी के सुधार तथा विस्तार

के रूप में अपने कार्यकलाप जारी रखे । प्रलेखों, राष्ट्रीय नेताओं तथा देश के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के चित्रों के रूप में अतिरिक्त प्रदर्शों को प्रदर्शित करने के लिए कदम उठाए गए । श्री विपिन चन्द्रपाल का तीन-चौथाई आकार का तैल-चित्र, चित्र वीथी के लिए नवीनतम अभिवृद्धि रही । दो अतिरिक्त प्रदर्शन-केस लगाए गए हैं, जिनमें जवाहर लाल नेहरु के जीवन तथा कार्यकलापों के विभिन्न चरणों को दर्शाने वाले दुर्लभ चित्रों को प्रस्तुत किया गया है ।

संग्रहालय द्वारा 1836 से 1842 तक की अवधि के दौरान कुमारी समिलि एडन द्वारा चुनिन्दा जलरंगों तथा मुगल भारत में सत्ता के स्थानान्तरण के संबंध में विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गई ।

सरकार द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर विक्टोरिया मेमोरियल हाल को, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के एक यग संग्रहालय में परिवर्तित करने का निर्णय किया गया है ।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संग्रहालय के प्रदर्शन-प्रबन्धों के पुनर्गठन में उल्लेखनीय प्रगति हुई । जवाहर लाल नेहरू की दसवीं पुण्य तिथि के अवसर पर "नव भारत का निर्माण" विषयक एक प्रदर्शनी आयोजित की गई । स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, जिस सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्गठन के कार्य को भारत ने जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में शुरु किया था, इस प्रदर्शनी में उसका विविध रूप में चित्रण किया गया था । जवाहर लाल नेहरू की विदेश नीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा तथा शान्ति के लिए उनकी आकांक्षा के संबंध में भी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी । इसके अतिरिक्त, विभिन्न वीथियों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा उसमें नेहरू की भूमिका की कहानी का चित्रात्मक प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है ।

नये पुस्तकालय भवन से, जो 27 जनवरी, 1974 को खोला गया था, पुस्तकालय के संसाधनों, तथा पाठकों के लिए उसकी सेवाओं में वृद्धि करना संभव हो सका है । 1 अप्रल, से 31 अक्तूबर, 1974 तक की अवधि में कुल 1,223 नई पुस्तकें प्राप्त की गई । पुस्तकालय ने लखनऊ के **पायनिर** के 1865 से 1949 तक के 781 खण्ड तथा बिहार में असहयोग आन्दोलन के एक विख्यात नेता,

मज्हरुल हक द्वारा सम्पादित एक साप्ताहिक **मदर लैण्ड** (1921-22) का एक खण्ड प्राप्त किया ।

बहुत से समाचार-पत्रों के पुराने अंकों की माइक्रोफिल्में तैयार की गई । पुस्तकालय ने कुछ विख्यात व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के निजी कागजात भी एकत्र किए ।

1 अप्रल, 1974 से 16 जनवरी, 1975 के बीच मौखिक इतिहास परियोजना के लिए 175 साक्षात्कार रिकार्ड किए गए और कुल मिलाकर इन रिकार्डों की संख्या 1570 (549 व्यक्तियों के साथ) हो गई है ।

जवाहर लाल नेहरू की दसवीं पुण्य तिथि के अवसर पर "स्वतंत्रता के बाद से भारत में विज्ञान" नामक लैक्चरों की एक नयी शृंखला आरंभ की गई । इस शृंखला में विख्यात भारतीय वैज्ञानिकों के तेरह लैक्चर शामिल हैं ।

भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, दिल्ली

लालकिला दिल्ली में स्थित भारतीय युद्ध स्मारक सग्रहालय में, 1914-18 के युद्ध में इस्तेमाल किए गए शस्त्र गोला बारूद, उपस्कर तथा वर्दियां प्रदर्शित की गई हैं । संग्रहालय की छत तथा भवन में की जा रही भारी मरम्मतों के कारण, चालू वर्ष के दौरान संग्रहालय जनता के लिए बन्द रहा ।

डा० जाकिर हुसैन स्मारक संग्रहालय, दिल्ली

स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसन की स्मति में एक मकबरा-एवं-संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है । मकबरा 1972 में पूरा हो चुका है तथा संग्रहालय का भवन पूरा होने वाला है । इस संग्रहालय में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त डा० जाकिर हुसैन के भू-वैज्ञानिक नमूनों के संग्रह सहित उनकी निजी वस्तुएं भी रखी जाएगी ।

राष्ट्रीय आधुनिक कला विथी, नई दिल्ली

आधुनिक कला तथा मूर्ति कला के विषय में आम जनता तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वीथी द्वारा आयोजित किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों को समीक्षाधीन अवधि के दौरान तेज किया गया । बहुत से स्कूली छात्रों ने स्लाइडों तथा फिल्मों के माध्यम सहित वीथियों के सुनियोजित शिक्षा-भ्रमणों का लाभ उठाया । विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर शिक्षकों तथा छात्रों के लिए कला को

समझने के संबंध में शिक्षा का एक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई तथा विभिन्न विषयों पर चित्रात्मक वार्तालापों का प्रबन्ध किया गया। दिल्ली नगर, निगम द्वारा भेजे गए प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए एक विशेषकला बोध सत्र का आयोजन किया गया था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, वीथी के संग्रह में 105 कला वस्तुओं की वृद्धि की गई तथा वीथी पुनः स्थापन प्रयोगशाला द्वारा 10 चित्रों को पुनः स्थापित किया गया था। आम जनता के लिए कला फिल्मों का साप्ताहिक प्रदर्शन जारी रखा गया।

आलोच्य अवधि के दौरान, प्रदर्शनी संबंधी सूचीपत्र, पुस्तिकाएं आंकड़ा स्कूल के चित्रों के रंगीन पुनरूत्पादन तथा कुछ विख्यात कलाकारों की महत्वपूर्ण कृतियों के रंगीन चित्र वाले पोस्टकाड भी वीथी द्वारा प्रकाशित किए गए।

गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली

गांधी दर्शन समिति के प्रबन्ध के अंतर्गत 2 अक्तूबर, 1970 को गांधी दर्शन प्रदर्शनी पुनः खोली गई, जिसमें पांच विषयों पर मण्डप लगाए गए थे, "मेरा जीवन मेरा सन्देश है", "मेरे स्वप्नों का भारत", "सत्याग्रह दर्शन", "सायता ही ईश्वर है", तथा "रचनात्मक कार्यक्रम"। इस प्रदर्शनी को वड़ी संख्या में दर्शकों ने देखना जारी रखा।

बापू निर्वाण दिवस, जलियांवाला बाग सप्ताह, गांधीजी का जन्म-दिवस तथा नेहरू जयंती जैसे महत्वपूर्ण दिवसों पर प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भजन, कीर्तन, फिल्म-दिखाना, सामूहिक कताई तथा सांस्कृतिक स्कूलों का आयोजन इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं होती हैं। मिट्टी का का बना हुआ एक वृत्ताकार दृश्य-पटल प्रतिरूपण प्रदर्शनी में लगाया गया है जिसम "भारत का स्वतंत्रता संग्राम" नामक राजाराम मोहन राय से लेकर स्वतंत्रता की प्राप्ति तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम चित्रित किया गया है।

बुनाई, कताई, हाथ का बना हुआ कागज तथा मिट्टी के बर्तन जैसी कुछ प्रदर्शन यूनिटें एक साधारण पैमाने पर चलाई जा रही हैं।

आयोजित दौरों के कार्यक्रम के अन्तर्गत, झुग्गी-झोंपड़ी" बस्तियों के बहुत से लोगों, तथा स्कूली बच्चों को गांधी दर्शन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

गैर-सरकारी संग्रहालयों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत देश के गैर-सरकारी संग्रहालयों को उनके वर्तमान भवनों में छोटे-मोटे विस्तार तथा विशेष मरम्मतों, प्रदर्शन तथा प्रयोगशाला उपकरणों को खरीदने और प्रकाशनों को निकालने के लिये राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रशासनों के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना में, संग्रहालय-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कुछ अध्येयताओं को वित्तीय सहायता -देने की भी व्यवस्था है। इस वर्ष योजना के अन्तर्गत भवन-गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देना संभव नहीं हो सका है, परन्तु प्रकाशनों को निकालने तथा अन्य अनुमोदित प्रयोजनों के लिए विभिन्न संग्रहालयों की सहायता की गई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना पर 30 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के प्रशासन की व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय पुस्तकालय, विधेयक, 1972 पर विचार करने के लिए नियुक्ति की गई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने 26 जुलाई, 1974 को लोक सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। विधेयक इस समय लोक सभा के सम्मुख विचाराधीन है।

संस्कृति विभाग को सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध समिति तथा कार्यवाहक पुस्तकाध्यक्ष के बीच राष्ट्रीय पुस्तकालय के कामकाज के सम्बन्ध में बहुत सी बैठकें हुई। समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझावों के सम्बन्ध में संस्कृति विभाग ने कार्रवाई आरम्भ करदी है।

पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, पुस्तकालय को कार्यात्मक आधार पर पुनर्गठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान, पुस्तकालय ने विस्तार-व्याख्यान माला प्रारंभकी और विख्यात विद्वानों ने पुस्तकालय में व्याख्यान दिए।

पुस्तकालय की आशुतोष मुखोपाध्याय संग्रह के उपहार के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पुस्तकालय ने एक प्रदर्शनी आयोजित की।

महाराष्ट्र मण्डल प्रतिष्ठान की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में पुस्तकालय ने मराठी भाषा तथा साहित्य संबंधी मुद्रित सामग्री की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन 19 दिसम्बर, 1974 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा किया गया था।

खुदा बक्श ओरीएन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना

खुदा बक्श ओरिएन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय , पटना एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, जिसमें प्राच्य भाषाओं की विशेषकर अरबी तथा फारसी भाषाओं की बहुमूल्य पांडुलिपियां तथा मुद्रित पुस्तकें हैं । अरबी तथा फारसी भाषाओं की पांडुलिपियों, मुलेख और चित्रकारी के नमूनों के अपने अद्वितीय संग्रह के लिए इसे विश्व व्यापी ख्याति प्राप्त है। अत: गतिविधियों का हमारा मुख्य क्षेत्र दुर्लभ संग्रह को सुरक्षित रखना तथा उसका विस्तार करना और अध्येयताओं तथा संस्थाओं को अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना है ।

वर्ष के दौरान, पुस्तकालय ने अपने कार्यकलापो का विस्तार करना जारी रखा और अनेक पांडुलिपियां तथा पुस्तकें प्राप्त की तथा अपने संग्रह की पुस्तकों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए भी कदम उठाए ।.प्राच्य अध्ययन क्षेत्र में विद्वानों तथा छात्रों को अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान की गई ।

दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय

दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय में एक केन्द्रीय पुस्तकालय, 4 शाखा पुस्तकालय, 7 उप-शाखाएं, 8 सामुदायिक पुस्तकालय, 16 पुस्तक जमा करने के केन्द्र तथा 5 ऐसी गश्ती पुस्तकालय गाड़ियां शामिल हैं, जो सप्ताह में एक बार दिल्ली संघ क्षेत्र के 57 केन्द्रों में जाती हैं, सम्मिलित हैं । इसकी विशेष सेवाओं में, एक ग्रामोफोन रिकार्ड पुस्तकालय, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक ब्रेल पुस्तकालय, केन्द्रीय जेल, तिहाड़ के वासियों के लिए एक पुस्तकालय तथा हिन्दूराव अस्पताल, गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल तथा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के लिए अस्पताल पुस्तकालय उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार यह पुस्तकालय दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में कुल 98 स्थानों पर अपनी सेवा प्रदान कर रहा है ।

आलोच्य अवधि के दौरान 31 अक्तूबर, 1974 तक पुस्तकालय में 20,554 पुस्तकों की अभिवृद्धि की गई, जिससे कुल पुस्तकों का भंडार 5,43,820 तक बढ़ गया, जिनमें से 3,10,499 हिन्दी में, 1,29,714 अंग्रेजी में, 69,243 उर्दू में, 26,922 पंजाबी में 1894 सिंधी में, 402 बंगला में और 5,146 ब्रेल लिपि की थीं । 31-10-1974 तक पुस्तकालय के पंजीकृत सदस्यों की संख्या 1,20,927 पहुंच गई थी । 31 अक्तूबर, 1974 तक जारी की गई कुल पुस्तकों की संख्या 13,17,564 थी । इस अवधि में 39,125 खण्डों को जिल्द बंधाई गई ।

पुस्तकालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यकलापों (अर्थात् व्याख्यान, वाद-विवाद, नाटक, फिल्म प्रदर्शन और टेलीविज़न दृश्य इत्यादि) में लगभग 30,411 प्रौढ़ों तथा 4,545 बच्चों ने भाग लिया। पुस्तकालय के पास 2,161 ग्रामोफोन रिकार्ड थे जिन्हें 31 अक्तूबर, 1974 तक 16,014 बार उधार लिया गया था।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार

1974-75 के दौरान, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपने नियमित योजनेत्तर कार्यक्रमों के अतिरिक्त बहुत सी विकास परियोजनाओं को आरम्भ किया। कुछ परियोजनाओं में प्राचीन पृष्ठभूमि के आधार पर ही किन्तु बड़े पैमाने पर कार्य किया गया। विभाग के निम्नलिखित मुख्य कार्यकलाप रहे :—

(i) **प्राप्तियां:**—वर्ष के दौरान, विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से 8,200 मिसिलों के प्राप्त होने के अतिरिक्त विभिन्न राज्य विधानों से पारित 34 अधिनियम सुरक्षा के लिए प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान विभाग ने निम्नलिखित बहुमूल्य संग्रह प्राप्त किए:—

(1) राजा महेन्द्र प्रताप, बनारसी दास चतुर्वेदी, सत्य भक्त तथा गुरुदास बनर्जी संग्रहों से संबंधित दस्तावेज।

(2) **अजीर नामा, नादिर-ए-निकात, हदायत नामा-ए-मालगुजारी** तथा कुछ मूल परवाने चार, टोंक राज्य से तथा दो अकबराबाद (आगरा) से संबंधित थे।

(3) विदेश से अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतियों में लार्ड मेकडोनल (उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल) के प्रलेखों का एक रजिस्टर, विलिंगडन कागजातों के 4 रजिस्टर, हेग अभिलेखों के, 3 रजिस्टर, पृथ्वीराज रासो की एक पुरानी पाण्डुलिपि का एक अभिलेख, 'इण्डियन' (1935–40) के 5 अभिलेख और 'इण्डियन पायनियर' (1929-30) का एक अभिलेख, सम्मिलित है।

(ii) **स्वतन्त्रता की ओर** : भारत में अधिकार स्थानान्तरण से संबंधित अभिलेखों के प्रकाशन के लिए, यह परियोजना भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के साथ संयुक्त रूप से, आरम्भ की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य अभिलेखों के 10 खण्ड प्रकाशित करना

है। वर्ष 1942 के डा० राजेन्द्र प्रसाद के पत्र-व्यवहार के अंशों का अनुलेखन कार्य किया गया है।

(iii) **प्रकाशन**:—फोर्ट विलियम इंडिया हाउस पत्र-व्यवहार के खण्ड X, XI तथा XIX को पूरा किया गया। विभागीय पत्रिका "इण्डियन आरकाइव्ज" खण्ड XXI अंक I मुद्रित हो गई।

सुधार तथा रेप्रोग्राफी : कमजोर अभिलेखों के पुन:स्थापन के अतिरिक्त जयाकर के संग्रह की माइक्रोफिल्म तैयार करने का कार्य भी आरम्भ किया गया। श्रींगेरी मठ के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म तैयार करने के लिए, अभिलेखागार के चल-कैमरा एकक को बंगलौर ले जाया गया।

अनुसंधान तथा संदर्भ सेवा: आलोच्य वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान सुविधाओं का विदेशी छात्रों सहित 380 छात्रों ने लाभ उठाया।

तकनीकी सेवा :—सदा की भांति विभाग ने, संस्थानों तथा विद्वानों को उनके संरक्षण में पुस्तकों, पाण्डुलिपियों आदि के संबंध में सहायता देना जारी रखा। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के तकनीकी अधिकारियों ने मुर्शिदाबाद स्थित हजरद्वारी महल में रखे अभिलेखों तथा पाण्डुलिपियों का निरीक्षण किया। उनको ठीक प्रकार से रखने के लिए सुझाव दिए गए।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग : भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का पुनर्गठन किया गया है। यह अब एक सुदृढ़ निकाय है जिसमें व्यापक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वानों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अभिलेखों का प्रबन्ध : भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने पंजाब और राजस्थान राज्यों की एजेंसियों की 52,552 मिसिलों का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है। अभिलेख प्रबन्ध की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन चल रहा है।

केन्द्रीय पुस्तकालय, टाउन हाल, बम्बई

यह उन तीन पुस्तकालयों में से एक है जो पुस्तक और समाचार-पत्र वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय), अधिनियम 1954, 1956 में यथासंशोधित, के अन्तर्गत देश में प्रकाशित पुस्तकें तथा समाचारपत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।

केन्द्रीय सरकार इस पुस्तकालय को इसके डी० बी० ए० अनुभाग पर कुल अनावर्ती खर्चे का दो-तिहाई तथा आवर्ती खर्चे का आधा भाग सहायता के रूप में देती है। वर्ष 1974-75 के दौरान, डी० बी० ए० अनुभाग के खर्चे को पूरा करने के लिए एक लाख रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

रज़ा पुस्तकालय, रामपुर

रज़ा पुस्तकालय, रामपुर को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए, रामपुर रज़ा पुस्तकालय विधेयक, 1974 को राज्य सभा ने पारित कर दिया है और अब यह लोक सभा के सम्मुख विचाराधीन है।

केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता

प्रकाशन :

भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थसूची (रोमन लिपि) के निम्नलिखित मासिक और वार्षिक खण्डों का प्रकाशन किया गया :—

(1) दिसम्बर, 1973 से जून, 1974 तक 7 मासिक अंक।

(2) वार्षिक खण्ड, 1972 ;

निम्नलिखित भाषा ग्रन्थसूचियां भी प्रकाशित की गईः—

(I) दासिय ग्रन्थ सूची, मलयालम विभाग (मलयालम लिपि में), 1972

(II) राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची, गुजराती विभाग (गुजराती लिपि में) मार्च, 1973 से जून, 1973 तक (4 मासिक अंक),

(III) राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची मराठी विभाग (मराठी लिपि में), 1967

राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची हिन्दी विभाग के 1965, 1966 तथा 1967 के वार्षिक खण्डों का (हिन्दी लिपि) प्रकाशन किया गया।

टी० एम० एस० एस० एम० पुस्तकालय, तंजावूर

इस पुस्तकालय के पास संस्कृत, मराठी, तेलुगु, तमिल, मोड़ी तथा अन्य भाषाओं की 40,000 से भी अधिक का समृद्ध संग्रह है जिसके अन्तर्गत वैदिक तथा वेदान्तिक दर्शनशास्त्र, ललित कला, संगीत, मूर्तिकला तथा चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकें सम्मिलित हैं। संस्कृति विभाग का अभिप्राय यह है कि इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त हो तथा इस संबंध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना अवधि में इस पुस्तकालय के लिए प्रस्तावित आवंटन 20 लाख रुपये का है और विभाग के 1974-75 के बजट में इस प्रयोजन के लिए 3 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत, सार्वजनिक पुस्तकालयों को, पुस्तकें, उपस्कर तथा पुस्तकालय फर्नीचर खरीदने तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की सिफारिशों के आधार पर पुस्तकालय भवनों के निर्माण हेतु सहायक-अनुदान दिया जाता है। वित्तीय सहायता हिस्से के आधार पर दी जाती है। पुस्तकें फर्नीचर और उपस्कर खरीदने के लिए अनावर्ती व्यय का केन्द्रीय सरकार का भाग 60% है और पुस्तकालयों के भवन निर्माण के लिए खर्चे का 40% परन्तु अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह एक निरन्तर चलने वाली योजनागत योजना है और पांचवीं योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित आबंटन 80 लाख रुपये का है।

तिब्बती रचनाओं का पुस्तकालय तथा अभिलेखागार, धर्मशाला

विदेश मंत्रालय के अनुमोदन पर यह पुस्तकालय महामहिम दलाई लामा धार्मिक कार्यों की परिषद् द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य तिब्बती पुस्तकों और पाण्डुलिपियों को प्राप्त करना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना है ताकि गहन संदर्भ सेवाओं की व्यवस्था की जा सके और संदर्भ ग्रन्थ-सूचियों तथा प्रलेखन सूचीयों इत्यादि का संकलन किया जा सके। पुस्तकालय के आवर्ती तथा अनावर्ती खर्चे की आवश्यकताओं का मूल्यांकन प्राधिकारियों की एक समिति द्वारा 1973 के दौरान किया गया था। इसकी सिफारिशों के अनुसरण में, इस संस्थान को अब तक (दिसम्बर, 1974) 1,50,000 रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

अंजुमन तरक्की-उर्दू-हिन्द, अलीगढ़

अंजुमन-तरक्की-उर्दू हिन्द, अलीगढ़, उर्दू की प्रोन्नति के क्षेत्र में कार्यरत पुस्तकालय संगठन है और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है।

इस संगठन के लिए वर्ष 1974-75 के लिए 88 हजार रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी और सितम्बर, 1974 में 40,000/– रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

"नवनालन्दा महाबिहार तथा हुएन सांग स्मारक भवन" योजना का समेकन तथा विकास

नवनालन्दा महाबिहार बौध अनुसंधान में कार्यरत एक संस्था है तथा बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तथापि, हुएन सांग स्मारक भवन का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। 1964 में भारत सरकार द्वारा स्थापित समिति की सिफारिशों के आधार पर दोनों संस्थानों को एक संयुक्त प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने तथा उसे बौध अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, नवनालन्दा महाबिहार तथा हुएन सांग स्मारक भवन, नालन्दा के समेकित विकास की योजना को, तीसरी और चौथी योजना अवधियों के दौरान इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा निश्चित धनाभाव के कारण भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत नहीं किया जा सका तथा उसे अन्तिम रूप भी नहीं दिया जा सका। इस योजना को पांचवीं योजना अवधि में आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् पुस्तकालय, सप्रूहाउस, नई दिल्ली

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और विश्व मामलों की भारतीय परिषद के मध्य सप्रूहाउस में स्थित पुस्तकालय के विभाजन के फलस्वरूप तथा पांचवीं योजना अवधि के दौरान पुस्तकालय को जारी रखने तथा उसका विकास करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं योजना के दौरान पुस्तकालय की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। आरम्भ में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय,

आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं के अध्येताओं और अनुसंधानकर्ताओं को संदर्भ और परामर्श की पूरी सुविधाएं प्रदान की गई ।

तुलसी सदन---यहां आधुनिक भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का एक संग्रह है जिसे पिछले वर्ष आरम्भ किया गया था, अब इसे दो खण्डों में बांट दिया गया है—

1. केन्द्रीय हिन्दी पुस्तकालय ।
2. क्षेत्रीय भाषाओं का पुस्तकालय ।

दोनों ही खण्ड भागलपुर हाउस में रहेंगे जिसे इस प्रयोजन के लिए नियत किया गया है।

आलोच्य वर्ष के दौरान, पुस्तकालय में इसकी रामकृष्णपुरम शाखा सहित 11,583 पुस्तकों की अभिवृद्धि की गई । 1606 भारतीय सरकारी दस्तावेज भी शामिल किए गए । पुस्तकालय को 965 पत्रिकाएं प्राप्त हुईं ।

पुस्तकालय द्वारा भारतीय शिक्षा सारांश (तिमाही इण्डियन एजूकेशन एब्सट्रेक्टस) का प्रकाशन भी जारी रखा गया ।

—o.o.o.—

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष के दौरान, मन्त्रालय ने अपने अधीन विभिन्न सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा प्रभागों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के जरिये शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी। इन रिपोर्टों की जांच की गई तथा समेकित किया गया और गृह मंत्रालय को भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त, मन्त्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्तियों और राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जायें।

इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हिन्दी भाषी राज्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर निश्चित रूप से हिन्दी में दिए जाएं। सामान्य सूचना से सम्बन्धित परिपत्र दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। विभाग के लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कामकाजी का ज्ञान है और25 अनुभागों में टिप्पणी और मसौदा लेखन में हिन्दी का आंशिक रूप से प्रयोग किया जाता है।

इस समय मन्त्रालय में हिन्दी के 43 टाइपराइटर उपलब्ध हैं। 12 और हिन्दी के टाइपराइटर शीघ्र ही मंगाये जाने वाले हैं।

अनुवाद

अब तक मन्त्रालय के 187 प्रपत्रों और नियम पुस्तिकाओं का हिन्दी में अनुवाद किया गया है।

अधिनियमों और संविधियों के अनुवाद का कार्य पूरा कर लिया गया है।

हिन्दी में अलग रजिस्टर

मन्त्रालय के सभी अनुभाग हिन्दी में प्राप्त पत्रों के लिए अलग से डायरी रजिस्टर रखते हैं और हिन्दी में भेजे गए उत्तर के बारे में विशिष्ट प्रविष्टियों की जाती हैं। जहां हिन्दी में उत्तर नहीं भेजे जाते हैं अथवा उत्तर भेजना आवश्यक नहीं समझा जाता, वहां सम्बन्धित अनुभाग उपयुक्त स्पष्टीकरण देता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मन्त्रालय और इसके छः अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना की गई है। इन समितियों की "त्रैमासिक बैठकें होती हैं और इन बैठकों में सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का पुनरीक्षण किया जाता है। बैठक के कार्यवृत्त गृह मन्त्रालय को सूचना के लिए भेजे जाते हैं। अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में, जिनके कुल कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, ऐसी समितियों की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

कर्मचारियों का हिन्दी में प्रशिक्षण

हाल ही में स्टाफ के अधिकारियों और सदस्यों के सम्बन्ध में किए गए पुनरीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि लगभग 80 प्रतिशत अधिकारी और स्टाफ के सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में ली थी या गृह मन्त्रालय द्वारा आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की थी और हिन्दी में काम करने का ज्ञान है। इसके अतिरिक्त 39 व्यक्ति विभिन्न हिन्दी शिक्षण कक्षाओं के लिए प्रतिनियुक्त किए गए। इस बात को देखने के लिए कि नामित किए गए व्यक्ति इन कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हों विशेष ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों के हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता रहा।

कार्यशालाएं

इस विभाग के हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षण देने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 1974-75 के दौरान अब तक इस प्रकार की तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

हिन्दी सलाहकार समिति

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग के लिए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में गठित हिन्दी सलाहकार समिति की पिछली बैठक 23 नवम्बर, 1974 को हुई। समिति ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और राजभाषा (संशोधित) अधिनियम, 1967 द्वारा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 में की गई व्यवस्था के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मन्त्रालय द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्राप्त की।

शिक्षा एवं संस्कृति विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में टिप्पणी

आलोच्य वर्ष के दौरान, इस उद्देश्य के लिए स्थापित कक्ष ने अपना कार्य करना जारी रखा तथा आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चितता की दृष्टि से शिक्षा एवं संस्कृति विभागों के सचिवालयों में की गई नियुक्तियों से सम्बन्धित रोस्टरों की वार्षिक जांच की, रोस्टरों की वार्षिक जांच की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त को भी भेजी गई थी।

परिशिष्ट 1

विभिन्न अध्यायों के अन्तर्गत चर्चित मदों का वित्तीय आबंटन (लाखों में)

क्रम सं०	मद		बजट प्राक्कलन 1974-75 मूल	बजट प्राक्कलन 1974-75 संशोधित	बजट प्राक्कलन 1975-76	कैफियत
1	2		3	4	5	6
	स्कूल शिक्षा :					
1.	यूनिसेफ—सहायताप्राप्त विज्ञान परियोजना	योजनागत	5.00	5.00	3.50	
2.	प्रिंटिंग प्रेस . . .	योजनागत	50.00	50.00	58.18	
3.	नेहरू बाल पुस्तकालय . .	योजनागत	9.00	6.00	8.00	
4.	पब्लिक/आवासीय स्कूलों में एन० सी० सी० के जूनियर डिविजन दल . .	योजनेत्तर	4.35	4.35	4.35	
5.	बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली .	योजनागत	3.00	1.00	1.75	
		योजनेत्तर	8.00	9.33	8.33	
6.	युद्ध के दौरान शहीद हुए या विकलांग हुए सशस्त्र सेना के अधिकारियों और जवानों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें .	योजनेत्तर	0.10	0.10	0.10	

1	2		3	4	5	6
7.	बाल केन्द्रों की स्थापना	योजनागत	—	—	1.00	
8.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक शैक्षणिक संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	7.00	7.00	5.00	
		योजनेत्तर	0.11	0.11	0.11	
9.	ऋणों के ब्याज को पूरा करने के लिए राज्यों एवं प्राईवेट संस्थानों को सहायता	योजनेत्तर	1.50	1.50	1.50	
10.	विस्तार सेवा केन्द्र	योजनागत	—	—	15.00	
11.	माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण	योजनागत	30.00	20.00	50.00	
12.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्	योजनागत	178.00	137.00	110.57	
		योजनेत्तर	(238.16)	275.42	308.09	
			(7.31)			
13.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	योजनागत	22.00	12.00	22.50	
14.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन		823.10	872.10	997.52	
15.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन		56.20	51.72	63.00	
16.	अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार		1.45	1.45	1.45	
17.	नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा		0.50	0.50	0.50	

1	2		3	4	5	6
	उच्च शिक्षा :					
1.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली . . .	योजनागत	11.00	8.59	18.00	
		योजनेत्तर	2.75	3.48	3.50	
2.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	योजनागत	4.06	3.00	4.00	
		योजनेत्तर	20.35	22.60	24.05	
3.	अखिल भारतीय महत्व की उच्च शिक्षा संस्थायें	योजनागत	4.00	3.00	4.00	
		योजनेत्तर	6.00	6.00	6.00	
4.	संवद्ध/संघटक कालेजों के छात्रावासों के निर्माण के लिए ऋण योजना . .	योजनागत	2.50	0.90	4.00	
5.	बड़े नगरों में स्वैच्छिक शैक्षणिक संगठनों को सहायता की योजना . .	योजनागत	2.00	0.60	1.50	
6.	पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण .	योजनागत	15.00	10.00	15.00	
7.	विश्वविद्यालयों/कालजों के अध्यापकों के वेतनमान . . .	योजनेत्तर	25.00	426.00	770.00	
8.	प्रैसीडेन्सी कालेज, कलकत्ता में शताब्दी पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक इत्यादि .	योजनेत्तर	0.03	0.03	0.03	

1	2		3	4	5	6
9.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग . .	योजनागत	2929.00	2629.00	3020.00	
		योजनेत्तर	1642.00	1959.00	2249.00	
10.	ग्रामीण उच्च शिक्षा/ग्रामीण संस्थानों को अनुदान	योजनागत	2.00	0.75	1.00	
		योजनेत्तर	20.20	20.52	15.40	
11.	शैक्षणिक सम्मेलन और प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान . . .	योजनागत	0.40	0.30	0.75	
12.	शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान . .	योजनागत	12.00	12.00	—	
		योजनेत्तर	—	—	12.00	
	तकनीकी शिक्षा :					
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान . .		1166.93	1494.80	1572.24	
2.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर .		155.00	186.00	243.41	
3.	प्रबन्ध संस्थान . . .		146.16	131.05	192.65	
4.	आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली		30.78	31.00	35.40	
5.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई . . .		33.82	38.66	47.89	
6.	राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई शिल्प विज्ञान संस्थान, रांची . . .		22.64	29.34	28.63	
7.	औद्योगिक डिजाइन का संस्थान .		13.50	9.50	7.80	
8.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज . .		338.00	247.53	333.50	

1	2		3	4	5	6
9.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धान .		80.00	54.00	40.00	
10.	गैर-सरकारी केन्द्रों का विकास . .		30.00	15.00	15.00	
11.	छात्रावासों के लिए ऋण . .		48.00	38.00	25.00	
12.	शिक्षुता प्रशिक्षण . . .		129.46	115.80	121.00	
13.	क्षेत्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान		72.37	77.39	80.04	
14.	कोटि सुधार कार्यक्रम . .		65.00	65.00	80.00	
15.	प्रबन्ध शिक्षा . . .		—	—	5.00	
16.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा परिषद् . .		12.00	6.00	6.07	
17.	एशिया प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक .		1.00	—	1.00	
छात्रवृत्तियां :						
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना . .	योजनागत	110.00	60.00	70.00	
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना .	योजनागत	28.00	28.00	60.00	
		योजनेत्तर	333.70	283.70	283.70	
3.	प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्र-वृत्तियां	योजनागत	2.00	2.00	0.30	

1	2		3	4	5	6
4.	ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियों की योजना	योजनागत	50.00	40.00	20.00	
5.	अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	योजनागत	10.00	5.00	10.00	
		योजनेत्तर	20.00	20.00	20.00	
6.	आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना .	योजनागत	15.00	15.00	28.00	
		योजनेत्तर	30.00	30.00	30.00	
7.	विदेश में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्र-वृत्तियां	योजनागत	20.00	11.00	38.00	
		योजनेत्तर	30.63	28.00	30.00	
8.	सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों की योजना	योजनेत्तर	30.00	30.00	30.00	
9.	बंगला देश के राष्ट्रिकों के लिए अधिछात्र-वृत्तियों/छात्रवृत्तियों की योजना .	योजनेत्तर	13.00	8.00	14.00	
10.	विदेशी छात्रों के लिए विशेष अंग्रेजी पाठ्यक्रम	योजनेत्तर	0.10	0.10	0.10	
11.	कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का निर्माण	योजनागत	1.00	—	1.00	
12.	छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि का कार्यान्वयन	योजनागत	—	—	68.70	
13.	विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियों के आधार पर विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां .	योजनेत्तर	3.00	3.00	3.00	

1	2		3	4	5	6
14.	चयन समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता . .	योजनेत्तर	1.00	1.00	1.00	
15.	भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रवृत्तियां	योजनागत	2.00	0.48	2.00	
		योजनेत्तर	7.00	7.90	8.15	
16.	आंशिक वित्तीय सहायता (ऋण) योजना	योजनेत्तर	1.00	0.90	0.90	
	पुस्तक प्रोन्नति तथा कॉपीराईट					
1.	पाठ्यपुस्तकों के सस्ते प्रकाशन : . .					
	(i) मूल्यांककों को मानदेय/अनुवाद के लिए अदायगी . .		1.25	0.15	0.50	
	(ii) संयुक्त भारत-सोवियत पाठ्य-पुस्तक बोर्ड की बैठकें		प्रावधान को मन्त्रालय के या० भ०/दै० भत्ता और आतिथ्य तथा जलपान के समग्र बजट में शामिल कर लिया गया			
	(iii) भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई विश्व-विद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकों के सस्ते संस्करणों के लिए सहायक अनुदान		5.03	12.03	12.00	
2.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड और उसकी गतिविधियां . . .		2.00	0.50	2.00	
3.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को उसके अनुरक्षण तथा उसकी सामान्य गतिविधियों के लिए अनुदान		11.60	10.90	11.75	

1	2	3	4	5	6
4.	आदान-प्रदान/श्रेष्ठ पुस्तक माला .	10.14	9.36	9.00	
5.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास—विश्व पुस्तक मेले का आयोजन . . .	6.00	0.05	6.00	
6.	पुस्तक निर्यात प्रोन्नति कार्यकलाप .	2.50	1.35	2.50	
7.	राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक स्रोत केन्द्र . . .				
	(i) कस्तूरबा गांधी मार्ग पर पाठ्य-पुस्तक सन्दर्भ पुस्तकालय (ii) आयातित पुस्तकों का प्रलेख और विश्लेषण	स्थापना, कार्यालय व्यय, या० भ०/दै० भ० इत्यादि के लिए प्रावधान को मन्त्रालय के बजट में शामिल कर लिया गया।			
8.	साहित्यिक और कलात्मक कार्य के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ को अंशदान	0.52	0.57	0.64	
9.	कापीराइट बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता . .	0.15	0.15	0.30	
10.	कापीराइट बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को मानदेय .	0.40	0.40	0.45	
11.	कापीराइट कार्यालय के लिए एक-मुस्त प्रावधान	—	—	0.50	

टिप्पणी : मद संख्या 9 और 10 के लिए बजट प्रावधान विभाग के कुल बजट में विद्यमान हैं। मद संख्या 11 के अलग से बजट शीर्षक नहीं हैं, बजट प्रावधान मुख्य शीर्ष '276' 3 ए० 1 (7) कापीराइट कार्यालय के लिए एक-मुस्त (योजनागत) 1975-76 के अन्तर्गत की गई है।

1	2		3	4	5	6
युवक कल्याण और खेल-कूद						
1.	राष्ट्रीय सेवा योजना . .	योजनागत	70.00	66.00	80.00	
2.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना .	योजनागत	5.00	3.00	10.00	
3.	आयोजना फोरम . . .	योजनागत	1.00	1.00	8.00	
4.	युवक कल्याण बोर्ड एवं समिति .	योजनेत्तर	1.00	1.50	1.00	
5.	नानक भवन . . .	योजनेत्तर	3.00	1.25	2.25	
6.	नेहरू युवक केन्द्र . . .	योजनागत	64.29	20.00	80.00	
		योजनेत्तर	30.00	30.00	32.00	
7.	राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर . . .		13.65	13.57	14.50	
8.	राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता अभियान		3.15	3.15	3.15	
9.	योग का प्रसार . . .		3.50	4.04	4.63	
10.	शारीरिक शिक्षा एवं खेल सम्बन्धी साहित्य की प्रोन्नति . . .		0.35	0.35	0.35	
11.	राष्ट्रीय खेल संस्थान को अनुदान तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना . .	योजनागत	20.00	14.00	23.00	
		योजनेत्तर	27.17	43.00	39.00	
12.	खेल संघों को अनुदान . .	योजनागत	15.00	10.00	15.00	
		योजनेत्तर	8.75	8.75	8.75	

1	2	3	4	5	6
13.	राष्ट्रीय खेल-कूद संगठन को अनुदान .	योजनागत	10.00	10.00	15.00
14.	राज्य खेल-कूद परिषद् को अनुदान .	योजनागत	20.00	10.00	20.00
15.	खेलकूद प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	5.00	4.00	4.00
		योजनेत्तर	4.00	2.50	3.50
16.	ग्रामीण खेल-कूद टूर्नामेंट	योजनागत	8.00	3.00	8.00
17.	राष्ट्रीय खेलकूद केन्द्र का विकास .	योजनागत	1.00	2.80	1.00
18.	विशेष खेलकूद स्कूल . .	योजनागत	50.00	—	24.20
19.	खेल-कूद (अर्जुन पुरस्कार इत्यादि) .	योजनेत्तर	0.15	0.20	0.20
20.	युवा सेवाओं के लिए कार्यक्रम . (नेहरू युवक केन्द्र, कार्य केन्द्र, युवा नेताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वागत केन्द्र सहित)		15.50	4.42	90.00
21.	स्काउटिंग एवं गाइडिंग . .	योजनागत	4.00	1.60	6.00
		योजनेत्तर	1.35	0.97	1.35
22.	राष्ट्रीय एकता—देश के एक भाग के छात्रों द्वारा दूसरे भाग का दौरा . .		4.00	1.50	4.00
23.	शिविर स्थलों के विकास सहित साहसिक सुविधाओं, पर्वतारोहण के प्रोत्साहन के लिए सहायता। . . .		7.00	4.00	7.00
24.	स्वैच्छिक युवक संगठनों को सहायता		2.00	2.00	2.00

1	2	3	4	5	6
25.	(क) राष्ट्रमण्डल युवक कार्यक्रम में भारत द्वारा भाग लेना . .	4.00	8.50	5.00	
	(ख) अन्य राष्ट्रमण्डल कार्यक्रम .	—	—	1.00	
26.	अन्तर्राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवक प्रतिनिधि मण्डलों का विनिमय	1.00	—	1.00	
27.	आई० एस० वी० एस०/आई० एन० वी० को अंशदान . . . योजनेत्तर	—	—	0.52	
28.	कैम्पस कार्य परियोजनाएं . .	1.00	0.80	0.80	
29.	राष्ट्रीय एकता समितियां . .	4.00	2.50	4.00	
30.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग योजनेत्तर	1.14	1.54	1.30	

भाषाएं

1.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति . . .	125.00	75.00	130.00	
2.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षण कालेजों की स्थापना . . .	15.00	1.50	13.00	
3.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी माध्यम के कालेजों तथा उनके वर्तमान कालेजों में हिन्दी माध्यम अनुभाग/विभागों का खोलना	2.00	0.50	2.00	

1	2	3	4	5	6
4.	ऐच्छिक हिन्दी संस्थाओं को वित्तीय सहायता	17.00	17.00	17.00	
5.	अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार . . .	0.30	0.30	0.40	
6.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा .	23.70	23.70	29.03	
7.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की योजनाएं .	8.00	8.00	8.00	
8.	पत्राचार पाठ्यक्रम . .	8.00	6.00	8.00	
9.	विदेशों में हिन्दी का प्रचार .	7.00	6.00	7.00	
10.	अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों द्वारा हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए छात्र-वृत्तियां	30.00	25.00	30.00	
11.	नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के हिन्दी पुस्तकालय का विकास . .	6.00	2.00	6.00	
12.	हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्या करने का संस्थान	—	—	2.00	
	(अ) उर्दू में पुस्तकों का निर्माण (तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड) . . .	12.82	7.30	12.00	
	(ब) सिन्धी में पुस्तकों का निर्माण .	1.00	0.25	1.00	
13.	कोर पुस्तकों का निर्माण . .	8.00	8.00	8.00	
14.	विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें लिखने के लिए छात्रवृत्तियां . . .	12.50	14.50	12.00	

1	2	3	4	5	6
15.	क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायक अनुदान .	48.00	48.00	80.00	
16.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से पुस्तक-निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	8.75	8.00	8.00	
17.	क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों के लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना .	7.87	4.00	3.00	
18.	अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद . . .	36.19	29.19	38.28	
19.	भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान मैसूर				
20.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों की स्थापना .	55.57	47.02	55.27	
21.	हिन्दी भाषी राज्यों के आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति .	3.00	—	3.00	
22.	स्वैच्छिक संस्कृत संस्थायें . .	20.00	20.00	21.00	
23.	संस्कृत साहित्य का निर्माण . .	6.25	5.70	8.00	
24.	संस्कृत की प्रोन्नति की अन्य योजनायें अखिल भारतीय वक्तृत्व प्रतियोगिता वैदिक सम्मेलन . . .	—	0.40	0.80	

1	2		3	4	5	6
25.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें .		20.00	15.00	20.00	
26.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान . .	योजनागत	25.00	15.48	26.00	
		योजनेत्तर	27.00	32.56	32.60	
27.	संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों/मैट्रिकोत्तर संस्कृत छात्रों/शास्त्री तथा आचार्य पाठ्य-क्रमों के लिए छात्रवृत्तियां .	योजनागत	5.00	8.00	5.00	
		योजनेतर	4.00	4.00	4.00	
28.	स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता तथा अरबी तथा फारसी के लिए छात्र-वृत्तियां		—	0.60	1.20	
	भारतीय राष्ट्रीय आयोग—यूनेस्को					
1.	यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों के लिए अनुदान . .	योजनेत्तर	3.00	3.00	—	
2.	यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों के लिए अनुदान—यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्य-कलापों में विस्तार . . .	योजनागत	1.00	0.50	1.50	

1	2		3	4	5	6
3.	यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों के लिए अनुदान——यूनेस्को द्वारा जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत द्वारा भाग लेना . .	(योजनागत)	1.00	——	——	
4.	यूनेस्को कूरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन के लिए यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का खर्चा	(योजनेतर)	——	——	4.35	
5.	यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान . .	(योजनेतर)	——	——	0.50	
6.	अन्य मदें——यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग . . .	(योजनेतर)	1.00	0.95	1.00	
7.	अन्य कार्यक्रम——मध्य एशिया की सभ्यता और बौद्ध कला का अध्ययन . .	(योजनागत)	0.60	0.60	——	
8.	अन्य कार्यक्रम——यूनेस्को से सम्बन्धित योजनाओं में आतिथ्य तथा जलपान .	(योजनेतर)	0.19	0.10	0.09	
9.	अन्य मदें——विदेशों में प्रतिनियुक्ति एवं प्रतिनिधिमण्डल . . .	(योजनेतर)	3.95	3.95	0.80	

1	2		3	4	5	6
10.	यूनेस्को सहयोग . .	(योजनेतर)	86.69	86.69	92.29	
11.	शैक्षिणक आयोजकों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालेज को अनुदान	(योजनागत)	10.00	5.00	5.00	
		(योजनेतर)	2.50	2.44	2.50	
12.	गांधी शताब्दी समारोहों के लिए राष्ट्रीय समिति	(योजनेतर)	3.84	0.34	3.50	
	प्रौढ़ शिक्षा					
1.	15–25 आयु वर्ग के युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम . .	(योजनागत)	21.00	6.00	25.00	
2.	किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम .	(योजनागत)	40.00	40.00	50.00	
3.	ग्रामीण पुस्तकालयों का जाल बिछाना	(योजनागत)	20.00	—	8.00	
4.	प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों का अधिकाधिक सहयोग . . .	(योजनागत)	10.00	—	2.00	
5.	किसान कार्यात्मक साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा में नवीनता और प्रयोग करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	(योजनागत)	20.00	10.00	15.00	
6.	बहुसंयोजक केन्द्रों और कामगर समाज शिक्षा संस्थानों के माध्यम से शहरी कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा . .	(योजनागत)	5.75	3.20	6.00	

1	2		3	4	5	6
7.	अन्य विभागों के सहयोग के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा को रोजगार एवं अन्य विकास कार्य-विधियों के साथ जोड़ना . .	(योजनागत)	1.00	—	1.00	
8.	विभिन्न स्तरों के प्रौढ़ नौसिखियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए साहित्य का निर्माण और आपूर्ति .	(योजनागत)	3.50	3.50	3.50	
9.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड . . .	(योजनागत)	14.03	7.60	14.00	
		(योजनेतर)	5.78	5.78	6.50	
10.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड और ग्रामीण विद्यापीठ	(योजनागत)	8.75	—	0.50	
	सांस्कृतिक कार्य					
1.	विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलों के दौरे—अभिनय तथा गैर-अभिनय	योजनागत	10.00	10.00	10.00	
		योजनेतर	9.16	9.16	9.16	
2.	साहित्य अकादमी . . .	योजनागत	3.00	2.00	3.00	
		योजनेतर	11.93	11.08	13.16	

956 M of Edu&SW/74

1	2	3	4	5	6
3.	ललित कला अकादमी . .	योजनागत	6.00	3.78	6.04
		योजनेतर	12.21	14.40	10.79
4.	संगीत नाटक अकादमी . .	योजनागत	5.60	3.37	8.04
		योजनेत्तर	25.75	26.10	28.02
5.	शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रदर्शनी .	योजनेत्तर	1.75	1.75	1.75
6.	स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को भवन अनुदान	योजनागत	6.00	3.00	5.00
7.	कालेज और स्कूल छात्रों के बीच संस्कृति का प्रचार . . .	योजनागत	9.00	4.00	8.00
8.	नृत्य, नाटक और रंगमंच मंडलियों को वित्तीय सहायता . . .	योजनागत	7.00	5.19	9.00
		योजनेत्तर	4.80	4.80	4.80
9.	सांस्कृतिक दलों का अन्तर-राज्य विनिमय	योजनागत	3.50	--	3.50
10.	प्लास्टिक तथा अभिनय साहित्यिक कलाओं के क्षेत्रों में विद्यमान संस्थाओं को सुदृढ़ करना और नयी संस्थाएं स्थापित करना।	योजनागत	3.00	--	3.00
11.	बच्चों के लिए पाठ्येतर सांस्कृतिक गतिविधियां . .	योजनागत	0.10	0.10	0.10
12.	भारत विदेश मित्रता सोसायटियों को सहायक अनुदान . . .		2.00	2.00	2.00

1	2		3	4	5	6
42.	नवनालन्दा महाबिहार तथा हुस्न सांग स्मारक भवन योजना का समेकित विकास	योजनागत	2.00	1.00	1.00	
43.	साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्यक्षेत्र में लगी संस्थाएं और संगठन	योजनेत्तर	1.40	1.40	1.69	
			3.15	3.15	2.11	
44.	बुद्ध दर्शनशास्त्र स्कूल, लेह . .	योजनागत	2.90	—	2.00	
		योजनेत्तर	3.82	3.72	4.00	
45.	संग्रहालयों का पुनर्गठन और विकास .	योजनागत	4.00	4.00	6.00	
46.	सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को सहायता	योजनागत	10.00	5.00	10.00	
47.	तिब्बती कृतियों का पुस्तकालय तथा अभिलेखागार धर्मशाला . .	योजनागत	1.50	1.50	1.50	
48.	टी० एम० एस० एस० एम० पुस्तकालय, तंजावर . . .	योजनागत	3.00	3.00	4.00	
49.	भारतीय विश्व कार्य परिषद पुस्तकालय, नई दिल्ली . . .	योजनागत	1.00	1.00	1.00	
50.	महाबीर की स्मृति में ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्रों की स्थापना . . .	योजनागत	6.00	—	6.00	

1	2		3	4	5	6
33.	केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता	योजनागत	2.50	1.65	2.27	
		योजनेत्तर	3.90	5.13	5.15	
34.	दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली	योजनागत	14.00	5.00	6.00	
		योजनेत्तर	16.00	15.75	17.25	
35.	खुदाबक्श ओरिएन्टल सार्वजनिक पब्लिक पुस्तकालय, पटना . . .	योजनागत	2.00	0.70	2.00	
		योजनेत्तर	2.00	2.80	2.90	
36.	केन्द्रीय पुस्तकालय टाउन हॉल, बम्बई	योजनागत	2.00	—	1.00	
		योजनेत्तर	1.00	1.00	1.25	
37.	रजा पुस्तकालय, रामपुर . .	योजनेत्तर	2.00	2.00	2.00	
38.	उच्च तिबब्ती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	योजनागत	4.70	—	3.00	
		योजनेत्तर	—	5.60	5.60	
39.	नामग्याल तिब्बती शास्त्र संस्थान, गंगटोक सिक्किम . . .	योजनेत्तर	1.19	1.05	1.16	
40.	देरातुल-मा-अरिफ-इल उस्मानिया, हैदराबाद . . .	योजनागत	0.90	0.60	0.60	
41.	अब्बुल कलाम आजाद प्राच्य अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद . .	योजनागत	—	0.18	0.18	

1	2	3	4	5	6	
24.	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता .	योजनागत	3.00	2.00	3.00	
		योजनेत्तर	9.00	10.65	10.80	
25.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता	योजनागत	2.50	2.00	2.50	
		योजनेत्तर	3.84	6.10	6.30	
26.	नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली . . .	योजनागत	4.00	2.18	5.00	
		योजनेत्तर	15.00	17.16	18.60	
27.	भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, दिल्ली	योजनेत्तर	0.37	0.51	0.49	
28.	डा० जाकिर हुसैन स्मारक संग्रहालय, दिल्ली	योजनागत	0.60	—	0.60	
29.	राष्ट्रीय आधुनिक कलावीथी, नई दिल्ली	योजनागत	6.25	6.00	6.00	
		योजनेत्तर	4.00	4.25	5.90	
30.	गांधी दर्शन, नई दिल्ली . .	योजनागत	1.00	0.25	1.00	
		योजनेत्तर	10.00	9.25	10.38	
31.	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता .	योजनागत	18.00	15.05	16.40	
		योजनेत्तर	39.00	43.29	43.61	
32.	भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार .	योजनागत	20.00	3.67	20.70 5.00	(राजस्व) (पूंजी)
		योजनेत्तर	27.80	33.04	32.96	

1	2		3	4	5	6
13.	विवेकानन्द वेदान्त सोसायटी, शिकागो		1.30	1.30	—	
14.	इंण्डिया हाऊस, पैरिस . .		0.27	0.27	0.27	
15.	भारतीय कलाश्रों का सांस्कृतिक केन्द्र, लन्दन		0.57	0.79	0.70	
16.	सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	2.50	1.10	3.00	
17.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कामगरों को छात्रवृत्तियां	योजनागत	1.00	0.70	2.00	
		योजनेत्तर	1.70	2.00	2.30	
18.	सास्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए केन्द्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला .	योजनागत	4.00	—	4.00	
19.	भारत का नरतत्वीय सर्वेक्षण . .	योजनागत	13.00	4.41	12.00	
		योजनेत्तर	38.56	47.32	56.92	
20.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण . .		517.56	473.35	590.32	
21.	राष्ट्रीय मानव संग्रहालय . .	योजनागत	1.00	—	1.00	
22.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली .	योजनागत	14.00	8.10	10.70	
		योजनेत्तर	24.00	24.25	26.20	
23.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद .	योजनागत	3.00	2.00	3.00	
		योजनेत्तर	8.00	9.65	9.80	

956MofEdu.&SW/74

प्रशासनिक चार्ट

संस्कृति विभाग

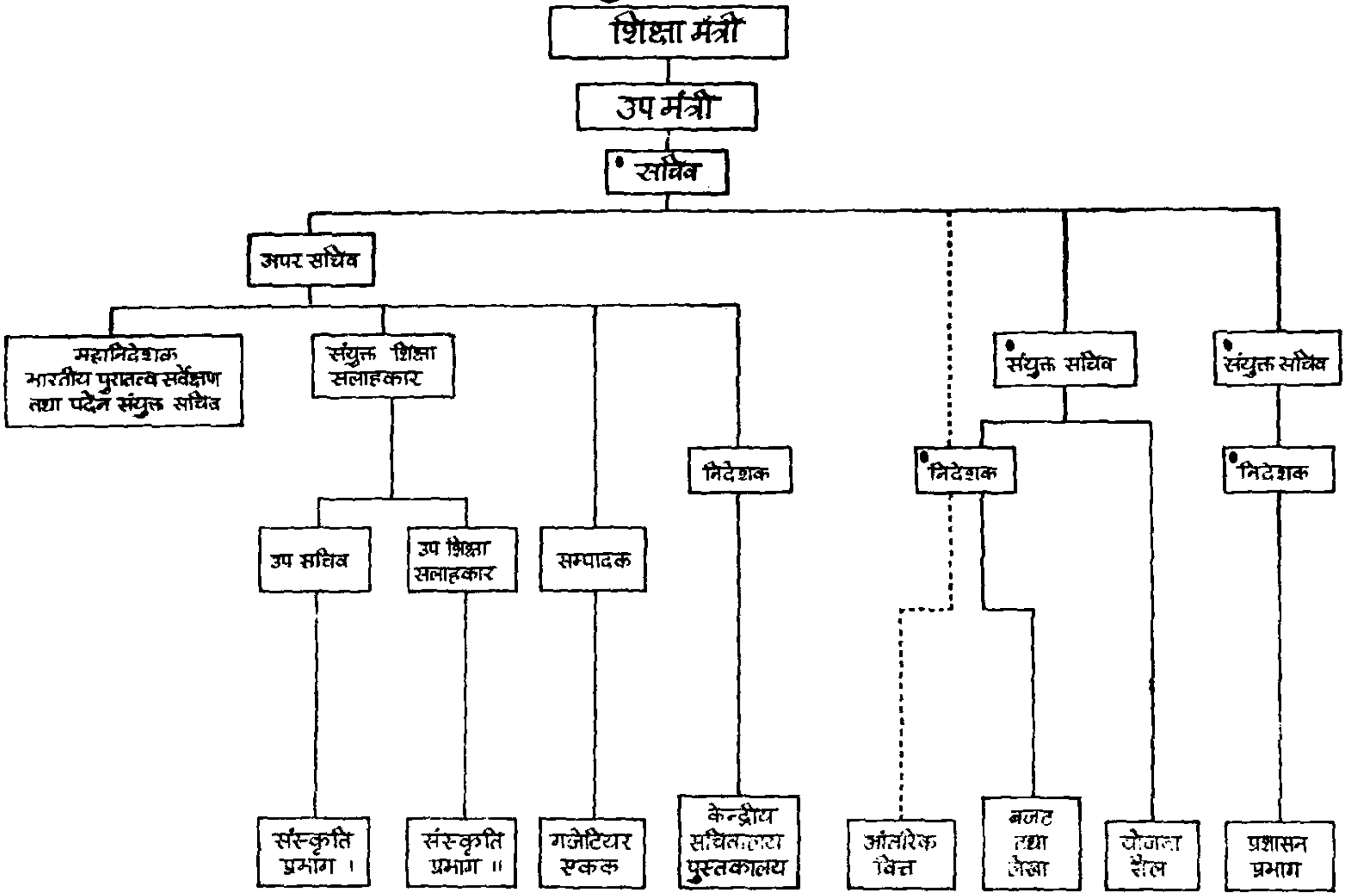

• शिक्षा तथा संस्कृति दोनों विभागों के लिये
1-3-1975 की स्थिति

956 Edu&SW/74

प्रशासनिक चार्ट
शिक्षा विभाग

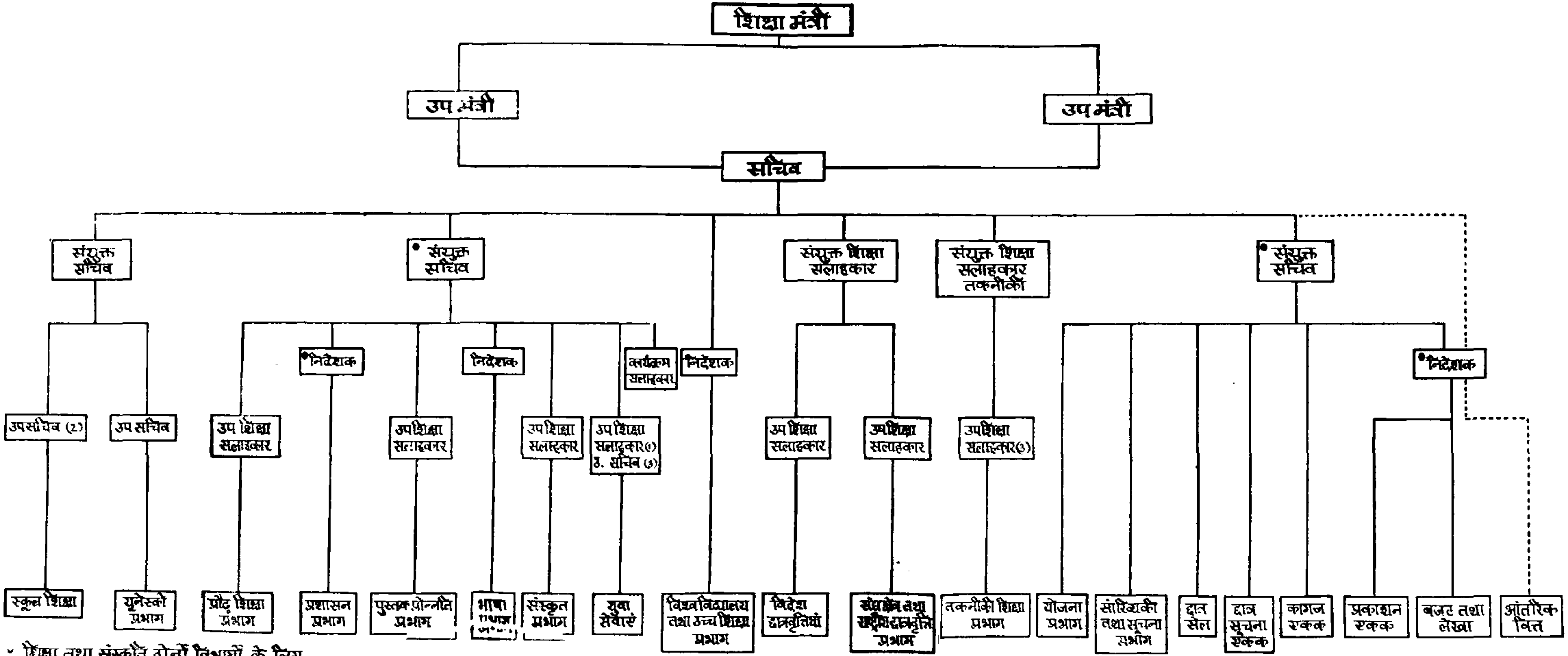

• शिक्षा तथा संस्कृति दोनों विभागों के लिए
1-3-1975 की स्थिति

956Edu&SW/74